www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

मानव आशुलिपि

तीव्र-गति अभ्यास

120 श. प्र. मि. के 100 अभ्यास

10 से 15 [illegible] की लम्बी डिक्टेशन के 25 आदर्श परीक्षा–पत्र

संघ लोक सेवा आयोग
कर्मचारी चयन आयोग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु
सभी आशुलिपि परीक्षाओं के लिये
अत्यन्त उपयोगी पुस्तक

मूल्य : 100/-

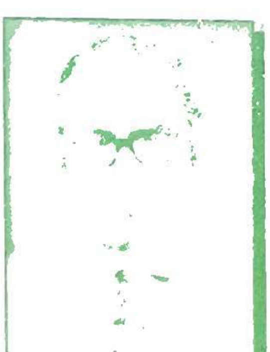

लेखक : डा. आ. म. साजनानी

एम.ए. (हिन्दी) पी.एच.डी

अवर सचिव तथा अनुभवी आशुलिपि–अनुदेशक

कृष्णा प्रकाशन

दिल्ली–110091

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-1

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस विधेयक पर आजकल जो बहस हुई / है, उसमें हमने पूरा-पूरा विरोध किया है और इस सम्बन्ध में अपने तर्क // पेश किये हैं । सरकार ने हमारे किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इन्कार कर /// दिया है । जहाँ तक इस कानून को अमल में लाने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार (1) पूरे तौर पर राज्य सरकारों पर निर्भर है । मंत्री महोदय ने कहा है कि कई / सूबों ने इस बारे में सहयोग देने का आश्वासन दिया है । लेकिन मैं जानता हूँ // कि कई सूबों ने इस कानून का बहुत सख्त विरोध भी किया है। उनका कहना /// है कि केन्द्रीय सरकार को किसी भी तरह सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के सम्बन्ध में (2) अपने अधिकार को प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ।

इस सुझाव को पेश करने में मेरा खास मकसद यह है कि अगर / सरकार ने इस विधेयक को अमल में // लाना ही है, तो फिर यह विधेयक सारे देश में एक-साथ अमल में आये /// और यह तमाम सहकारी बैंकों या सहकारी संस्थाओं पर एक-साथ लागू हो / वरना, जिस (3) सूबे की सरकार यह मान लेती है कि इस विधेयक को वहाँ पर अमल में / लाया जाय वहाँ की सहकारी बैंकों को प्रीमीयम देना पड़ेगा । इसका परिणाम यह होगा कि // यह नया बोझ उस सूबे के बैंकों पर नहीं पड़ेगा, जिसकी सरकार इस विधेयक को /// मानने से इन्कार करती है ।

मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने का यह भी लाभ (4) होगा कि अगर केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि इस कानून को किसी भी हालत / में अमल में लाना चाहिए और सहकारी बैंकों में पैसा रखने वाले लोगों // को तत्काल कानून का संरक्षण देना चाहिए, तो उस पर भी यह बंधन रहेगा कि /// चूँकि उसने इस विधेयक को एक साल में अमल में लाना है, इसलिए यह जल्दबाजी करके (5) इस विधेयक को पूरे देश पर एक-साथ अमल में ला पायेगी । (312 शब्द)

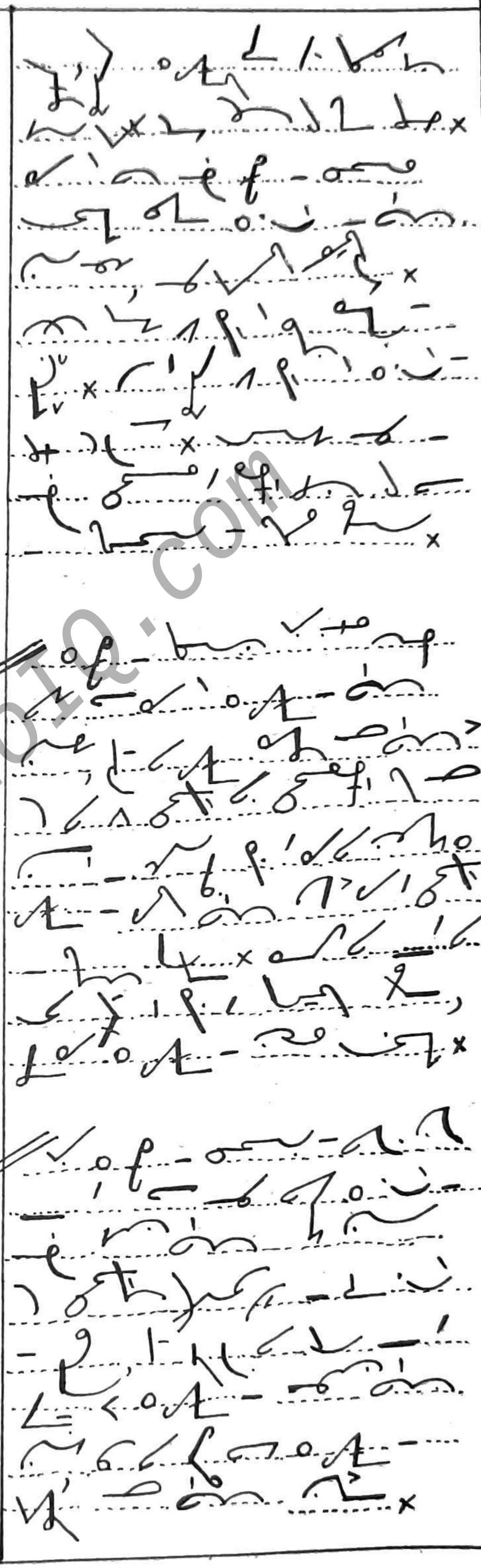

www.StenoIQ.com

अभ्यास-2

उपाध्यक्ष जी, यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महत्व कुछ कम हो गया है तो /उसका कारण यह है कि आधुनिक प्रशासन की समस्याएं अत्यन्त जटिल हैं और विधानमंडल तथा // विधायक इतने साधन-सम्पन्न नहीं हैं कि विधान तथा नीति-निर्माण की समस्याओं पर गहराई /// से विचार कर सकें तथा प्रशासन की कारगर ढंग से निगरानी कर सकें । इसलिए यह (1) मांग सर्वथा उचित है कि सचिवालयों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से / सरकार की ओर से होना चाहिए । एक विधायक या संसद सदस्य से यह आशा करना, कि // वह अपने वेतन में से एक समर्थ व्यक्ति या विधि-विशेषज्ञ का खर्चा वहन कर /// सके अव्यावहारिक है । विधान-सभाओं और संसद के सचिवालय पर सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य (2) का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शासक-वर्ग का हो या विरोधी दल का । / इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य // केवल विधेयकों की भूमिका दें और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवालय ले । /// मगर सचिवालय पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम (3) करना होगा ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के सम्बन्धों का है । / इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलतफहमियां पैदा हो गयी हैं । यद्यपि अध्यक्ष प्रायः // शासक-वर्ग का ही एक सदस्य रहता है फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के /// बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त हो कर उस प्रतिनिधि-सभा (4) के प्रति हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो । / बदलते हुए राजनैतिक नक्शे के साथ-साथ यह जरूरी हो गया है कि विधानसभाओं // और संसद में विभिन्न दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाये । विरोधी-दल अब उतने /// कमज़ोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके । मगर साथ ही उन (5) की संख्या इतनी ज्यादा है और विचार-धाराएं इतनी भिन्न हैं कि उनके लिए संसद और अनेक विधानसभाओं के बीच कोई प्रभावशाली और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है । (330 शब्द)

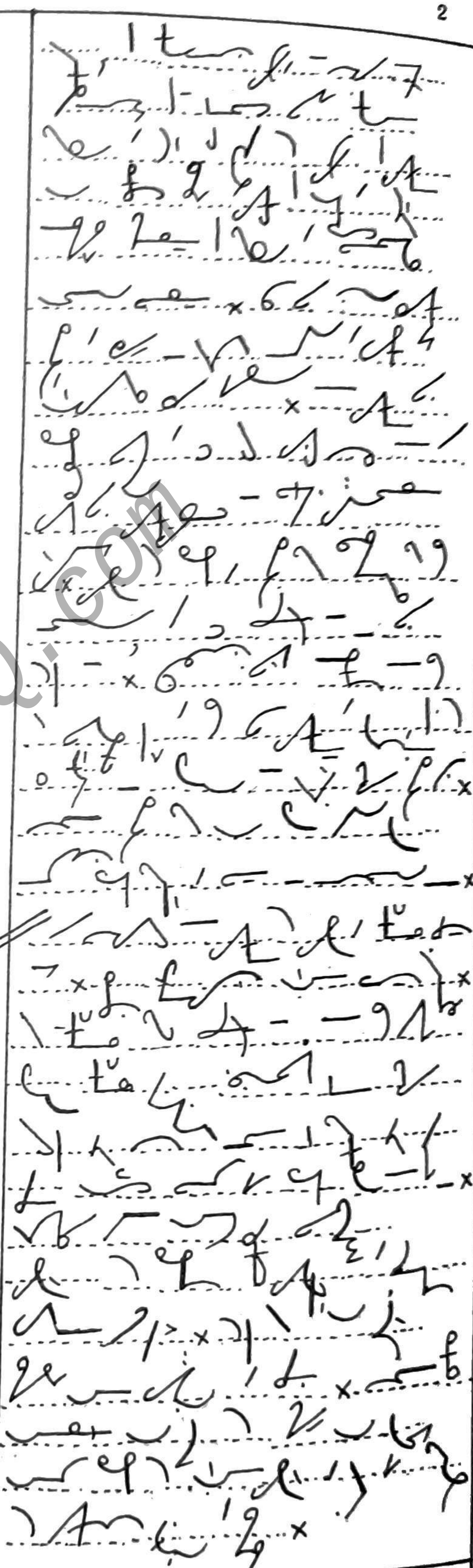

www.StenoIQ.com

अभ्यास-3

अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग / बहस कर रहे हैं वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है । उड़ीसा, बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई // है लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ /// की विशेषता है कि वहां पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ । आपको यह सुनकर ﴾1﴿ ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से / उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा । उसके बाद सन् 1967 में कटक // जिले में चक्रवात आया । परिणामस्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं । /// कटक जिले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। मेरा यह सरकार के खिलाफ ﴾2﴿ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पुरी जिले में 26 तारीख को जब चक्रवात / हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी // को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहां पर जायें या कुछ /// मंत्रियों को भेजें लेकिन वह तत्काल वहां पर नहीं गए । एक महीना इस तरह से ﴾3﴿ हो गया । अब जाकर केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहां पर गए हैं । / स्थिति की भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग // बेघरबार हुए हैं और करीब-करीब 4 लाख 88 हज़ार एकड़ ज़मीन पूरे धान की /// फसल, जो कि एकमात्र वहां की फसल है वह सब खत्म हो गयी है । // सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुर्नवास कैसे किया जाये । /// मेरा पहला सुझाव यह है कि वहां राहत कार्य के लिए राशन मुफ़्त दिया जाये ﴾5﴿ और तब तक दिया जाये जब तक वहां और कोई इन्तज़ाम नहीं हो जाता । / आपको यह भी पता है कि वहां पर बच्चों की पढ़ाई काफी पीछे पड़ गई // है । हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं । इसलिए वहां के बच्चों की फीस // माफ की जाए और परिक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाए । ﴾6﴿
﴾360 शब्द﴿

=

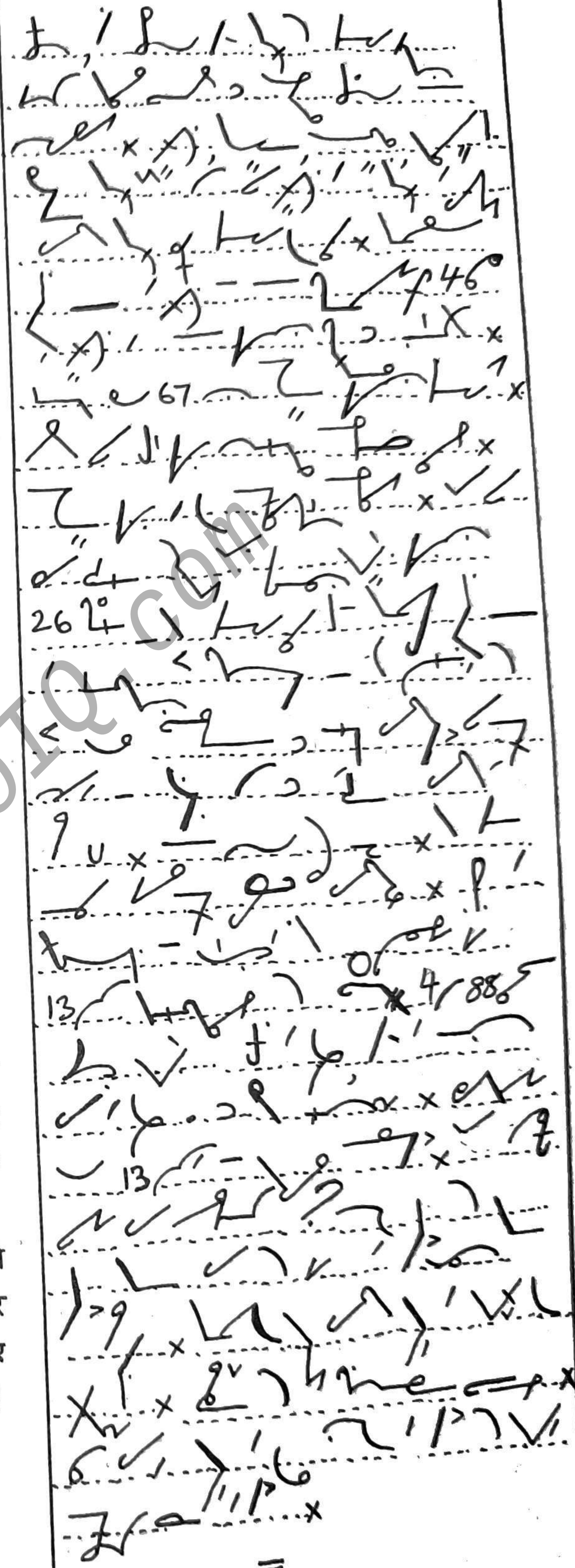

www.StenoIQ.com

अभ्यास-4

माननीय सदस्यगण, हाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने हिन्दी के विकास के बारे में जो / विचार प्रकट किये हैं वे अज्ञान के सूचक नहीं, एक धारणा के सूचक हैं जो, // हमारा अनुमान है, राज्यपाल महोदय तक सीमित नहीं है बल्कि कांग्रेस के अधिसंख्य नेताओं की /// धारणा है। बहुत से इसे स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं करते तो इसलिए नहीं कि ‖1‖ वे पूर्वाग्रह से मुक्त हैं बल्कि इसलिए कि इससे राष्ट्रभाषा सम्बन्धी एक व्यापक पाखंड की / सुविधाजनक ओट उन्हें मिल जाती है ।

राज्यपाल महोदय ने इस बात पर बहुत ज़ोर // दिया कि हिन्दी का विकास अखिल भारतीय दृष्टि से ही होना चाहिये सुनने में बात /// बड़ी अच्छी लगती है । यह बात और भी अच्छी है कि इस भाषा का विकास ‖2‖ अखिल मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से ही होना चाहिये । लेकिन जो लोग इस / ढंग की बातें करते हैं वे न भाषा विकास के नियम समझते हैं न किसी // भाषा के विकास में कोई योग देते हैं । इस तरह के लोगों की कृपा केवल/// हिन्दी पर होती है क्योंकि हिन्दी को संभाव्य राष्ट्रभाषा का नाम देकर इस विचार ‖3‖ के सब लोग उस पर मनमानी लाद देना चाहते हैं और इसके स्वाभाविक विकास में / रोड़ा अटकाते हैं ।

हम अखिल भारतीय दृष्टि से विरोधी नहीं हैं । बल्कि हमने सदा प्रादेशिक, साम्प्रदायिक या किसी तरह की भी संकुचित मनोवृत्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि और चिन्तन ///का समर्थन किया है । लेकिन हमें यह बात दोहराना भी आवश्यक जान पड़ता है कि ‖4‖ भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही सबसे अधिक और सबसे अधिक निष्ठापूर्वक अखिल भारतीय / दृष्टि से सोचती रही है और अखिल भारतीय उत्तरदायित्व वहन करने के योग्य बनने का // स्वतः प्रयत्न करती रही है । इसलिए कि यह मध्यप्रदेश की भाषा की सहज स्वाभाविक /// प्रवृत्ति और ऐतिहासिक नियति है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को राज्य की भाषा के विकास के लिए ‖5‖ अनुदान देते हुए यह आशा या मांग करे कि राज्य अपनी भाषा विकास में / योग देते हुए एक व्यापक दृष्टि को पनपाने का प्रयत्न करे तो यह आशा या // मांग सही होगी । ‖333 शब्द‖

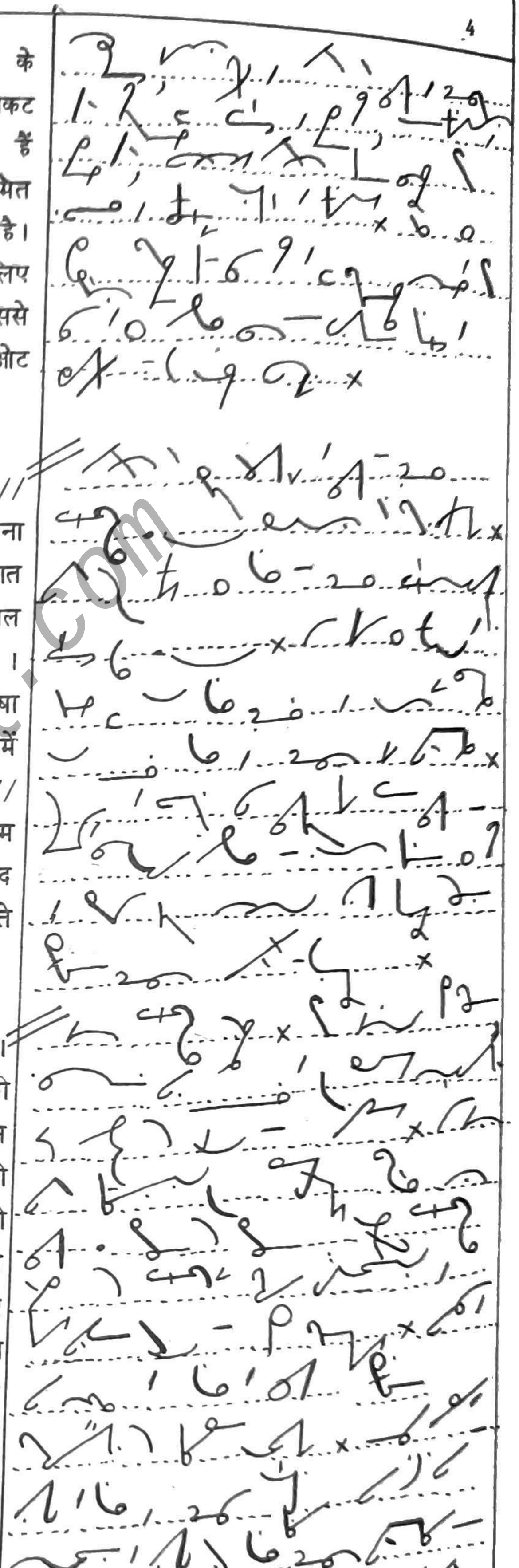

www.StenoIQ.com

अभ्यास-5

आदरणीय मंत्री महोदय तथा उपस्थित आदरणीय सदस्यों, हमारी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता तब तक पूरी / न होगी जब तक कि हम उपनिवेशवाद की आखिरी निशानियों को समाप्त कर दें । हाल ही // में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे नई विश्व व्यवस्था के कमजोर ढांचे पर एक और /// छाया पड़ी है । एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने {1} और तमाम राज्यों की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वाधीनता का समादर करने के सिद्धान्त / शान्तिपूर्ण सहजीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है और सबसे महत्वपूर्ण है ।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में // अगर बल प्रयोग का त्याग न किया गया और राष्ट्रों के अधिकार और जातियों की /// समानता का आदर न किया गया, तो तनाव को कैसे कम किया जा सकेगा अथवा {2} लड़ाई के खतरे को कैसे दूर किया जा सकेगा । सारा विश्व बुरे चक्र में फंस / गया है । इसके कारण राज्यों के बीच के सम्बन्ध नियमित करने का अच्छा अन्तर्राष्ट्रीय // तंत्र भी धीरे-धीरे शिथिल पड़ता जा रहा है और अंततः समाप्त हो जाने /// का खतरा है ।

आजकल एटमी हथियार हिंसा की चरम परिणति है। सब लोगों ने एटमी {3} हथियारों को जीवन का तथ्य मान लिया है और इसलिए वे इस खतरे के प्रति कुछ / हद तक बेखबर से हो गए हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास // किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न देश एटमी लड़ाई के लिए अपनी /// क्षमता निरन्तर बढ़ा रहे हैं । हथियारों की होड़ करने और नए से नए हथियार बनाने {4} के कारण शक्ति-सन्तुलन का सिद्धान्त बेमानी हो गया है । राज्यों द्वारा एटमी हथियारों / का परीक्षण रोक देने से इन्कार करने के कारण आंशिक रूप से परीक्षण रोक संधि // को सीमित /// रखने से ही शांति की पक्की नींव डाली जा सकती है । {295 शब्द}

=

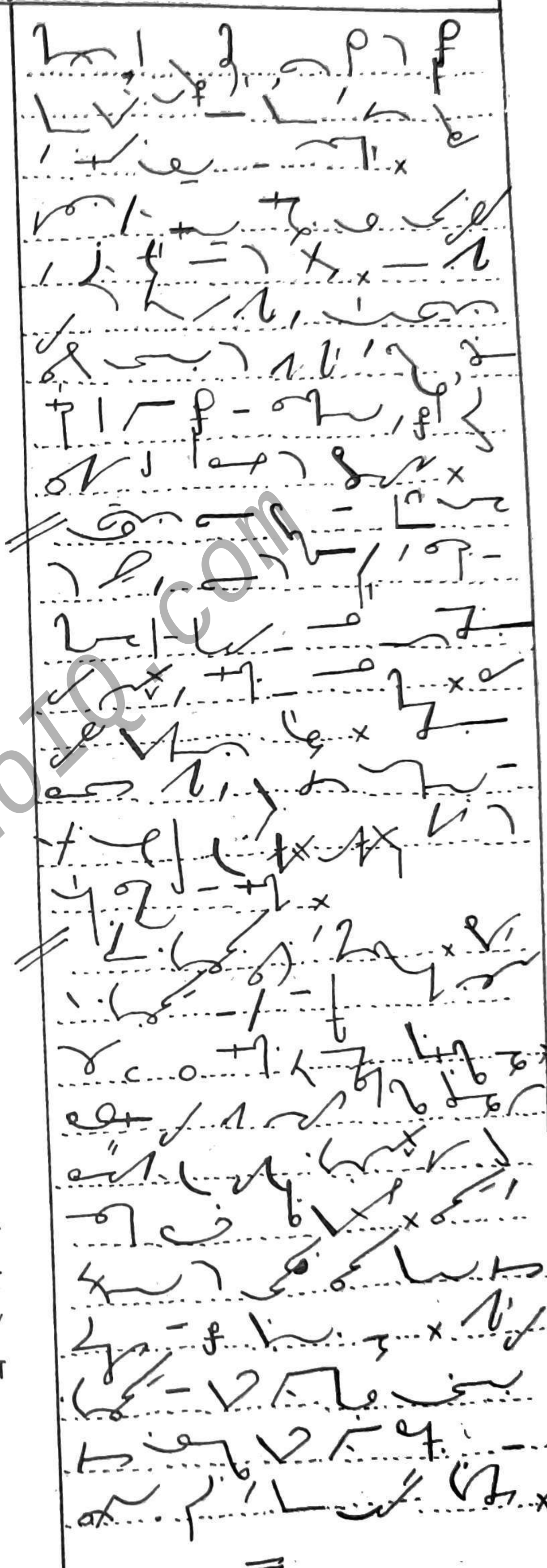

www.StenoIQ.com

उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र विश्वशांति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और सारी मानव जाति की उम्मीदें लगी हैं । संयुक्त राष्ट्र के रहने से ही यह आश्वासन मिलता है कि // विश्व के सम्मुख निर्भीक रूप से सच्चाई और न्याय लाया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र /// की यह महासभा और इसकी एजेंसियाँ जो कुछ भी कार्य करती हैं, उनमें उन्हें इन {1} आशाओं को पूरा करना है और शांति को बढ़ावा देना है । भारत के पहले / प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इस महासभा के सम्मुख भाषण किया था और कहा // था कि अमीर और गरीब देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाये । /// व्यापार और विकास के विषय पर दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे । {2} सदस्य राज्यों ने इन कार्यों में जो रुचि दिखाई, उससे विकासशील देशों में बड़ी / आशा बंधी । हमने बड़े देशों की शक्ति में भागीदार होने की चेष्टा नहीं की और // न हमने यह चाहा कि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की खातिर अपने लोगों /// की इच्छाओं का बलिदान करें । हमें {3} अपनी प्रगति के लिए स्वंय परिश्रम करना है और आगे बढ़ना है । लेकिन, हमने परिवर्तन का कोई जादू हो जाने की आशा नहीं की । / हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास का मार्ग कितना लम्बा और कठिन है । // हम इतना जरूर चाहते हैं कि लोगों की अमूर्त इच्छाओं को समझा जाए जो कि /// बहुत अरसे तक विदेशी दासता में रहे हैं।

खेद की बात है कि आर्थिक सहयोग {4} की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और न राजनीतिक क्षेत्र में अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग की / दिशा में ही कोई उल्लेखनीय प्रगति हो सकी है । इस असफलता के बहुत से // स्पष्ट कारण हैं । राजनीति पर आर्थिक और फौजी शक्ति का प्रभुत्व बना रहा । नीति बनाते /// और उस पर अमल करते समय अब भी यह ख्याल रहता है कि प्रभाव क्षेत्र {5} कैसे तैयार किया जाए । अन्य राष्ट्रों को अपने मनसूबों में ढलने की इच्छा से ही प्रचार / किया जाता है और इससे अविश्वास के बीज बोए जा रहे हैं । {328 शब्द}

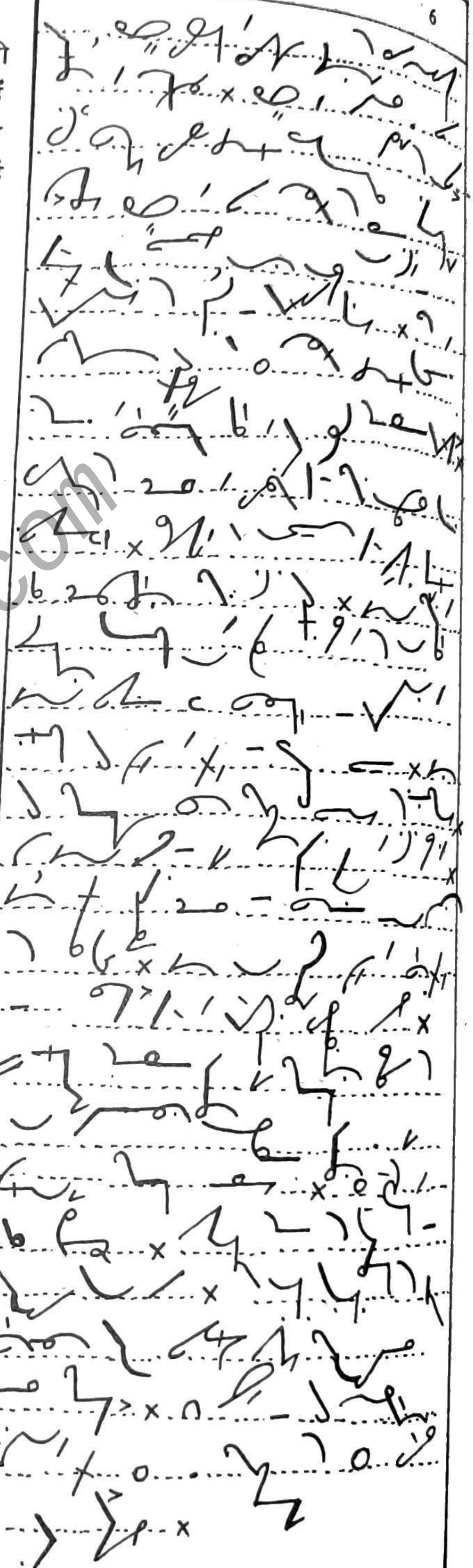

www.StenoIQ.com

अभ्यास-6

उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र विश्वशांति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और सारी मानव जाति की उम्मीदें लगी हैं । संयुक्त राष्ट्र के रहने से ही यह आश्वासन मिलता है कि // विश्व के सम्मुख निर्भीक रूप से सच्चाई और न्याय लाया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र /// की यह महासभा और इसकी एजेंसियाँ जो कुछ भी कार्य करती हैं, उनमें उन्हें इन §1§ आशाओं को पूरा करना है और शांति को बढ़ावा देना है । भारत के पहले / प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इस महासभा के सम्मुख भाषण किया था और कहा // था कि अमीर और गरीब देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाये । /// व्यापार और विकास के विषय पर दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे । §2§ सदस्य राज्यों ने इन कार्यों में जो रुचि दिखाई, उससे विकासशील देशों में बड़ी / आशा बंधी । हमने बड़े देशों की शक्ति में भागीदार होने की चेष्टा नहीं की और // न हमने यह चाहा कि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की खातिर अपने लोगों /// की इच्छाओं का बलिदान करें । हमें §3§ अपनी प्रगति के लिए स्वंय परिश्रम करना है और आगे बढ़ना है । लेकिन, हमने परिवर्तन का कोई जादू हो जाने की आशा नहीं की । / हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास का मार्ग कितना लम्बा और कठिन है । // हम इतना जरूर चाहते हैं कि लोगों की अमूर्त इच्छाओं को समझा जाए जो कि /// बहुत अरसे तक विदेशी दासता में रहे हैं।

खेद की बात है कि आर्थिक सहयोग §4§ की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और न राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की / दिशा में ही कोई उल्लेखनीय प्रगति हो सकी है । इस असफलता के बहुत से // स्पष्ट कारण हैं । राजनीति पर आर्थिक और फौजी शक्ति का प्रभुत्व बना रहा । नीति बनाते /// और उस पर अमल करते समय अब भी यह ख्याल रहता है कि प्रभाव क्षेत्र §5§ कैसे तैयार किया जाए । अन्य राष्ट्रों को अपने मनसूबों में ढालने की इच्छा से ही प्रचार / किया जाता है और इससे अविश्वास के बीज बोए जा रहे हैं । §328 शब्द§

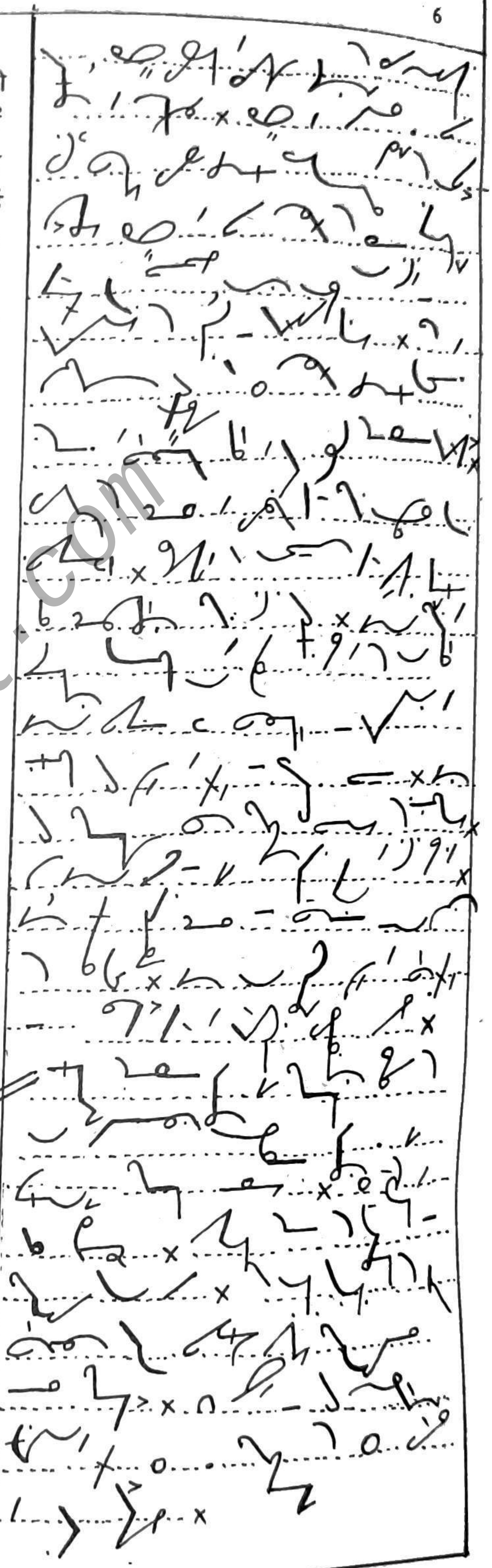

www.StenoIQ.com

अभ्यास-7

आदरणीय महोदय, प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन के बाद केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने / बताया है कि अगले अप्रैल में गेहूँ और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में // ले लेगी । सब प्रदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गये हैं । अन्न का जो संकट /// आज देश के सामने है, समूचे अर्थतंत्र के सरकारीकरण की बात सोचने वालों का उससे (1) हौंसला बढ़ा है, हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने / ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात, निर्यात, चीनी, कपड़ा, लोहा, अनाज // आदि सब के व्यापार पर सरकार कब्ज़ा करना चाहती है, क्योंकि इस सरकारीकरण को ही /// समाजवाद का पर्याय समझा जाता है । वित्त मंत्रालय पहले पचास लाख टन से अधिक के (2) भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी दो करोड़ टन अनाज / की खरीद-फरोख्त में 20 अरब रुपया फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके // पीछे क्या आर्थिक तर्क हैं, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं । /// अभी तक सिर्फ छह प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, (3) लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण / भी स्पष्ट नहीं ।

सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ // क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए । अनाज का /// क्षेत्र ऐसा ही है । जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका (4) यदि निभाये और अभाव की पूर्ति का ही जिम्मा सम्भाले, तो समस्या का द्विपक्षीय हल / भी निकाला जा सकता है और सरकार बहुत सी परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच // सकती है । लेकिन अब जो कदम उठाया जा रहा है, उसका परिणाम इससे भिन्न न /// होगा कि जनता की पहल खत्म होती जायेगी । एक के बाद दूसरे क्षेत्र के सरकारीकरण (5) की आवश्यकता महसूस होगी और सरकार तथा जनता की दूरी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जायेगी । / (315 शब्द)

=

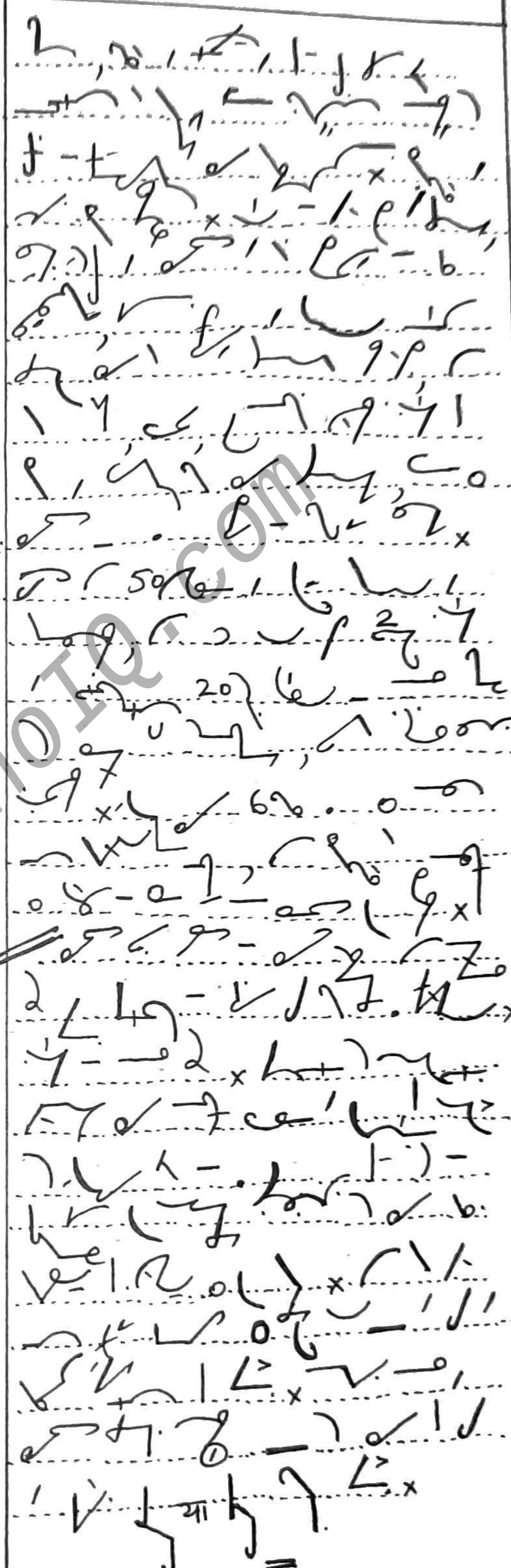

www.StenoIQ.com

अभ्यास-8

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से दूसरे स्तरों पर तथा क्षेत्रों में अनुकूल संहिता की व्यवस्था / तथा उसका पालन आवश्यक है, इस दिशा में भी जो महत्वपूर्ण तथा लाभदायक कदम उठाये // गये हैं उनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर संसदीय कमेटी का गठन महत्वपूर्ण है । /// परन्तु इस सम्बन्ध में यदि कार्य का स्वस्थ विकास करना चाहते हैं तो कमेटी के §1§ क्रियाकलापों पर संसद अनावश्यक हस्तक्षेप न करें । अतः इस कमेटी द्वारा एक निश्चित विधान द्वारा / कार्य हो, इसके लिए संसद केवल नीति सम्बन्धी प्रश्नों तथा समालोचनाओं तक ही अपने को // सीमित रखे । यही सब लोगों द्वारा भी अनुभव किया गया है । तत्पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्रों पर /// नियुक्त कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह प्रशासनिक तथा व्यापारिक प्रश्नों पर यूनिट द्वारा §2§ निर्धारित नीतियों पर गहराई से सोचें ।

संसद के पास पहले ही इतने कार्य होते हैं कि वह यूनिटों के सब पहलुओं का परीक्षण नहीं कर सकती । इसलिए यह सारा कार्यभार // कमेटी पर हो जाता है । सीमित समय होने के बावजूद भी एक कमेटी ने प्रत्येक /// यूनिट के कार्यों का पूरी तरह से निरीक्षण करने का प्रयत्न किया है और इस §3§ सम्बन्ध में लाभदायक सुझाव दिये हैं। विस्तृत प्रश्नावली भेजने के अतिरिक्त कमेटी के सदस्यों ने/ योजनाओं का तात्कालिक निरीक्षण भी किया है, अधिकारियों से भी आवश्यक पूछताछ की है तथा // अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व दूसरी आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की है । इस प्रकार /// से यूनिटों में जहाँ कहीं सुधार की आवश्यकता रही है, कमेटी इस बारे में महत्वपूर्ण §4§ भूमिका अदा करती रही है। इसी प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में / सरकार का क्या कुछ रवैया हो, इस बारे में भी प्रयत्न किए जाते रहे हैं । // सर्वांगिण विकास के लिए यह जरूरी भी है कि सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के /// सम्बन्ध में सब लोगों द्वारा ठीक प्रकार से जान लिए जायें । इस संबंध में सरकार §5§ यूनिटों के लिए कुछ मार्ग-दर्शन निर्धारित कर रही हैं । अतः मेरा सरकार से अनुरोध / है कि इस बात का पूरी तरह से पालन हो जिससे कि लक्ष्य प्राप्ति हो सके । //   §330 शब्द§

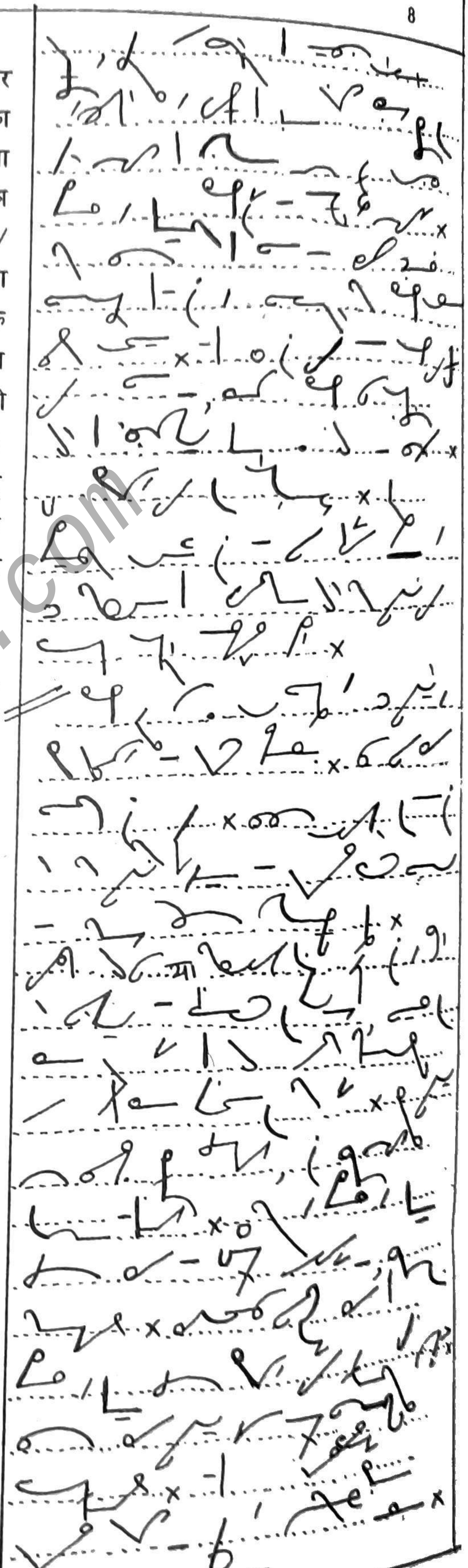

www.StenoIQ.com

मान्यवर, जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस कदम को समाजवाद की ओर एक कदम / मानते हैं, वही इस पर ज़ोर देते हैं । वे लोग ज़ोर नहीं देते जो पूँजीवादी // अर्थव्यवस्था को स्वच्छ करने को उत्सुक हैं । परन्तु भले ही जिस रूप में वह प्रस्तुत /// किया गया है और लक्ष्य चाहे कोई भी हो, आम तौर पर यह कदम उस ﴾1﴿ इच्छा का प्रतीक है जो एकाधिकार को आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विरूद्ध लड़ना चाहते / हैं । यहाँ तथ्य क्या हैं ? निःसन्देह, चन्द एक बैंक देश की अधिकांश निजी पूँजी के // अधिकार में हैं, इनकी कुल जमा पूँजी के अनुपात में अदा किया गया मूलधन तथा /// रिज़र्व बहुत ही कम हैं । यानी बड़े बैंकों में 2 प्रतिशत से भी कम इन ﴾2﴿ बैंकों के शेयरों का अधिकांश भाग कई लोगों के हाथों में बिखरा हुआ है जिसमें / से प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पूँजी रखता है। इससे बैंकों पर कारगर नियंत्रण रखने के // लिए अपेक्षाकृत अधिक शेयर रखने वालों के समूह को सहायता मिलती है । यह देखा गया /// है कि जिनका नियंत्रण बैंकों पर है उन्हीं का सम्बन्ध उद्योगों तथा व्यवसाय से होता है ﴾3﴿ । कुछ एक तो इस तरह बड़े व्यवसायिक घराने बन बैठते हैं । ये घराने फिर / बैंकों से बड़े-बड़े ऋण ले लेते हैं जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हितकर // नहीं होता । ज़ाहिर है कि इस तरह के ऋण कम शेयर मालिकों के व्यापक /// हितों के विरूद्ध जाता है । राष्ट्रीयकरण इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करता है । ﴾4﴿

ये तथ्य ही ऐसे हैं कि जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती । इस पर बहस / हो सकती है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया // जाए । सरकार के विचार में इस त्रुटि को तभी दूर किया जा सकता है जब /// कि सरकारी रिज़र्व बैंक के हाथ में अधिक नियंत्रण शक्ति हो, और इन बैंकों के ﴾5﴿ निदेशकों की समिति में कुछ सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हों । इसी / तरह से अन्य उपाय सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं । ﴾324 शब्द﴿

=

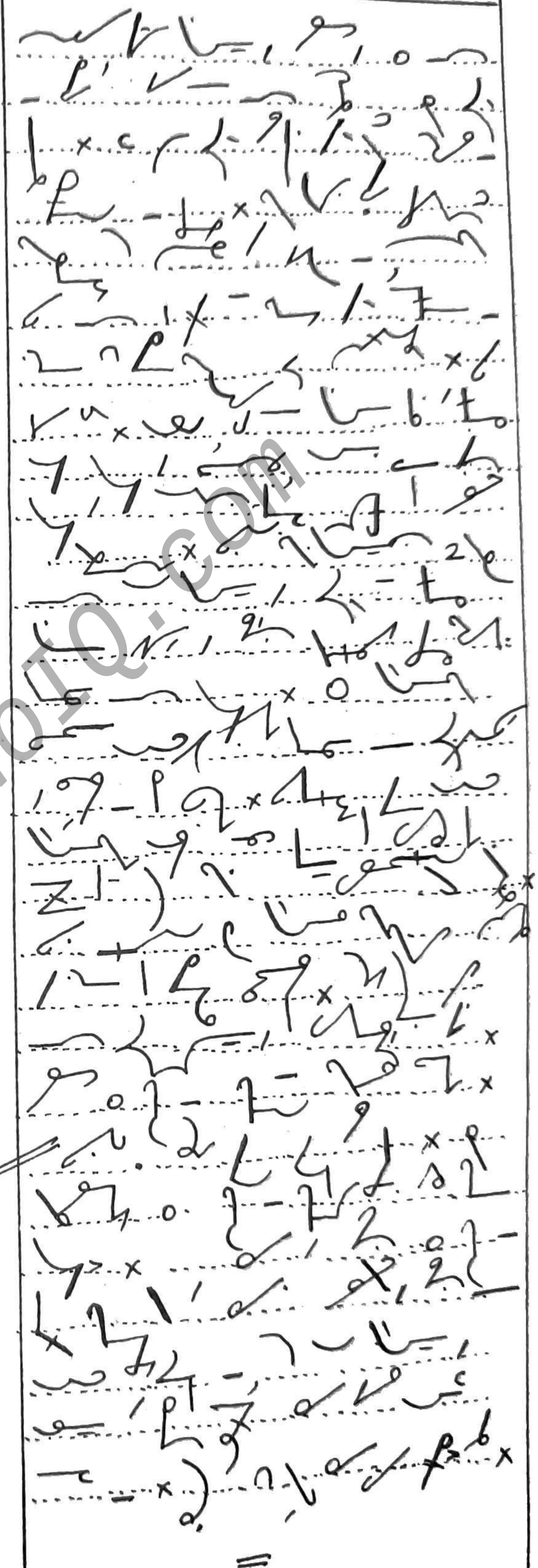

www.StenoIQ.com

अभ्यास-10

उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया / है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़-फोड़ करने वालों को मृत्युदंड दिया जाये । // दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को चाहे वे जासूस हों या तोड़-फोड़ करने वाले /// इस तरह के कठोर दंड दिये जाने की व्यवस्था है । सरकार ने इस आशा से §1§ कि लोगों में सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी इस तरह की कानूनी / व्यवस्था से बचने की कोशिश की । एक कारण यह भी रहा कि मृत्युदंड समाप्त करने // के पक्ष में जैसी जनभावना है, केन्द्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा । /// यही वजह थी कि सात साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधन किया §2§ गया तब तीन से सात साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गयी । / लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना // पड़ा कि वह तोड़-फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें।/// सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़फोड़ §3§ की घटनाएँ होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि / वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाये ।

रेल दुर्घटनाओं के संबंध में बाँचू समिति // ने जो रिपोर्ट दी, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उसकी बातों को /// सामने रखें । रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने §4§ के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं । रेलवे जाँच के बाद जिन दुर्घटनाओं के / लिए तोड़-फोड़ करने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है // और जहाँ यह मानती भी है कि दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई वहाँ ऐसे /// लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है । बाँचू समिति ने कहा है कि पुलिस §5§ ने 27 तोड़-फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 13 को ही स्वीकार किया और इनमें / से भी सात घटनाओं में वह मुलजिमों का पता लगाने में असफल रही । §334 शब्द§

=

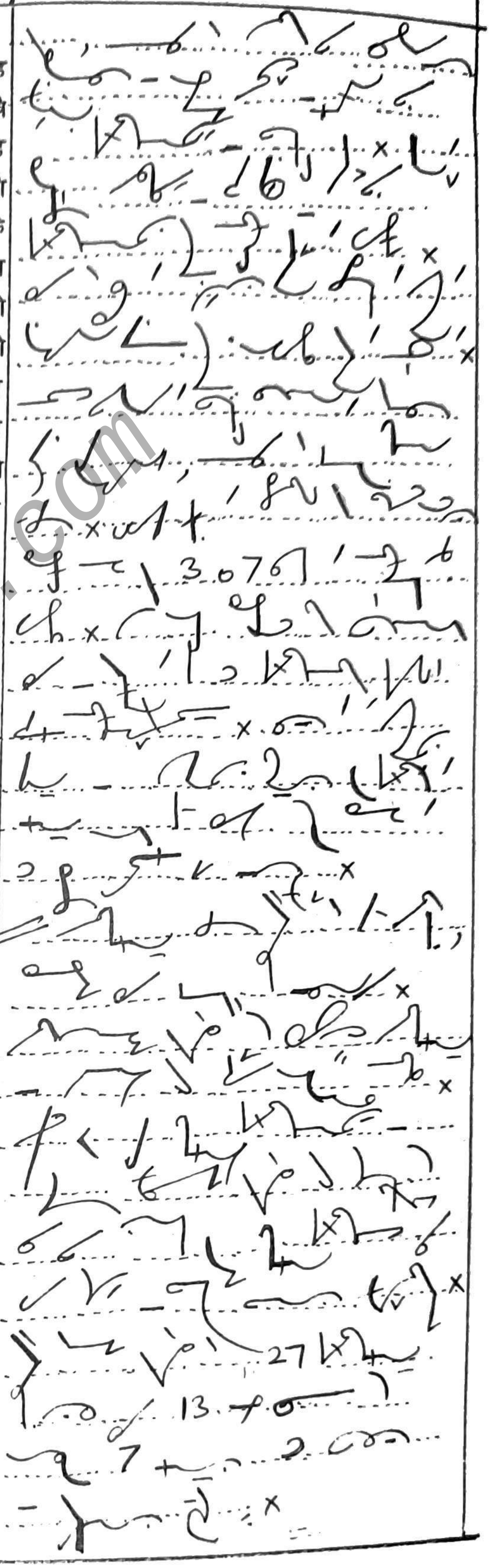

www.StenoIQ.com

उपाध्यक्ष जी, अभी दो दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार / को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है //। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किन्तु इससे /// आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती अथवा उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। गृहमंत्री ने {1} इस आरोप के जवाब में यह जरूर कहा कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के / लिए सरकार कदम उठा रही है। जहाँ कहीं से अत्याचार की शिकायत आती है, // वो अपराधियों को दंडित किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है इसके /// लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह {2} आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराये / जायें। यह सब सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से इस // सिलसिले में आवश्यक सम्पर्क रखा है किन्तु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का /// काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल इक्का-दुक्का कोई ही {3} उसका उदाहरण नहीं है स्वयं गृहमंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्य सभा में रखा / उससे भी इसकी पुष्टि हुए बिना नहीं रहती। वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक // हरिजनों पर अत्याचार की भिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएँ घट चुकी हैं। आदिवासियों /// पर जो अत्याचार हुए उसकी घटनाएं उनमें शामिल नहीं हैं। वक्तव्य में यह भी {4} बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाये। पर / यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं, जब तक यह सिद्ध नहीं होता // कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएँ कम हो रही हैं। फिर बहुत से मामले ऐसे भी /// हैं जिनमें कोई कानूनी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। अकेले मध्यप्रदेश में ही 40 {5} मामले ऐसे हैं। ऐसी सूरत में कार्यवाही सम्बन्धी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा / सकता है। {317 शब्द}

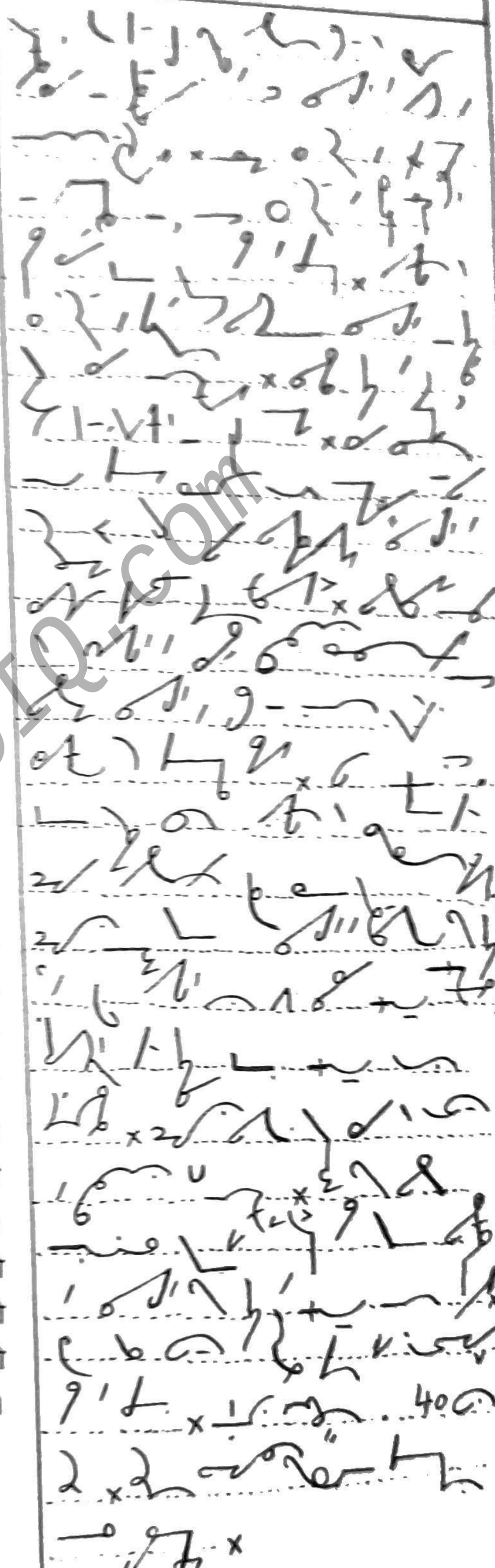

अभ्यास-12

उपाध्यक्ष महोदय, समस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से सम्बन्ध रखती है । मैं / जानना चाहता हूँ कि अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया, और क्षेत्रफल को बढ़ने से // रोक दिया और उस सूरत में किसान ने पैदावार के अच्छे साधन अपना कर जितनी /// ज़मीन में वह गन्ना पैदा करता है उसमें ही अधिक गन्ना पैदा कर दिया {1} तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी ? मेरा निवेदन है कि यह सवाल / घनी खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है। सवाल यह है कि जितना // गन्ना चीनी में खप सकता है आज वह उस सीमा तक पहुँच गयाहै । /// अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम {2} उठाया जा सकता है । जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना / होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है । इसका हमें // थोड़ा-सा विचार करना चाहिए कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद /// बढ़ नहीं सकती है । गांव में जाकर हम देखें बहुत से लोगों को चीन खाने {3} के लिए नहीं मिलती है । वे चीनी खाना भी चाहते हैं मगर चीनी के / दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर गांव वाले चीनी खरीद नहीं सकते हैं । // अभी कन्ट्रोल हटा है चीनी के दाम भी कुछ कम हुए हैं । इसके फलस्वरूप /// चीनी की खपत बढ़ी है । मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के समय में जब {4} विवाह शादियों का मौका था अगर यह कन्ट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत / और भी बढ़ सकती थी। इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि चीनी की खपत / बढ़ाई जाए । इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक्साइज़ ड्यूटी में कुछ कमी करने के /// सवाल पर सरकार को विचार करना होगा । कुछ दिनों से समचार पत्रों में इस तरह {5} की बात छप रही है कि सरकार चीनी पर एक्साइज़ ड्यूटी कम करने के बारे में / विचार कर रही है, लेकिन केवल विचार करने से ही काम नहीं चलेगा । अब समय // आ गया है कि इसे क्रियात्मक रूप दिया जाए । लोग इसका बेसबरी से इंतजार कर रहे /// हैं और इसका अवश्य स्वागत करेंगे । {350 शब्द}

=

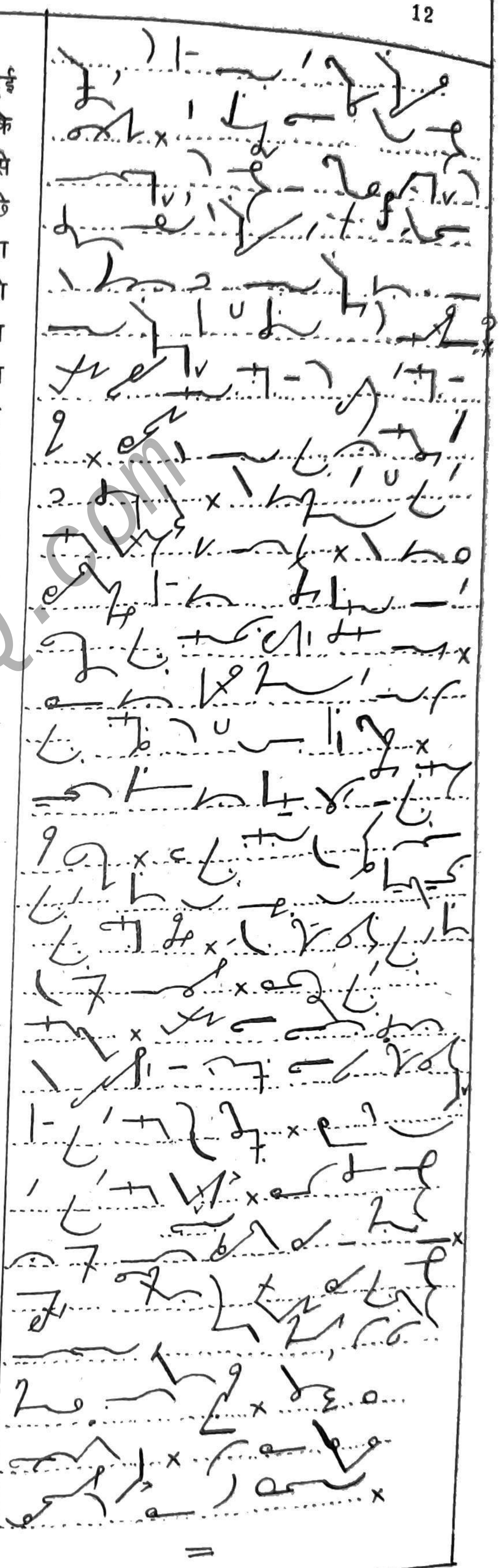

www.StenoIQ.com

अभ्यास-13

उपसभाध्यक्ष जी, अंग्रेज़ी समझने वालों की संख्या 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है । यहाँ की / दूसरी भाषाओं के जानने वाले कई करोड़ नागरिक हैं । उसमें से अगर इस 2 फीसदी // को काट दिया जाये, तो शेष लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए तथा ज्ञातव्य /// देने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं {1} के माध्यम से करें और अंग्रेज़ी से केवल अनुवाद मात्र हुआ करे । जैसाकि कई / सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है सन् 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा राजभाषा // हिन्दी होगी और अंग्रेज़ी उसकी सहकारी भाषा बनी रहेगी । मैं चाहता हूँ कि अभी /// से ऐसे कदम उठाये जायें कि देश भर में हिन्दी के माध्यम के द्वारा यह {2} कार्य सुचारू रूप से चलने लगे ।

हमें कुछ आंकड़े दिये गये थे उसमें बतलाया गया है / कि प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो में हिन्दी विभाग के सोलह कर्मचारी हैं । मैं मंत्री महोदय को // बतलाना चाहता हूँ कि सोलह वर्ष पूर्व भी इतने ही कर्मचारी थे । इसमें कोई प्रगति /// नहीं हुई है । उर्दू विभाग में चार सूचनाधिकारी हैं और हिन्दी में केवल एक जबकि {3} अंग्रेज़ी में पन्द्रह बीस सूचनाधिकारी मुकर्रर हैं । जबकि हिन्दी का इतना बड़ा काम / हमारे देश में हो रहा है, हर काम हिन्दी माध्यम से हो रहे हैं // ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आपकी लोकसभा में हिन्दी के काम में /// बहुत उन्नति हो रही है, और अगले सत्र से हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में आप {4} साथ-साथ अनुवाद दिलाया करेंगे । अगर इस काम में सूचना मंत्रालय पिछड़ा बना रहे, / अपनी भाषा सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में, तो यह बड़ा असन्तोषजनक, आश्चर्यजनक तथा दुखदायी होगा । // इसलिए मैं चाहता हूँ कि सूचना मंत्री इस प्रतिवेदन पर तो ध्यान दें, जिसके लिए /// वे बधाई के पात्र हैं, साथ ही साथ कोशिश करें कि हिन्दी माध्यम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा {5} काम होने में प्रगति हो सके । {306 शब्द}

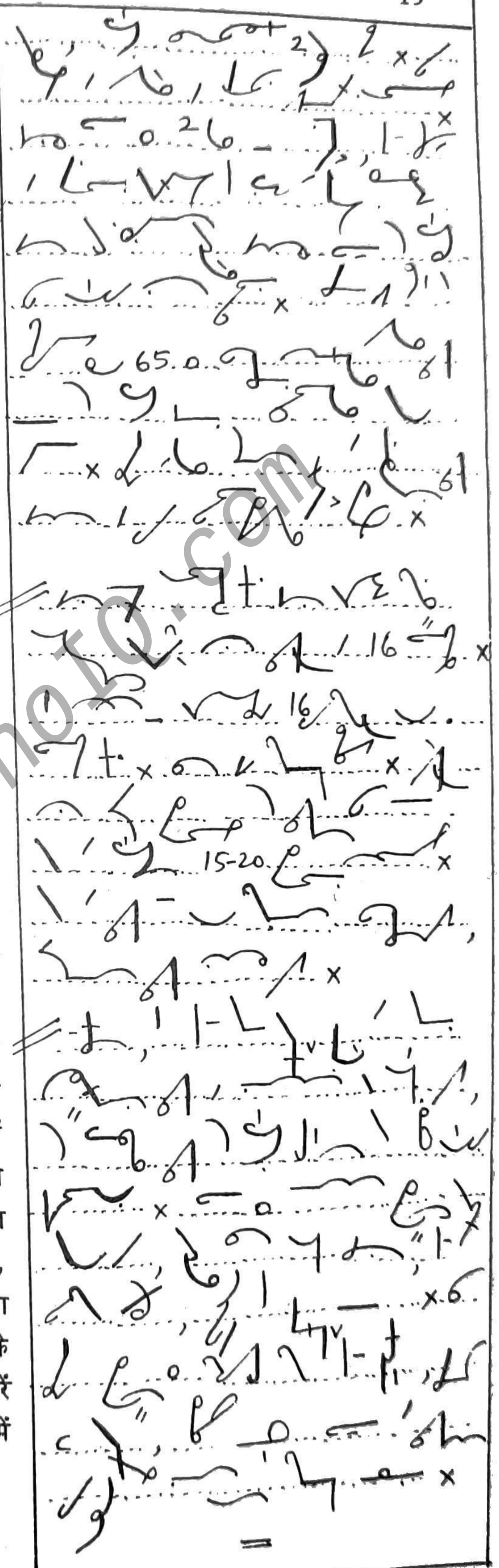

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

अभ्यास-14

आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं छात्र-संघों के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना / चाहता हूँ । आज का नवयुवक छात्र विश्वविद्यालयों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर // रहा है । उस समूची शिक्षा-पद्धति के ढाँचे को बदलने के पक्ष में है और /// उसकी यह मांग आज की आवश्यकता को देखते हुए समीचीन जान पड़ती है क्योंकि आज (1) की शिक्षा का जीविका से सम्बन्ध छूट-सा गया है । छात्र आन्दोलन की स्वर्ण-जयन्ती / के अवसर पर क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है । सारे देश के विश्वविद्यालयों के छात्र संघों // को प्रति वर्ष एक करोड़ रूपया मनमाने रूप से व्यय करने के लिए मिलता है । /// यह एक बड़ी धन-राशि है ।

गाँधी जी ने देश से कहा था कि (2) मुझे एक करोड़ रूपए और एक लाख स्वयंसेवकों को दो तो मैं देश स्वतंत्र करा /दूँगा । आज के छात्र-संघ के पास एक करोड़ से भी ज़्यादा रूपया और दस // लाख से भी अधिक स्वयंसेवक हैं । युवा छात्रों को अवसर देना चाहिए कि वे /// ही शिक्षा का नया संविधान तैयार करें । वे ही पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा पाठयक्रम का निर्माण (3) करें । इसके लिए छात्र-संघ का अविधवेशन बुलाया जाये जिसमें उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के तीस वर्ष से कम आयु के // प्रतिनिधि छात्र-छात्राओं का उचित प्रतिनिधित्व हो ।

सब मिलकर सविधान और आचार-संहिता तैयार /// करें, उस संविधान और संहिता के अनुसार शिक्षा-प्रदान करने वाले कुछ विश्वविद्यालय उन्हें (4) सौंप दिए जाए और शेष विश्वविद्यालयों के आंदोलनकारी छात्रों को उसी विश्वविद्यालय में भेज दिया / जायें । इस प्रकार छात्रों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा । अन्य विश्वविद्यालय छात्र-आन्दोलन से बच // जायेंगे और शिक्षा-पद्धति की नयी प्रयोगशाला भी तैयार हो जाएगी । किन्तु इस कार्य में /// कुछ समय लग जाएगा तब तक आन्दोलनकारी छात्रों को नियमों का पालन करना अनिवार्य (5) बना दिया जाये । (302 शब्द)

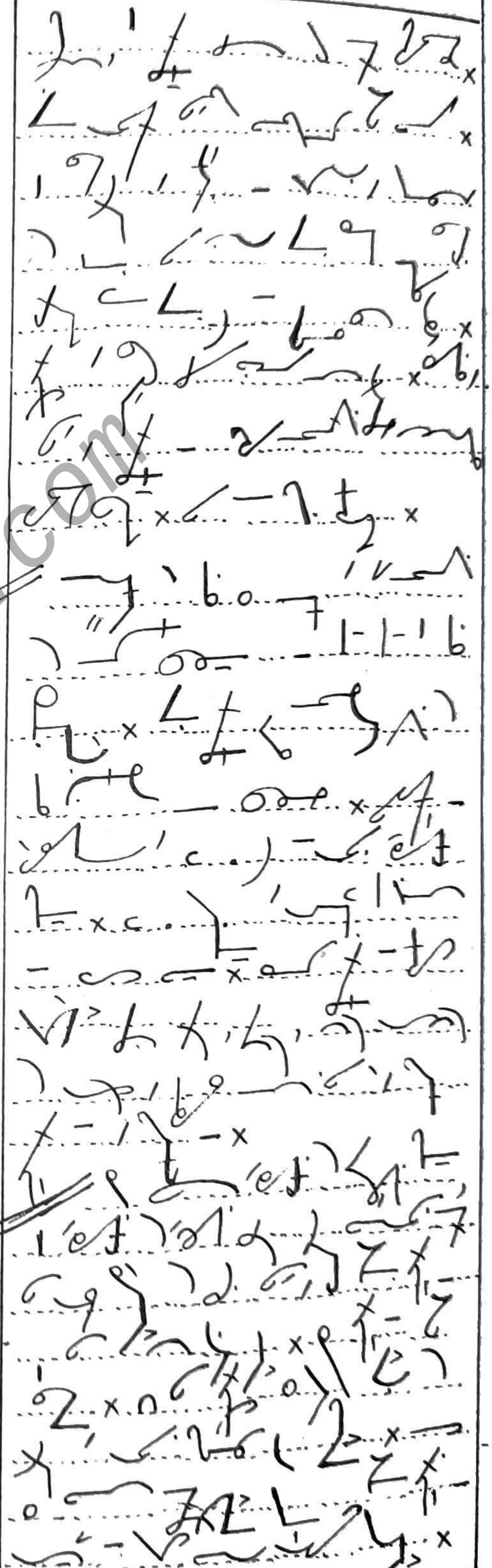

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-15

सभापति महोदय, संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में यह घोषणा की गयी है कि पिछड़े / इलाकों के औद्योगीकरण के लिए प्रोत्साहन की वर्तमान योजना की समीक्षा करके संशोधित योजना // तैयार की जा रही है । यह भी बताया गया है कि इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन /// की चालू योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव के बारे में जितने भी अध्ययन {1} किए गए हैं, उस सब की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक अन्तरमंत्रालयी समिति / बनाई गई है। इसके अतिरिक्त राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस संबंध // में शीघ्र अपने विचार भेजें । मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा कि देश के /// विभिन्न इलाकों में औद्योगिक असमानता दूर करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। {2} उनके फलस्वरूप इस वर्ष जनवरी से सितम्बर तक जितने औद्योगिक पत्र जारी किए गए हैं / उनमें से 52 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों के लिए थे । अतः मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

मेरे विचार में बेरोज़गार युवकों के लिए स्वयं-रोज़गार योजना को अब तक के अनुभवों /// के आधार पर संशोधित करने की ज़रूरत है । पिछले दो साल से चल रही {3} इस योजना में जो कमियाँ दिखाई दी है उन्हें दूर किया जाए । ऋण के आवेदन पत्रों / पर जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए और निर्णय होने के बाद पैसा देने में // विलम्ब न हो । स्वयं-रोज़गार योजना पर अमल में निरन्तर प्रगति हो रही है। फिर /// भी सुधार की गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता । मार्च, 1985 तक {4} 8 लाख 94 हज़ार आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से 3 लाख 68 हज़ार के सम्बन्ध / में ऋण देने की सिफारिशे की गई और सवा दो लाख मामलों में कुल 390 // करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए । इससे 90 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति होने का /// पता चलता है । इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के पहले चार महिनों में औद्योगिक उत्पादन {5} की विकास दर 6·1 प्रतिशत रही । जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में भी / 17·2 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस सबसे औद्योगिक वातावरण में सुधार होने का प्रमाण // मिलाता है । {332 शब्द}

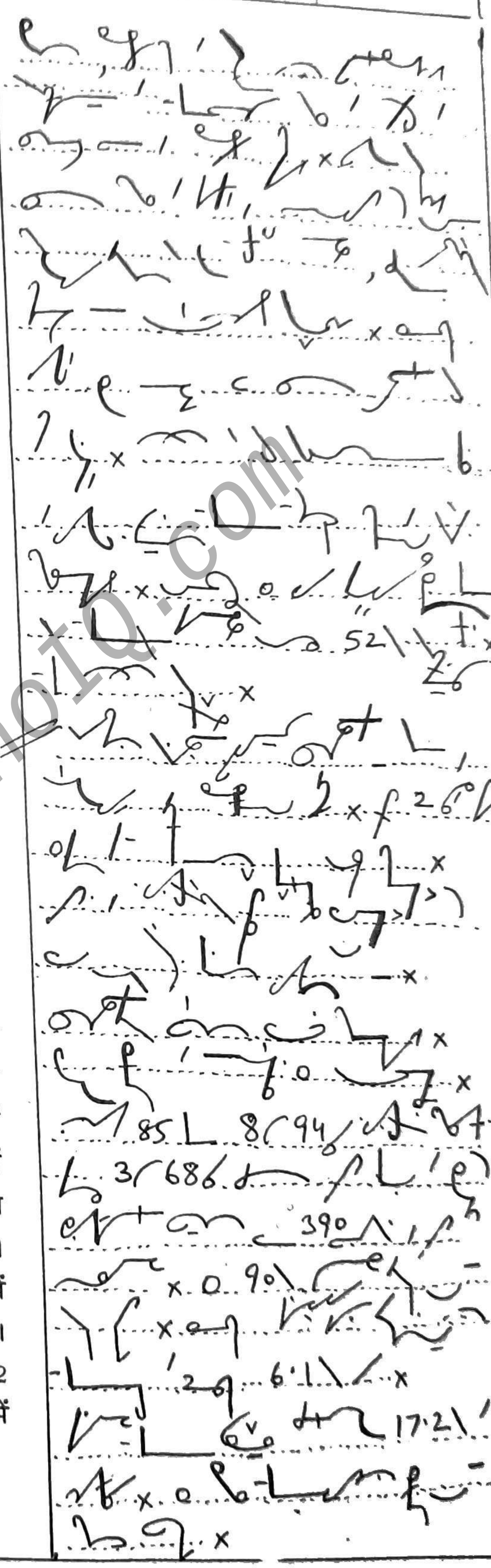

www.StenoIQ.com

अभ्यास-16

माननीय मंत्री जी, इस बार का शिक्षक दिवस किस प्रकार मनाया गया यह हम सब / जानते हैं । एक तरफ राष्ट्रपति देश भर के चुने हुए शिक्षकों को अलंकृत कर रहे // थे और प्रधानमंत्री शिक्षकों को उनकी गरिमा की याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ /// कई शिक्षक और छात्र-संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे । यों तो {1} समाज का कोई भी वर्ग आज संतुष्ट नहीं दिखाई देता परन्तु शिक्षक वर्ग आजकल कुछ // अधिक ही असंतुष्ट दिखाई पड़ता है । सवाल यह है कि जिन लोगों को आप भावी /// पीढ़ी का निर्माता मानते हैं, आप उन्हें वास्तव में कितना मान देते हैं यह किसी {2} से छुपा नहीं है ।

प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की नींव है । परन्तु क्या आपने सोचा / है कि वह कितनी मज़बूत है । देश के प्राथमिक स्कूलों में कोई 14 लाख शिक्षक // साढ़े पांच करोड़ बच्चों को ज्ञान की रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं । /// आपने कभी यह भी सोचा है कि देश के हज़ारों प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई {3} का इंतज़ाम है या नहीं । आज से 21 साल पहले शिक्षा आयोग की रपट आई / थी, जिसमें सुझाया गया था कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कम से कम छः प्रतिशत // शिक्षा को जाना चाहिए । आज भी यह 3 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं । आज प्राथमिक /// और माध्यमिक स्कूलों को दी जाने वाली रकम का 15 प्रतिशत अकेले वेतन पर ही {4} खर्च हो जाता है । स्कूलों के लिए मकान, ब्लैक-बोर्ड, पुस्तकालय, खेल-कूद तथा बच्चों / के मनोरंजन के दूसरे साधनों के लिए कुछ बचता ही नहीं । प्राथमिक शिक्षकों को // इस बात का दुःख है कि स्कूलों से निकले एक प्रतिशत बच्चों को कालेजों में /// पढ़ाने वालों को जितना मिलता है उसका 10 प्रतिशत भी हमें नहीं मिलता । शिक्षक नौकरशाही {5} के इशारे पर चलने वाला शंतरज का एक मोहरा मात्र रह गया है । अतः मेरा / माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे समय रहते इस सम्बन्ध में कुछ करें // ताकि शिक्षक-वर्ग के अन्दर जो यह असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है /// दूर हो सके। {348 शब्द}

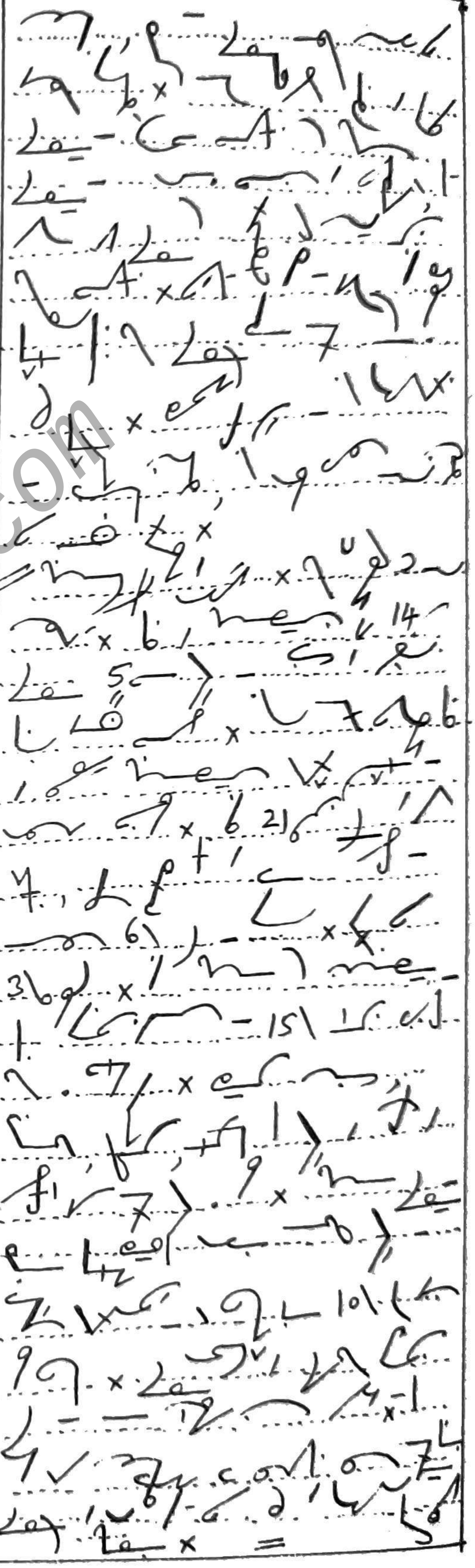

www.StenoIQ.com

अभ्यास-17

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार उद्योगपतियों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए / हमेशा तैयार है लेकिन वह किसी भी बेईमान आदमी को माफ नहीं करेगी । सरकार // पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने बिना किसी तैयारी और आधार के बड़े-बड़े /// औद्योगिक घरानों पर छापे मारे । यह प्रचार इतना ज़्यादा किया गया कि मजबूर होकर सरकार ﴾1﴿ को संसद में उन औद्योगिक घरानों के नाम बताने पड़े, जो अपने ही सलाहकारों की / राय के खिलाफ कर चोरी कर रहे थे । मेरा कहना यह है कि सरकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कर चोरी के सिलसिले में अपना रवैया बदलने के लिए समय /// देने को तैयार हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर कर चोरी को बर्दाश्त नहीं ﴾2﴿ करेगी । सरकार ने करों की दरें इसलिए कम की ताकि कर चोरी कम हो और छापों / का सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि चोरी की कीमत ज़्यादा देनी पड़े और लोग कर // चोरी से बचें ।

सरकार प्रत्यक्ष करों के बारे में इस साल एक और अधिक सम्पूर्ण /// आचार-संहिता पेश करेगी । इसके साथ ही साथ सम्पत्ति ज़ब्त करने और छापें मारने के ﴾3﴿ बारे में मोटे नियमों की घोषणा भी की जाएगी । मैं उद्योगपतियों को यही सलाह दूंगा / कि वे सरकार पर अंधाधुन्ध छापे मारने का आरोप लगाने की बजाय उत्पादन शुल्क // और सीमा-शुल्क की चोरी का अपना रवैया बदलने की बाबत सरकार से खुलकर बात /// करें । सरकार खुले बजट में विश्वास रखती है तथा अब बजट परीक्षण के लिए सुलभ है। ﴾4﴿ बजट में तर्क-संगत परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। सरकार प्रशासनिक तौर पर / मूल्य वृद्धि के बारे में शीघ्र ही एक नीति की घोषणा करेगी । इसके साथ-साथ // संसद के चालू सत्र के दौरान ही सार्वजनिक क्षेत्र के सामान के सम्बन्ध में एक /// मूलनीति की भी घोषणा की जायेगी । मेरे विचार में सरकार जो कुछ कर रही है ﴾5﴿ सोच-समझकर ही कर रही है और यह पूंजीपतियों के अपने हित में होगा । ﴾315 शब्द﴿

=

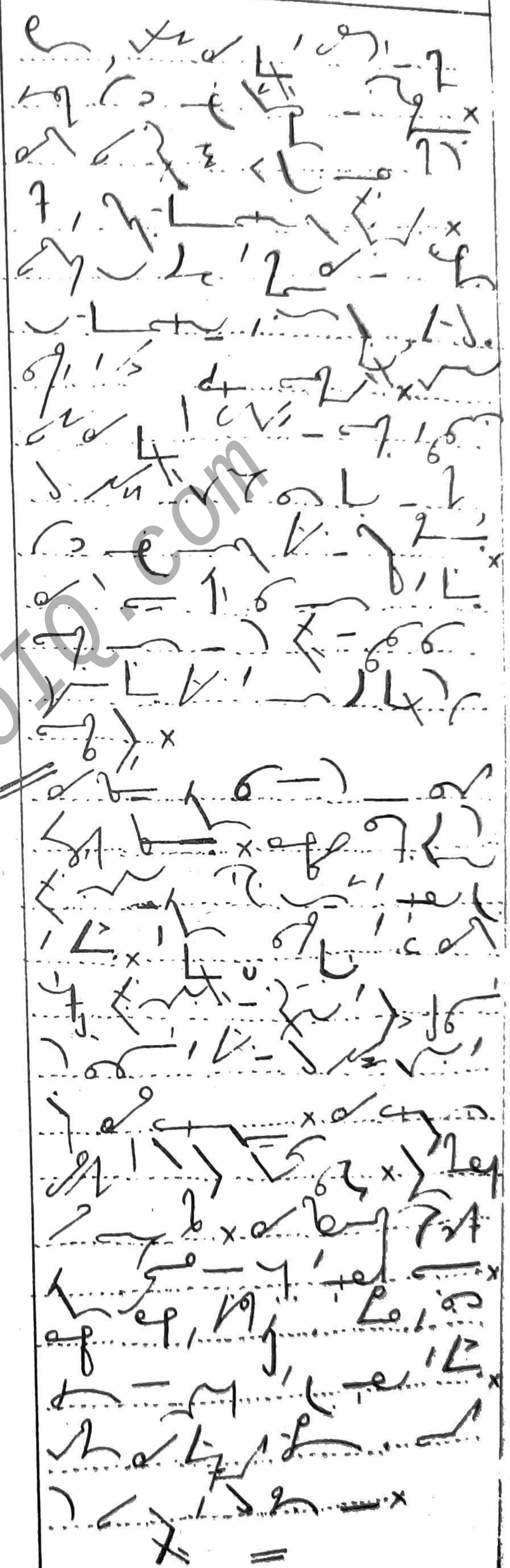

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

आदरणीय सभापति जी, हमारे राष्ट्र को स्वतन्त्रता प्राप्त किए हुए अड़तीस वर्ष हो गए हैं / लेकिन किसी ने भी यह कल्पना तक न की होगी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हमें आतंकवाद के दौर से भी गुज़रना पड़ेगा । वर्तमान स्थिति यह है कि /// हमारे यहाँ कोई भी किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक "वाद" से भली-भाँति परिचित हो अथवा {1} न हो परन्तु वह आतंकवाद से भली-भाँति परिचित होगा । यह ठीक है कि सम्पूर्ण भारत / में सर्वत्र आतंकवाद नहीं है परन्तु क्या राष्ट्र के किसी एक भाग में ही आतंकवाद की उपस्थिति खतरनाक नहीं है ? यह भी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य /// पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं की गूंज पड़ोसी राज्यों एवं केन्द्र में भी सुनाई पड़ {2} रही है । इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद के सूत्रधारों, पोषकों एवं कार्यकर्ताओं / की यह एकमात्र इच्छा यही है कि आतंकवाद सम्पूर्ण राष्ट्र में फैले जिसके फलस्वरूप // भारत अखण्ड न रह पाए ।

सन् 1984 के आम चुनावों में हमारे सत्तारूढ़ नेताओं ने /// चुनाव प्रचार में नारा यह भी बुलन्द किया था कि आतंकवाद हमारे घर के {3} दहलीज़ तक पहुँच गया है, जिस पर उस समय विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति भी / की थी, लेकिन आतंकवाद तो चारों ओर फैल रहा है। इसके लिए उत्तरदायित्व किसका है । // मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्तरदायी हैं । इसके /// साथ-साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियाँ भी नहीं चाहती कि भारत {4} एक मज़बूत तथा अखण्ड राष्ट्र बना रहे और अपनी स्वतन्त्र नीतियों पर चलता रहे । मेरे / विचार में वर्तमान सरकार का दोष केवल यही है कि इसने आतंकवाद की // समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया । राजनीतिक लाभ उठाना एक अलग विवाद का विषय हो सकता है /// परन्तु राष्ट्र के भविष्य तथा उसकी एकता के साथ खिलवाड़ करने को कोई भी क्षमा {5} नहीं कर सकता । {303 शब्द}

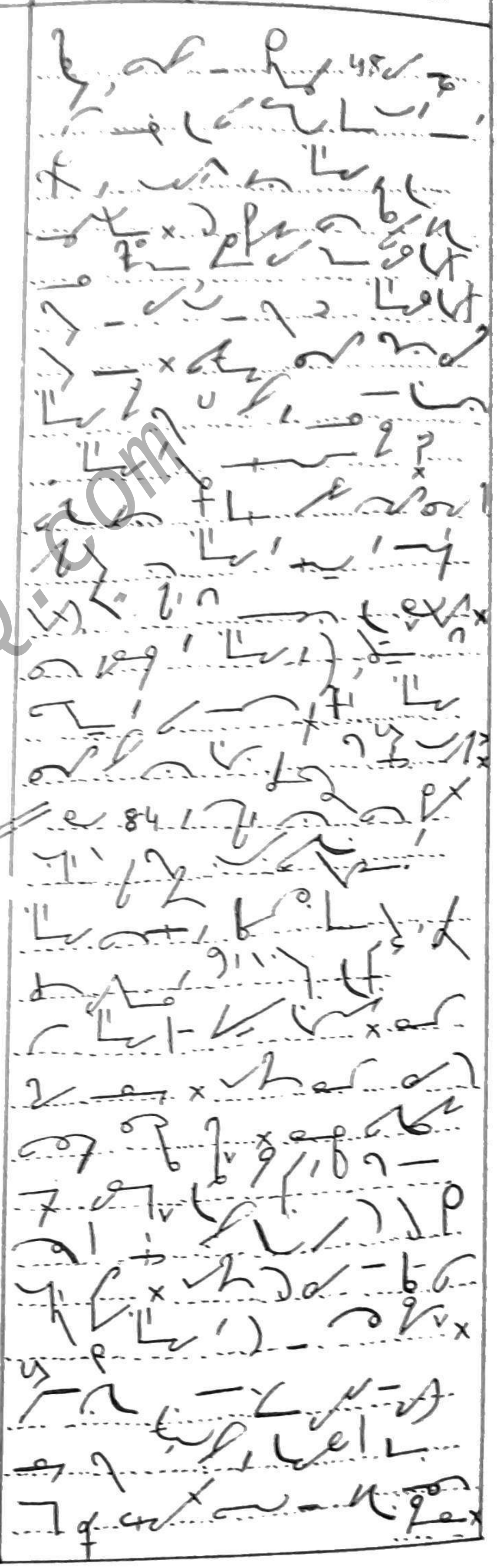

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-19

अध्यक्ष जी, मैं भारतीय व्यावसायिक समुदाय से अनुरोध करता हूँ कि वे देश की अर्थव्यवस्था / के विकास के हित में विदेश व्यापार में वृद्धि में अधिकाधिक योगदान करें। सरकार // अपनी नीतियों के ज़रिए आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रही हैं। भारतीय /// उद्योगपतियों को इसका लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को बल देना चाहिए। §1§ विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ने से नई तकनीक के आयात तथा पूँजी की उपलब्धि / के अवसर बढ़ गए हैं। इससे भारतीय माल के लिए नए हाट मिल सकते हैं। // किन्तु इन सुविधाओं का देश को तभी लाभ मिलेगा जब हमारे उद्योगपति तथा व्यावसायी /// अपनी क्षमता व कुशलता का उपयोग करके विकास कार्य में हिस्सा लें।

जैसे-जैसे देश §2§ की अर्थव्यवस्था का विकास होगा विदेशों में काम करने के लिए हमें अधिक से अधिक / अवसर मिलेंगे और आधुनिक तकनीक के आयात की माँग भी बढ़ेगी। किन्तु आयात की ज़रूरतों को // निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के ज़रिए ही पूरा किया जा सकेगा। सरकार को अपनी ओर से /// इसके लिए हर सम्भव प्रयास करने में पूरा सहयोग देना चाहिए। विदेशों में संयुक्त उद्यमों / की स्थापना तथा उनके सही तौर से संचालन में भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ जैसे // संगठन बहुत मदद दे सकते हैं। विदेशी वाणिज्यिक संगठनों से सम्पर्क तथा सहयोग बढ़ाने की /// भी ज़रूरत है। साथ ही भारतीय माल को विश्व बाज़ार में प्रतियोगी बनाने के लिए उपाय §4§ किए जाने चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार तथा / व्यावसायियों के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। अगले दस वर्षों में वार्षिक पांच प्रतिशत की // दर से आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत के निर्यात में /// वार्षिक 9·12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आर्थिक विकास में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता §5§ जा रहा है। §303 शब्द§

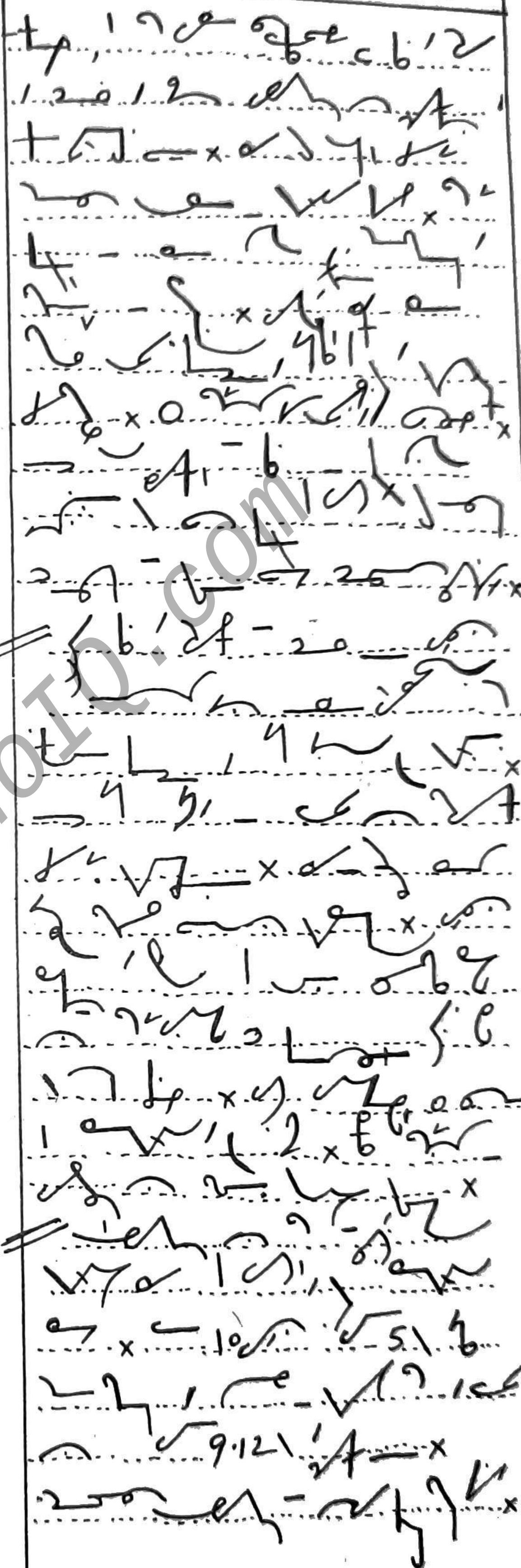

अभ्यास-20

माननीय सदस्यों, आज भारत की एकता सर्वोपरि है। सभी राजनैतिक नेताओं तथा सभी नागरिकों से / मेरी अपील है कि वे प्रजातांत्रिक संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करें और राष्ट्रीय // सामंजस्य के लिए एकजुट होकर कार्य करें । सब लोगों को अपने कर्तव्य का निष्ठा से /// निर्वाह करना चाहिए । मेरा लोगों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक {1} मूल्यों की रक्षा करके धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्त्र के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता के / निर्वाह में अधिकाधिक योगदान करें ।

पिछले वर्ष हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है । // सातवीं योजना की शुरूआत से देश के उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का मार्ग /// प्रशस्त हो चुका है । कानून का शासन हमारी लोकतन्त्रीय प्रणाली का एक दूसरा बुनियादी {2} असूल है । यह हर नागरिक को समान रूप से रक्षा की गांरटी देता है । हमारे देश / में कानून के सामने हर नागरिक समान है । इसलिए इसका परिपालन अति-आवश्यक है । कानून लागू // करने वाली एजेंसियों का फ़र्ज़ है कि वे शांतिप्रिय समाज के हितों के लिए कानून /// को मज़बूती से लागू करें ।

हमारा गणतन्त्र सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर {3} आधारित है । यह हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है । लोकतन्त्र विभिन्न शक्तियों में तालमेल / रखता है और समाज को एक समान लक्ष्य की ओर ले जाता है । राजनीतिक // मतभेदों को दुश्मनी का रूप नहीं लेना चाहिए । जनता के अधिक से अधिक कल्याण /// के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम तैयार करने में राजनीतिक दलों को एक-दूसरे से {4} बढ़-चढ़कर कोशिश करनी चाहिए । यह सभी जानते हैं कि लोकतन्त्र में मतदाताओं का फैसला / सर्वोच्च होता है । इसलिए जनता की इच्छा को स्वीकार किया जाना चाहिए । अगर हमारे अन्दर किसी तरह का मतभेद /// पैदा होता है तो मेरे विचार में हमें उसे आपसी बातचीत और सद्‌भावना {5} के जरिए हल करना चाहिए । {303 शब्द}

=

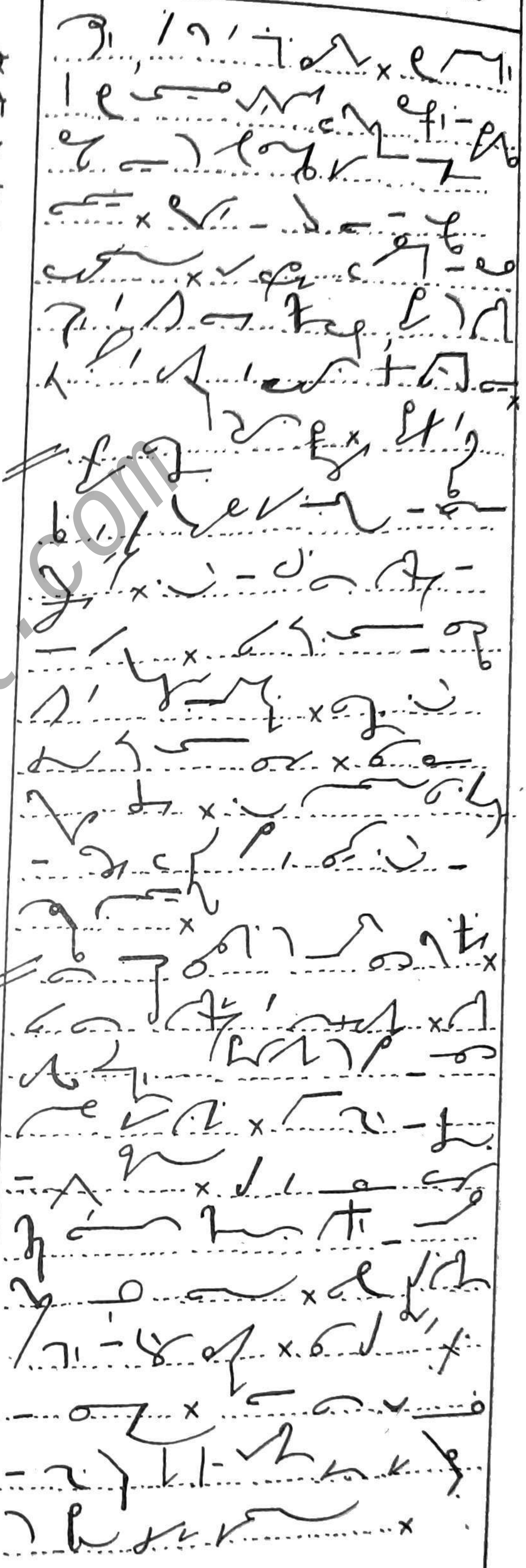

=

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

अभ्यास-21

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी मौजूदा आर्थिक नीति के तहत बड़े उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा / विदेशी पूँजी के समक्ष पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके समाजवादी और गाँधीवादी विचारधाराओं का // घोर उल्लघंन किया है । आश्चर्य की बात है कि सातवीं योजना के दस्तावेज़ में भी /// गरीबी, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असन्तुलन, गांवों का पिछड़ापन, बेरोज़गारी, विदेशी मुद्रा का संकट तथा काले §1§ धन का प्रसार जैसी समस्याओं के समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं सुझाया गया है । / आर्थिक प्रस्ताव में सरकार की सूती कपड़ा नीति की भी तीखी आलोचना की गई है // तथा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र को वरीयता नहीं /// दी गई है । इस नीति में संगठित कल-कारखानों को सस्ते मूल्य के कपड़े बनाने §2§ के सामाजिक दायित्व से भी पूरी तरह मुक्त रखा गया है । मेरे विचार में इस / बात पर ज़ोर दिया जाए कि कुटीर उद्योग के उत्पादों को लघु उद्योग क्षेत्र में और लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों को बड़े उद्योग क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति कदापि /// न दी जाए और यह नीति कई चरणों में लागू की जाए।

मैं लघु इकाई §3§ प्रोद्योगिकी के विकास और अनुसंधान का भी समर्थन करता हूँ । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार / के पर्याप्त अवसर सुलभ होंगे । कुछ सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया है कि मौजूदा // सरकार ने आर्थिक विकेन्द्रीकरण की गाँधीवादी विचारधारा को उल्टा करके रख दिया है और उसके /// समस्त विकास कार्यक्रम पूंजीपतियों की ज़रूरतें पूरी करने वाले हैं । इस आरोप का भी खण्डन §4§ नहीं किया जा सकता । मैं उद्योग और कृषि में वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग के खिलाफ़ नहीं हूँ । लेकिन इसके साथ-साथ मेरा कहना है कि आम उपयोग की चीज़ों के // निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक का अनापशनाप ढंग से आयात करने के विरुद्ध हूँ । /// सरकार की आर्थिक नीति में कही गई चहुँमुखी विकास की बात भ्रामक है और उसमें §5§ सामाजिक न्याय व समान वित्त प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान न देकर आर्थिक असमानता बढ़ने तथा / एकाधिकारियों के हाथ में धन व्यवस्था केन्द्रित करने का इन्तज़ाम किया गया है। §328 शब्द§

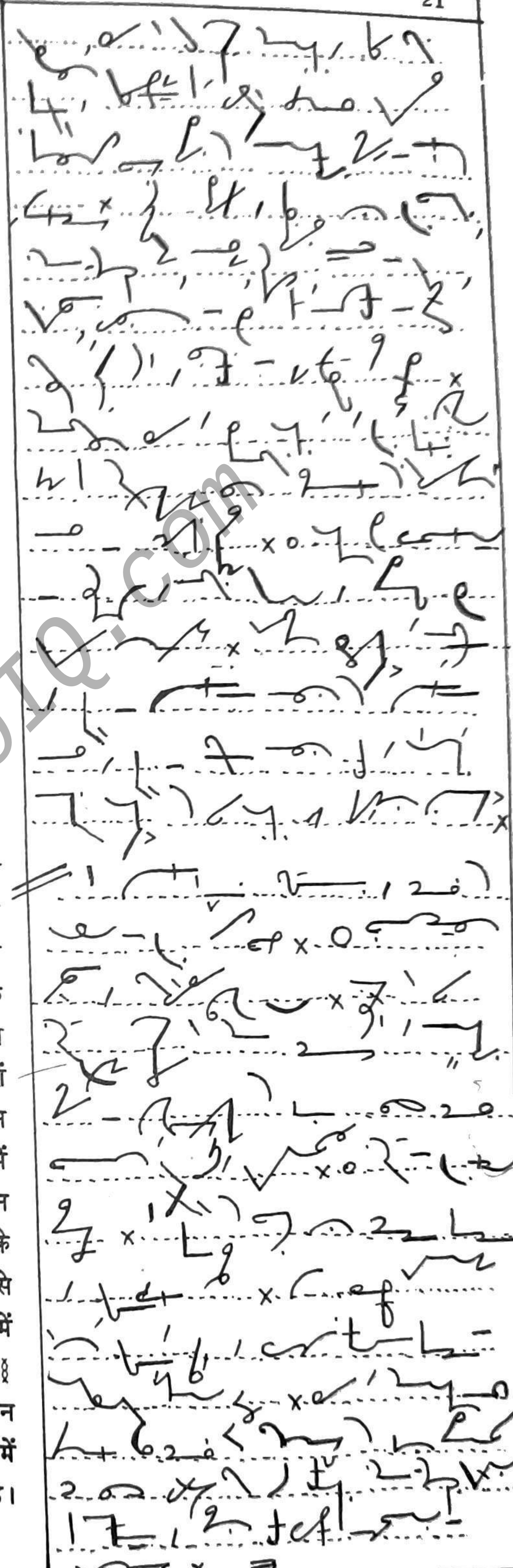

www.StenoIQ.com

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-22

22

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं व्यापारियों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अपने कुछ विचार / व्यक्त करना चाहूँगा । सरकार का कहना है कि व्यापारी अंधाधुन्ध मुनाफा कमाने के इरादे से // जमाखोरी करते हैं । मेरा कहना है कि अगर सरकार ऐसा समझती है तो सरकार के /// पास इस सम्बन्ध में जो भी कानून के हथियार है उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती ? लेकिन ॥1॥ क्या आप समझते हैं कि सरकार ऐसा करेगी और ऐसे कानून के हथियारों का व्यापारियों के प्रति प्रयोग करेगी जो जमाखोर हैं, मुझे इसमें शक ही है । आज के वातावरण में यह सम्भव नहीं है । आप जानते हैं कि चुनाव कौन जीतते हैं । ऐसे लोग चुनाव जीतकर /// आते हैं जो साधन-सम्पन्न होते हैं या जिन पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों ॥2॥ की कृपादृष्टि होती है। कोई भी गरीब आदमी आसानी से चुनाव जीत कर नहीं आता । / इसका क्या कारण है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव जीतने के लिए // जितना पैसा चाहिए वह केवल पूंजीपतियों अथवा बड़े-बड़े व्यापारियों के पास ही होता है । /// जब ये लोग अपने प्रतिनिधि के लिए पैसा लगाते हैं तब उनकी यही अपेक्षा रहती ॥3॥ है कि जितना पैसा खर्च किया है उससे कई गुना अधिक वे मुनाफे के रूप में वसूल कर लें और ऐसा ही हो रहा है । प्रत्येक चुनाव में कुचक्र // चलता रहता है ।

वस्तुतः दोष मतदाता का ही है । चुनाव के दिनों में मतदाता चुनाव /// पर किए गए भारी-भरकम रकम तथा उसके स्रोत की ओर देखना बिल्कुल महत्वहीन समझता है, उसके निश्चित परिणामों की कल्पना तक नहीं करता उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता । ऐसे में व्यापारियों तथा पूंजीपतियों द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी करना बिल्कुल स्वाभाविक है । फिर सरकार // द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनों का इस्तेमाल लगभग असम्भव भी है क्योंकि /// भविष्य में भी तो सरकार ने इन्हीं व्यापारियों और पूंजीपतियों के सहयोग से चुनाव जीतना है । ॥5॥ ॥300 शब्द॥

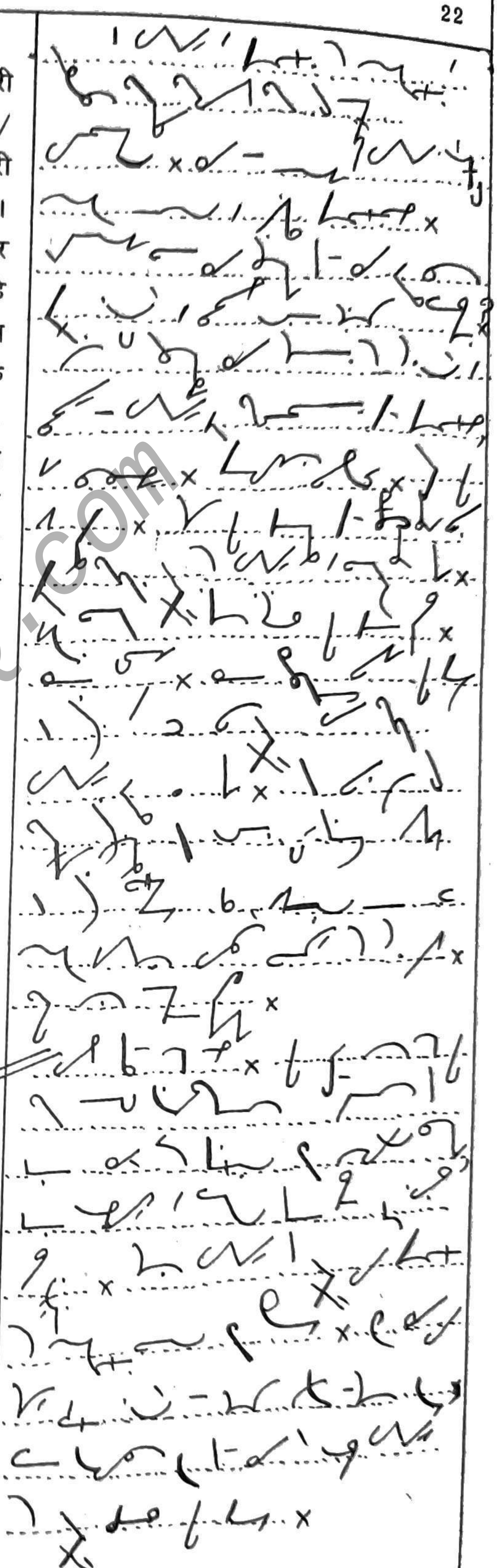

अभ्यास-23

सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि हाल ही में गेहूँ, चावल तथा उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक जैसी ताकतों का दबाव काम // कर रहा है । विश्व बैंक तथा मुद्राकोष बराबर इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि /// खाद्यान्न तथा उर्वरकों पर सहायता राशि धीरे-धीरे बन्द कर देनी चाहिए । यह खेद की ﴾1﴿ बात है कि हमारी सरकार इस नीति को अपना रही है और उन लोगों के / हाथ में खेल रही है जो नहीं चाहते कि भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने ।

दूसरी बात यह है कि अब पैट्रोल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस की /// कीमतों में वृद्धि की गई है जो न्यायोचित नहीं क्योंकि इससे आम आदमी की कठिनाइयाँ ﴾2﴿ बढ़ जाएगी । दुनियाँ भर में कच्चे तेल के मूल्यों में कमी हो रही है । ऐसी / स्थिति में भारत में उर्वरकों तथा डीज़ल-पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई // भी औचित्य समझ में नहीं आता । सरकार की ऐसी नीतियों से किसान खेत में और /// उपभोक्ता बाज़ार में लुट रहा है। उपभोक्ता समझता है कि किसान को आज का मूल्य ﴾3﴿ ज़्यादा मिलने से खाद्यान की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन दरअसल किसान को भी खाद्यान्न / की ज़्यादा कीमत नहीं मिल रही है । मसलन, गेहूँ का बिक्री मूल्य 18 रूपए प्रति // क्विंटल बढ़ गया है जबकि किसान को केवल 5 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे । /// शेष 13 रूपए प्रति क्विंटल कहाँ जाएगा समझ में नहीं आता ।

मेरा सुझाव है कि ﴾4﴿ किसानों को उत्पादन का क्षेत्रवार मूल्य मिले क्योंकि हर क्षेत्र में ज़मीन और पानी के / अन्तर के कारण उपज पर लागत अलग-अलग आती है । फिर किसानों को अखिल भारतीय // स्तर पर उत्पादन का एक जैसा मूल्य क्यों दिया जाता है ? मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर पुनर्विचार करे और जल्दी से जल्दी किसानों के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाए ﴾5﴿ जिनसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे । ﴾308 शब्द﴿

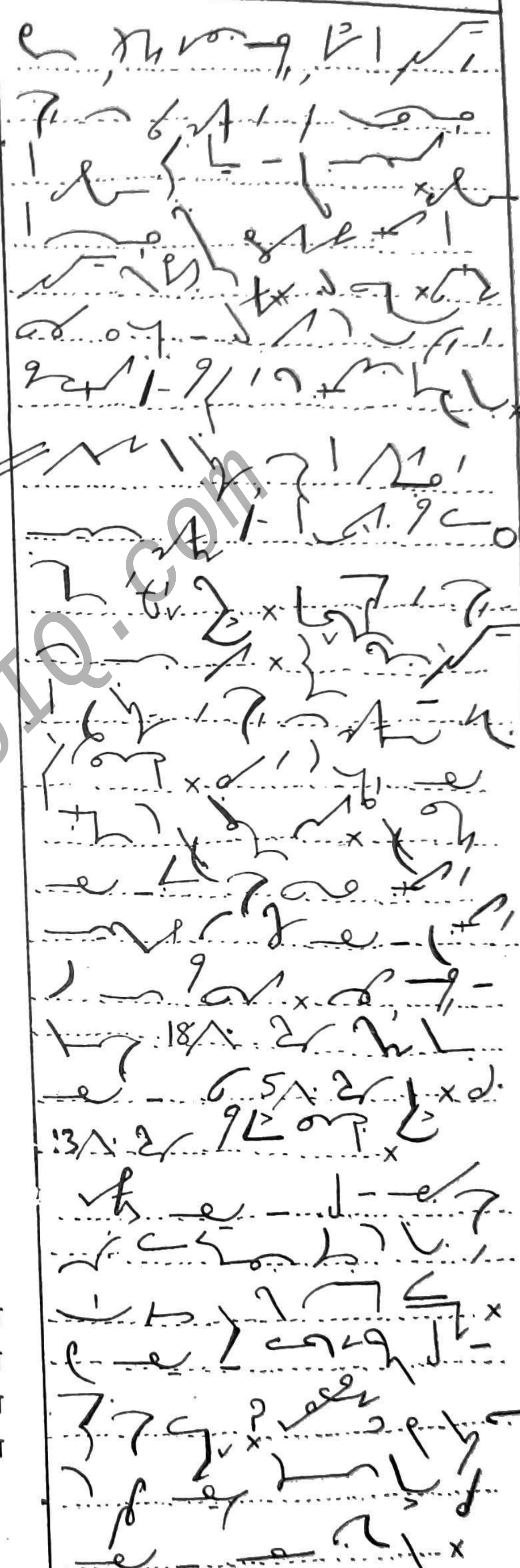

www.StenoIQ.com

अभ्यास-24

माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि पर्यावरण सुरक्षा के मामले में राज्य सरकारें अपनी / ज़िम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रही हैं । कुछ राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में // दी गई रियायतों तथा अनुदानों का दुरूपयोग भी कर रही हैं । मेरे विचार में कोई /// भी विकास योजना बनाते समय पर्यावरण का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । इससे तालमेल बिठाकर {1} ही योजना बनानी चाहिए । जब श्रीमती इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री थी तब पर्यावरण सुरक्षा पर / ज़ोर देने वालों को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ता था यहाँ तक कि उन्हें // पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित समझा जाता था । लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है । लोगों में /// पर्यावरण के प्रति काफी जागरूकता पैदा हुई है । लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न पर {2} आम जनता को शिक्षित करने की दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं कर सके । अतः / मेरा अनुरोध है कि सरकार विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण पर सेमीनार आयोजित करें।

आज नौकरशाही // का बोलबाला है । उनका ध्यान सिर्फ एक सफल मॉडल पर ही रहता है । किसी क्षेत्र /// में अगर कोई एक मॉडल सफल हो गया तो वे उसे हर क्षेत्र में कार्यान्वित {3} करने का प्रयास करते हैं । यहाँ तक कि कुछ राजनीतिज्ञ भी इसी ढंग से सोचते हैं । / लेकिन मेरा कहना यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न विकास कार्यक्रम वहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। आज स्थिति यह है कि /// भारत की केवल 11 प्रतिशत भूमि पर जंगल हैं । सरकारी आंकड़ों में इसे 22 प्रतिशत {4} दर्शाया गया है लेकिन इसमें से आधा जंगल बिल्कुल काट दिया गया है । यदि जंगलों की / भूमि विकास योजनाओं के लिए दी गई तो 35 प्रतिशत में जंगल रखने का // सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा । अतः पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि /// जंगलों का पूरी तरह से संरक्षण किया जाए तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में लोगों के {5} मन में जो भ्रम हो उसे भी दूर किया जाए। {310 शब्द}

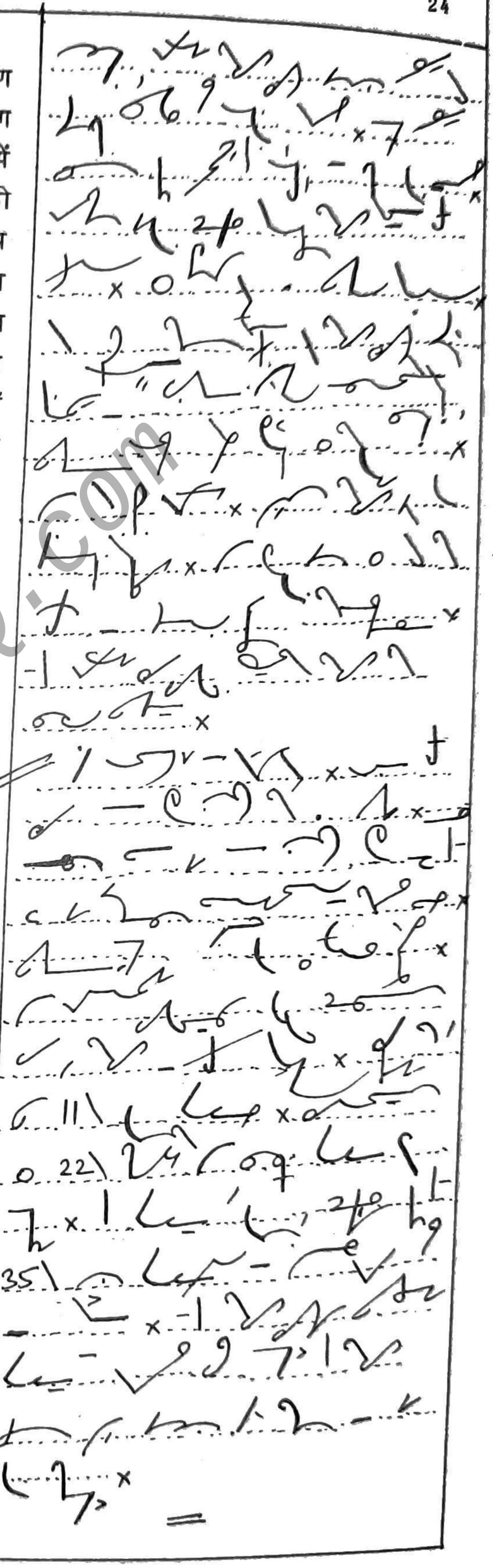

www.StenoIQ.com

अभ्यास-25

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की आर्थिक नीति के बयान में कहा गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम / को क्रियान्वित करने में गांव के स्तर से लेकर प्रशासन के उच्चतम स्तर तक // जनता के सहयोग और साझेदारी की व्यवस्था की जाए । इस भावना के अनुरूप देश के /// लगभग दो दर्जन से अधिक राजनीतिज्ञों, विधि और प्रशासन विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान जारी (1) करके सरकार से अनुरोध किया है कि वह पंचायतों को लोकतंत्र की आधारभूत इकाई मानकर / उन्हें इस व्यवस्था के संरक्षक के रूप में विकसित करें ।

जनता पार्टी ने प्रशासन के // विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया है । इसके अनुसार उन्हें अधिक स्वायतता प्रदान की जाए और /// उसकी शुरूआत गांवों और तहसीलों की पंचायतों से की जानी चाहिए । कुछ वर्ष पूर्व (2) इस कानून द्वारा पंचायत राज की स्थापना की गई थी, तब उद्देश्य यही था कि जो / अधिकार जनता का है और जिस दायित्व को संभालने की अपेक्षा की जाती है उसे // जनता को सौंपा जाना चाहिए । लेकिन सिद्धान्त रूप में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने पर /// प्रदेश सरकार के अधिकारों में कटौती हो जाती है जो उन्हें मान्य नहीं था । प्रदेश सरकार (3) के पास जो वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार थे उनको वे गांव पंचायतों को नहीं देना / चाहते । उन्हें इस व्यवस्था में सबसे बड़ा खतरा यह नज़र आया कि नेतृत्व बीस फ़ीसदी // शहरी हाथों से निकलकर 80 फीसदी देहाती हाथों में चला जाएगा । यही वजह थी /// कि गांवों की बराबर उपेक्षा होती रही और गरीबी तथा बेरोज़गारी बढ़ती गई । लेकिन अब (4) वर्तमान लोकसभा तथा जनता-शासित प्रदेशों में ग्रामीण प्रतिनिधित्व एक तिहाई से भी अधिक हो / गया है। जनता पार्टी के नेतृत्व, विचार और व्यवहार से भी यह सच्चाई उजागर होती है, // जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । अब आवश्यकता इस बात की है कि गांवों /// में विकास की गति को और तेज़ किया जाए क्योंकि गांवों के विकास से ही (5) शहरी विकास में सन्तुलन कायम किया जा सकता है।

(310 शब्द)

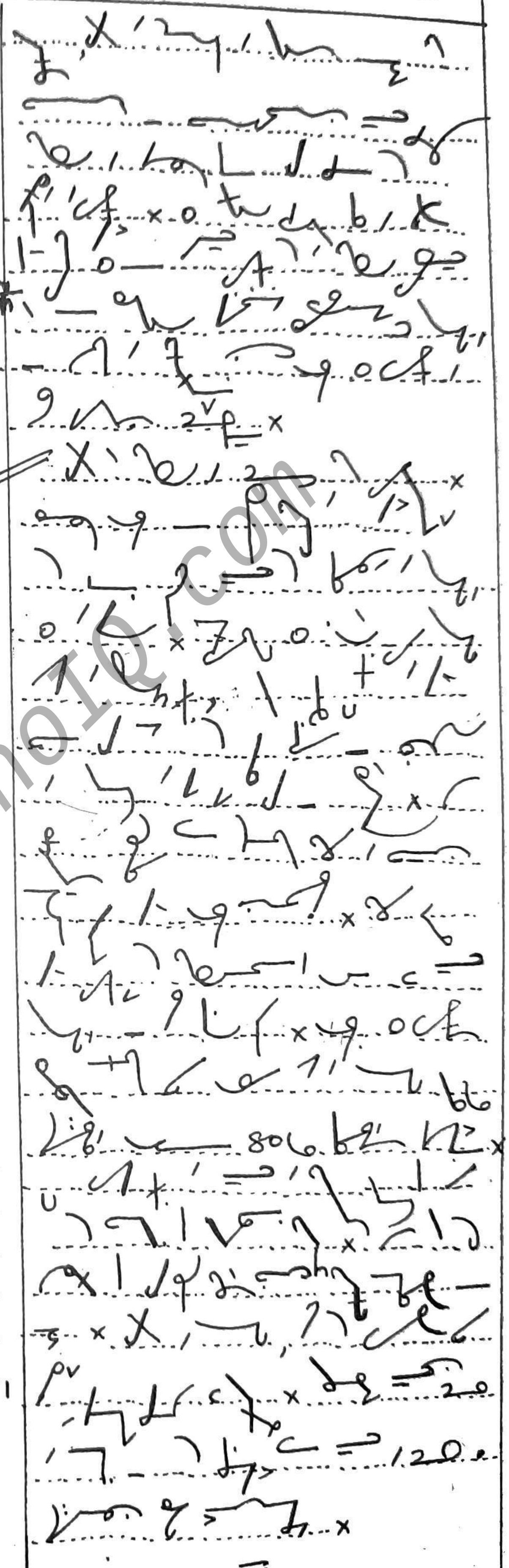

www.StenoIQ.com

अभ्यास-26

अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है, उसको हमारे दल के / नेता ने इस सदन में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है । मैं फिर से इसी बात // को दोहराना नहीं चाहता हूँ । मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या /// है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है । (1) कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और / हम लोग इस बात के खिलाफ हैं । आप और हम भी यह जानते है कि कुछ विदेशी शक्तियाँ, जिनकी // चर्चा सदन में भी हो चुकी है, यह सभी काम कर रही हैं । यह समस्या न केवल असम राज्य में // है, बल्कि धीरे-धीरे यह देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है । ऐसी विदेशी शक्तियों की (2) यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग-अलग हिस्सों में बंट जाए ।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में / हम सरकार के साथ हैं । हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे । इस // सब के बावजूद हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि केन्द्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं, जिनसे /// असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो । इस सदन के मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे (3) थे कि असम की आर्थिक-स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियाँ वहाँ पर अपना काम कर रही है । / मैं भी इस बात से सहमत हूँ लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की // आर्थिक-स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारा जाए ताकि विदेशी शक्तियाँ वहाँ की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा /// सकें । मुझे याद है, असम राज्य के मुख्य-मन्त्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति (4) के साधन हैं, वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं और इस ओर उन्होंने केन्द्र सरकार का ध्यान भी / आकर्षित किया था । लेकिन उस समय केन्द्र सरकार ने मुख्य-मंत्री जी की इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं // दिया । इसी तरह से यदि आप देखें तो आम असम राज्य की ओर भी विकास की योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान /// नहीं दिया गया है । यही कारण है कि असम राज्य का अब तक उतना विकास नहीं हुआ, जितना कि होना (5) चाहिए । (402 शब्द)

अभ्यास-27

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है । मैं / आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए क्योंकि मुझे काफी बातें कहनी है । // कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला वे परिस्थितियाँ बड़ी कठिन थीं क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था । इस सबके बावजूद भी रेल मंत्री जी (1) ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई

www.StenoIQ.com

मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन कुछ महीनों में बड़ी
देना चाहता हूँ । / मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इन कुछ महीनों में बड़ी
सफलता के साथ सभी कठिनाइयों // का सामना किया गया है । देश में सूखा पड़ने के
कारण उस समय काफी कठिनाई आ गई थी, इस समय भी /// रेलवे ने दूर-दूर के
क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुँचाया है ताकि आम जनता
§2§को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े । मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि
बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों / में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहाँ पर
भी रेलों द्वारा पीने के पानी को // पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुँचाई गई है ।

महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी /// धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह भी आम जनता को राहत पहुँचाने
वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है । ऐसे समय में
जब कि / सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई मंहगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट
में इस तरह की व्यवस्था करना // जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक
स्वागत योग्य बात है । रेलवे विभाग में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार /// को भी समाप्त करने
का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है । जब तक §4§
सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं
करेगी तब तक किस प्रकार से / देश का विकास हो सकता है, यह सोचने योग्य बात है
। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ // कि वे इस तरह की व्यवस्था करें
जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जा सके /// ताकि भविष्य में कोई
भी कदम उठाने की हिम्मत न करे और मंत्रालय के काम में बाधा न पड़े । §5§
§400 शब्द§

अभ्यास-28

आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल
महानगरों में मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है । / यह बीमारी दिन-प्रतिदिन
बढ़ती ही जा रही है । यहाँ तक अब तो शिक्षा संस्थानों में भी मादक पदार्थों के //
बढ़ते हुए इस्तेमाल से भयानक समस्या पैदा हो गई है । मेरा सरकार से निवेदन है कि
इसके निदान के लिए /// युद्ध-स्तर पर कार्य हो ताकि आज की युवा-पीढ़ी इसके चंगुल से
शीघ्र निकल सके । मैं समाज के §1§ हर वर्ग से अपील करता हूँ कि वह सरकार का
साथ दे ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया / जा सके ताकि यह मर्ज़ काबू के
बाहर न निकलने पाए ।

आखिर मादक पदार्थों के सेवन के पीछे क्या कारण है, // क्यों अधिक से अधिक
हमारी युवा पीढ़ी इसकी ओर भागती नज़र आती है ? मेरे विचार में इसका एकमात्र कारण
/// यह है कि मादक पदार्थों का कारोबार, सबसे पहले, अधिक लाभदायक कारोबार है ।
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह, विशेषकर अमेरिका में §2§ बैठे लोग मानव-जाति पर यह घातक

www.StenoIQ.com

प्रहार कर रहे हैं । यहाँ तक कि पंजाब में तनाव उत्पन्न करने / के लिए भी मादक पदार्थों के तस्करों से मिले धन का प्रयोग किया जा रहा है । पंजाब सीमा पर कुछ // तस्करों को पकड़े जाने पर तथा उनसे पूछताछ करने पर इस तथ्य की पुष्टि भी हो चुकी है ।

मेरा यह /// भी निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था को इस सम्बन्ध में काफी चौकस रहना चाहिए तथा वह मादक पदार्थों की माँग {3} एवं पूर्ति की मात्रा पर कड़ी निगाह रखें । कई लोग मादक पदार्थों के क्रिय-विक्रय में पुलिस की मिलीभगत / की भी शिकायत करते हैं, जो किसी हद तक सही है लेकिन शत-प्रतिशत सही नहीं है । दूसरी ओर वर्तमान कानून // भी इस दिशा में काफी सक्षम नहीं है । सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि लोगों में इसके प्रति /// जागृति पैदा की जाए ताकि नशीले पदार्थों के सेवन करने वाले नये मरीज़ न बनने पाएँ । इसके साथ-साथ {4} इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो व्यक्ति इनके सेवन के आदती बन चुके हैं उनके इलाज की / पूरी सुविधाएँ / अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएँ । अगर सम्भव हो तो इसके लिए अलग अस्पताल कायम किए जाएँ जहाँ पर // उनकी इस आदत को छुड़ाया जाए और उन पर पूरी निगाह रखी जाए ताकि अस्पताल से चले जाने के /// बाद भी वे इस आदत के दुबारा न शिकार बनने पाएँ और एक अच्छा नागरिक बन कर अपना जीवन {5} व्यतीत करें । {402 शब्द}

अभ्यास-29

अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे दुराहे पर खड़े हैं, जहाँ हमारा भविष्य हमें आगे की तरफ ढकेल रहा है और अतीत पीछे / की तरफ घसीट रहा है । हम इस उलझन को किस तरह सुलझायें और अपने जीवन का कैसा ढाँचा तैयार // करें जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो और हमारे मन और आत्मा को भी खुराक मिलती रहे । हम अपने किन पुराने /// आदर्शों को कौन-सा नया रूप दे सकते हैं ? हमारे देश की अपनी खास समस्याएँ हैं और साथ ही हम {4} दुनिया के बड़-बड़े मामलों से गुँथे हुए हैं । दुनिया आज गज़ब की तरक्की करने के बावजूद ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने आप पर से विश्वास खोती जा रही है । भारत में हम इस वक्त अपनी माली // हालत सुधारने में लगे हुए हैं । पंचसाला योजनाओं से हम अपनी जनता का रहन-सहन उठाने की कोशिश कर /// रहे हैं और बहुत ठीक कर रहे हैं । बगैर इसके किसी भी तरह की तरक्की सम्भव नहीं, कल्याणकारी राज्य का {2} आदर्श तो अच्छा ही है । फिर भी यह एक थोथी और बेजान चीज़ हो सकती है क्योंकि आज ऐसे देश / भी दुनिया में हैं जो इस मकसद को पा चुके हैं पर उनके सामने भी नये-नये सवाल और // नयी-नयी गुत्थियाँ आ गयी हैं और इन गुत्थियों को वे मशीनों से या माली हालत को सुधार कर सुलझा /// नहीं पाये । मानव स्वभाव की कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में अब तक धर्म और मज़हब का काफी बड़ा {3} हाथ रहा है, मगर इस तरह के धर्म की

पकड़ अब ढीला हो चली है, उसका असर फीका पड़ चुका है / और वह आजकल की दलीलों और साइंस के सामने टिक नहीं पा रहा है । धर्म में विश्वास हो या // न हो पर इन्सान के लिए किसी ऐसे आदर्श में अडिग विश्वास का रखना ज़रूरी है, जिससे जीवन का रस /// मिलता रहे और जो हमें आपस में गुंथे रखे ।

हमें तो आगे की तरफ देखना है और उसके लिये पूरे ‖4‖ जोश और विश्वास के साथ काम करना है । हमें साथ ही अपनी पिछली विरासत को भी कायम रखना है और / उसी से शक्ति प्राप्त करनी है । परिवर्तन ज़रूरी है, मगर अपने पुराने इतिहास से मुँह फेरना अपनी ही जड़ों को // खोदना है । अतः इस परिवर्तनशील समाज में यह देखना भी आवश्यक है कि इस परिवर्तन से कहीं किसी स्थान पर /// सामाजिक ढांचों को चोट तो नहीं पहुँचती या किसी रूप में सामाजिक अहित तो नहीं हो रहा । अगर ऐसा होता है ‖5‖ तो फिर उस परिवर्तन से कोई लाभ होने वाला नहीं ।

अभ्यास-30

सभाध्यक्ष जी, बिजली वितरण संस्थान के महाप्रबंधक ने अन्य राज्यों के तुलनात्मक आँकड़े देकर दिल्ली में बिजली की दर कम / होने की चर्चा करते हुए वर्तमान बिजली शुल्क में सुधार की सिफारिश की है । उन्होंने अपने भाषण में इस बात // की शिकायत की है कि घरेलू उद्योग के लिए जो बिजली ली जाती है, उसका उपयोग बहुत से उपभोक्ता रेडियो, /// टेलीविजन और अन्य कार्यों में करते हैं । उनकी यह शिकायत किसी सीमा तक सही है । बहुत से स्थानों पर ऐसा ‖1‖ अवश्य होता होगा । यदि एक पैसा शुल्क बढ़ाने की माँग का समर्थन भी नागरिक करें, तो कम से कम जो / गर्मियों के दिनों में बिजली आँख-मिचौनी का खेल खेलती है, उसे बंद करने का भी तो प्रबन्ध होना चाहिए । / नागरिक केवल अफसरों की सुख-सुविधा के लिए शुल्क बढ़ा कर दें यह कोई उचित बात नहीं लगती । /// यही हालत पानी के मामले की है । अनेक बस्तियों में अभी तक पानी नहीं है ऐसी हालत में लोगों पर जल ‖2‖ में वर्तमान शुल्क-वृद्धि उचित नहीं लगती, जल योजनाओं का उपयोग जनसाधारण के लिए किये जाने की दिशा में / प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

45 दिन तक चलने वाली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने पर एक विशेष संकट सफाई // कर्मचारियों और नगर निगम के सामने उत्पन्न हो गया है । निगम के सत्ताधारी वर्ग का कहना है कि वे सफाई /// कर्मचारियों ने जितने दिन काम नहीं किया है, उतने दिन का वेतन नहीं देंगे । यदि निगम अपने इस निर्णय पर ‖3‖ अटल रहा , तो सफाई कर्मचारी नगर की सेवा मन से नहीं कर पायेंगे । उनकी हानि की पूर्ति के लिए कहीं/ न कहीं से चाहे महापौर कोष से अथवा किसी अन्य कोष से हड़ताल के दिनों में अनुपस्थिति सहायता की जानी // चाहिए । जब ये सफाई कर्मचारी हड़ताल के दिनों का कूड़ा भी उठायेंगे, तब उन्हें हड़ताल के दिनों का वेतन यदि ///

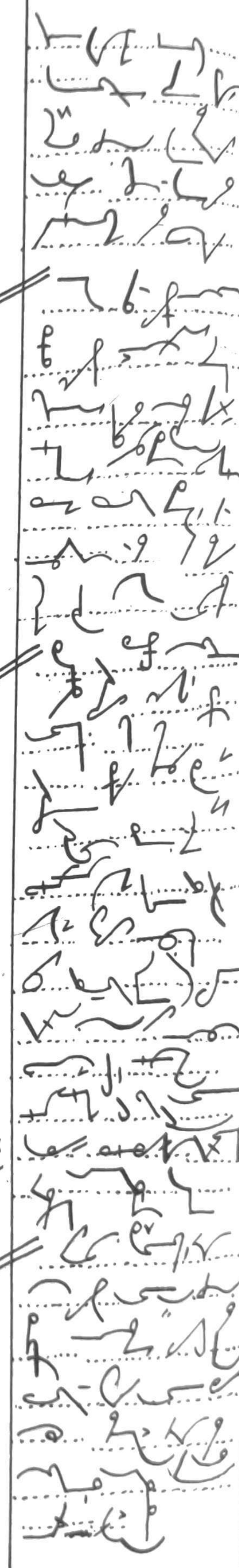

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

नहीं दिया जा सकता, तो वार्षिक छुट्टियाँ मिलाकर कुछ न कुछ आर्थिक सहायता अवश्य की जानी चाहिए । ऐसा करने {4} पर ही सफाई कर्मचारियों का दिल जीता जा सकता है । इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि सरकार / ऐसे कदम उठाए जिससे फिर ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे सफाई कर्मचारियों को फिर हड़ताल करने पर मजबूर होना // पड़े । मैं सरकार से अनुरोध करूँगा की प्रत्येक समस्या को जितना हो सके आपसी बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करें । /// इसके लिए यह ज़रूरी है कि अपने कर्मचारियों की प्रत्येक समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अगर उनकी माँगे {5} न्यायोचित हैं तो उन्हें स्वीकार करने में विलम्ब न हो । ऐसा करने पर कोई भी हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाएगा । / {420 शब्द}

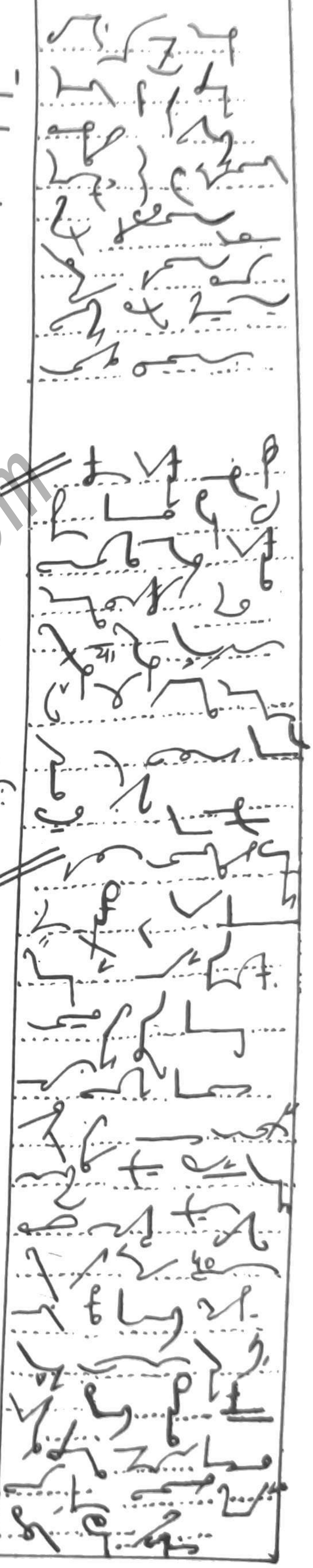

अभ्यास-31

अध्यक्ष महोदय, जब कोई देश पराधीन होता है तो किसी भी स्थिति में उससे औद्योगिक विकास सम्भव नहीं होता । शासन करने वाला देश यह कभी नहीं चाहता कि पराधीन देश का औद्योगिक विकास हो और वह आर्थिक रूप से // समृद्धिशाली बन सके । ऐसा होने से उसे अपनी प्रभुसत्ता बनाये रखने में कठिनाई पैदा हो जाती है और इसलिए वह /// चाहता है कि राजनीतिक रूप से पराधीन देश आर्थिक रूप में भी पराधीन बना रहे । अपने देश, भारत का उदाहरण {1} हमारे सामने है । जब तक यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य रहा, तब तक उन्होंने यहाँ किसी भी उद्योग को पनपने नहीं / दिया और इस प्रकार वह हमारी प्रगति के मार्ग में सदा ही रोड़े अटकाते रहे ।

अभी हाल ही में कुछ // आँकड़े प्राप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि भारत ही नहीं, एशिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं, /// जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारी औद्योगिक प्रगति की है । कोरिया भी एक ऐसा ही देश है, जिसे भारत से {2} कुछ ही वर्ष पहले आजादी मिली थी । आँकड़ों से पता चलता है कि आज़ादी से पूर्व 1944 में वहाँ जितना / औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष में होता था, अब उतना उत्पादन वह देश केवल 12 दिन में कर लेता है । // भारत की तरह ही यहाँ पर सामाजिक औद्योगीकरण की राह पर चलते हुए बड़े उद्योगों को केन्द्र के नियंत्रण में /// रखा गया और मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों को स्थानीय उद्योग बना दिया गया । इसके साथ यहाँ छोटे उद्योगों को {3} अधिक महत्व दिया गया । आज यहाँ के छोटे उद्योगों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो रहा है । इन उद्योगों में / हर वर्ष चालीस करोड़ मीटर कपड़ा तो बनता ही है, साथ ही दैनिक ज़रूरत की प्रत्येक वस्तु इन उद्योगों में // बनायी जाती है । यह सामान यहाँ इतनी मात्रा में बनता है कि इससे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो /// जाती हैं । इस सबका श्रेय एक स्वाधीन देश के आधुनिक उद्योग को ही जाता है, जिसके पास अपना कच्चा माल है {4} और तकनीकी विकास करने के लिए उत्तम कारीगर हैं । उत्तरी कोरिया की सबसे बड़ी सफलता रेलवे का विद्युतीकरण है । रेलवे विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उस देश की यातायात में शीघ्रता आती है जिसके //

www.StenoIQ.com

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

फलस्वरुप देश के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुँचया जा सकता है और कच्चे माल /// की कमी नही रहती । इसके साथ-साथ लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होती है तथा वे एक स्थान {5} से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुँच जाते हैं । मेरे विचार में भारत सरकार को भी कोरिया की भांति रेलवे के / विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए । {426 शब्द}

अभ्यास-32

माननीय मन्त्री जी, पंचवर्षीय योजनाएं, सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षित माँग पैदा करने में विफल रही हैं और केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र / के कारखानों को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने में असफल रही हैं । ठीक 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से लेकर मैं // सरकारी कारखानों के इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ । पर बावजूद इसके मुझे इस बात का पता नहीं लग /// सका है कि सरकारी कारखनों का उद्देश्य क्या है, वे क्या चाहते हैं ?

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस में भी सरकारी उद्योग {1} चल रहे हैं । वहाँ उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे असाधारण खतरों की स्थिति में निर्मित हों । जैसे // अंतरिक्ष तथा अणुशक्ति सम्बन्धी कार्यक्रम को लेकर सरकारी कारखाने खोले जाते हैं, परन्तु उन देशों में सरकारी उद्योग क्षेत्र अपने /// आदर्शों की पूर्ति के लिए निजी उद्योगों को काम में लाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं ।

कुछ लोग कहते {2} है कि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है और राष्ट्रीय उद्योगों में आदर्शों की ऊँची गद्दी / पर बैठकर वार्षिक प्रगति लाना है । चौथी योजना तक तीनों योजनाओं के कागज़ भी बहुत कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के // कारखानों के अतिरिक्त माँगों पर निर्भर करते आ रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूँ, आदर्शों की ऊँची गद्दी क्या है /// और यह किस उद्देश्य से है ? मेरे विचार में सरकारी कारखानों को केवल लाभदायकता के मानदण्ड से मापना ठीक नहीं {3} हिन्दुस्तान इस्पात को देखिये । इसका उद्देश्य था देश में इस्पात की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के / आम विकास की आवश्यकता के अनुसार इस्पात की कई किस्मों को काफी मात्रा में तैयार करना लक्ष्य था । यदि केवल // लाभ के लिए यह कारखाना खोला गया होता तो इसकी शक्ल-सूरत कुछ और ही होती ।

सरकारी क्षेत्र के /// कारखानों की सफलता के लिये दो स्पष्ट व महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और जो लोग उनमें काम करते हैं उनमें उचित मनोबल नितांत आवश्यक है । हिन्दुस्तान इस्पात को केवल लाभदायकता के मानदण्ड से जाँचना इसके उद्देश्य को नज़र-अंदाज करना है । / जो सरकारी कारखाने देश की किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए जाते है जैसे कि // हिन्दुस्तान इस्पात, ऐसे कारखानों में पहले

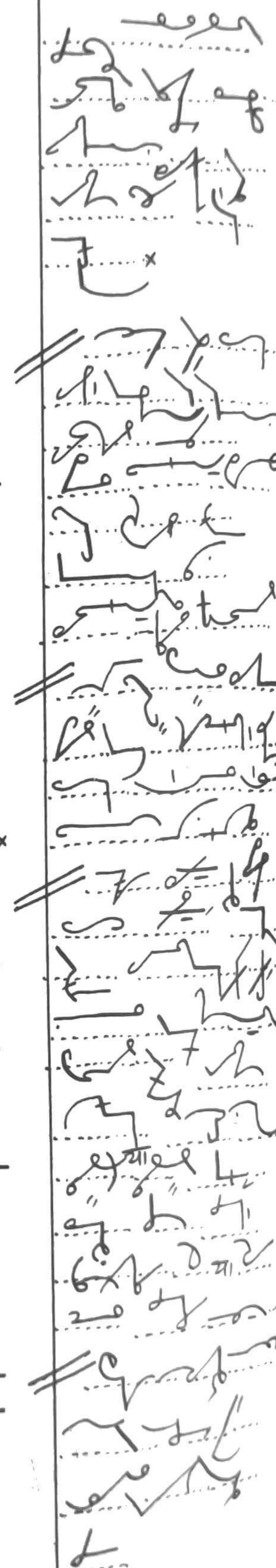

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

तो लाभ होने का सवाल ही नहीं उठता / । ऐसे सरकारी कारखानों से कुछ वर्षों के लिए /// लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें देश की उस आवश्यकता को पूरा करने का पूरा-पूरा अवसर §5§ प्रदान करना चाहिए । कुछ सालों के बाद स्वतः उनसे लाभ होगा । §411 शब्द§

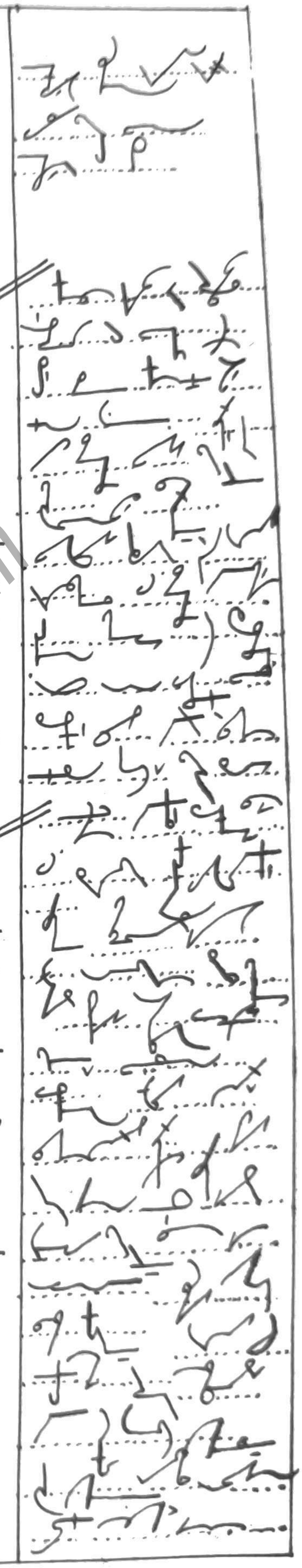

अभ्यास-33

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया । शिक्षामंत्री ने / संसद के दोनों सदनों को सूचित किया कि सरकार धमकियों और आन्दोलनों के आगे घुटने नहीं टेकेगी । छात्रों के उत्पात // का समर्थन नहीं किया जा सकता और न यह उचित है कि सरकार या विश्वविद्यालय के प्रबंधक तोड़फोड़ करने /// वालों से समझौता करें । लेकिन यह भी सही है कि छात्रों में जो देशव्यापी अशांति फैल रही है उसे पुलिस §1§ तरीकों से शांत नहीं किया जा सकता । छात्रों को उनके राजनीतिक विचारों के लिए दंडित करने का तरीका गलत है / और विश्वविद्यालय के अधिकारी इस तरह सफल नहीं हो सकते । कम्यूनिस्ट नियंत्रित विद्यार्थी संघ या कांग्रेस द्वारा चलायी जा रही छात्र संस्थाएँ ही सही हैं और अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को विश्वविद्यालय के अहाते में घुसने का अधिकार नहीं यह /// विचार तानाशाही का सबसे प्रबल संकेत है और इसका विरोध होना स्वाभाविक है ।

केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने सब राजनीतिक §2§ दलों से अनुरोध किया है कि वे छात्रों को समझाये और शांत करें । इस अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए । / लेकिन, छात्रों की समस्या पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जिस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं या समस्या को // हल करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं उनके बारे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि /// उनको न चाहते हुए भी राजनीतिक कलंक लग गया है और इस प्रतिक्रिया को शांत कर सकना या §3§ गलत सिद्ध कर पाना कठिन हो रहा है कि राजनीतिक दल अपनी लड़ाई विश्वविद्यालय के अहाते में लड़ रहे हैं । / छात्र आन्दोलन पिछले कई वर्षों से जिस तरह चल रहा है और एक दल अपने पैर ज़माने की जिस तरह // कोशिश कर रहा है और इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जो टकराव हो रहे हैं, विश्वविद्यालय के प्रबंधकों को उनको /// समझ कर समस्या का हल निकालना होगा । लेकिन, ऐसा नहीं हो रहा । राजनीति अब छात्रों तक ही सीमित नहीं बल्कि §4§ अध्यापकों में भी फैल रही है । अध्यापकों में ज़बर्दस्त खींचातानी मची है जिसे उपकुलपति भी महसूस कर रहे हैं कि / यह रोग असाध्य है और वे ऐसे डाक्टर नहीं कि इस रोग का इलाज कर सकें तो फिर कौन इसका // इलाज करेगा । मेरे विचार से अगर विद्यार्थियों की न्यायोचित माँगों को शीघ्र मान लिया जाए और विश्वविद्यालय के मामलों में /// राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिसकी वजह से सरकार को अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को §5§ कठिनाई का समाना करना पड़े । §405 शब्द§

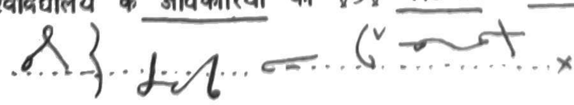

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-34

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिन्दी को देश की सम्पर्क भाषा बनाने के लिए दक्षिणवासियों से उसे सीखने के लिए / अपील की है । दक्षिण में एक ऐसा वर्ग हो सकता है और है जो राजनीतिक कारणों से उसे सीखना चाहता // हो और जो उसके प्रचार-प्रसार में बाधक बन रहा हो, किन्तु इस संबंध में दोराय नहीं हो सकती कि /// यदि देश को एकता के सूत्र में बांधना हो तो उसके लिए एक सम्पर्क भाषा सबसे मजबूत एवं प्रभावशाली सूत्र (1) हो सकता है और वह सम्पर्क भाषा सबसे अच्छी केवल हिन्दी हो सकती है । प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है / और ठीक कहा है कि उत्तर भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्र दक्षिण में ऐसी धारणा न बनने दें कि वे // देश के कुछ भाग पर अपनी भाषा लाद देना चाहते हैं, किन्तु क्या इस बात से इन्कार किया जा /// सकता है कि हिन्दी के सिवा कोई और ऐसी भाषा नहीं है जो देश में सम्पर्क भाषा का स्थान ले सके । (2) दक्षिण के राज्यों में अपनी भाषा के प्रति मोह हो सकता है, किन्तु हिन्दी के सम्पर्क भाषा के रूप में / पनपने पर उनकी भाषाओं को कोई हानि नहीं पहुँचेगी और उसका एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि उत्तर-दक्षिण // पहले की अपेक्षा बहुत निकट आ सकेंगे । कम-से-कम राष्ट्रीय एकता का यह तकाज़ा है और दक्षिण के लोग /// उसे पूरा करके ही अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं । इसलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा है कि देश (3) में बहुत सी भाषाएं ज़रूर हैं, परन्तु यह एक देश है और कोई इस बात से असहमत नहीं हो सकता / है कि हमें ऐसी हर बात करनी चाहिए जिससे वह एकता मजबूत होती हो । हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने में // योग देना ऐसी ही एक बात है । भारतीय संविधान के अनुसार सोलह राष्ट्रीय भाषाएं हैं, परन्तु हिन्दी ही एक ऐसी /// राष्ट्र भाषाहै जो सम्पर्क भाषा की अधिकारिणी है । इसलिए संविधान में उसे देश की एकमात्र राजभाषा होने का अधिकार (4) दिया गया है । यह और बात है कि राजनीतिक कारणों से उसका विरोध हुआ, उसके खिलाफ तमिलनाडू में ज़बर्दस्त हिंसात्मक / आंदोलन हुए और कुछ लोग आत्मदाह करने पर तुल गये, पर इससे उसके अधिकार को खंडित नहीं किया जा सकता । // हिन्दी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष के सबसे अधिक क्षेत्र में /// बोली जाती है और समझी जाती है तो फिर इसमें दुविधा क्यों होनी चाहिए कि वह राष्ट्र भाषा का (5) पद न ले सके । मेरे विचार में ऐसा करने पर ही राष्ट्र की एकता बनी रह सकती है । विदेशी भाषा / कितनी भी अच्छी हो वह हमेशा सबके लिए देश की राष्ट्र भाषा या सम्पर्क भाषा नहीं बन सकती । किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी भाषा होना गौरव की बात ही नहीं, अनिवार्य भी है । (452 शब्द)

अभ्यास-35

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो फाइनेन्स बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ । / सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि

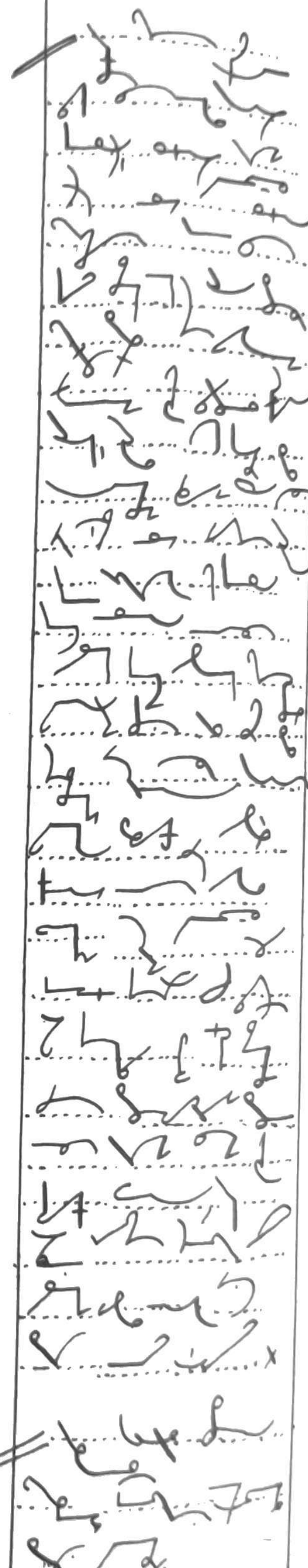

www.StenoIQ.com

कि हमारे शासन की जो टैक्स लगाने की नीति है उसका तो // मैं विरोध करती ही हूँ
लेकिन यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारे वित्तमंत्री जी जनता पर टैक्स ///
लगाते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि जनता टैक्स देने की क्षमता रखती है या नहीं ।
उन्होंने जनता के {1} के ऊपर इतने टैक्स लगा दिये हैं यह अनुचित मालूम होता है ।
इस समय हमारे देश की स्थिति यह है इसके / बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगी और
न इस सम्बन्ध में उन बातों को दोहराना चाहूँगी जिनके बारे में // मैंने पूर्व में तथा
माननीय सदस्यों ने यहाँ पर काफी चर्चा की है । किन्तु इस विधेयक की जैसा कि ///
यह है उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का केवल
एक मात्र {2} लक्ष्य यह था कि इसमें इस तरह का संशोधन किया जाये जिससे पैसा
अधिक से अधिक प्राप्त हो सके । / यह बात अवश्य है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने
इस बिल द्वारा यह कोशिश की है कि निर्यात करने // वालों को ज्यादा प्रोत्साहन मिले,
पैसा बचाने वालों को पैसा बचाने की दिशा में ज्यादा प्रोत्साहन मिले । लेकिन इसके ///
साथ ही साथ उन्होंने अधिक मात्रा में टैक्स द्वारा पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया है ।
मेरी समझ में यह {3} बात नहीं आती है कि जनता इतना टैक्स वहन करने की
समर्थता रखती है या नहीं । यह नहीं देखा गया । इस विभाग के बारे में एक बहुत
विचित्र बात यह है कि हाल में यानी सन् 1961 में इन्कमटैक्स बिल // पास किया गया
जो पहली अप्रैल सन् 1962 से लागू होने वाला था । इस विधान की अच्छी तरह से
शुरुआत /// भी पूरी तरह से नहीं हो पाई कि उसमें अनेकों संशोधन करने पड़ गये हैं ।
बाद में जो संशोधन फाइनेंस / बिल से किये उस बिल की अच्छी तरह से स्याही भी
सूखने नहीं पाई थी कि हमारे वित्त मंत्री जी / ने इस बिल में केपीटल गेन्स के बारे //
में संशोधन पर संशोधन पेश कर दिए हैं । केपीटल गेन्स के बारे में इस बिल में मुख्य
परिवर्तन किया गया है । इससे ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी का विभाग ///
एक निश्चित योजना बना कर नहीं चलता है । अतः यह ज़रूरी है कि अच्छी बातों के
आने पर संशोधन किया जाना चाहिए । {5} {400 शब्द}

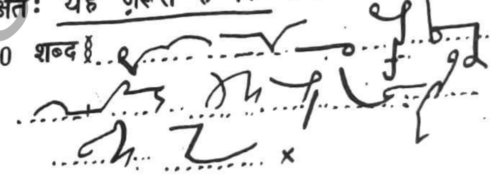

अभ्यास-36

नीतियाँ और कार्यक्रम कुछ भी हो, किन्तु यह भूलने वाली बात नहीं कि उन्हें
अमल में लाने के लिए एक / उपयुक्त वातावरण एवं परिस्थिति की ज़रूरत होती है ।
उसमें यह भी देखना होता है कि कहीं उन पर तेज़ी से // अमल कोई ऐसी प्रतिकूल
परिस्थिति पैदा न कर दे कि जो अगले काम में रुकावट पैदा कर दे । /// आखिर यह
लोकतंत्र है । इसमें जनमत की उपेक्षा करके तानाशाही या कम्युनिस्ट तरीके से नहीं चला
जा सकता । नीतियाँ और {1} कार्यक्रम कितने भी अच्छे हों पहले उन जालों को हटाना
होता है जो उनके अमल में बाधक हैं । फिर भी / यह भी देखना होता है कि जो
उत्पादन गरीबी और अन्याय मिटाने का एक बहुत बड़ा सधान है उसमें सब // का
सहयोग प्राप्त हो सके । ऐसी सूरत में यदि कांग्रेस अपने वचनों को पूरी नहीं कर रही है
तो वह /// बहुत अधिक योग्य बात नहीं है ।

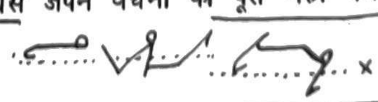

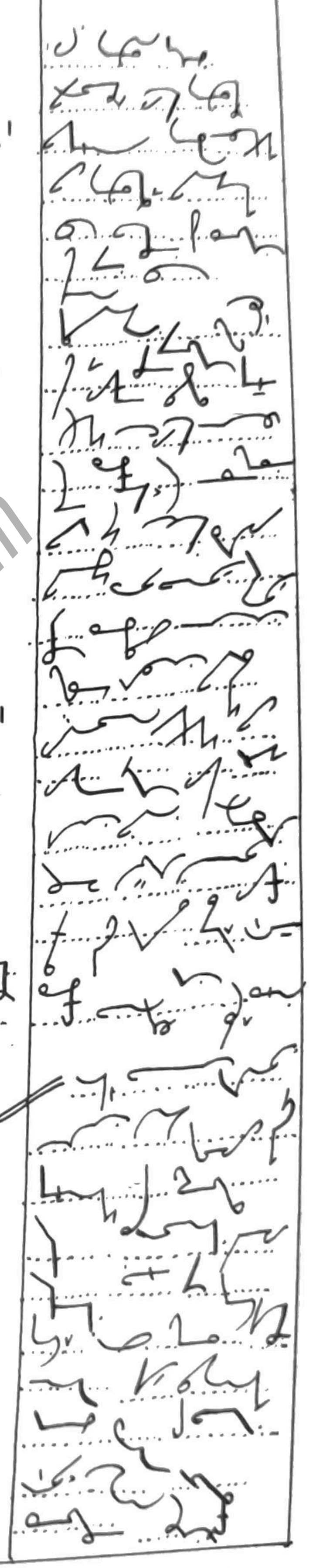

प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीबी हटाओ का कांग्रेस का §2§ नारा कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि उसके घुमाते ही गरीबी दूर हो जाए । यह इस बात पर आश्रित है / कि कांग्रेस में लोग कहाँ तक एक होकर चल रहे हैं और जनता कार्यक्रमों को अमल में लाने में // कहाँ तक सहयोग दे रही है । यह स्पष्ट है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण कांग्रेस विरोधी ही नहीं /// अपितु कांग्रेसी भी उसमें बाधा पहुँचा रहे हैं । फिर कुछ कांग्रेसी तत्वों का यह सोचना भी गलत है कि बाहर §3§ का समाजवाद इस देश में आ जायेगा । इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा है कि हमारा समाजवाद हमारी मिट्टी और / पानी से बना होगा । हम दूसरे देशों के समाजवाद की नकल नहीं कर सकते । यह उन लोगों को करारा जवाब है // जो एकदम सब चीज़ों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं ।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ठीक दिशा /// में चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि सामाजिक न्याय को वे सार्वजनिक महत्व देती है और §4§ वह उसमें किसी प्रकार बाधक नहीं बनना चाहती । जब तक समाज में सबको बराबर का न्याय नहीं मिलेगा तब / तक देश में किसी का भी हित नहीं हो सकता । आज सामाजिक न्याय की सबसे अधिक आवश्यकता है गरीब // वर्ग को। अमीर लोग तो पैसे के बल पर सब कुछ कर लेते हैं परन्तु वह बिचारा गरीब कहाँ जाए /// जिसके पास कोर्ट-कचहरी जाने के लिए पैसे नहीं । आज ऐसे गरीब लोगों को समाजिक न्याय दिलाने की बहुत §5§ ज़रुरत है । §402 शब्द§

www.StenoIQ.com

अभ्यास-37

आदरणीय सभापति महोदय, सोवियत संघ की स्थापना की 50वीं वर्ष गाँठ पर भारत और रुस के नेताओं ने जो / उद्गार व्यक्त किये, उनसे इसी आवश्यकता को बल मिलता है कि अशांति और समस्याओं से भरे इस विश्व में शांति // सहयोग और सह-अस्तित्व की ज़रुरत है । जैसा कि भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा, रुस ने क्रांति का एक रास्ता /// दिखाया । क्रांति के लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए । लेकिन, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए यह ज़रुरी नही कि हिंसा का §1§ ही रास्ता अपनाया जाय । जिस प्रकार ईश्वर तक पहुँचने के लिए धर्म अनक हैं, उसी प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों / को पूरा करने के लिए अनेक पद्धतियाँ हैं । प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता, संभावना एवं उपलब्ध ज्ञान और परम्परा के /// अनुसार अपने अनुकूल व्यवस्था का चुनाव करता है । यह भिन्नता झगड़े का कारण भी बन सकती है और सहयोग का /// स्वस्थ आधार भी प्रस्तुत कर सकती है ।

भारत और §2§ रुस का बढ़ता सहयोग इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में एकरूपता न होते हुए / भी दो देश मानवता के एक समान लक्ष्य की ओर किस तरह बढ़ सकते हैं । जहाँ तक रुस का ताल्लुक है, // इससे

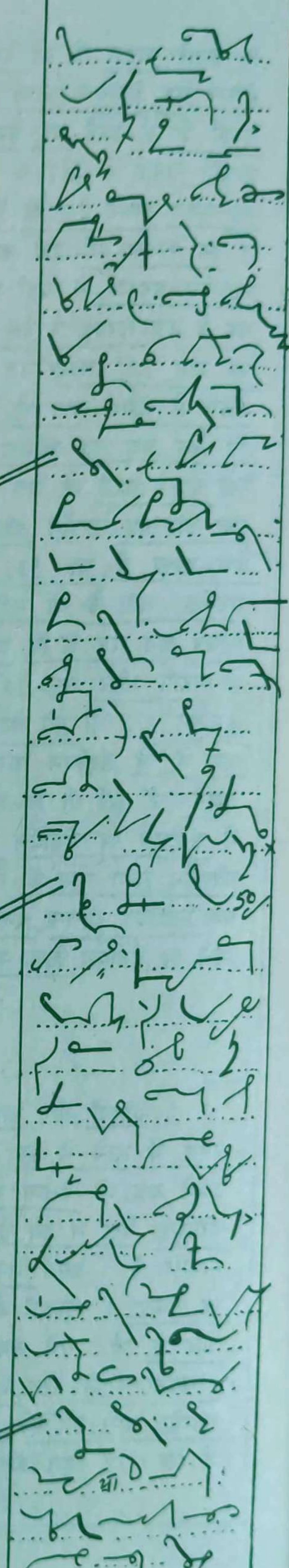

इन्कार नहीं किया जा सकता कि 50 वर्ष की अवधि में वह विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया । /// इसका श्रेय जहाँ सोवियत सामाजिक व्यवस्था को है, वहीं उस टेकनालॉजी को है, जिसके विकास के लिए सोवियत व्यवस्था की {3} स्थापना से पूर्व भी काफी काम हुआ और आज भी हो रहा है । ज्ञान-विज्ञान पर एकाधिकार का दावा कोई / एक देश नहीं कर सकता । यह तो समूची मानवता की थाती है और जाति, वर्ण, धर्म, वाद आदि से ऊपर उठ // कर उसके सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम है । रूस ने बाहर से बहुत कुछ लिया है और अब वह उसका नैतिक /// दायित्व है कि ज्ञान के इस पुराने ऋण को अदा करे । रूस अपने इस नैतिक दायित्व को विकासशील देशों की {4} मदद करके निभा रहा है । हालांकि भारत रूस के विचारों से पूरी तरह से सहमत है तथा भारत जानता है / कि रूस के आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धान्त भारत भी अपना सकता है लेकिन दोनों देशों के राजनीतिक सिद्धान्तों में बहुत // अन्तर है । रूस की राजनीति तानाशाही है जबकि भारत की राजनीति प्रजातांत्रिक है जिसके अनुसार भारत में जो भी आर्थिक, समाजिक /// तथा राजनीतिक परिवर्तन होंगे वे प्रजातांत्रिक तरीकों से होंगे न कि ज़ोर-ज़बरदस्ती द्वारा । यही वह मुख्य अन्तर है जो {5} रूस तथा भारत के राजनीतिक सिद्धान्तों को अलग करता है ।

{410 शब्द}

अभ्यास-38

जहाँ तक शिक्षा, भर्ती और प्रशिक्षण की बात है उस का भी बुरा हाल है । शिक्षा को ऐसा रूप नहीं / दिया गया है कि शिक्षितों की उन सिद्धान्तों एवं आदर्शों में आस्था हो सके जो देश के कल्याण के // लिए निर्धारित किये गये हैं । इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं किया गया कि उन पर आधारित नीतियों में उनकी /// आस्था स्थापित हो सके । जहाँ तक भर्ती का प्रश्न है उसमें यह देखने का कष्ट नहीं किया जाता कि {1} भर्ती किये जाने वालों का विश्वास भी उक्त आदर्शों और नीतियों में है या नहीं । उस में पक्षपात और भ्रष्टाचार / का ज़ोर है । प्रशिक्षण का रूप भी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग तैयार हों जो आदर्श एवं सिद्धान्त विशेषों // से बंधे हों । कोई यह कह सकता है कि ऐसा लोकतन्त्र के विरुद्ध होगा । लोकतन्त्र में जिस दल का शासन /// है वह खास नीतियों और सिद्धान्तों से बंधी हो सकती है, किन्तु जिस माध्यम से वह उन्हें अमल में लाती है {2} उस की उनके प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक नहीं है । लोकतंत्र में शासक दल, बदलते रहते हैं । यदि शासक दल बदलते / रहते हैं या किसी दल विशेष के आदर्शों एवं सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध हो गया तो वह किसी दूसरे // दल के शासनकाल में अपने काम को सही अंजाम कैसे दे सकेगा । तब तो हर बार शासन बदलने पर प्रशासन /// तंत्र में आमूल परिवर्तन करना होगा । इसलिए उसकी प्रतिबद्धता की आवश्यकता क्या है ? सरकारी नीतियों एवं आदर्शों के {3} क्रियान्वयन के लिए मात्र माध्यम बने रहना ही उस के और देश के हित में है । किसी सीमा तक यह / बात तर्कसंगत सी प्रतीत होती है, किन्तु तर्क का विश्लेषण करने पर वह बिल्कुल बेजान पड़ जाता है । फिर यदि // इस आधार पर चला जाये तो कोई भी शासन अपनी नीतियों एवं सिद्धान्तों पर अमल करवा कर देश की तस्वीर /// नहीं

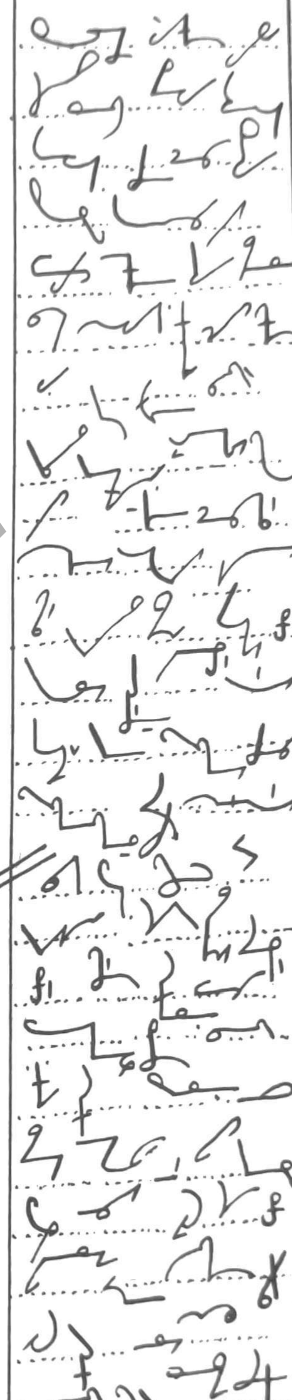

www.StenoIQ.com

बदल सकता । वह तो तभी सम्भव है कि तस्वीर बदलने का काम जिन्हें करना है वे भी तस्वीर बदलने [4] में आस्था रखें - उन सिद्धान्तों एवं आदर्शों के प्रतिबन्ध हों जिन पर अमल करने से तस्वीर बदलती है । [1] इसके लिए ज़रूरी यह है कि समाज में जिन आदर्शों को अच्छा समझा जाए उनके क्रियान्वयन के लिए // लोग स्वेच्छा से आगे आएं और दिल से यह चाहें कि ऐसे सिद्धान्त उनकी भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं । /// ऐसा करने पर ही प्रत्येक को सामाजिक न्याय हासिल होगा और देश को वास्तविक रूप में कल्याणकारी कहा जा सकेगा । [5] [400 शब्द]

अभ्यास-39

उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के पश्चात् देश में सार्वजनिक क्षेत्र का उदय मुख्य रूप से इस लक्ष्य से हुआ कि विशेष महत्व के उद्योगों / के विकास का दायित्व सरकार सम्भाले । उसी नीति के आधार पर गत दो दशक में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार // ने प्रवेश किया । लेकिन सरकारी क्षेत्र के विस्तार से केन्द्रीयकरण तथा एकाधिकार प्रवृत्तियों में न कमी हुई और न वृद्धि /// हुई है । आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कर-भार है । लेकिन हमारे यहाँ की [1] कर-व्यवस्था से वह लक्ष्य कृषि आय पर कर-मुक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार के कारण पूरा नहीं होता । / लोग कर बचाने के लिए इन दो मुख्य स्थितियों की शरण लेकर कर बचा लेते हैं । इस सन्दर्भ में एक // बात और भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आय में जो असमानताएं हैं उसे केवल ऊपर वालों की गर्दन /// काटने से ही समाप्त नहीं होगी । असमानता मिटाने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि आम आदमी का जीवन [2] स्तर ऊँचा हो सके । अमेरिका एक पूँजीवादी देश होकर भी वहाँ आय की असमानताएं इतनी नहीं हैं जितनी हमारे / यहाँ हैं । यहाँ तक कि सोवियत संघ में आय की असमानताएं अमेरिका से ज्यादा हैं । भारत में सरकारी क्षेत्र को // लीजिये । एक छोटे चपरासी को 500 रु0 मासिक मिलता है और सरकारी उद्योग के प्रमुख प्रबन्धक को 10,000 रु0 मिलते हैं । /// इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में ही यह अन्तर 20 गुना है जबकि निजी क्षेत्र में तो यह अन्तर सैंकड़ों गुना [3] तक है । लेकिन अमेरिका में यह अन्तर 10-15 गुना से ज्यादा नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के विस्तार ने निश्चत / रूप से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण और एकाधिकारी की प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्तुत किया है । लेकिन यह विकल्प // इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि केन्द्रीयकरण और एकाधिकारी की प्रवृतियों को समाप्त कर दे । राष्ट्र के 3500 करोड़ /// रुपये के विनियोग सरकारी क्षेत्र में करके भी हम उस विनियोग से इतने लाभ एवं परिणाम नहीं प्राप्त कर सके [4] हैं, जितने हमें प्राप्त करने चाहिए । सरकारी क्षेत्र की इस दुर्दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य है कुशल प्रबन्ध / का अभाव तथा लोगों में कठिन परिश्रम करने की नैतिक भावना की कमी । आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है । छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े अफसरों तक में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है । // आयोजित काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है

तभी वह कार्य होता है, नहीं तो लोगों को परेशान /// किया जाता है । लोग अपनी इच्छा से घूस नहीं देते बल्कि ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है । इसको §5§ दूर करने के लिए कुशल प्रबन्ध तथा लोगों को नैतिक बनाए जाने की आवश्यकता है । §416 शब्द§

अभ्यास-40

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि देखने में यह विधेयक बहुत छोटा सा है लेकिन अपने आप में इसका बहुत महत्व है । / जैसा कि मंत्री महोदय ने उद्देश्य और कारणों में इसका विवरण दिया है जितने भी हमारे केन्द्रीय नियम बनते हैं अथवा आदेश जारी होते हैं उन सब का अनुवाद राज्यों की भाषाओं में, जिन-जिन राज्यों में जिन-जिन भाषाओं /// को अपनी राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत किया हुआ है उन सभी में अधिकृत रूप में प्राप्त हो सके §1§ और उसको विधि के रूप में मान्यता प्राप्त हो इसलिए इस प्रकार का यह विधेयक यहाँ पर लाया गया है । / जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया यद्यपि वे राज्य अपनी-अपनी राजभाषा में उस प्रकार के अधिनियम और नियम // तैयार करते हैं लेकिन वे अधिकृत विधान माने नहीं जा सकते और हमारे द्वारा जो केन्द्रीय अनुवाद होते हैं /// उन अनुवादों को भी अगर इस तरह का विधेयक नहीं लाते हैं तो वह भी प्राधिकृत अनुवाद कहे जा सकें §2§ इसके लिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी ।

मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में 15 / भाषाओं को अधिकृत भाषाओं के रूप में मान्यता दी है । लेकिन वित्तीय ज्ञापन के पैराग्राफ तीन में उन्होंने बताया है // कि भाषाओं में वह अनुवाद करेंगे । चार भाषाएँ उन्होंने छोड़ी हैं । मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वह चार /// भाषाएँ जो छोड़ी हैं वह क्यों छोड़ी हैं ? उन में अनुवाद करने की आवश्यकता है या नहीं । यदि नहीं तो §3§ मंत्री महोदय बताए कि वह आवश्यकता क्यों नहीं है ।

मंत्री महोदय ने यह भी अपने वित्तीय ज्ञापन में दिया है / कि एक व्यवस्था तो राज्य सरकारों की अपनी है जो इस प्रकार के अधिनियमों, नियमों आदि का अनुवाद अपने-अपने // राज्य क्षेत्र में करती है और उसके अधिनियमों, नियमों और उपनियमों के अनुवाद को देखेगी और उसके बाद उसको यह अन्तिम स्वीकृति प्रदान करेगी । §4§ तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें यह दोहरी व्यवस्था न हो कि राज्य में अलग और केन्द्र में अलग हो । यदि हम केन्द्रीय स्तर पर ही इस तरह के अनुवाद करें और केन्द्रीय स्तर // पर किए गए अनुवाद ही अधिकृत अनुवाद माने जायें और फिर वह राज्यों को भेज दिए जायें तो मैं समझता हूँ /// कि दोहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी कि राज्य सरकार अपने यहाँ पर करें और उसको आप ही अन्तिम रूप दें §5§ मंत्री महोदय इसको भी स्पष्ट करने की कृपा करें । §409 शब्द§

अभ्यास-41

उपाध्यक्ष महोदय, पाँचवीं योजना पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है । किन्तु मंत्रिमंडल में लगभग दो माह तक विचार / किये जाने के बाद योजना के दृष्टिकोण पत्र में अनेक परिवर्तन किये गये हैं । योजना आयोग मंत्रिमंडल के सुझावों को // अब दृष्टिकोण-पत्र में शामिल कर उसे अन्तिम रूप दे रहा है । राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाकर /// उसकी भी दृष्टिकोण-पत्र पर स्वीकृति लेने का प्रस्ताव है । दृष्टिकोण-पत्र पर इतनी लम्बी बहस मंत्रिमंडल में पहले (1) कभी नहीं हुई । इस पर विचार के समय हर मंत्रालय से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विस्तृत तौर चर्चा / हुई । योजना आयोग ने अपने नोट में लगभग हर क्षेत्र में विकास में शिथिलता आ जाने तथा प्रगति धीमी पड़ // जाने की चर्चा की थी । अनेक मामलों में नीतियों तथा कार्यक्रमों पर नये सिरे से विचार का भी सुझाव दिया /// गया था । आयोग की इस राय से आर्थिक मंत्रालयों ने सहमति प्रकट नहीं की बल्कि विदेश व्यापार मंत्री ने (2) दृष्टिकोण-पत्र में विदेश व्यापार के मामले में आयोग के विचारों को बदलने पर जोर दिया तथा तथा इसके लिए उन्होंने / अपनी ओर से कुछ मसौदा लिख कर भेजा । कच्चे माल की कमी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट, हमारे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय भाव // पर कच्चा माल न मिलने तथा करों में अनेकता इत्यादि पर भी खुलकर विचार किया गया ।

विशेषज्ञों की राय है /// कि निर्यात उद्योग को जब तक वही सुविधा नहीं दी जाती, जो अन्य देशों में उत्पादकों को प्राप्त है, तब (3) तक हम अपना माल विदेशी बाज़ार में प्रतियोगी नहीं बना सकते हैं । फिर निर्यात कैसे बढ़ेगा । लाइसेंस नीति तथा राष्ट्रीयकरण / और ऋणों को शेयर में बदलने सम्बन्धी सरकारी घोषणाओं के कारण औद्योगिक विकास की गति रुक गयी है । नयी पूँजी // का विनियोजन अधिक नहीं हो पा रहा है । उद्योगों का विस्तार भी रुका पड़ा है । बल्कि कच्चा माल न मिलने /// तथा हड़ताल आदि के कारण अनेक कल-कारखाने बंद हो गये हैं अथवा पूरी क्षमता से उसमें उत्पादन नहीं हो (4) पा रहा है । इससे औद्योगिक क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हो गया है । योजना आयोग ने इस स्थिति पर चिन्ता व्यक्त / की है । लेकिन चिन्ता करने से ही काम नहीं चलेगा इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे ऐसे कदम उठाए // जिससे देश में अधिक से अधिक औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, नये-नये कल-कारखाने खुले तथा उद्योगों को कच्चे / माल, बिजली पानी इत्यादि की कोई भी कमी महसूस न हो । जो कल-कारखानें किसी भी कारण से बन्द पड़े है (5) उन्हें फिर से चालू करवाने के लिए सरकार को पूरे-पूरे प्रयत्न करने चाहिए ताकि वे फिर से खुलकर देश / के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकें । (427 शब्द)

अभ्यास-42

मान्यवर, पटना में हुए अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन के रास्ते में कई रुकावटें आयी फिर भी उल्लेखनीय बात यह है कि / वह सफल हुआ । इन्हीं रुकावटों

www.StenoIQ.com

और बाधाओं के कारण सम्मेलन में उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं रही । सम्मेलन की शुरुआत किये // जाने के समय जो आश्वासन मिले थे वे सब भी पूरे नहीं हुए । सम्मेलन से पहले एक संकल्प /// प्रकाशित-प्रेषित किया गया था, जिसे मानने वाले इस सम्मेलन में भाग ले सकते थे । इस संकल्प की मुख्य बातें थीं : (1) साम्राज्यवाद के सभी रूपों का अंत होना चाहिए । विभिन्न धर्मों के अनुयायी नागरिकों में कोई फर्क न हो, कानून/सबके लिए समान हो, भारत-पाक का नकली बटवारा खत्म हो, हरिजन, शुद्र, आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यकों और औरतों को // विशेष अवसर दिये जायें, केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के कामकाज और व्यापार से तथा शिक्षा के माध्यम और अनिवार्य विषय /// के रूप में अंग्रेजी तत्काल हटे । जब तक भारतीय राज्य हैं तब तक उस की सीमाओं की रक्षा हो, (2) जब तक उत्पादन आधुनिक नहीं होता खपत की आधुनिकता बिल्कुल बन्द हो, सभी निजी खर्चों पर 1500 रुपये मासिक / की सीमा लगे, अन्याय के विरुद्ध लड़ने में सिविल नाफरमानी एक मूल्यवान हथियार है, जिसका बढ़ता हुआ इस्तेमाल होना चाहिए, // नर-नारी के बीच पूर्ण समता की प्रतिष्ठा हो और शिक्षा जगत में विषमता का अंत हो और पूर्ण विचार-स्वातन्त्रय /// के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन हो ।

सम्मेलन में पढ़े गये लेखों पर विचार-विमर्श हुआ । इन विषयों (3) पर सुझाव और विश्लेषण सामने आये । चर्चा में यह बात सामने आयी कि पिछले दिनों दंगों का स्वरूप बदला है । / वे आकस्मिक न होकर नियोजित होने लगे हैं । यह भी कि जो इन के पीछे होते हैं उन पर सीधी // चोटें होने से दंगे बन्द हो जाते हैं और अब दंगे शिक्षित वर्ग को भी अपने में समेट लेते हैं । /// राजनीतिक स्थिति और आर्थिक नीति विषयक लेखों व चर्चा में यह बात सामने आयी कि कुछ लोगों को लगातार इन (4) का विश्लेषण करते रहना चाहिए । आर्थिक नीतियों का ज्यादा ठोस अध्ययन ज़रूरी है । समस्या का विश्लेषण ही नहीं उसका निराकरण / भी सामने आना चाहिए । वस्तु-स्थिति यह है कि अब तक ऐसे कई सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें बहुत अच्छे-अच्छे विचार // रखे जाते हैं । लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों की मनोवृति में स्थाई परिवर्तन नहीं होता । जब तक /// वे सम्मेलनों में रहते हैं तब तक तो सोचते और महसूस करते हैं कि जो कुछ कहा गया है वह (5) बिल्कुल सही है और इन बातों पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए । लेकिन दूसरे ही क्षण जब वे सम्मेलन / के पंडाल से बाहर आते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं । (432 शब्द)

अभ्यास-43

नगर निगम जिस आशा और विश्वास के साथ बनाया गया था, उसे निगम की दलगत राजनीति ने सफल होने का / अवसर नहीं दिया । जिस दल का प्रभुत्व रहा, वह अपने ही तरीके से हथकंडे अपना कर नागरिकों को नचाता रहा । // इस मामले में कहाँ तक किसे दोष दिया जाय । अनेक बार उद्घाटनों में हमने नगर निगम के

नेताओं के /// जो भाषण और प्रवचन सुने, उनसे ऐसा लगता था कि न तो दिल्ली में अब अस्पतालों की कमी रहेगी और (1) न पानी और बिजली की । अब भी जिस तेज़ी के साथ दिल्ली का चारों तरफ विस्तार हो रहा है वहाँ / नागरिक सुविधाएँ बड़ी अत्यन्त अल्प मिल पा रही हैं और कहीं-कहीं तो नागरिक अपने बलबूते पर ही नगर में // जिंदा हैं ।

नगर निगम ने अपने बजट में पानी व बिजली का वर्तमान मूल्य बढ़ाने पर बल दिया है /// और निगमायुक्त ने धार्मिक स्थानों पर पानी देने की सुविधा वापस लेने का का सुझाव दिया है । उन्होंने जो इस सम्बन्ध (2) में तर्क दिया है, वह बड़ा महत्व रखता है । निगमायुक्त का कहना है कि जब धार्मिक संस्थान बिजली शुल्क अदा / कर सकते हैं, तो उन्हें पानी का शुल्क अदा करने में क्या कठिनाई होगी । दिल्ली में अनेक ऐसे धार्मिक संस्थान हैं // जिनका निजीकरण कर दिया गया है । धर्मशालाएँ जिन्हें पूर्वजों ने कभी बनाया था, अब कई पीढ़ियों के बाद वर्तमान /// उत्तराधिकारी उन्हें अन्य कार्यों में उपयोग कर रहें हैं । नगर निगम को यह भी पता नहीं कि ऐसी संस्थाएं हैं, (3) जो सम्पत्ति-कर चुकाती है । इस तरह से अनके स्थानों पर निगम के आय के साधन बढ़ाये जा सकते हैं । / उस दिशा में नगर निगम ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया । निगम की अब भी ऐसी अनेक सम्पत्तियाँ हैं जिन // पर दूसरों के कब्ज़े हैं, बहुत सी जगहों पर अनधिकृत निर्माण भी हो चुका है, पर निगम का इस सब /// को देखने भालने के लिए कोई फुरसत नहीं । निगम में इस समय जिस ढंग से अफसरशाही का बोलबाला है, उसे देखते हुए (4) लगता है कि नगर निगम में कोई भी दल सत्ता में आये, उससे आम नागरिक को सुविधाएँ नहीं मिल पायेंगी । / आखिर लोगों को सुविधाएँ क्यों न मिले जिनके कि वे अधिकारी हैं । अब करों की चोरी नहीं होती, सभी लोग // ईमानदारी से कर चुकाते हैं । फिर उन्हें सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं । मेरे विचार में इस पर खुलकर /// बहस होनी चाहिए और सब सदस्यों की राय ली जाए कि ऐसी स्थिति में लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग (5) कैसे करना चाहिए । (403 शब्द)

www.StenoIQ.com

अभ्यास-44

सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा अब तक उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव है । समिति इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति और उसकी सफलता // तथा भविष्य में इसमें सुधार लाने के बारेमें सुझाव देगी । अगले दो वर्षों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने /// की भी एक योजना तैयार की गई है । गृह मंत्रालय ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार (1) किया है । हिन्दी सलाहकार समिति ने 22 जून को यहाँ अपनी बैठक में इस पर स्वीकृति दे दी है । मंत्रालय / ने खुद ही अनेक पुराने फैसलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की है ।

अब तय हुआ है // कि भारत में हस्ताक्षर किये जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा संधियाँ जो हिन्दी में तैयार होने वाली हों, /// अवश्य ही हिन्दी में तैयार होने लगेंगे । करारों, संविदाओं तथा टेंडरों के फार्मों आदि को हिन्दी और अंग्रेज़ी में तैयार {2} करने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री ने की । बैठक में गृह मंत्रालय के / राज्यमंत्री ने भी भाग लिया । हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पारस्परिक पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी का उपयोग // बढ़ाया जायेगा । पहले वर्ष में हिन्दी में न्यूनतम पत्र-व्यवहार 30 प्रतिशत तथा अगले वर्ष में उसे बढ़ा कर 50 /// प्रतिशत करने का फैसला किया गया है । जनता को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भेजे जाने वाले सभी पत्र हिन्दी में {3} भेजें जायें, फाइलों पर टिप्पणी भी हिन्दी में चढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है । प्रेस विज्ञप्ति आदि का हिन्दी में भी / पर्याप्त मात्रा में प्रकाशन न होने के कारण इस काम में तेज़ी से प्रगति करने पर ज़ोर दिया गया है । // जिन कार्यालयों में 25 से अधिक तथा 100 से कम कर्मचारी हों उनमें कम से कम एक हिन्दी टाईपराइटर ज़रूर /// खरीदा जाना चाहिए तथा हिन्दी टाईपिस्ट तथा स्टेनोग्राफ़र भी नियुक्त किए जाएँ । ये निर्देश तो हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं । लेकिन केवल निर्देश देने से काम नहीं चलता / सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के सोचने के ढंग में परिवर्तन आना चाहिए // । लोगों को चाहिए कि वे स्वेच्छा से अपना दिन-प्रति-दिन का कार्य हिन्दी में करें और यह न सोचें /// कि हिन्दी में कार्य करने पर लोग उन्हें अनपढ़ समझेंगे । जब तक लोगों के अन्दर यह हीन भावना विद्यमान रहेगी {5} कि अंग्रेजी में काम करने पर या अंग्रेजी में बातचीत करने पर ही दूसरे उन्हें पढ़ा-लिखा समझेंगे, तब तक / हिन्दी का प्रयोग नहीं बढ़ सकता चाहे सरकार कितने ही प्रयत्न कर ले या धन खर्च कर ले ।
{436 शब्द}

अभ्यास-45

उपाध्यक्ष महोदय, संसद का शीतकालीन अधिवेशन पाँच सप्ताह चलने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया । इस अधिवेशन / में बहुत हँगामा भी हुआ । इस अधिवेशन के दौरान संसद ने देश की खाद्य स्थिति, मूल्य-वृद्धि, विदेश नीति, // सी0आई0ए0 की गतिविधि तथा देश के अन्दरूनी मामलों में उसका हस्तक्षेप इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया /// और इसके साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए जिसमें विवादास्पद मुल्की नियम विधेयक भी पारित किया गया । लोकसभा में इस विधेयक पर काफी विवाद उठा । इससे पहले जब सरकार / ने इस विधेयक को सदन में पेश करना चाहा तो संवैधानिक व कानूनी आधार पर विपक्ष ने इसका प्रबल विरोध // किया और विधेयक को पेश नहीं

www.StenoIQ.com

होने दिया था । वास्तव में विपक्ष ने इस सम्बन्ध में जो तर्क पेश /// किए वे काफी जानदार थे । इसीलिए मंत्री महोदय को अन्त में यह कहना पड़ा कि वे सभी आपत्तियों पर {2} सर्वप्रथम स्वयं विचार करेंगे तथा अपने को संतुष्ट करना चाहेंगे तथा वह फिर पेश किया जाएगा । अन्ततोगत्वा विधेयक पेश / करने की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा ।

दूसरे दिन अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब विधेयक को पेश किया // जा सकता है । लेकिन विपक्ष ने, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, विधेयक पेश करने विषयक मतदान का बॉयकाट कर दिया । /// फिर जब इस विधेयक पर विचार शुरू हुआ तो संगठन कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी ने विचार का यह कह कर {3} बहिष्कार कर दिया कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में बहुत जल्दबाज़ी की है और सदस्यों को इस पर / सोचने का अधिक अवसर नहीं दिया । इसके फलस्वरूप आन्ध्र और तेलंगाना की जनता, ऐसा प्रतीत होता है कि, यह धारणा बना चुकी है कि अब वह एक साथ नहीं रह सकती /// और मुल्की-नियम विवाद का एकमात्र हल राज्य का शीघ्रतातीशीघ्र विभाजन ही है । लोकसभा में भी कई सदस्यों ने {4} इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं । इसलिए मुल्की नियम विधेयक के पारित होने और इस विषय में प्रधान-मंत्री की घोषणा से कि आन्ध्र का विभाजन नहीं किया जाएगा, लोगों को निराशा होगी और इसके साथ ही साथ // उनकी प्रतिक्रिया भी रोषपूर्ण होगी । यह स्वाभाविक भी है । लेकिन अगर इसको व्यापक राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखा जाए /// तो प्रधानमंत्री की यह घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य है तथा इस पर पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए । {5} {400 शब्द}

अभ्यास-46

प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता जार्ज वॉल्ड का कहना है कि अगर वर्तमान दुनिया खत्म हुई तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी / अमेरिका की होगी । उसके अनुसार यह कहना गलत है कि शस्त्रों की दौड़ के लिए कई राष्ट्र ज़िम्मेदार हैं । आज // केवल अमेरिका ही मौत का सबसे बड़ा सौदागर है । वह सच्चा लोकतंत्र नहीं, एकदलीय तानाशाह है, - जहाँ परमाणु हथियारों का /// विरोध करने वाली राजनीतिक शक्तियों का आभाव है । उन्होंने अत्यन्त मार्मिक शब्दों में बताया कि अमेरिका का शासक वर्ग किस {1} हद तक दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है । उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार सबसे पहले अमेरिका ने बनाए / और प्रयोग किए और फिर भी कहता रहा कि वे तो आत्म-रक्षा के लिए हैं । आज अन्तरिक्ष युद्ध के // हथियार भी वही बना रहा है और कह रहा है कि वे दुनिया के सारे परमाणु हथियारों को खत्म /// करने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों बातें झूठी हैं ।

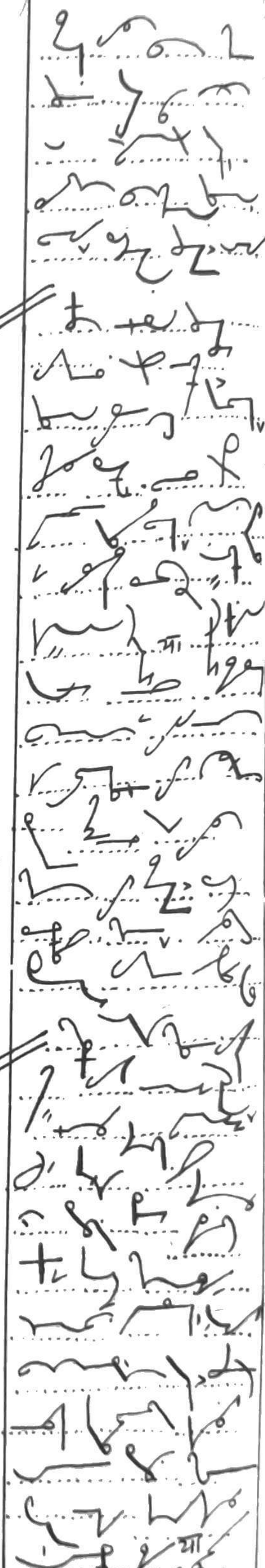

www.StenoIQ.com

अमेरिका का इरादा हमेशा आक्रमण का रहा है {2} और धीरे-धीरे उसने युद्ध के इस तामसिक इरादे को अपना व्यवसाय बना लिया है । अमेरिका की समृद्धि का सबसे / बड़ा रहस्य उसका युद्ध-उद्योग है । हथियारों के कारखानों को राष्ट्रपति रेगन ने खुली छूट दे रखी है । यह आश्चर्य // की बात है कि हथियार बनाने वाली कम्पनियाँ सबसे अधिक मुनाफा कमा रही हैं और सब से कम /// आयकर दे रही हैं इससे स्पष्ट है कि अमेरिका को इन भयानक हथियार बनाने वाली कम्पनियों का कितना ख्याल है । {3} दुःख की बात है तो यह है कि हम असहाय वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के अलावा इस देश में कोई ऐसा संगठित / वर्ग नहीं है जो राज्य के इन सत्यानाशी इरादों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें ।

अमेरिका में दो पार्टी व्यवस्था फेल // हो चुकी हैं । दोनों पार्टियाँ एक ही रथ के दो पहियों की तरह हैं । युद्ध-उद्योग की तानाशाही के आगे /// दोनों पार्टियाँ नतमस्तक हैं । अमेरिका की आम जनता इन राजनैतिक दलों की चाल को समझने में असमर्थ हैं । लोकतन्त्र {4} युद्धतन्त्र में बदल गया है । अखबारों में वे खबरें छपने नहीं दी जाती जो परमाणु परीक्षणों की पोल खोलती है । / उन्होंने अपने भाषण के अन्त में अमनपसन्द लोगों से अपील की कि वे संगठित होकर परमाणु हथियारों तथा परीक्षणों के विरुद्ध // आवाज़ उठाएँ । उन्होंने निरस्त्रीकरण के लिए की गई "दिल्ली घोषणा" की तथा भारत द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रयत्नों /// की सराहना की और कहा कि आज आवश्यकता ऐसे देशों की है जो इस सम्बन्ध में आगे आकर स्थाई शान्ति {5} के लिए प्रयत्नशील हों । {404 शब्द}

अभ्यास-47

माननीय मन्त्री जी, मैं सरकार की कर-नीति के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ । सरकार की / कर और कीमत-नीति जनकल्याण के लिए नहीं बनाई गई हैं । आज यह आम लोगों पर कहर ढाने लगी हैं । // उद्योगों तथा कम्पनियों को अधिक से अधिक राहत देने से जनता की आम खपत की चीज़े महँगी की जा रही /// हैं । अर्थशास्त्रियों की राय में इससे एक ओर प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तथा दूसरी ओर इसके साथ ही साथ {1} महँगाई भत्ते की माँग भी बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप योजना खर्च में वृद्धि होगी । अभी से कोयला, चावल, गेहूँ, चीनी, / खाने के तेल और पेट्रोल, डीज़ल, रसोई-गैस, उर्वरक और मिट्टी के तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो चुकी है // जिससे न केवल कम आय वाले लोगों पर बल्कि मध्य वर्ग के लोगों पर भी जीवन-यापन का काफी बोझ /// बढ़ा है । इससे सब्जियों फलों तथा आम-खपत की हर तैयार वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा । अर्थव्यवस्था फिर से कीमतों में {2} व्यापक वृद्धि और विस्तार का शिकार हो जाएगी । इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने अपना बढ़ता हुआ घाटा पूरा / करने के लिए ये कदम उठाए हैं किन्तु यह

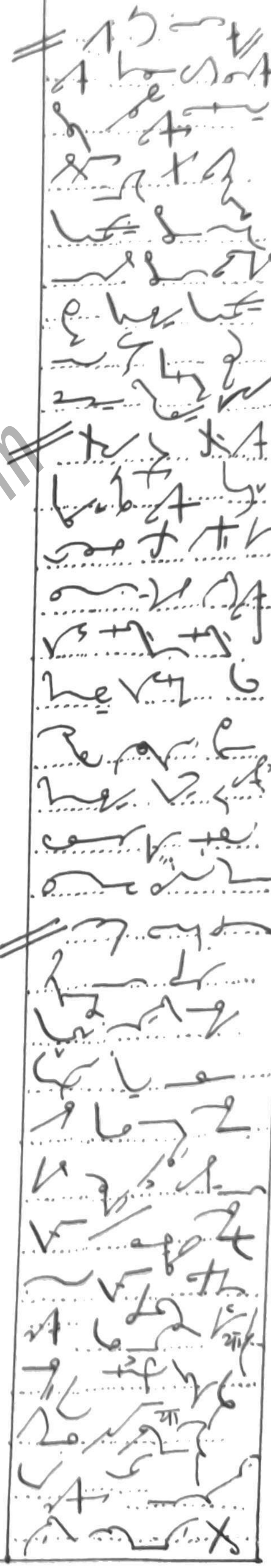

www.StenoIQ.com

विचारणीय है कि इससे खर्च के हर क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होगी // यह निश्चय ही मुद्रा स्फीति की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा ।

बड़े-बड़े शहरों में आए दिन बसों के भाड़े बढ़ाये जाते हैं । अब देखना है कि रेलवे बजट में क्या होता है । पेट्रोल मँहगा होने से स्कूटर और टैक्सी के §3§ भाड़े भी बढ़ेंगे । परिवहन खर्च बढ़ने से भी उपभोक्ता बस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी । सरकार द्वारा घोषित उदार आर्थिक नीतियाँ आम / लोगों के लिए अचानक ही कठोर और निर्मम कैसे बन गई, समझ में नहीं आता । अतः मेरा प्रधान मंत्री और // वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और विभिन्न करों के प्रस्ताव रखने /// से पहले गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को अवश्य दृष्टि में रखें । ऐसा न करने पर कीमतों में अधिक वृद्धि से §4§ गरीब लोगों तथा निशिचत आय-वर्ग समूह के लोगों की कमर टूट जाएगी ।

पुराने जमाने में लोग नये करों के / लिए सिर्फ बजट के दिन ही घबराते थे लेकिन अब वर्ष का कोई भी दिन ऐसा नहीं जब लोगों को / बढ़ती मँहगाई से घबराहट न हो । अतः मेरा पुनः निवेदन है कि इससे पहले कि इस जनविरोधी नीति के /// विरुद्ध समूचे देश में ज़ोरदार आन्दोलन शुरु किया जाए, आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और ऐसे कदम उठाएँ जिससे §5§ आम उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती हों और हरेक आदमी को / आसानी से मिल सकें । §424 शब्द§

अभ्यास-48

उपाध्यक्ष महोदय, आज सब चीज़े जिस प्रकार इस देश में उलझी हुई हैं, अन्यत्र नहीं । यहाँ धर्म, दर्शन, विचार, राजनीति / भाषा, रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा सब उलझी हुई हैं । इस उलझन का मुख्य कारण है नज़र का साफ न होना । // आज धर्म को राजनीति की नज़र से देखा जा रहा है, भाषा को धर्म की नज़र से देखा जा रहा है, /// दर्शन को आधुनिक रहन-सहन की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिससे समस्याएँ बढ़ रही हैं । जिस प्रकार राजनीति, §1§ दल, जाति और राज्य से जुड़ी हुई है, उसी तरह भाषाएँ भी जाति, धर्म और राज्य से जुड़ी हुई हैं । / यह बिडम्बना नहीं तो क्या है ? हिन्दुओं की भाषा हिन्दी कैसे हो गई ? शायद इसलिए कि इसकी लिपि देवनागरी है । // उर्दू मुसलमानों की भाषा शायद इसलिए है कि करोड़ों, हिन्दुओं के मुसलमान बनने पर भी मुसलमान सबकी नज़र में विदेशी /// रहे और उर्दू लिपि को विदेशी माना गया । बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश आदि के हिन्दुओं की भाषा हिन्दी नहीं है और §2§ न ही वहां मुसलमानों की भाषा उर्दू है । बंगाली, मद्रासी, असमी हिन्दुओं की भाषा हिन्दी नहीं होने के कारण ही / हिन्दी भाषी हिन्दुओं से उनका पृथक अस्तित्व बना हुआ है ।

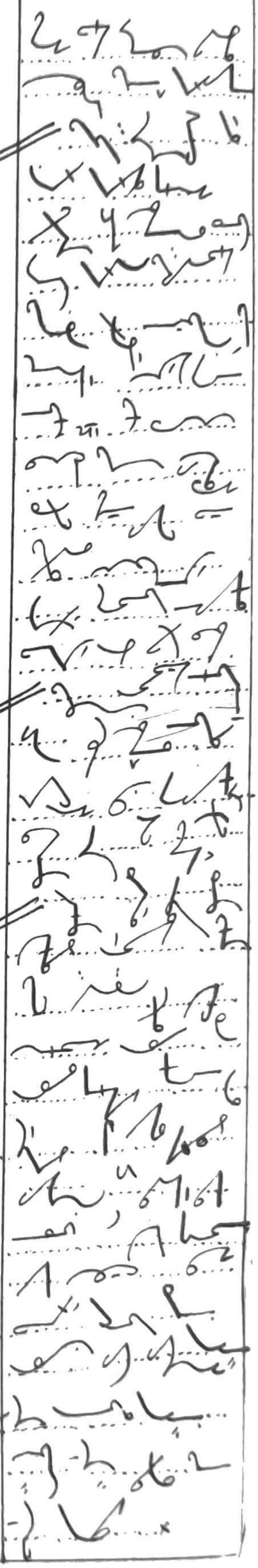

राजनीति ने भाषाओं को जो / नुकसान पहुँचाया है वैसा किसी ने नहीं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ हैं। उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा /// भी नहीं है फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम उर्दू क्यों हो। आजकल विश्वविद्यालयों में परीक्षा का माध्यम बहुत ‖3‖ अटपटा है। हिन्दी-भाषी क्षेत्रों को छोड़कर कहीं परीक्षा और शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप हिन्दी मातृभाषी / को अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देनी पड़ती है। भाषा को धर्म और जाति से जोड़कर जो / हाल पंजाब का किया गया, अब वही हाल उत्तर प्रदेश और बिहार का किया जा रहा है। अंग्रेजी अगर इतनी /// व्यर्थ और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में बाधा पहुँचाती है तो भारत सरकार एक अध्यादेश द्वारा अंग्रेजी को समाप्त ‖4‖ क्यों नहीं कर देती। क्या अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने से देश का विभाजन हो जाएगा? / यह आरोप कि हिन्दी संस्कृतनिष्ट होती जा रही है, बेबुनियाद है। यह हिन्दी का कठिन होना नहीं यह तो भाषा // के विकास की प्रक्रिया है, इसे आप रोक नहीं सकते। जैसे-जैसे मानवता और संस्कृति में विकास होता रहता है, उसी /// प्रकार भाषाओं में भी विकास होता रहता है और यह सहज स्वाभाविक है। सत्य को सत्य के रूप में ही स्वीकार ‖5‖ करना चाहिए और भाषा को धर्म, जाति और राज्य या राजनीति से मिलने की ज़रूरत नहीं। ‖416 शब्द‖

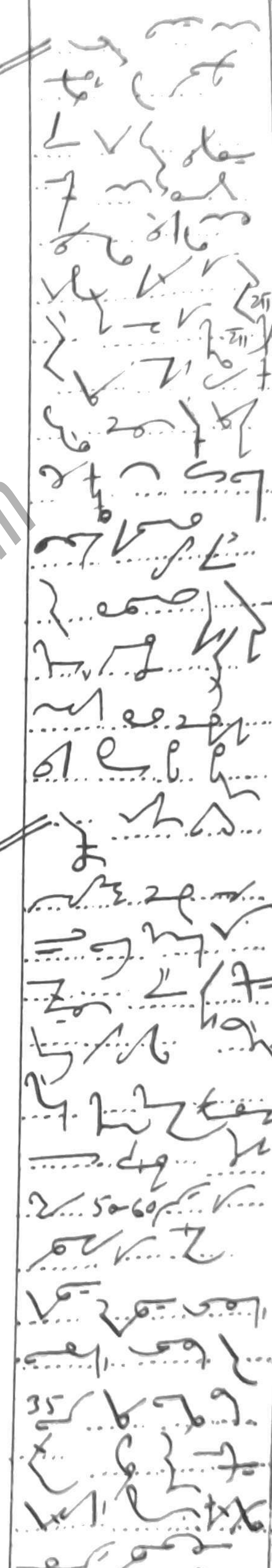

अभ्यास-49

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि विकास की दृष्टि कहाँ केन्द्रित हो। / गाँवों और कृषि को प्राथमिकता देने की बात को लेकर कुछ क्षेत्रों में आशंका प्रकट की जाती है कि बड़े // उद्योगों की उपेक्षा हो रही है। विभिन्न स्तरों पर इस भ्रान्ति को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। /// माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि केन्द्र बड़े उद्योगों के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब समस्या यह ‖1‖ है कि प्रति वर्ष 50-60 लाख लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी हो तब हल ऐसा खोजना होगा, / जिससे बेरोज़गारों और अर्द्ध-बेरोज़गारों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हों। कांग्रेसी नेताओं के आँकड़ों के अनुसार अब भी // 35 करोड़ लोग बेहद गरीब हैं और 10-15 करोड़ लोगों के पास सर छिपाने का ठौर नहीं। ऐसी स्थिति /// में सरकार को चाहिए कि वह कुटीर-उद्योगों को बढ़ावा दें जिनकी स्थापना में थोड़ा पैसा लगे और ‖2‖ अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। सरकार को बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए जिसमें पैसा / भी अधिक लगता है और उनमें कम लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। 60-70 लाख आबादी वाले बम्बई नगर // की समस्या हल करने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था के स्थान पर अगर डेढ़ लाख गाँवों में /// रहने वाले करोड़ों लोगों को पीने का पानी पहुँचाने को प्राथमिकता दी जाए तो अधिक अच्छा होगा। शहरों और गाँवों ‖3‖ में बेरोज़गार व्यक्तियों को ऐसे खुला छोड़ देने के स्थान पर उन्हें गाँवों में कोई लघु उद्योग स्थापित करने को / प्रोत्साहित करके गाँवों में क्रान्ति लायी जाए और शहरों का बोझ हलका किया जाए।

समस्याएँ जिस रूप में उभर रही है // उनको अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता । गरीबी का मोर्चा तोड़ने में विफल रहने के बावजूद जनता ने /// कांग्रेस को अब तक कई वर्षो का मौका दिया है लेकिन मौजूदा सरकार कामयाब नहीं हो सकी है । बड़े उद्योगों ॥4॥ के अपने विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि गाँवों में रहने वाली देश की 80 प्रतिशत जनता की क्रयशक्ति / बढ़ाएँ । बड़े उद्योग समाज के केवल एक छोटे वर्ग की आवश्यकताएँ पूरा करके ही संतुष्ट नहीं रह सकते । छोटे उद्योगों / और कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने और उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत को भारतीय मानक संस्थान के सत्रहवें अधिवेशन में भी /// महत्व दिया गया । आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मशीनों से होड़ में मनुष्य हार रहा है । ॥5॥ समस्या एक दार्शनिक रूप भी अख्तियार कर चुकी है । यह समझ में नहीं आ रहा कि लोकतंत्र इंसान के लिए / है या रबोटों के लिए । ॥425 शब्द॥

अभ्यास-50

मेरे प्रधान मंत्री पद पर रहने के पहले वर्ष के दौरान देश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात / हुई वह यह कि लोगों का मूड बदला है उनके सोचने का ढ़ंग बदला है । एक साल पूरा होने // पर हम खुद को सौहार्दपूर्ण और मैत्री की राजनीति पर अमल करने वाला कह सकते हैं और साथ ही एक /// गतिशील अर्थव्यवस्था होने का तथा मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित समाज के निर्माण का दावा कर सकते हैं । ॥1॥ महात्मा गांधी की हत्या के बाद सबसे दुःखद बात श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या थी । लेकिन उस समय तनाव, / चिन्ता और दुःख का जो वातावरण था वह आज आशा और विश्वास में बदल गया है । पिछले आम चुनाव तो // देश के लिए एक ज़बर्दस्त मोड़ थे । देश के टुकड़े न हो जाएं इस डर से लोगों ने एक साथ /// मिलकर हमें ज़बर्दस्त समर्थन दिया । इसी समर्थन के कारण हम पंजाब और असम जैसी समस्याओं को हल करने की भरसक ॥2॥ कोशिश कर रहे हैं । असम की समस्या तो अब हल हो चुकी है ।

हमने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा / दी तथा दलबदल जैसी खतरनाक राजनीतिक व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने में सफल हो सके । इस समय जिस चीज़ // पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है वह है जनसंख्या नियन्त्रण और मानव संसाधनों का विकास । हम अधिक लाभ /// पाने के लिए उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों को हर काम में लगा रहे हैं । साथ ही जन्म-दर कम करने ॥3॥ के लिए परिवार नियोजन पर भारी पैसा खर्च किया जा रहा है । समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार बहुत / महत्वपूर्ण है तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा कर इस दिशा में सही कदम उठाया // गया है ।

निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को जड़ों से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं उसकी जड़े अधिक फैली हुई हैं। /// आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कानून और व्यवस्था मशीनरी को गतिशील और मज़बूत {4} बनाया जाना चाहिए। पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि राजनीतिक प्रक्रिया को वहाँ पुनः बहाल किया जाए तो आतंकवाद खत्म करने की दिशा में शुरुआत मानी जाएगी। पंजाब में समस्या यह है कि // वहाँ आतंकवाद राजनीति तथा धर्म के साथ मिल गया है। लेकिन वहाँ चुनाव के बाद आतंकवाद मुख्यधारा से कट /// सा गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आतंकवाद ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। इसे रोकने {5} और पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मज़बूत राजनीति और लगातार सतर्कता ज़रूरी है। {415 शब्द}

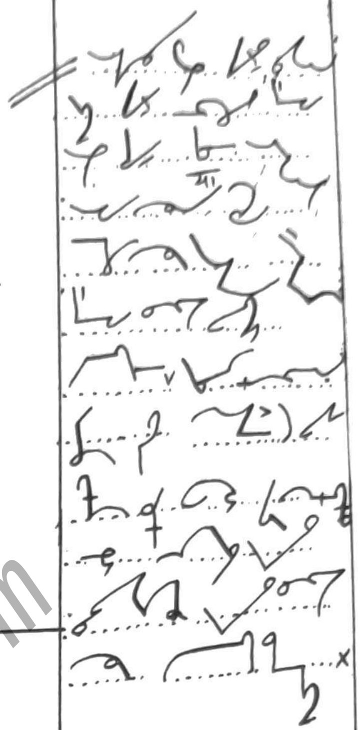

डा० आ० म० साजनानी
की
मानक आशुलिपि पर प्रत्येक
पुस्तक के लिए
लिखें :
मुख्य वितरक
कृष्णा प्रकाशन
229ए-, पाकेट-सी,
मयूर विहार, फेज़-II,
दिल्ली-110091
दूरभाष :
मो० : 9811344544
8010220282

100 श० प्र० मि० अभ्यास

www.StenoIQ.com

अभ्यास-51

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है / और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है । सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस // ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है । यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोज़गार वर्ग /// है वह क्रान्ति कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा । अतः मेरा सुझाव है कि सरकार (1) को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए । यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूँक मारते ही दूर हो जाएगी । इसके / लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा । नये-नये रोज़गार के अवसर सरकार को ढूँढने होंगे, पढ़ाई के ढाँचे में परिवर्तन करना // पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा । 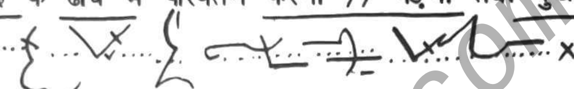

अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में /// भी कुछ कहना चाहता हूँ । मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही है । एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि (2) इस वक्त हिन्दुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है । लोगों के पास सामान खरीदने के / लिए पैसा नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं । ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने // की कोशिश करते हैं । इसी प्रकार दंगे-फसाद बढ़ रहे हैं । इन सबका कारण मूल्यों में वृद्धिसे लगाया जा सकता है । लोगों /// में बेरोज़गारी पहले से ही काफी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएँ सस्ते दामों पर न मिल सकें तो उनकी हालत (3) और भी खराब हो जाती है । एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाज़ार में होगा चाहे वह चीनी हो, गेहूँ / हो, चावल हो या कुछ भी हो और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे । इसके // अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है । इस सबकी ज़िम्मेदारी किसकी /// है ? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की हैं ? मेरे विचार में इस सबकी ज़िम्मेदारी सरकार की है और इसके (4) लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका कोई न कोई इन्तज़ाम किया जाये । 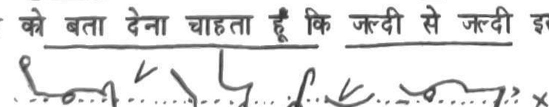

आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों / में एक समझौता हो चुका है । सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है परन्तु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और / इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गये हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से /// निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जो गरीबी, तथा भुखमरी का दौर चल रहा है इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ (5) इन्तज़ाम किया जाये । (503 शब्द)

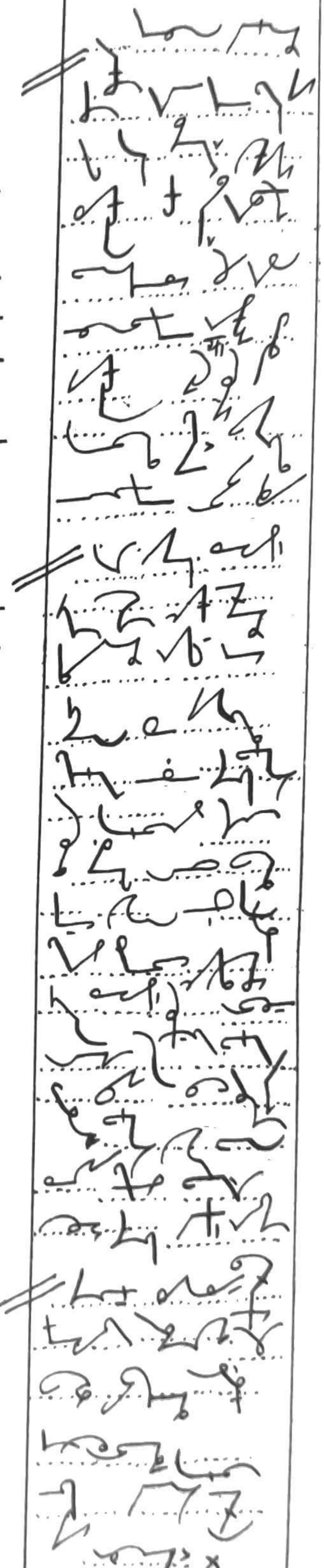

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

अभ्यास-52

मान्यवर, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ । सबसे पहले मैं टूरिज़्म यानी पर्यटन को लेना चाहता हूँ । हमारे देश / में बाहर से टूरिस्ट दिन-प्रतिदिन आ रहे हैं । पिछले साल को छोड़कर दिन-प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या इस देश // में बढ़ती जा रही है । कुछ धन संबंधी कठिनाइयाँ होंगी ऐसा लगता है । लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन का इन्तज़ाम किया जाना चाहिए । (1)

टूरिस्ट के लिए हमारे देश में बहुत से केन्द्र हैं, जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, पुराने मन्दिर, जंगल, शेर आदि हैं जिनकी वजह से बहुत / से टूरिस्ट आते है, और जब वे यहाँ आते हैं तो जो जंगल हैं, जहाँ दूर-दूर मन्दिर पड़े हुए हैं वहाँ उनके लिए // होटलों की सुविधाएँ नहीं हैं । वहाँ रहने और खाने-पीने की सुविधायें नहीं हैं ऐसी सुविधायें जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहियें ।

मेरे अपने जिले /// में पर्यटन उपमंत्री आयी थीं । गिर जंगल में जानवरों के लिए एक जगह बनायी हैं । सारे एशिया में एक ही जगह शेर हैं, उसको (2) देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट्स आते हैं । लेकिन वहाँ उनके रहने की सुविधाएँ नहीं थीं । एक होटल वहाँ बनाया गया है जिससे / कुछ सुविधा होगी । मगर वहाँ मकान बनाने से भी टूरिस्ट जा नहीं सकेंगे क्योंकि वहाँ जाने के लिए सड़क की सुविधायें नहीं है । /// जो सड़कें चाहियें वे नहीं बनी हैं । इस कारण अन्य दूसरी सुविधायें भी बेकार हैं, और उनका लाभ टूरिस्ट्स नहीं उठा सकते । इसलिए /// यातायात के साधन अच्छे किए जायें ।

बम्बई से हवाई सेवा वहाँ जाने के लिए अवश्य है । उसके नज़दीक एक हवाई अड्डा है । वहाँ (3) जो हवाई सेवा है वह डेकोटा द्वारा है । जिसकी वजह से लोग नहीं जा रहे हैं, ; क्योंकि उसमें काफी तकलीफें रहती हैं । मैंने इस बारे में बार-बार कहा है कि डेकोटा को बन्द करके वहाँ कोई और सेवा चालू कीजिये । लेकिन उस दिशा में // भी कुछ नहीं किया गया । एक बार मैं मंत्री महोदय के साथ वहाँ जाते समय समुद्र का किनारा देखा । अगर वहाँ छोटे-छोटे टेंट लगाये जायें तो यूरोप से भी अधिक (4) टूरिस्ट्स यहाँ आयेंगे और उससे हमको काफी आमदनी हो सकती है । मगर उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया । मेरा मंत्री / जी से निवेदन है कि आप ऐसी योजना बनायें जिससे पिछड़े हुए जिलों को, जो कि टूरिस्ट केन्द्र बन सकते हैं, कुछ न कुछ // फायदा मिले । हमारे यहाँ एक छोटा सा जिला है वहाँ अच्छा समुद्र-बीच है, उसके विकास के लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए । /// हवाई सेवा में बराबर जो हड़ताल हो रही है उसको बन्द करना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ । (5) (500 शब्द)

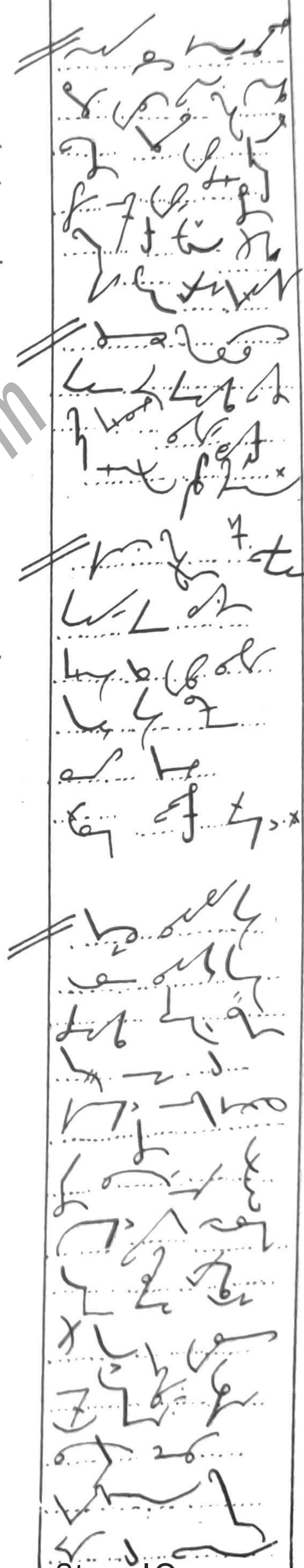

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-53

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी बड़े महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय किए हैं जिनका हमारी अर्थव्यवस्था की मज़बूती और उन्नति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । मुख्य निर्णय / यह है कि रुपये का विनिमय मूल्य घट गया है । बाकी आर्थिक निर्णय, जिनका मैं आगे चलकर ज़िक्र करूँगा, इसी मुख्य निर्णय के परिणाम है । /// मैं आपको अब यह बताना चाहता हूँ कि यह परिवर्तन क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या राज़ है और इससे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में /// कैसे मदद मिलेगी ।

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की दृष्टि में रुपये के विनिमय मूल्य से क्या अर्थ है । {1} इसका सीधा मतलब यह होता है कि रिज़र्व बैंक में जो विदेशी मुद्रा दी जाती है, उसके बदले वह किस हिसाब से रुपया देता है / और उससे जो विदेशी मुद्रा ली जाती है, उसके लिए वह किस दर से रुपया लेता है दूसरे शब्दों में विनिमय दर का अर्थ है // कि देशी विनिमय की दर । इस माने में जिस तरह और चीज़ों का दाम होता है उसी तरह वह भी है और यह कोई ऐसा मसला /// नहीं जिसके कारण किसी के सम्मान को किसी तरह की ठेस पहुँचे या कोई उत्तेजना उत्पन्न हो । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख {2} स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहूँगा । चाहिए तो यह कि अन्य प्रकार के माल की तरह विदेशी मुद्रा का दाम तय करने में भी केवल आर्थिक बातों / का ही ध्यान रखा जाए । वास्तव में विनिमय मूल्य आर्थिक वास्तविकता के अनुसार ही होना चाहिए । केवल तभी मूल्य का मुख्य प्रयोजन पूरा होता है // जो साधनों के उचित आबंटन को सम्भव और सुविधामय बना सके । दूसरे रूप में तथा इसके अलावा यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसके विपरीत उससे /// उलझनें ही बढ़ती जाएंगी जिससे अर्थव्यवस्था को सिर्फ नुकसान ही होगा ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दस वर्ष पहले रुपये का जो मूल्य था {3} आज नहीं है । यह सर्वविदित है कि कई वर्षों से देश के अन्दर प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं । दस वर्ष पूर्व जो दाम थे / आज उससे 80 प्रतिशत अधिक है । दूसरी ओर,सन् 1949 के बाद से रुपए के सराकरी विनिमय मूल्य में कोई फेरबदल नहीं हुआ है । // संसार के जिन बड़े देशों के साथ हमारा व्यापार होता है वहाँ चीज़ों के दाम इतने नहीं बढ़ते हैं जितने कि भारत में / इसका नतीजा /// यह होता है कि हमारा माल वहाँ की मंडियों में औरों के मुकाबले महँगा बैठता है जिसके फलस्वरूप वहाँ का खरीददार निरुत्साहित हो जाता है । {4} इसके साथ ही साथ हालत यह है कि हमारे लिए निर्यात बढ़ाने की ओर विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक कमाने की आवश्यकता बराबर बनी रहती है । / इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेशी मंडियों में अपने माल को औरों के मुकाबले सस्ता करने के लिए हमने कई उपाय काम में // लाए हैं । उदाहरण के लिए निर्यात को सहारा देने के लिए हमने कई प्रकार की सहायता दी है । हमने निर्यातकों को कच्चा- माल तथा मशीनरी /// आयात करने का अधिकार दिया, उनको सीधी आर्थिक सहायता दी और हाल ही में, कर ऋण-पत्रों की भी सुविधा प्रदान

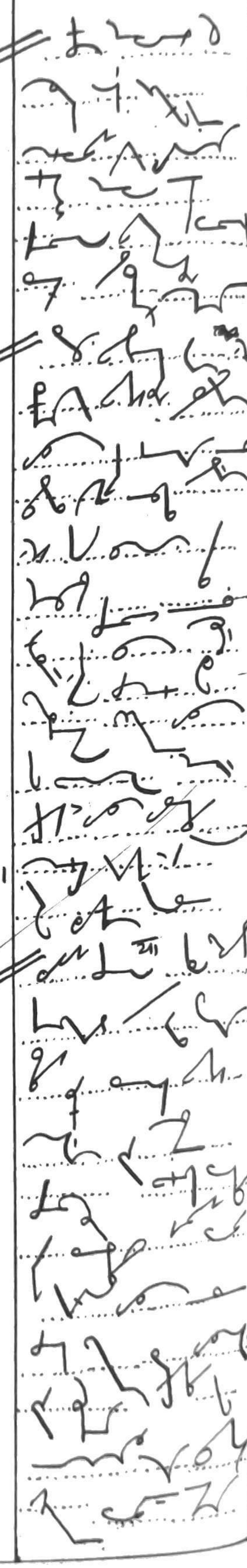

www.StenoIQ.com

की । परन्तु इन उपायों §5§ का ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि हमारी कठिनाइयाँ ज्यादा गहरी हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि चीज़ों के दाम पाँच वर्ष पहले जो थे / आज हम उनको फिर वापस नहीं ला सकते बल्कि दाम और अधिक बढ़ते ही जा रहे हैं । §542 शब्द§

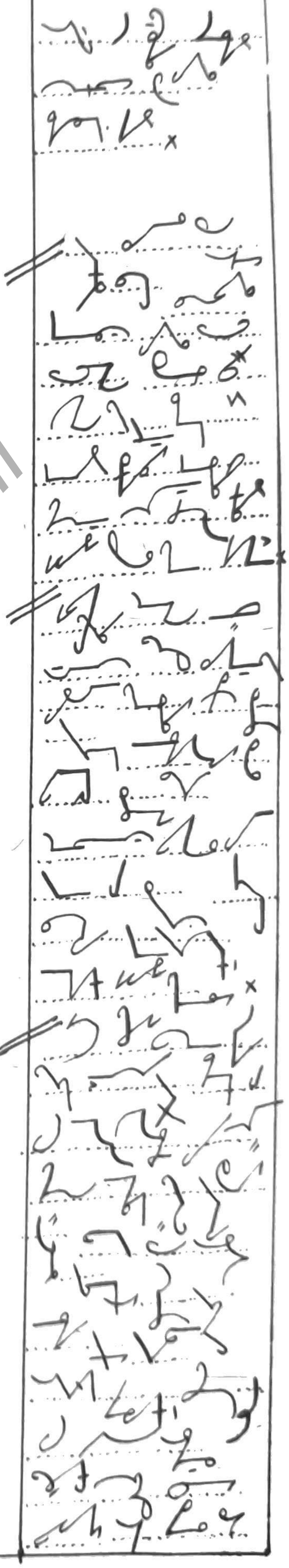

अभ्यास-54

उपाध्यक्ष जी, सरकारी क्षेत्र का स्थान महत्वपूर्ण होने के कारण जनता द्वारा उसके कार्य सम्पादन का सामान्य रूप से और उसके औद्योगिक सम्बन्धों का विशेष / रूप से निरन्तर निरीक्षण किया जाना स्वाभाविक ही है । सही-सही आलोचना से सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों में सतर्कता आयी है और उसके परिणामस्वरूप उनके // काम में सुधार हुआ है । उसके साथ ही साथ श्रमिकों और मालिकों के सम्बन्ध भी और अच्छे हुए हैं । मुझे विश्वास है कि अच्छे औद्योगिक /// सम्बन्धों की स्थापना से सरकारी क्षेत्र अवश्य तरक्की करता चला जाएगा ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आर्थिक चेतना के अगस्त अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था §1§ में सरकारी उद्योगों पर एक विशेषांक प्रकाशित हुआ है । सचमुच, इस देश में हिन्दी आर्थिक पत्रकारिता का गहरा अभाव है और इस दृष्टि से आर्थिक / चेतना हिन्दी आर्थिक पत्रकारिता में एक नया योगदान है । आज इस बात की आवश्यकता है कि लोगों को सरल हिन्दी में हमारे आर्थिक कार्यक्रमों, नीतियों // और योजनाओं से अवगत किया जाए । जब तक जनता और सरकार के बीच इस प्रकार में आदान-प्रदान की समुचित व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक /// हमारी आर्थिक उपलब्धियों में गतिरोध बना रहेगा । मुझे विश्वास है कि इस गतिरोध को हिन्दी आर्थिक पत्रकारिता ही दूर कर सकती है ।

भारत का हमेशा §2§ यह आदर्श रहा है कि मुल्क आज़ाद रहे और प्रजातन्त्र कायम रहे । पूँजीपति अर्थव्यवस्था में हम विश्वास नहीं करते जिसमें चन्द लोग सारी जनता का / शोषण करते हैं । ऐसी अर्थव्यवस्था से देश को कभी भी लाभ नहीं हो सकता । कई देशों में, विशेषकर अमेरिका, जर्मनी तथा कुछ हद तक // ब्रिटेन में पूँजीवाद सफल रहा है । प्रत्येक देश की परिस्थिति भिन्न होती हैं । हमारे जैसे गरीब देश में पूँजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है । /// ऐसे देश में जहाँ पिछड़ापन गहरा पहुँच चुका हो, जहाँ बेरोजगारी हो, जहाँ अनपढ़ता हो, जहाँ करोड़ों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध §3§ न हो, जहाँ सबको चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध न हों वहाँ श्रेयस्कर यह होगा कि समाज का संचालन ज्यादा से ज्यादा शासन के पास ही रहना / चाहिए । इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान ने हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है । मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें निजी // तथा सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलित विकास होता रहता है । इससे एक ओर निजी क्षेत्र के उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और दूसरी ओर /// सार्वजनिक क्षेत्र भी उन्नति

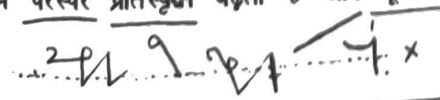

www.StenoIQ.com

करता रहता है जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में लोगों को रोज़गार उपलब्ध होता है ।

गतवर्षों में सरकारी क्षेत्र पर §4§ 3500 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है जिसे प्रशंसनीय माना जा सकता है । इस विनियोग ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव डाली है । / यद्यपि इन सरकारी उद्योगों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने तथा लाभ एवं उत्पादनशीलता बढ़ाने के ज्वलन्त प्रश्न हमारे सामने हैं तथापि आशा है // कि निकट भविष्य में इन सार्वजनिक उद्योगों से अधिक से अधिक लाभ होगा तथा उत्पादन बढ़ेगा । लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि /// इस क्षेत्र पर निरन्तर निगरानी रखी जाए तथा इनमें योग्य प्रबन्धकों को नियुक्त किया जाए । तभी इस क्षेत्र को हमारी अर्थव्यवस्था का लाभप्रद घटक बनाया §5§ जा सकता है । आशा है कि आर्थिक चेतना का यह विशेषांक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास के प्रश्न पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर सकेगा । §525 शब्द§

अभ्यास-55

अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल में कुछ भी मतभेद रहा हो, परन्तु यह खुशी की बात है कि उसने शिक्षा के मामले में / एक राष्ट्रीय नीति स्वीकार कर ली है । भले ही शिक्षा को संविधान की संवर्ती सूची में न रखा गया हो और इसके संबंध // में निर्णय करने का एक-मात्र अधिकार राज्यों को दिया गया हो, परन्तु केन्द्र द्वारा इस विषय में एक राष्ट्रीय नीति का स्वीकार किया जाना /// इस बात का सबूत है कि अधिकारों के झमेले में न पड़ कर शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व को अब स्वीकार कर लिया गया है । §1§ वैसे इसमें कोई शक भी नहीं कि राष्ट्र के समुचित विकास एवं निर्माण में शिक्षा का जो स्थान है उसकी दृष्टि से उस विषय में / एक राष्ट्रीय नीति अपना कर देर से अनुभव किये जा रहे एक अभाव की पूर्ति की गयी है । शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्था और // असंतोष चल रहा है उसका उससे अंत हो जाएगा यह कहना अभी कठिन है ।

यह सत्य है कि नीति सम्बन्धी जो योजना केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय /// ने बनाई वह कोठारी आयोग की सिफारिशों तथा उस पर संसदीय समिति के निर्णयों पर सर्वाधिक आधारित है । यह भी सही है कि इस सम्बन्ध §2§ में राज्यों से भी परामर्श लिया गया है । परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संसद द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के बाद भी / उस पर अमल शुरू हो जाएगा । यह बात राज्यों पर आधारित है और यह किसी से छुपा नहीं कि कुछ राज्य सरकारों का शिक्षा के // विभिन्न मुद्दों पर कुछ न कुछ मतभेद हमेशा रहा है । ऐसी सूरत में शिक्षा-विषयक मुद्दों की घोषणा के बाद भी उस पर अमल की /// गारंटी तभी सम्भव हो सकती है जब शिक्षा केवल राज्यों का विषय न होकर केन्द्र का भी विषय होता तथा केन्द्र का उस पर §3§ पूरा-पूरा नियन्त्रण होता । मेरे विचार में इसके लिए अगर आवश्यकता पड़े तो

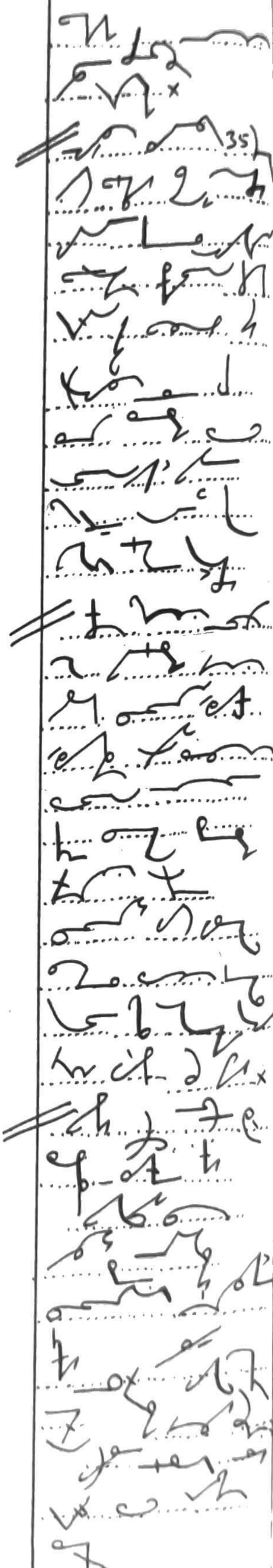

www.StenoIQ.com

संविधान में परिवर्तन करना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ और अधिक खिलवाड़ / न हो सके। अब तो संसद सदस्यों को विभिन्न दलों की संसदीय समिति का बल भी प्राप्त है, ऐसी हालतमें इस परिवर्तन में कोई // भी फेरबदल नहीं हो सकता।

अब तक केन्द्र और राज्यों की ओर से शिक्षा पर काफी व्यय किया जा रहा है, लेकिन इससे विशेष लाभ /// नहीं हो रहा क्योंकि शिक्षा में दोहरी व्यवस्था चल रही है। कई कार्यक्रम जो केन्द्र में हैं वे राज्यों में नहीं और जो ॥4॥ राज्यों में हैं उन्हें केन्द्र स्वीकार करने से हिचकिचाता है। ऐसी दिशा में शिक्षा के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति स्वीकार करना निहायत ज़रूरी है। यह / केवल केन्द्र ही कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इसे जल्दी से जल्दी किया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार को यह देखना होगा कि // कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसे ध्यान में रखकर शिक्षा के मद पर कितने प्रतिशत खर्च करना सम्भव हो सकेगा और फिर /// उससे शिक्षा क्षेत्र में क्या उन्नति सम्भव है। अगर हो सके तो इसके लिए एक निशिचित न्यूनतम अवधि निर्धारित कर दी जाए। इस समय राष्ट्र ॥5॥ के पास धन की कमी हो सकती है परन्तु इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे विशाल देश की निरक्षरता को / समाप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा के मद पर अधिक से अधिक व्यय किया जाए। क्रान्ति के बाद रूस में इस // मद पर बहुत व्यय किया गया था और आज भी वह राष्ट्रीय आय का एक उल्लेखनीय भाग इसमें लगा रहा है। ॥571 शब्द॥

अभ्यास-56

उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नये समाज को जो विरासत मिलती है, उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी / कंपनियाँ ही इस स्थिति में होती है कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले ले। पूँजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है। // इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, सिवा इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या व्याज देती है। /// उत्पादन को मज़दूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई ॥1॥ अन्तर नहीं पड़ता। हाँ उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है, क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता / इससे उनकी कार्यक्षमता में भी धीरे-धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और वे अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं // । लेकिन क्रान्ति के अगले रोज़ ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता। अतः क्रान्ति का तात्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, /// न ऐसा कभी हो सकता है। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत ज़रूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी ॥2॥ आधार पर होने लगता है, तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है।

समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है, उन वस्तुओं का उत्पादन जो / आम लोगों की जरूरतों को पूरा करें । मसलन, हमारे देश में लगभग नौ करोड़ मकानों की जरूरत है, करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त // क्या साधारण उन्नी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबें नहीं होती । अतः समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीजों को प्रमुखता दी जाती है । ///

पूँजीवादी उत्पादन में, जहाँ यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किये बिना उन्हीं चीजों का §3§ उत्पादन किया जाता है, जिनसे से अधिक लाभ हो । आजकल जो सरकार की नीति है वह पूँजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है, समाजवादी वस्तुओं का निर्माण / की ओर कम । कहने का नारा समाजवाद का है, परन्तु वास्तव में हम पूँजीवादी युग में में जी रहे हैं । इसकी सबसे बड़ी खामी यह है // कि वितरण पर चूँकि कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उत्पादित वस्तुएँ जनता तक पहुँचने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टाक हो जाती है । /// अतः उत्पादन के वितरण पर समाज का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता । दुर्भाग्य से हमारे देश में §4§ समाजवाद महज़ एक शब्द बन कर रह गया है । एक शब्द से अधिक कुछ नहीं । तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पच्चीस वर्ष बाद भी लोग / समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं, कभी माओ दीखता है, कभी लेनिन कभी नेहरू तो कभी लोहिया । हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट // नहीं है । लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत वर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की /// उपज होगा । हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह-मशिवरा नहीं करना बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद §5§ के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है । §511 शब्द§

अभ्यास-57

महोदय मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ जिन पर पिछले कई दिनों से सदन में चर्चा होती आ रही है । लेकिन मैं / समझता हूँ पृष्ठिभूमि तैयार है, सारे कारण मौजूद हैं । इस प्रस्ताव को मन्जूर करने के लिए चाहे गोवा का सवाल हो, पाकिस्तान का सवाल हो, // या चीन का सवाल हो, सारी चीजें मौजूद हैं जिनके आधार पर देश को तैयार करना है किसी भी खतरे का सामना करने के लिए /// मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि इस प्रस्ताव का कतई यह मंशा या अर्थ नहीं है और न ही इसका §1§ यह अर्थ किया जाना चाहिये । इस मुल्क में या इस मुल्क के बाहर हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि लड़ाई / की भावना पैदा हो या यह चाहते हैं कि किसी पर हमला बुला दिया जाए या दुनिया में लड़ाई की भावना पैदा करना चाहते हैं ।// ऐसी बात हरगिज़ नहीं है । लेकिन यह बात जरूर है कि हमें अपनी शक्ति कायम रखनी है, हमें किसी से डरना नहीं है, हमें इस /// भावना को पैदा करना है कि हम किसी पर हमला बुलाने वाले नहीं हैं लेकिन इसके साथ-साथ यह बात भी जरूर है कि §2§

www.StenoIQ.com

हमें किसी से डरने वाले भी नहीं होना चाहिए । मैं समझता हूँ कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, अभी प्रारम्भिक स्टेज पर तो / यह केवल उन विद्यार्थीयों पर लागू होगा जो कि कालिजों और विश्वविद्यालयों / में पढ़ते हैं और जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है और आगे // चलकर भविष्य में चलकर हमें हमें इसको उन लोगों पर भी लागू कर देना चाहिए जिनके शरीर इस लायक हैं कि वे फौजी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनको भी फौजी {3} शिक्षा दी जानी चाहिए । सारी परिस्थितियों को देखते हुए और सीमाओं पर जो संकट पैदा हो गया है उसको देखते हुए भी तथा अपनी स्थिति / को साफ करने के लिए देश में और बाहर भी यह अनिवार्य हो गया है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और मुल्क में // यह भावना पैदा करे कि कुछ भी हो हमारे देश में कितनी भी मतविभिन्नता हो, राजनीतिक उद्देश्यों में विभिन्नता हो जहाँ तक देश की सुरक्षा /// का सवाल है देश की सीमाओं पर किसी खतरे का सवाल है, उसका सामना करने के लिए इस देश का बच्चा-बच्चा तैयार है । {4} देश की रक्षा करने करने के लिए अपने खून की आखरी बूंद बहाने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा । मैं समझता हूँ कि इस तरह / की भावना पैदा करने के लिए इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । फौजी शिक्षा से एक और लाभ होगा, वे अनुशासन-प्रिय बनेंगें और आप जानते हैं कि किसी भी देश के लोगों में अनुशासन /// कितना आवश्यक होता है । आज चारों और बढ़ते हुए अनुशासनहीनता को देखते हुए यह और भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह के प्रस्ताव {5} को सरकार फौरन स्वीकार कर लें । {506 शब्द}

अभ्यास-58

महोदय, गाँधी जी जिस समाज का स्वप्न देखते थे शायद उस ओर हम नहीं जा रहे हैं । विनोबा जी के आन्दोलन से कुछ-कुछ लगता / है कि हम भी उस ओर जा सकते हैं पर और जितनी चीजें हमारे देश में हो रही हैं वे विपरीत देखने में आ रही // हैं और हम उनकी ओर ही जा रहे हैं । मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को भली प्रकार से देखें और समझें । /// सब चीजों पर विचार करने का गाँधी जी का अपना एक उद्देश्य था । वे इस प्रकार के समाज का गठन करने के लिये उनके अनुकूल {1} वातावरण पैदा करना चाहते थे । उनके कार्यक्रम / के अनुसार चल सकें तो हम उस प्रकार का समाज स्थापित कर सकते हैं जैसा कि गाँधी जी चाहते थे । परन्तु यदि हम उनके बताये // हुए रास्ते से विपरीत ही चलें तो उसका परिणाम वह नहीं हो सकता, जैसा वे चाहते थे ।

हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हमको /// उस पर विचार करना चाहिये । हो सकता है कि परिस्थिति इतनी प्रतिकूल हो कि हम चाहे कुछ भी करें, उससे हम उस परिस्थिति को नहीं {2} बदल सकते । परन्तु इसका अर्थ यह भी तो नहीं हो सकता कि हम प्रयोग करना ही छोड़ दें । मेरा तो विश्वास है कि यदि हम / थोड़ा-सा भी उस मार्ग पर चलेंगे और उस ध्येय को अपने सामने रखेंगे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज नहीं तो कल, कल // नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमारे देश के लोग उस

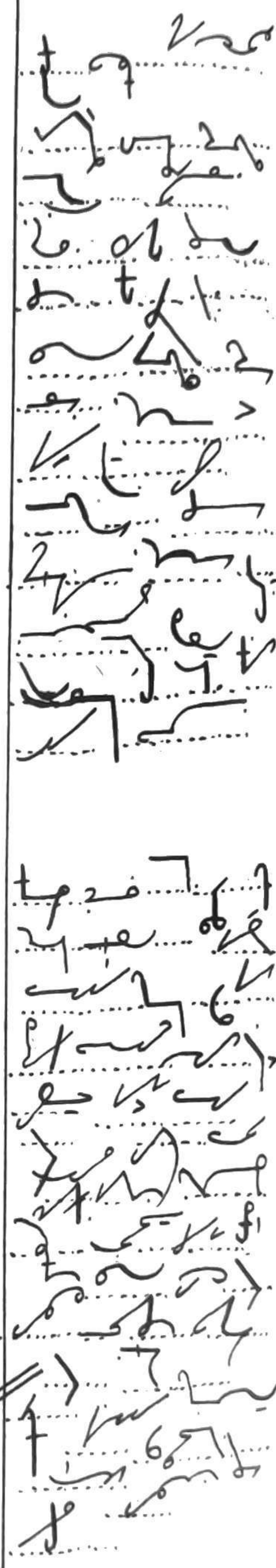

पर ध्यान देंगे और दूसरे देशों के लोग भी हमारा /// साथ देंगे । इसलिये जो गाँधी जी की विचारधारा के मानने वाले हैं उनसे जब मेरी बातें होती हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि {3} प्रतिकूल परिस्थिति भी कभी न कभी उनके अनुकूल ही हो जाएगी । कौन यह कह सकता था कि हम इतनी जल्दी या इतनी आसानी से स्वराज्य / पा सकेंगे । उस समय हमारा ध्येय यही था कि चाहे जिस प्रकार हो हमें स्वराज्य लेना है और हम उस ध्येय तक पहुँचे । हमको समझना // चाहिये कि आज की परिस्थिति न तो उतनी प्रतिकूल है और न कभी हो सकती है जितनी कि गाँधी जी के दिनों में थी । /// जब उन्होंने काम आरम्भ किया आज भले ही चारों ओर कठिनाइयाँ और संकट देखने में आये तो भी हमें उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है । {4} मैं आशा करता हूँ कि आपने चर्खा चला कर आज जो काम आरम्भ किया है तथा विनोबा जी सारे देश में भूदान का जो / काम कर रहे हैं और अब उन्होंने कूप-दान की बात जो उठाई है हम सभी स्थानों के लोग अपना अपना सहयोग देकर इस कार्य // को आगे बढ़ाते जाएँगे जो बाद को एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेगी । ईश्वर की कृपा हुई तो उस नदी में एक बाढ़ /// भी आ सकती है । उस बाढ़ की आशा में हमें इन छोटी-छोटी नालियों में अपनी-अपनी बूँद डालने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । {5} {500 शब्द}

अभ्यास-59

अध्यक्ष जी, विकास को गति देने के उद्देश्य से उदार अर्थनीति की घोषणा के परिणामस्वरूप अगला वित्तीय वर्ष प्रगति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा / वर्ष होने जा रहा है । 1986-87 सातवीं योजना का दूसरा वर्ष होगा, जो नीतियों के कार्यान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है । // विशेषज्ञों तथा उद्योगों की राय है कि नई नीतियों का लाभ अगले वर्ष पूँजी-निवेश के विस्तार तथा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के रूप /// में परिलक्षित होना चाहिए । वर्तमान स्थिति में नये करों के ज़रिए साधनों से वृद्धि की संभावना कम है किन्तु वित्त मंत्रालय को आशा है कि {1} बचत तथा करों की वसूली से केन्द्रीय राजस्व में वृद्धि होगी । 1986-87 की योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था का / अनुमान है । राजस्व में वृद्धि तथा कीमतों की स्थिति को देखकर इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है ।

बजट के घाटे तथा दो पूरक माँगों // के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष का घाटा 6000 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है । वित्त मन्त्रालय का अनुमान है कि करों की वसूली में /// वृद्धि से इसमें कुछ कमी की जा सकेगी । चालू राजस्व के आधार पर 1986-87 में बजट का घाटा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 0·2 प्रतिशत से कुछ अधिक होने का अनुमान है ।

लाभदायक	लोककल्याण	विद्रोह-ही	वितरक
लोकपाल	लोककल्याणकारी	विद्यार्थी	वितरित

www.StenoIQ.com

इस समय अर्थव्यवस्था का / मूल आधार कृषि उत्पादन है । यदि 1986-87 में औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में वृद्धि नहीं हुई तो आर्थिक समस्याएँ काफी जटिल बन सकती हैं । // चालू वित्तीय वर्ष में विदेश व्यापार का घाटा 600 करोड़ रुपए से अधिक होने जा रहा है । कम्पनियों को करों में राहत तथा प्रोत्साहन, उत्पादन /// और निर्यात में तेज़ी से वृद्धि के लिए दिए गए हैं । विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई नीतियों का फल मिलने में समय लग सकता है । {3} दूसरी ओर उत्पादन और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई तो विकास के लिए वित्तीय साधनों में वृद्धि करना बहुत कठिन हो जाएगा । यह खुशी / की बात है कि वित्त मंत्रालय इस समय काफी हद तक अनुमानों के आधार पर बजट की तैयारी में लगा हुआ है । वर्तमान अनुमानों // के अनुसार 1985-86 में पाँच वर्ष की दर से आर्थिक प्रगति का लक्ष्य पूरा होना कठिन दीख रहा है । यदि निजी क्षेत्र में पूँजी /// निवेश, क्षमता का उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि हुई तो 1986-87 में 5% का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी ।

इस समय उर्जा की {4} सप्लाइ तथा परिवहन की स्थिति में सुधार से औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला है । तो भी परिवहन तथा अनेक इंजीनियरी उद्योग मांग / में कमी के शिकार हैं । योजना के कार्यान्वयन से उनकी स्थिति सुधर सकती है । किन्तु निर्यात की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण अभी अनुकूल नहीं है । // इसके कारण विदेश व्यापार के बारे में अनिश्चितता अगले वर्ष भी बनी रहने वाली है । दूसरी ओर आयात में भारी वृद्धि हुई है । इस वर्ष /// तो चीनी का भी आयात करना पड़ा है । इस तरह अगले वर्ष के लिए विकास की दृष्टि से स्पष्ट तौर पर कुछ कहना मुश्किल है । {5} {500 शब्द}

अभ्यास-60

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद ने केन्द्र द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के भविष्य पर विचार करने के लिए योजना आयोग की सलाह पर एक समिति का / गठन किया जिसमें कई बातों पर विचार-विमर्श किया गया । यह भी तय हुआ कि उसकी बैठकों को समय-समय पर बुलाया जाएगा जिनमें // राष्ट्र से संबंधित कई समस्याओं पर विचार किया जाएगा और अगर सम्भव हुआ तो तुरन्त उनके हल के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे ताकि /// जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े । सर्वप्रथम परिषद की बैठक में जम्मू व कश्मीर की सरकार को बर्खास्त किए जाने {1} के प्रश्न पर गैर-कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों के बहिर्गमन के बाद स्वीकृत प्रस्ताव को आज वापस लेने की मांग की गई । प्रधान मंत्री ने / जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री से अपील की कि वे इस घटना को भूल जाएँ । उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की बातें // नहीं दुहराई जाएँगी ।

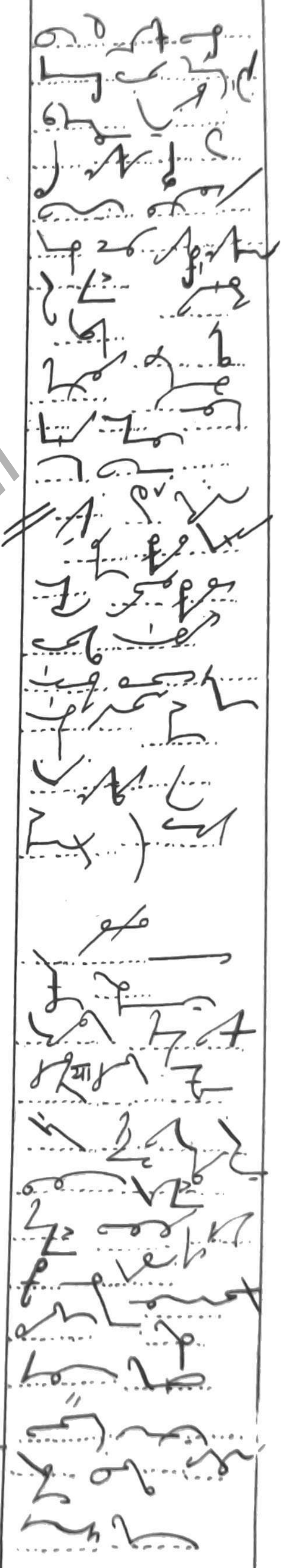

वायुमण्डल ... भलीभांति ... जनसंख्या

शिक्षा के बारे में सदस्यों ने कहा कि वे गरीब वर्ग के लोगों को भी उच्च-शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के पक्ष /// में हैं । यह सर्वसम्मति से पारित किया गया कि अच्छी शिक्षा के लाभ को केवल धनी वर्ग के बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता ॥2॥ इस पर गरीब-वर्ग के बच्चों का भी उतना ही अधिकार है तथा उनके लिए भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए । / यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में खाद्यान्न के निर्यात पर खुल कर विचार किया गया । सब सदस्यों ने सर्वसम्मति // से यह स्वीकार किया कि सरकार गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्यक्रम तैयार करें जिसमें गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करने के /// बाद ही निर्यात करने पर विचार किया जाए । ज़रूरत के अनुसार चावल के आयात के लिए सरकार गेहूँ का निर्यात कर सकती है । बैठक में ॥3॥ औद्योगिक माल की कीमत कम करने पर भी ज़ोर दिया गया और कहा कि इसके बिना उसकी खपत नहीं बढ़ सकती । इन वस्तुओं को आम / लोगों की पहुँच तक लाने के लिए पूरी-पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दृष्टि से उत्पादन खर्च में कमी करना अनिवार्य हो जाएगा । राज्यों की // योजना के लिए कम धन उपलब्ध कराने की भी शिकायत की गई तथा आलोचना की गई । लेकिन वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में असमर्थता प्रकट /// करते हुए कहा कि योजना में 15 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है जिसे जन-साधनों के विकास पर खर्च किया जा ॥4॥ सकेगा और ये कार्यक्रम भी राज्यों में लागू किए जाएंगे जिसमें उन्हें अधिक धन मिल जाएगा ।

सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति प्रकट की / कि भुगतान संतुलन की स्थिति इस समय ठीक है । साथ ही उन्होंने प्रत्यक्ष करों से साधन जुटाने पर बल दिया । इस बात पर सन्तोष व्यक्त // किया गया कि योजना विदेशी मदद पर निर्भर नहीं है । इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या किसी अन्य संगठन के दबाव में आकर नीतियाँ बदलने का /// कोई सवाल नहीं उठता । योजना आयोग के उपाध्यक्ष का यह आश्वासन प्रशंसनीय था कि सातवीं योजना में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम का सही मूल्यांकन होगा ॥5॥ जो कि सही-सही आँकड़ों पर आधारित होगा । साफ पीने के पानी की देश भर में व्यापक व्यवस्था की जाएगी । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया / कि भविष्य में बिहार जैसे अन्य गरीब राज्यों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा । साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उनके // विकास के लिए सर्वाधिक मदद दी जाएगी । इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे । बैठक की समाप्ति पर सभी /// सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया तथा प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का धन्यवाद किया । ॥593 शब्द॥

अभ्यास-61

सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा । सरकार इस विधेयक के प्रारूप के बारे में विरोधी दलों और सम्बद्ध एजेंसियों से / विस्तार से बातचीत कर रही है । मैं मन्त्री महोदय की इस घोषणा का भी स्वागत करता हूँ जो उन्होंने दल-बदल

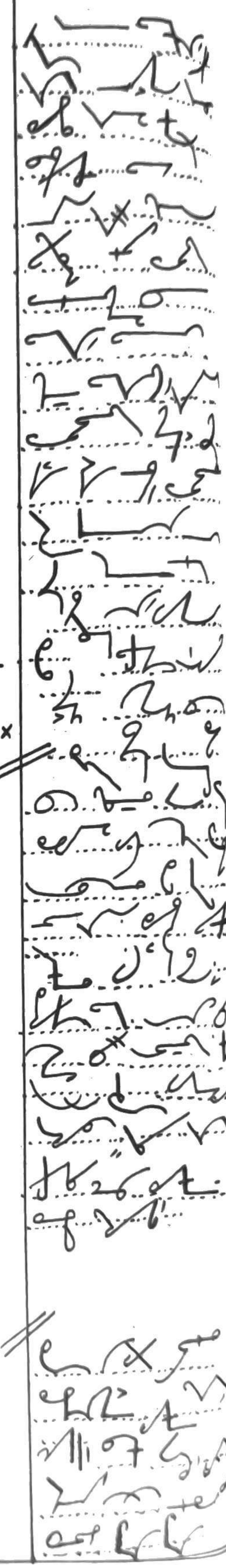

विरोधी कानून पर आयोजित // एक विचार-गोष्ठी में की । मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं । नई सरकार /// जब बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल-बदल विरोधी कानून बना कर उठाया । जैसा कि आप सब जानते हैं दल-बदल हमारी {1} राजनीति में कोढ़ बन गया है । इससे न तो सत्तारूढ़ दल और न ही विरोधी दल अछूते रहे हैं । मतदाताओं को भी दल-बदल के / द्वारा समय-समय पर धोखा दिया जाता रहा है । लोग जीतते किसी एक दल के माध्यम से हैं लेकिन बाद में अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए // या किन्हीं अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं । मतदाता लाचार सा यह सब देखता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता । /// दल-बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतन्त्र को साफ-सुथरा, स्वस्थ एवं मजबूत बनाया जाए ।

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट {2} करना चाहता हूँ कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए नहीं है । इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाएगा । कुछ लोगों में / इस बारे में आज भी संशय है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह अपने मन से संशय को हटा लें । हो सकता है कि इस // कानून में कुछ कमियाँ रह गई हों । इन कमियों को आपस में विचार-विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर की जा सकती है जो /// इस दिशा में बहुत ही सहायक साबित हो सकता है । यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह {3} चाहते हैं कि दल-बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो । एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व / सदन में इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय हैं । उस माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक // तंत्र के लिए दल-बदल का कुचक्र हमारी राजनीतिक मान्यताओं को खोखला करता /// जा रहा है । अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए । इसमें कोई शक नहीं कि दल-बदल विरोधी कानून का सर्वत्र स्वागत {4} हुआ है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोष मुक्त या स्थाई हो । समय और परिस्थितिवश इसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक / ही नहीं अनिवार्य भी है । कभी कोई चीज़ स्थाई नहीं रहती । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में एक सम्मेलन का आयोजन // करें जो इस पर विचार करें कि इस कानून को किस ढंग से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा सकता है । इस कानून के बारे में /// बुद्धिजीवियों, विधिवेताओं और अन्य राजनीतिज्ञों के विचार क्या है, इसका विवेचन भी सम्मेलन में किया जाए । इस विचार-गोष्ठी की एक रिपोर्ट भी सरकार को {5} विचारार्थ भेजी जाए । {503 शब्द}

अभ्यास-62

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पाँच मिनट लूँगा । मुझे यह अर्ज़ करना है कि जो बिल आज आपके सामने है इसके ज़रिये किरायेदारों को सिवाय बाहर निकालने / के कुछ मदद नहीं मिल सकती । हमारा पहला जो एक्ट था उसमें आपने देखा होगा यह साफ लिखा गया था कि मकान मालिक किरायेदारों से // ज्यादा किराया न वसूल कर सकें । किरायेदारों को उसमें

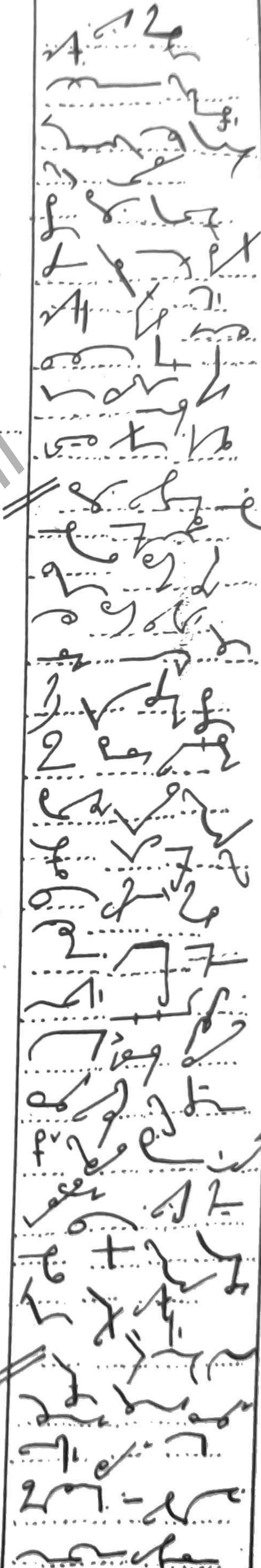

संरक्षण दिया गया था । लेकिन नये बिल के द्वारा इनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है /// बल्कि मकान मालिकों को ज्यादा किराया वसूल करने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है । इसमें व्यापारिक मकानों को खाली कराने के लिये ज्यादा तरफदारी {1} दिखायी गयी है । इसके कारण मकान मालिकों को अख्तियार मिल जाता है और वे किरायेदार को कानूनी शिकंजे में आसानी से फंसा सकते हैं । / कई कारोबार मौसमी होते हैं, कोई 6 महीने का ही होता है और केवल 3 महीने का ही होता है जैसे कोल्ड स्टोरेज़ का // कारोबार है या आईसक्रीम का कारोबार है या सोडा वाटर का कारोबार है और उस कारोबार पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी 3 या 6 /// महीने की आमदनी से ही साल भर अपना काम चलाते हैं और रोटी खाते हैं । लेकिन अपने कारोबार के सिलसिले में अगर कोई आदमी चार महीने {2} अपनी दुकान बन्द रखता है, तो आपके इस बिल के हिसाब से उसका निकाला हो जाना चाहिए । तो ऐसे लोग अपने कारोबार से चले जायेंगे । / इसलिये किरायेदारों में रिहायशी और गैर-रिहायशी करके तकसीम हो सकता है लेकिन वास्तव में उसका विभाजन नहीं हो सकता और न ही उन लोगों // का कारोबार बदल सकता है । अगर ऐसा किया गया तो इससे लोगों की आदमनी पर असर पड़ेगा और नतीजे के तौर पर रोज़गार भी नहीं /// बढ़ सकता ।

आपने इसमें यह भी कहा है कि अगर किसी मकसद के लिये मकान किराये पर लिया गया है और किरायेदार उस मकसद को {3} बदलता है तो उसका घर निकाला होना चाहिए । ऐसा होने के बाद किरायेदार को अपना पेशा बदलने का अख्तियार नहीं रहेगा और किसी कारोबार में / तरक्की नहीं हो सकेगी और इसके साथ ही साथ किरायेदार को व्यक्तिगत रूप से भी मकान-मालिक को काफी दखल मिल जायेगा । इसके अलावा आज // लगभग 35,000 मुकदमें मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच चल रहे हैं । आपके इस बिल के पास होने से एक तूफान सा आ जाएगा और /// इतने ज्यादा मुकदमें कोर्टस में पहुँच जायेंगें कि गवर्नमेंट उनको सम्हाल नहीं सकेगी । इस बिल में इतनी कमियाँ हैं कि गवर्नमेंट उनको सम्हाल नहीं {4} सकती । पहले से ही इतने अधिकार मकान मालिकों को दिये गये हैं कि जब चाहें वे मकान खाली करवा सकते हैं । यह बहुत कोई बड़ी / अक्लमन्दी की बात नहीं होगी कि हम किसी मकान को किरायेदार से इसलिये खाली करवायें कि मकान मालिक का हक ज्यादा है और जिस किरायेदार // ने उस मकान में जन्म लिया, बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसका कोई लिहाज़ न हो । मकान चाहे रिहाइशी हो अथवा व्यापारिक /// अधिकतर इसलिए खाली करवाया जाता है कि किराएदार उसका किराया कम दे रहा है और मकान मालिक पुराने किराएदार को उठाकर नये किराएदार को {5} अधिक किराए पर मकान देना चाहता है । अतः कानून में अगर इस बात की व्यवस्था हो कि समय-समय पर अपने आप किराया बढ़ाया जा / सके तो फिर मकान मालिक को बार-बार किराएदार को मकान खाली करवाने की आवश्यकतानहीं पड़ेगी क्योंकि उसको अपने मकान का किराया बढ़ा हुआ मिलेगा । // {550 शब्द}

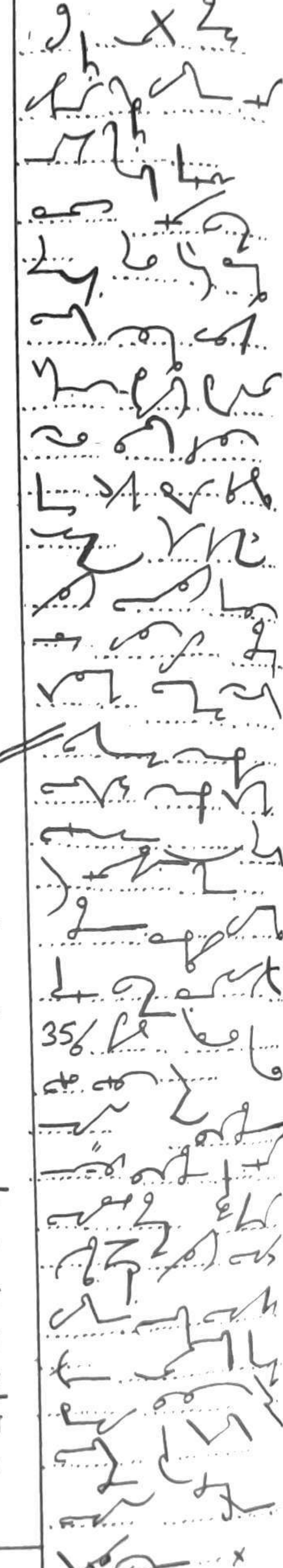

जनसाधारण गुटनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष
जनसमूह गुटनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता
जनसमुदाय वनस्पति शिक्षा-दीक्षा

विज्ञप्ति
प्रेस-विज्ञप्ति

www.StenoIQ.com

अभ्यास-63

उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का यह कथन बिल्कुल सही है कि देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की / ज़रूरत है । आज निरक्षरता जिस व्यापक रूप में फैली हुई है उस सूरत में यह सम्भव नहीं कि अल्पसाधनों और अल्पसमय में उससे मुक्ति // पायी जा सके । दुर्भाग्य यह है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और न ही इसके लिए /// राज्य तथा केन्द्र स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था की गई हैं । इसलिए मेरे विचार में, प्राप्त साधनों और शक्ति को कुछ इस प्रकार संगठित करना {1} होगा कि इस समस्या पर जल्दी से जल्दी विजय पायी जा सके ।

अकेले साक्षरता का ही महत्व ज़रूरी नहीं है । परन्तु साक्षरता लोकतन्त्र में वह / समझ और भावना पैदा करने में बहुत मददगार होती है जिससे व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास होता है । इसीलिए शिक्षामन्त्री जी ने // ठीक ही कहा है कि जब तक निरक्षरता का उन्मूलन नहीं होगा, देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकेगा । श्री जय प्रकाश नारायण /// का यह कथन भी विस्मरणीय नहीं कि आदमी लिखना-पढ़ना सीख कर अपने तथा अपने समाज को अधिक सुव्यवस्थित रख सकता है । अधिकारियों, सूदखोरों {2} और कानूनों के जिस भय से आज मानव पीड़ित है, उससे मुक्ति इसी साक्षरता के माध्यम से ही मिल सकती है । इसी प्रकार यूनेस्को / के अध्यक्ष का यह निशिचत मत है कि निरक्षर लोगों में मानवीय विकास बहुत कठिन है और एक केनेडियन शिक्षा-शास्त्री ने तो यहाँ तक // कहा है कि देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए निरक्षरता का खात्मा बहुत ज़रूरी है । यूनेस्को ने इसीलिए इस मद में इस वर्ष के लिए /// 70 लाख डालर रखे हैं और उसकी ओर से 30 देशों में निरक्षरता समाप्ति अभियान चल रहा है ।

भारत में निरक्षरता की स्थिति यह है {3} कि प्रत्येक तीन व्यक्तियों के पीछे दो निरक्षर हैं । अनुमान यह है कि लगभग 35 करोड़ व्यक्ति लिखना-पढ़ना जानने से शून्य हैं । यद्यपि / सन् 1961 की जनगणना के बाद से साक्षर लोगों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । परन्तु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में निरक्षरता // दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है । इसीलिए शिक्षामंत्री ने यह भी संकेत दिया है निरक्षरता और बड़ा परिवार साथ-साथ चलते हैं । /// इसीलिए निरक्षरता को दूर करने के लिए परिवार-नियोजन पर पूरा-पूरा ध्यान देना अति आवश्यक है । अतः पहले को दूर करने के लिए {4} दूसरे पर अंकुश लगाना होगा । यही कारण है कि गाँवों में निरक्षरता का अनुपात सबसे अधिक है । गाँवों का दुर्भाग्य यह है कि वहाँ साक्षरता / का तो कोई उचित प्रबन्ध है ही नहीं, परिवार नियोजन के प्रति भी आवश्यक सचेतना नहीं है । इसके विपरीत शहरों में जहाँ साक्षरता अधिक है // इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन पर भी लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है कि निरक्षरता को दूर करने के /// लिए तथा परिवार-नियोजन के लिए हमें गाँवों की तरफ अधिक ध्यान देना होगा । निरक्षरता की समस्या से केवल भारत ही नहीं दुनिया के और {5} बहुत से देश भी ग्रस्त हैं, जिनमें अरब और अफ्रीकी देश प्रमुख हैं । एक सर्वेक्षण के अनुसार इन देशों में भी परिवार नियोजन / पर ठीक अमल न होने से निरक्षरता निरन्तर बढ़ रही है ।

{536 शब्द}

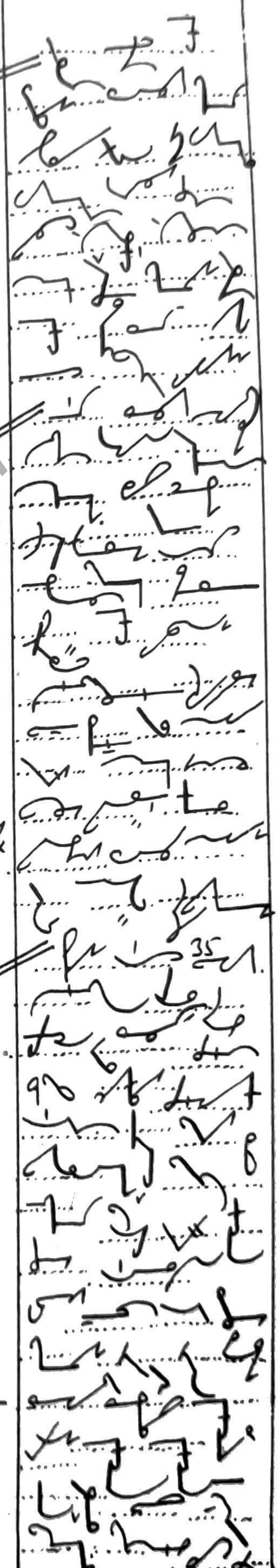

www.StenoIQ.com

अभ्यास-64

सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में आवास को बहुत निचला स्थान मिला हुआ है ।
पाँचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में लोगों की मूल आवश्यकताओं को / पूरी कर सकने का
दावा किया गया है । लेकिन आवास और शहरी विकास की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनायी
गयी है । जबकि दक्षिण अमरीकी देशों // ने कम खर्च के मकान बनाने के काम में बड़ी
प्रगति कर ली है । किसी भी राष्ट्रीय आवास नीति का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि
/// ज्यादा से ज्यादा मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाये और शहरों में किराये इस
स्तर पर नीचे रखे जायें कि मकानों के किरायेदार उनका {1} बोझ झेल सकें । लेकिन लगता
है कि अब तक केवल ध्यान इस बात पर दिया गया है कि शहरी ज़मीन और सम्पत्ति की
कीमतों में / तथाकथित अनर्जित वृद्धि को किस प्रकार बटोरा जाये और जो व्यक्ति या संस्थाएँ
आवास के क्षेत्र में कुछ पहल या उद्यम दिखाते हैं, उन के रास्ते में किस प्रकार ज्यादा से
ज्यादा अड़चने डाली जाएं । मकानों का अकाल मुख्य रूप से सरकार का बनाया हुआ है,
क्योंकि शहरी /// संपत्ति पर सरकारी हमलों से इस क्षेत्र में पूँजी नियोजन नहीं हो पा रहा
है ।

संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में कहा गया है कि {2} सन् 2000 ई0 में विश्व की
जनसंख्या दुगुनी हो कर 7 अरब हो जायेगी और इसमें से 60 प्रतिशत लोग शहरों में रह
रहे होंगे, जबकि 1960 में 40 प्रतिशत आबादी शहरों में थी यानी इस शताब्दी के अंत में
10 में से 6 व्यक्ति नगरों में निवास कर रहे // होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या को
शहरों में ले जाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण ही स्थायी हल दिखाई देता है ।
// इस समय आवश्यकता गाँवों में आवास की व्यवस्था करने की है । साथ ही शहरी क्षेत्रों
में गंदी बस्तियों की सफाई की योजनाएँ सुचारू बनाने /// की भी जरूरत है । शहरों में
मकानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मकानों का निर्माण धीमी गति से हो रहा
है । {3} आवास के क्षेत्र में निजी पूँजी नियोजन के आकार के बारे में विश्वसनीय जानकारी
के अभाव में देश में आवास की स्थिति को सही / तौर पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता ।
इस क्षेत्र में निजी पूँजी नियोजन सरकारी पूँजी से कहीं ज्यादा है । नगरों में निजी मकानों
// का निर्माण कार्य अवश्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सरकारी संस्थाएँ कुल माँग का
कम हिस्सा ही पूरा कर सकती है । सरकारी नेता प्रायः /// निजी क्षेत्र की इस बात के
लिए आलोचना करते हैं कि उसका ऐश्वर्यपूर्ण और बहुमूल्य मकानों के निर्माण में खर्च हुआ है
। {4} यह सभी चाहते हैं कि इमारती सामान और धन का प्रयोग लाखों सादे मकान बनाने
में किया जाना चाहिए । किन्तु इस बारे में कुछ विश्वसनीय / आँकड़े इकट्ठा करना ज़रूरी है
कि निजी क्षेत्र का ऐश्वर्यपूर्ण मकानों के निर्माण में कितना धन और इमारती सामान // लगा है,
जिसे प्रस्तावित प्रतिबंधों से बचा कर आम जनता के लिए आवास उपलब्ध कराने में लगाया जा
सकता था । लगता है कि सरकार /// वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है
। यह सर्वमान्य तथ्य है कि चाहे गरीब हो अथवा अमीर प्रत्येक को बनाये रखने के लिए
{5} आवास, भोजन, वस्त्र की आवश्यकता होती है । इस दृष्टि से आज हमारी स्थिति
मात्र गरीबी हटाने की नहीं अपितु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कंगाली / कम करने की
है । {529 शब्द}

अभ्यास-65

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आया है इसे कोई बुनियादी प्रश्न बना कर कहना गलत होगा । जहाँ तक प्रिवी पर्स का ताल्लुक है यह / 5 करोड़ रुपये का सवाल है और जो कि हर साल के बाद ज्यों प्रिंस मरते जाते हैं यह खत्म होती चली जाती है । // आज देश के सामने जो समस्यायें हैं आन्तरिक और बाहरी उन समस्याओं के मुकाबले में यह कोई समस्या नहीं है । वास्तव में जनता का ध्यान /// जो देश की बुनियादी समस्यायें हैं उनसे हटाने के लिये उन्होंने इस प्रकार का सवाल पैदा किया है वरना मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि §1§ अगर यह पाँच करोड़ रुपया सब में बांट भी दो तो कितने लोगों का जीवन स्तर आप ऊँचा करने वाले हो ? इसलिये हमें इस प्रश्न / का जो वास्तविक रूप है हम उस वास्तविक रूप को देखें । यह प्रिवी पर्स राजाओं को दी गई जिसमें उन्होंने अपना राजपाट दिया । एक विशेष // परिस्थिति हुई और मेरे जैसे आदमी जो उस समय रियासतों में थे और उस समय जो संघर्ष कर रहे थे रियासतों को भारत के साथ /// मिलाने का, वह जानते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति थी । उस समय यदि देश के अन्दर स्वर्गीय सरदार पटेल न होते उनकी होशियारी न होती §2§ उनकी कार्यकुशलता न होती, उन्होंने प्रिंसिज़ के साथ जिस ढंग से काम किया वह न किया होता तो आज भारत का रूप क्या होता / यह कोई नहीं कह सकता है । वास्तविकता यह है कि सरदार पटेल ने जो भारत को एक किया आज जो लोग इस प्रकार की बातें // कर रहे हैं वे लोग सरदार पटेल के काम को खत्म करना चाहते हैं और वह इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं । मैं उनसे /// कहूँगा कि परमात्मा के वास्ते यह चीज़ जो है इसको आम मत कीजिए । सवाल यह नहीं है कि वे राजा खराब हैं या आज §3§ के कांग्रेसी राजा अच्छे नहीं हैं । यह डेमोक्रेसी का भी सवाल नहीं है । जहाँ तक आम जनता का सवाल है कोई बड़े से बड़े कांग्रेसी राजाओं के मुकाबले में पुराने राजाओं को पसन्द करती है । // आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है । परन्तु सवाल यह है कि आज लोकतंत्र के युग में जिसमें हम सब को समाने अधिकार हैं, /// किसी को भी कोई विशेषाधिकार मिलें, यह अखरता है । विशेषाधिकार चाहे राजा के पास हों, मन्त्रियों के पास हों या किसी और आदमी §4§ के पास हों, वे अखरते हैं ।

आम आदमी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं किसी और आदमी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, दूसरी पार्टियों में राजा / होंगे, लेकिन मेरी पार्टी में राजा या अमीर आदमी नहीं हैं । मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के अन्य लोगों के जो विशेषाधिकार हैं, // जिन्होंने पिछले बीस सालों में धन इकट्ठा किया है, जो आज मंत्री हैं, उनको भी समाप्त किया जाये । राजा लोग भी कभी डाके मारते होंगे, // लेकिन आम आदमी आज यह चाहता है कि आज भी लोग समाजवाद या पूँजीवाद के नाम पर डाके मार रहे हैं, उनके डाकों को बन्द किया जाये । §5§ वह चाहता है कि उसके अधिकारों पर जो डाका मारा जा रहा है, उसको खत्म किया जाये । आज जरूरत इस बात की है कि हम / इस देश के बुनियादी सवालों पर ध्यान दें । §533 शब्द§

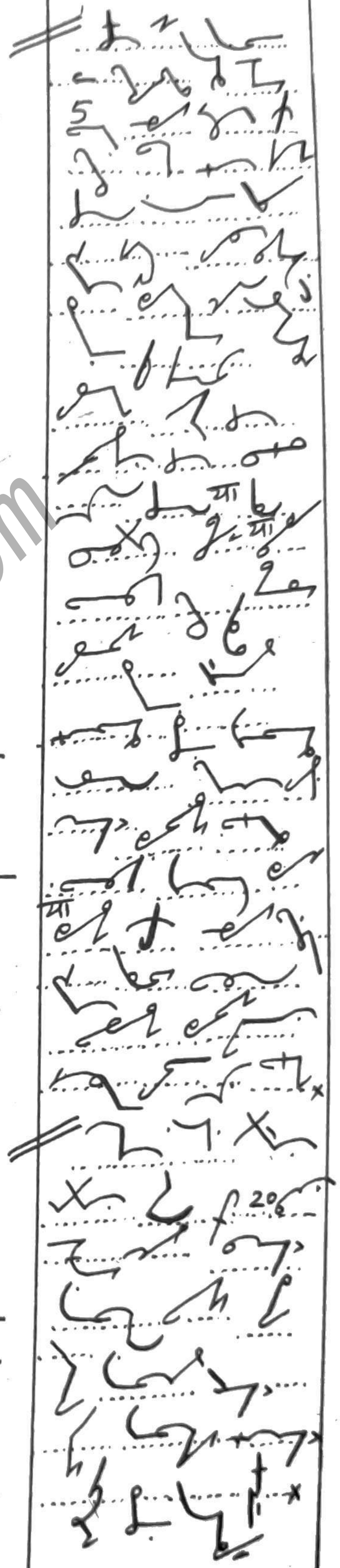

विश्व ... विस्फोटक ... विकल्प ... वैकल्पिक

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

अभ्यास-66

आदरणीय सदस्यगण, अगर आपसे पूछा जाये कि आज आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है तो आप क्या कहेंगे ? आप अपने परिवार, अपने घर अपनी/ज़मीन का नाम लेंगे । ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें आपको प्यारी हैं, किन्तु आपके पास इनसे भी कीमती एक चीज़ और है और वह // है आपकी आज़ादी । और भी बहुत सी चीजें हैं, जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती हैं । लेकिन जो आदमी आज़ाद नहीं, /// उसकी कोई इज़्ज़त नहीं । आज हम आज़ाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आज़ादी पर खुश होने का खास कारण है । लगभग दो (1) सौ वर्ष हुए हमारी आज़ादी विदेशियों ने छीन ली थी । उसे फिर से पाने के लिए हमें एक बहुत लम्बी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी ।

आखिरकार 15 अगस्त, 1947 को आज़ादी का सुनहला दिन आया । देश का शासन हमारे अपने हाथों में आ गया । हमारे लिए यह खुशी का एक // ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते । हर साल इसे हम अपने स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाते हैं । जिन दिनों आज़ादी की /// लड़ाई चल रही थी, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आज़ादी की शक्ल क्या हो, (2) आज़ादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतन्त्र भारत की सरकार क्या कुछ करे । जो बात बिलकुल साफ थी वह यह / कि स्वतन्त्र भारत की सरकार जनता की होगी, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी । दूसरी बात यह थी कि यह सरकार देश के // सभी लोगों के साथ बराबरी का बरताव करेगी । जाति, धर्म क्षेत्र या स्त्री-पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी हर-एक /// व्यक्ति को एक आज़ादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने और रहन-सहन का मनचाहा तरीका अपनाए । तीसरी बात यह कि सरकार जनता (3) की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथों में लेगी । /

इन सब बातों के लिए कभी-कभी कुछ भारी-भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे समाजवाद, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि । // सीधे-सादे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, जनता की उन्नति और खुशहाली के लिए काम करती जाए । हमारे लोकतन्त्र /// में वे सब बातें मौजूद हैं । जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रख कर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उन्हीं को पूरा करने (4) के लिए महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरु तथा दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतन्त्र का निर्माण हुआ है । हमारे लोकतन्त्र का क्या स्वरूप / हो, राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करें, और राष्ट्रीय नीति के मोटे-मोटे सिद्धान्त क्या हों, ये सारी बातें // ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में दी गई हैं, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं । स्वतन्त्र होने के बाद देश की जनता के प्रतिनिधियों ने /// एक संविधान सभा बनाई थी । हमारे संविधान की यह विशेषता है कि उसमें समय-समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा (5) सकता है और अब तक इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं । (512 शब्द)

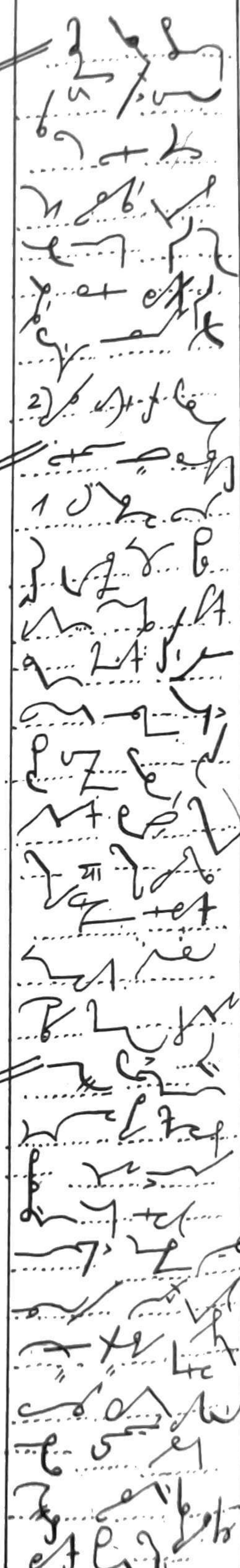

www.StenoIQ.com

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

अभ्यास-67

उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि भारत और आस्ट्रेलिया ने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ पर चिन्ता व्यक्त करते हुए / एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है । हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने भाषण // में बिल्कुल ठीक कहा है कि केवल बड़ी शक्तियाँ ही विश्व के भाग्य की निर्णायक नहीं हैं । दूसरे देशों को भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी है । /// दक्षिण अफ्रीका को झुलसने से बचाने के लिए अभी भी समय है, परन्तु समय बहुत थोड़ा रहा गया है । रंगभेदी सरकार के खिलाफ प्रतिबन्ध §1§ लगाने के लिए यूरोप में अनुकूल वातावरण बन रहा है । इसका प्रसार उन देशों में भी होगा जो इतिहास की धारा मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं । अमेरिकी संसद ने भी प्रशासन को प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर कर दिया है । दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के // खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने चाहिए, इसमें सब राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए ।

जो सरकारें खुले तौर पर शान्ति के लिए खतरा बनें, उनके // खिलाफ संयुक्त अन्तराष्ट्रीय कार्रवाई जरूरी है । संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट प्रावधान है । आक्रमण उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफ्रीकी कोष §2§ स्थापित किया गया है, जो स्वागत योग्य है । इसके साथ-साथ परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी रोक होनी चाहिए जो परमाणु राष्ट्रों पर भी लागू हों । / सोवियत संघ को एक तरफा रोक लागू किए एक साल हो गया है । दूसरों कोइसका अनुसरण करना चाहिए । ताकतवर देश यह सोचते हैं // कि वे अपनी संहारक शक्ति का विस्तार करके परमाणु अस्त्रों का उपयोग रोक सकते हैं । इस इरादे से वे विनाशकारी हथियारों का संग्रह करते जा /// रहे हैं । परन्तु मानवता के अस्तित्व की रक्षा उनके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती जिनके पास दुनिया को बर्बाद करने की ताकत हैं । उनका शक्ति पर §3§ एकाधिकार हो सकता है, विवेक पर नहीं ।

हिन्द महासागर में शक्ति स्पर्द्धा की खूब चर्चा हो रही है । हमारे क्षेत्र की शांति सुरक्षा और व्यापार / इस बात पर निर्भर है कि हिन्द महासागर बाहरी शक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा से मुक्त हो । संयुक्त राष्ट्र घोषणा में हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित // किए जाने के बावजूद भी आज यह तनावग्रस्त है । विदेशी नौसेना परमाणु अस्त्रों सहित वहाँ मौजूद है । संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने मौजूदा अधिवेशन में हिन्द /// महासागर विषयक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है ताकि उक्त योजना को अमली जामा पहनाया जा सके । यदि हिन्द महासागर जंगी ताकतों का §4§ अखाड़ा बना तो हम इसकी प्रचुर सम्पदा से वंचित हो जायेंगें ।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन वस्तुतः राष्ट्रों का लोकतंत्र है । इसमें हर देश की बराबर की / आवाज है, चाहे उनमें आकार, सम्पदा या सैन्यबल का कितना भी अन्तर क्यों न हो । इस अर्थ में यह आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र का प्रतिरूप है । // उपनिवेशवाद के दिन लद गए । सार्वभौम समानता के मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र अब विश्व का ज्यादा सही प्रतिनिधित्व

www.StenoIQ.com

कर रहा है । खेद की /// बात है कि इसका स्वागत करने की बजाय कुछ ताकतें इसे कमज़ोर करने पर तुली हुई हैं । लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि अनथक §5§ परिश्रम के बाद इस विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ है । §512 शब्द§

अभ्यास-68

आदरणीय महोदय, नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में आज 1987-88 के लिए निगम के बजट प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया / है कि आंकड़ों में हेरफेर करके बजट को बचत वाला बनाने की कोशिश की गई है । जिस बजट को जनोपयोगी और विकासोन्मुख होने का // ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसकी असलियत यह है कि कुल बजट का केवल 20 प्रतिशत ही नागरिक सुविधाओं पर व्यय किया जा रहा है । /// दो अरब सात करोड़ रुपए के बजट में से केवल 43 करोड़ रुपए जन-कार्यों के लिए रखा गया है । बजट का करीब 69 प्रतिशत §1§ तो प्रशासनिक व्यय के लिए रखा गया है। बजट को लाभ वाला दिखाने के लिए उसमें ऐसी अनेक वसूलियाँ शामिल की गई हैं, जिनकी कोई संभावना / ही नहीं है ।

निगम की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रहार करते हुए कहा गया है कि निगम ने पुरानी दिल्ली के निवासियों के साथ खिलवाड़ किया है । // पुरानी दिल्ली में सर्वाधिक कटरे है । करीब तीन हज़ार कटरे नगर-निगम के अधीन हैं । पिछले वर्ष बजटमें कटरों के सुधार के लिए एक /// करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन कुल 61 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके । नए बजट में केवल 75 लाख रुपए इस मद के §2§ लिए रखें गए हैं । निगम की की आय बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि अनधिकृत रूप से बिना लाइसेन्स चल रही करीब 50 हजार / औद्योगिक इकाइयों को तदर्थ लाइसेंस दिए जाएँ । इससे निगम को काफी आमदनी होगी । जो आय निगम को होनी चाहिए वह इस समय अफसरों की जेब // में जा रही है । इससे एक लाभ और होगा और वह यह कि नगर-निगम को इस बातका ज्ञान भी होगा कि कौन /// सी ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनका रिहायशी इलाकों में चलना बहुत ही खतरनाक है तथा ऐसी इकाइयों को फौरन वहां से हटा कर शहर §3§ से दूर बसाया जाए ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें । आज वस्तुस्थिति यह है कि कुछ औद्योगिक इकाइयां / ऐसी है जिनसे वायु का प्रदूषण बढ़ जाता है तथा वहाँ के रहने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है । कई लोगों ने इन // इकाइयों की कड़े शब्दों में शिकायतें भी की हैं लेकिन इसमें लोगों की सुनवाई न होकर अफसरों तथा इंस्पेक्टरों की जेबें ही भरती है । ///

निगम के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी दो शब्द कहना चाहूँगा । इसमें कोई शक नहीं कि निगम के अस्पताल और डाक्टर अच्छे हैं §4§ अपनी डियूटी के पाबन्द हैं, लेकिन इन अस्पतालों में न तो दवाइयाँ हैं और न कम्बल तथा चादरें हैं । जब निगम का स्वास्थ्य विभाग इन / अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध करता है तो फिर ये

चीज़ें कहाँ चली जाती हैं ? रजिस्टर में दर्ज रहता है कि दवाइयाँ // मरीज़ों को दी गईं । मरीज़ों को यही शिकायत रहती है कि साधारण दवाइयाँ भी उन्हें नहीं मिलती । इससे गरीब लोगों को काफी कठिनाई का /// सामना करना पड़ता है । अतः मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई निष्पक्ष समिति का गठन किया जाए जो इस समस्या का हल बता सके । (5)

मैं दिल्लीवासियों पर करों का बोझ न लादने के लिए आयुक्त को बधाई देता हूँ । नये कार्यों के लिए गत वर्ष छह करोड़ 65 लाख के / मुकाबले नए वर्ष में 17 करोड़ 74 लाख रुपए रखा जाना इस बात का सूचक है कि हम निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर हैं । // (550 शब्द)

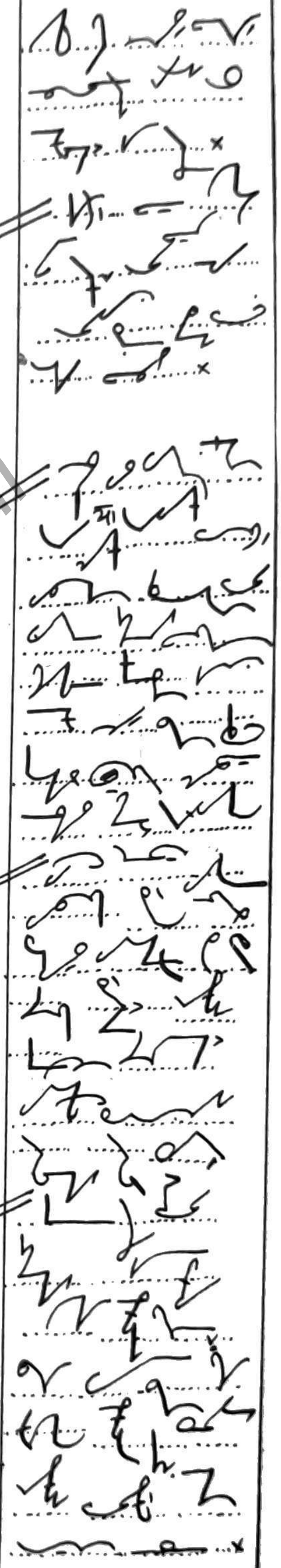

अभ्यास-69

महोदय, विदेश व्यापार के घाटे में भारी वृद्धि तथा नर्म शर्तों पर विदेशी मदद में कमी के सन्दर्भ में सरकार निर्यात, उत्पादन, नीति तथा उसके / प्रबन्ध व संचालन में व्यापक परिवर्तन पर विचार कर रही है । हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी की अध्यक्षता में हाल में गठित मंत्रियों की // समिति इस बारे में दिशा-निर्देशन देने जा रही है । इस मामले पर मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गहराई से विचार किया गया है । /// निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में कुछ ही समय में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ किए जाने की सम्भावना है ।

निर्यात के काम में विदेश मंत्रालय के (1) आर्थिक मामलों के विभाग को विशेष जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव है । सभी भारतीय दूतावासों में आर्थिक तथा वाणिज्यिक विभागों को संगठित और सबल बनाने का / प्रस्ताव है । इस बारे में उन्हें अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी । मेरा सुझाव है कि उत्पादन से सम्बन्धित विभागों को उद्योग मंत्रालय में शामिल किया जाए // तथा वाणिज्य मंत्रालय का कुछ काम विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को सौंपा जाए । अभी तो सुनने में आ रहा है कि /// वाणिज्य मंत्रालय का पुनर्गठन किया जा रहा है । उसके पुनर्गठन के बाद उसका स्वरूप क्या होगा, अभी कहना कठिन है ।

औद्योगिक सूत्रों के अनुसार (2) आयात-निर्यात नीति में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है । हालांकि पिछले वर्ष सरकार ने तीन वर्ष की विदेश व्यापार / नीति की घोषणा की थी । आर्थिक और कर नीतियों में परिवर्तन के बाद उद्योग व व्यापार ने विदेश व्यापार नीति को भी अधिक लचीला बनाने // का सुझाव दिया है, जिससे निर्यात की प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक बन सके । इस बारे में कंट्रोल में कुछ ढील देने का सुझाव भी /// दिया गया है जो स्वागत-योग्य हैं । मेरा सुझाव है कि निर्यात संगठनों को उनके कामकाज में अधिक सुविधा तथा नियमों में अधिक से अधिक छूट दी जाए ।

विश्वविद्यालय ... वर्गीकृत ... हकदार ...
विश्वविद्यालयिक ... वर्गीकरण ... साझेदार ...

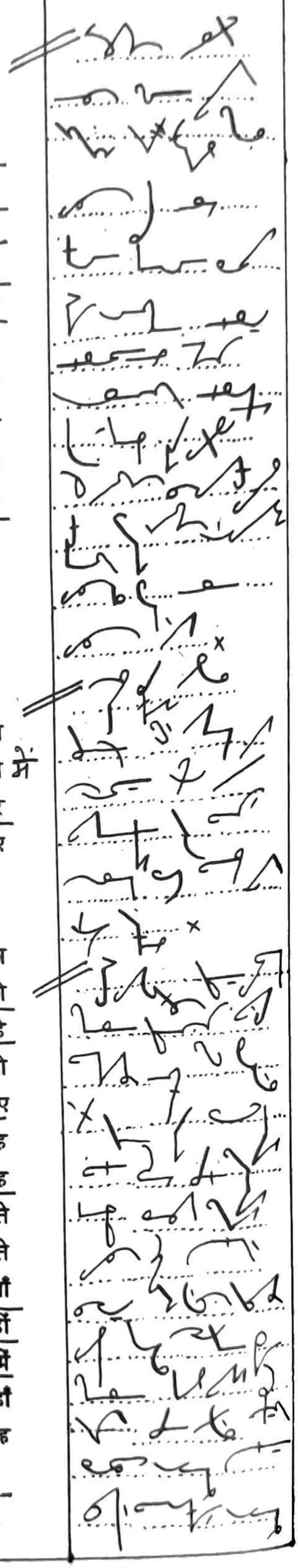

भारत का निर्यात दुनिया के हर हिस्से में बढ़ा है । तो भी अब उसमें उचित वृद्धि नहीं हो पा रही है । / रिज़र्व बैंक की यह सलाह भी बहुत अच्छी है कि निर्यात करने वाले माल को किस्म तथा कीमतों के मामले में अधिक प्रतियोगी बनाया जाए । // पश्चिम यूरोप तथा अमेरिका में भारत के निर्यात की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ गई हैं, किन्तु हम इसका पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पा /// रहे हैं । पश्चिम यूरोप तथा अमेरिका में निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आय में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है । सरकार आधुनिक तकनीक {4} तथा संयत्र के आयात के लिए अनेक तरह की छूट की घोषणाएँ कर चुकी हैं । निर्यात क्षेत्र को कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर उपलब्ध कराने / की घोषणा की जा चुकी है । तो भी निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पायी है । इससे सरकार चिन्तित है । विश्व बैंक ने भी भारत // की अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट में निर्यात सम्वर्द्धन की ओर विशेष तौर से ध्यान देने पर बल दिया है । मेरे विचार में भारत के लिए अब अनिवार्य हो गया है कि वह आयात के लिए विदेशी मदद से अधिक निर्यात पर अपनी निर्भरता बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके । {506 शब्द}

www.StenoIQ.com

अभ्यास-70

महोदय, आज स्थिति यह है कि एक ओर हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है, देश का बहुसंख्यक वर्ग हिन्दी बोलता और समझता है, भारतवर्ष / के आठ प्रान्तों का राजकाज हिन्दी में हो रहा है, देश की सभी महानगरियाँ हिन्दी में ही विचार-विनिमय करती हैं, दूसरी ओर यह देख // कर दुःख होता है कि अब भी कार्यालयों की मानसिकता अंग्रेजी का आग्रह लिए बैठी है । यह बात हमें कुछ चिन्तन के लिए बाध्य करती हैं । //

आए दिन विभिन्न भाषाओं में छपी पुस्तकों के विक्रेता और प्रकाशक पुस्तक मेले का आयोजन करते रहते हैं । हिन्दी को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की {1} पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो जाती हैं । हिन्दी में पाठकों का बढ़ना तो दूर रहा निरन्तर कम होता जा रहा है आखिर ऐसा क्यों है ? / जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है/ और उसके साथ-साथ साक्षरता भी बढ़ रही है तब हिन्दी पाठक न बढ़े, यह वास्तव में आश्चर्य की बात // है । लाखों रूपए सेमिनारों और भाषणों में बहाए जाते हैं । वस्तुतः अगर पैनी दृष्टि से देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस स्थिति /// के लिए स्वयं प्रकाशक ही दोषी हैं । हिन्दी का पाठक यह चाहता है कि उसे पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध हों, जैसा कि दूसरी भाषाओं के {2} सस्ते संस्करण निकलते हैं । हिन्दी में अच्छे-अच्छे लेखकों और साहित्यकारों की प्रसिद्ध पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकलने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की । / हिन्दी में जितनी भी ग्रंथावलियाँ निकाली जाती हैं उनके दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि साधारण पाठक उसको खरीद नहीं सकता । ऐसा लगता है कि // हिन्दी की पुस्तकों का प्रकाशन हिन्दी पाठकों को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता । इनका प्रकाशन किया जाता है केवल सरकारी खरीद के लिए । जहाँ /// उद्देश्य ही सरकार पर आश्रित रहना हो वहाँ पाठकों की कौन परवाह करेगा और परवाह

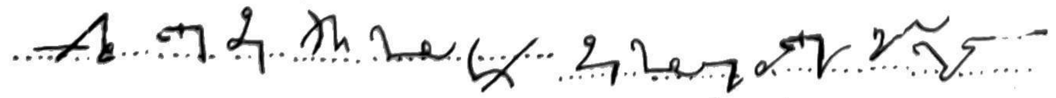

करने की जरूरत भी क्या है ? आज यही स्थिति ‖3‖ हिन्दी में प्रकाशित ग्रन्थावलियों की है ।

इस माहौल में पाठक यदि निरन्तर घटते रहे तो आश्चर्य क्या ? शुरू-शुरू में जब चाय का आविष्कार हुआ / था तब लोगों को चाय के बारे में पता तक न था । इस स्थिति में चाय के वितरक पहले मुफ्त में चाय पिलाते थे, केवल // चाय की रुचि पैदा करने के लिए क्योंकि वे समझते थे कि जब रुचि पैदा हो जाएगी तो वे चाय खरीद कर भी पीएँगे, और /// यही हुआ, उनकी यह दूरदर्शिता काम कर गई और आज चाय का प्रचलन ज़ोरों पर है । यही बात पाठकों पर भी लागू होती है, ‖4‖ अगर पाठकों को पढ़ने की रुचि निरन्तर बढ़ती रहेगी । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज / हिन्दी प्रकाशक का ध्यान सबसे पहले अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की ओर जाता है । दूसरी ओर प्रकाशक को पाठकों की जेब का अन्दाज़ा // बिल्कुल नहीं या फिर अगर इस बात का अन्दाज़ा है तो उसकी परवाह नहीं है /// सरकारी अनुदान की / किस प्रकार सरकारी अनुदान प्राप्त किया जाए और उसका उपयोग नहीं वरन् उपभोग किया जाए । यही कारण है कि आज ऐसे अनुदानों ‖5‖ के विरोध में आवाज़ उठने लगी है । ‖507 शब्द‖

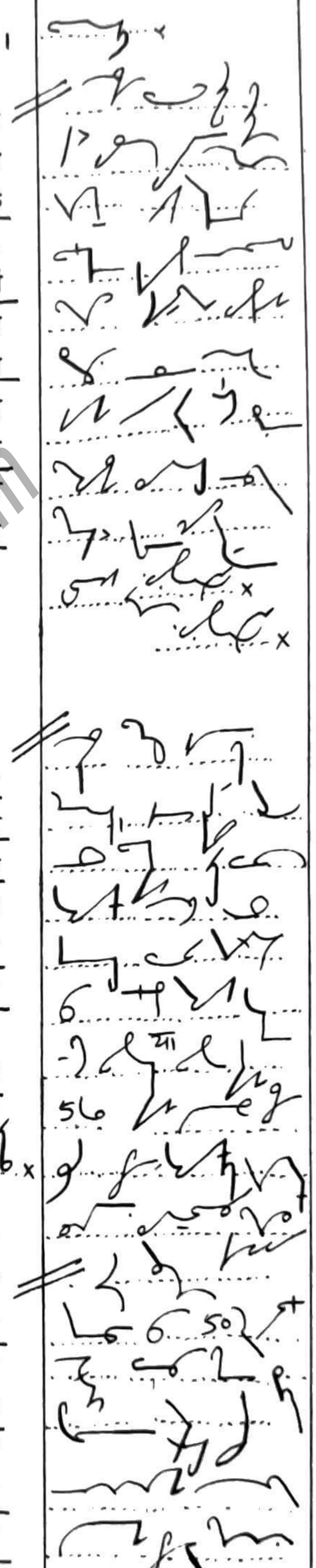

अभ्यास-71

महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था हालाँकि सरकार की उदार आर्थिक नीतियों के कारण तंदुरुस्त बनने की कोशिश करती जा रही है, लेकिन 1986 के दौरान कुल मिला / कर आर्थिक अभिवृद्धि के मिश्रित निष्कर्ष निकले हैं । औद्योगिक उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इस साल घोषित उदार आर्थिक नीतियों के बावजूद // अभी तक उसके अच्छे असर दिखाई नहीं दिए । अब यह साफ होता जा रहा है कि वर्ष 1986-87 के दौरान पाँच फीसदी अभिवृद्धि दर /// का लक्ष्य शायद हासिल नहीं हो पाएगा । ज्यादा से ज्यादा पिछले साल की साढ़े चार प्रतिशत अभिवृद्धि दर तक ही उपलब्धि सीमित रहेगी । सरकारी ‖1‖ आँकड़ों के अनुसार, 1986 में अप्रैल से अगस्त के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक पिछले साल के पाँच महीनों के मुकाबले 5.6 प्रतिशत ज्यादा था / लेकिन यह अप्रैल-अगस्त 1985 में 1984 के मुकाबले हासिल 5.8 प्रतिशत की दर से कम हैं ।

शेयर बाज़ार में नए शेयरों के लिए पूँजी // के धन में बाढ़ सी आ जाने के बावजूद उद्योग के क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के पहले पाँच महीनों में उत्पादन वृद्धि /// की दर अपेक्षाकृत कम रहीं । इस साल नए शेयरों के लिए 50 अरब रुपए की रिकार्ड पूँजी इकट्ठी की गई, जो कि 1985-86 ‖2‖ के तेरह अरब रुपए से कहीं ज्यादा है । भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले साल तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी कि नए पूँजी विनियोजन को / किस तेज़ी के साथ / काम में लाया जाता है । अच्छी अर्थव्यवस्था का अन्दाज़ा आमतौर पर शेयर बाज़ार से लगाया जाता है । // शेयर बाज़ार में पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रारम्भ में संकट के लिए /// बाज़ार में आई दस अरब रुपए की नई पूँजी को ज़िम्मेदार ठहराया है । इन सूत्रों का यह भी कहना है कि कई बेच कर नए शेयर खरीदने के कारण इनके भाव गिर रहे हैं । अतः उनकी / आशा सरकार द्वारा शेयर बाज़ारों के कामकाज में सामंजस्य कायम करने के

प्रयासों पर टिकी हुई है ।

कृषि के क्षेत्र में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल कम बारिश के बावजूद पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ ज्यादा उत्पादन होगा । राजस्व वसूली के क्षेत्र में इस /// साल भी बड़ा अच्छा रूख रहा । चालू वित्त वर्ष के पहले छह महनों के दौरान राजस्व वसूली में 19 फीसदी का इज़ाफा हुआ । इसके बावजूद (4) इस साल बजट घाटा अनुमान से कुछ ज्यादा रहेगा । इस साल व्यापार घाटा पिछले साल के 873 करोड़ रूपए से काफी कम होने की उम्मीद है । / यह मुख्यतः आयात में कटौती करने की वजह से संभव हो सका । पिछले साल निर्यात में एक प्रतिशत वृद्वि हुई थी जबकि चालू वित्त वर्ष // में यह वृद्वि 16 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है । इस साल सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए जबरदस्त कदम उठाए । इसके तहत निर्यातकों को /// उदारतापूर्वक नकद मुआवज़ा दिया गया तथा शुल्क और व्याज दर में काफी कटौती की गई । इसके अलावा आय-कर में भी छूट दी गई । (5) सारी बातें सही हैं लेकिन एक बात ऐसी है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कायम नहीं हो पाता और वह है बढ़ती हुई मँहगाई, जिससे सभी परेशान हैं, लेकिन फिर भी यह बढ़ती ही जा रही है । कुछ अर्थशास्त्रियों ने आशंका व्यक्त की है कि इस साल // मुद्रास्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दो अंकों में पहुँच सकती है ।
(565 शब्द)

अभ्यास-72

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की तरफ से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में माँग की गई है कि राज्यपालों / की नियुक्ति और विधानमण्डलों में बहुमत का परीक्षण कराने के उनके अधिकारों के बारे में एक स्पष्ट सामान्य सिद्वान्त लागू होना चाहिए । यह ज्ञापन // आज यहाँ संसद में जनता पार्टी के नेता ने जारी किया । ज्ञापन में यह साफ-साफ कहा गया है कि अकसर राज्यपालों की नियुक्ति दलगत /// दृष्टिकोण के साथ और राजनीतिक संरक्षण देने के लिए की जाती है । राज्यपालों की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमन्त्रियों से सलाह-मशिवरा नहीं किया (1) जाता और न उनसे सहमति ली जाती है । यह भी नहीं देखा जाता कि भावी राज्यपाल योग्य, सक्षम और निष्पक्ष है भी या नहीं । / अतः मेरे विचार में इस पृष्ठिभूमि में यह ज़रूरी है कि राज्यपाल के अधिकारों और कार्यक्षेत्र के बारे में संविधान में पर्याप्त सुरक्षा हो ।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है और मेरा भी यही सुझाव है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत के दावे का परीक्षण विधानसभा के /// अन्दर होना चाहिए, राज्यपाल के निवास या कक्ष में नहीं । बहुमत के सम्बन्ध में अगर कुछ सन्देह पैदा होने पर ज़रूरी है कि (2) राज्यपाल मुख्यमन्त्री को विधानसभा में बहुमत सिद्व करने के लिए उचित निर्देश दें । यही पद्वति लोकसभा में बहुमत का पता लगाने के लिए / राष्ट्रपति को अपनानी चाहिए । सरकार गिरने की हालत में अगर कोई दल या संयुक्त मोर्चा विधानसभा में अपना बहुमत स्थापित न कर सके तो // विधानसभा भंग कर दी जानी चाहिए और जल्द ही नये चुनाव कराए जाने

चाहिएँ । केवल मुख्यमन्त्री की सलाह मानकर राज्यपाल को विधानसभा /// का सत्र स्थगित नहीं करना चाहिए और न ही अध्यादेश जारी करना चाहिए ।

ज्ञापन में यह भी माँग की गई है कि संविधान में संशोधन §3§ करके ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे राज्य विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत विधेयक पर राष्ट्रपति तीन महीने के अन्दर विचार करने के लिए बाध्य हो । / मेरा यह भी सुझाव है कि प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जाए-न केवल केन्द्र से राज्यों तक बल्कि पंचायत स्तर तक // इन अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो । कई केन्द्रीय एजेन्सियाँ और बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो राज्य के अन्दर आने वाले विषयों और /// संविधान की सातवीं अनुसूची के समवर्ती विषयों में शामिल हैं । इसमें से कुछ केन्द्रीय संगठन राज्यों के स्वायत-अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे रोकना चाहिए । §4§

केन्द्र तथा राज्यों के वितीय सम्बन्धों के प्रसंग में मेरा सुझाव है कि आयकर, जिसमें कि कम्पनी कर भी शामिल हैं, केन्द्र और राज्यों में / समुचित आधार पर बटवारा होना चाहिए । केन्द्र और राज्यों के खर्च की जांच के लिए एक राष्ट्रीय व्यय आयोग की स्थापना की जाए । अधिकतर // ओवर ड्राफ्ट की शिकायत सुनने में आ रही है । ओवर ड्राफ्ट इसलिए होता है चूंकि राज्य अपनी विकास से सम्बद्ध जिम्मेदारियों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों /// में सन्तुलन नहीं बना पाते । इसे दूर करने की ज़रूरत है ताकि राजनीतिक आधार पर ओवर ड्राफ्ट देने की कोई गुंजाइश ही न रहे । §5§ उल्लेखनीय है कि केन्द्र पहले ही आगे से ओवर ड्राफ्ट खत्म करने की घोषणा कर चुका है। §517 शब्द§

अभ्यास-73

उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की और शर्मनाक बात है कि आज़ादी के 38 वर्ष बाद भी विधानमंडलों के सदस्य संयम और शिष्टाचार से काम नहीं / करते । आए दिन विधानमंडलों में जूते-चप्पल दिखाने और हंगामा करने की घटना घटती रहती है । मैं विधायकों से अपील करता हूँ कि अपने // सदनों में गरिमा, विनम्रता तथा शिष्टाचार से काम करके संसदीय संस्थाओं को लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत करने का प्रभावी माध्यम बनाए रखें । किसी भी तरह /// का हंगामा या अव्यवस्था हर हाल में सदन के समय का दुरुपयोग ही है और इससे किसी का भी भला नहीं होगा । देश भर के §1§ विधानमंडलों के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वे सामूहिक ज़िम्मेदारी से न भागें, आपको इस जिम्मेदारी को / निभाना ही है । अपने-अपने कार्य का पूरी तरह निष्पक्ष निष्पादन करके लोकतंत्र की रक्षा करें तथा उसे और सुदृढ़ बनाएँ । आप सभी लोकतंत्र के // रक्षक हैं । आपने लोकतंत्र की रक्षा नहीं की तो आप देश के लोगों के साथ नाइन्साफी करेंगे ।

अधिकारीवर्ग तालमेल मार्गदर्शन

अनुपूरक उल्लंघन मार्गदर्शक

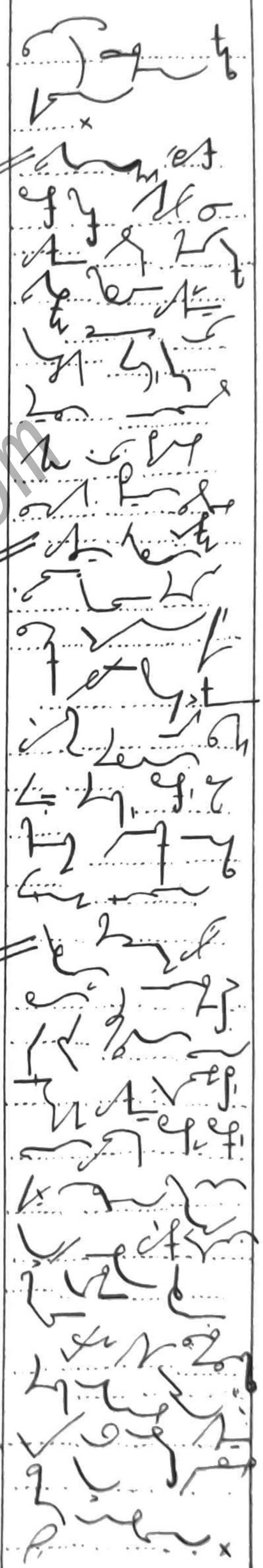

www.StenoIQ.com

संसद तथा विधामंडलों के सदन /// विचारों के आदान-प्रदान और उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए बनाए गए मंच हैं । उनके संचालन में किसी तरह की नकारात्मक दृष्टि ǁ2ǁ घातक हो सकती है । जब भी यह सुनने में आता है कि किसी सदन में चप्पल-जूते दिखाए गए या इसी तरह की कोई और / गड़बड़ी की गई तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । अतः मेरा निवेदन है कि सदन में कितनी भी उत्तेजना क्यों न हों, आपको // पूरे संयम से काम लेना चाहिए और प्रत्येक समस्या का हल बातचीत तथा वादविवाद के ज़रिए निकालना ही संसद की मर्यादा का पालन करना है । ///

सदन का ठीक ढंग से संचालन करने के लिए दोनों पक्षों के सदस्यों को विश्वास में लेकर काम किया जाए । किसी भी पक्ष को नज़रअन्दाज ǁ3ǁ करने पर काम नहीं चल सकता । हमें यह तय करना है कि शासन लोकतंत्र के माध्यम से चलाया जाय या कि बल प्रयोग के सहारे । / बलपूर्वक शासन चलाने का मतलब होगा कि तानाशाही लागू की जाए । पर इसके लिए हमारे देश के लोग कदापि तैयार नहीं होंगे क्योंकि सदियों से // हमारे दिलों में लोकतंत्र बहुत गहरे बैठा हुआ है । सदस्यों को चाहिए कि सदनों की कार्यवाहियों में अधिक से अधिक दिलचस्पी लें । जो सदस्य ऐसा /// नहीं करते वे अपने साथ और अपने मतदाताओं के साथ न्याय नहीं करते । इस तरह की नकारात्मक गतिविधियों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है । ǁ4ǁ

यह बड़े खेद की बात हैकि समय-समय पर पूरी गंभीरता से प्रयास किये जाने के बावजूद केन्द्रीय और राज्यों की विधायिकाओं को नियमित / तथा व्यवस्थित ढंग से चलाने की कोई कार्य-प्रणाली अब तक तैयार नहीं की जा सकी है । अतः मेरा विचार है कि इस // सम्बन्ध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए नियमों के प्रारूप को आदर्श मानकर विभिन्न विधायिकाओं के नियम बना लेने चाहिए तथा प्रत्येक विधायक के /// लिए यह बाध्य किया जाए कि उन नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए । इसके साथ ही दलबदल की बुराई को समाप्त करने के लिए ǁ5ǁ भी कानून बनाए जाएं तथा उनका कड़ाई से पालन हो । ǁ510 शब्दǁ

www.StenoIQ.com

अभ्यास-74

उपस्थित सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे यहाँ आगमन पर आज आपने जो मेरा भव्य और कृपापूर्ण स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सब / को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम इसी तरह से आगे के लिए भी बना रहेगा । आपके देश // केकई प्रतिष्ठित नेता हमारे देश भारत में आ चुके हैं जिनका हमें स्वागत करने का सुअवसर मिला है, इसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं । /// अभी कुछ ही महीने पहले आपके देश के माननीय राष्ट्रपति का भारत में आगमन हुआ था जिसे हम हर्ष के साथ स्मरण करते हैं । ǁ1ǁ इन यात्राओं से हमारे दोनों देशों के बीच अधिक जानकारी और सद्भावना का संचार हुआ है तथा मित्रता और दृढ़ होती जाएगी ।

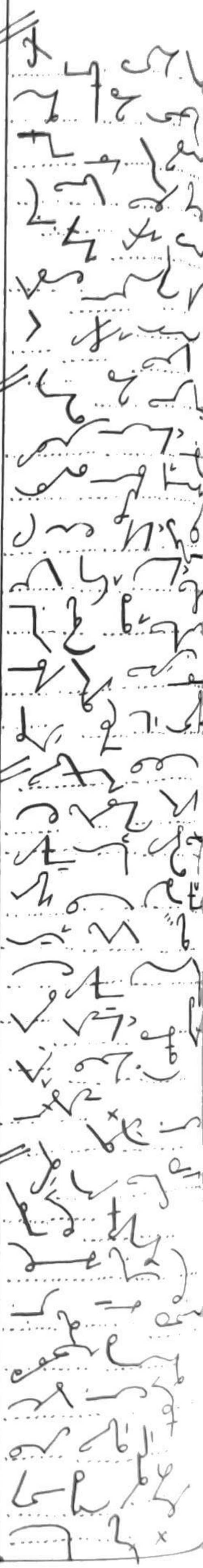

वास्तव में, आपके देश की यात्रा करने की मैं उत्सुकता से राह देखता रहा हूँ। // वस्तुस्थिति यह है कि रूस भारत का पड़ोसी है । मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब यहाँ आ सका हूँ और मुझे विश्वास है /// कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए मेरी यह यात्रा सुखद ही नहीं ज्ञानपरद भी होगी । आपके देश ने जो महान् और आश्चर्यजनक प्रगति की है ﴾2﴿ और दूसरे विश्वयुद्ध के विध्वंस और कष्टों केबाद पुनर्निमाण के विशाल कार्य को जिस प्रकार पूर्ण किया है उसके बारे में हमने बहुत / कुछ सुना है । विज्ञान और टैकनोलॉजी के क्षेत्र में आपके वैज्ञानिकों ने अद्भुत सफलताएँ प्राप्त की हैं तथा उनके द्वारा अन्तरिक्ष और दूसरे लोगों के // अन्वेषण के सम्बन्ध में भी हमने बहुत कुछ सुना है । और सबसे बढ़कर आपने उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में जो तरक्की की है /// और जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ सम्पन्न हुआ है और यहाँ के लोगों का रहन-सहन का मान ऊँचा हुआ है, उसके बारे में भी हमने ﴾3﴿ सुना है । हमें भारत में अपने भाग्य का निर्णायक बने अभी थोड़ा ही समय हुआ है । तब से हम औद्योगिकी द्वारा और अपनी खेती के / काम में सुधार करके अपने राष्ट्रीय साधनों को और अपने रहन-सहन को उन्नत करने में लगे हुए हैं । हमें खुशी है कि इन // दोनों क्षेत्रों में हमें आपके देश से उदार सहायता मिली है । वास्तव में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के कारण दुनिया सिकुड़ कर इतनी छोटी /// हो गई है कि एक प्रकार से एक देश की समस्याएँ सभी देशों की सामान्य समस्याएँ हो गई हैं । किन्तु इन सब समस्याओं पर विश्वशांति ﴾4﴿ का प्रश्न छाया हुआ है । मानव ने जो प्रगति की है, शान्ति के अभाव में वह सभी जगह और शायद सदा के लिए नष्ट की / जा सकती है । हमें इस बात का गर्व है कि विश्वशांति स्थापना के इस कार्य में आपके महान नेताओं ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । // हम सच्चे दिल से आशा करते हैं कि इस देश में उनके और अन्य बड़े देशों के नेताओं के प्रयत्न सफल होगें जिससे कि मानव /// समाज युद्ध के भय से मुक्त हो सके ।

क्या मैं एक बार फिर आपके कृपापूर्ण स्वागत के लिए, जिसे कि मैं भारवासियों के प्रति महान ﴾5﴿ सोवियत राष्ट्र के लोगों का मैत्रीपूर्ण भावनाओं का प्रतीक मानता हूँ, आभार प्रकट कर सकता हूँ और फिर कह सकता हूँ कि आपके देश की / यात्रा करने, आपके देशवासियों से मिलने और आपकी कुछ विलक्षण सफलताओं को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ । ﴾520 शब्द﴿

अभ्यास-75

उद्योग मन्त्री का यह प्रस्ताव प्रशंसनीय तथा स्वागत योग्य है कि पूरा नवम्बर माह लघु-उद्योगों के लिए क्वालिटी माह के रूप में मनाया जाए । / दूसरे शब्दों में नवम्बर माह में हर लघु उद्योगी जीव अपने उद्योग की क्वालिटी अर्थात गुणों में सुधार करे । इसका अर्थ यह हुआ कि बाकी // साल भर जैसा चलता है चलने दें । ठीक जैसे पुलिस वालों के लिए शिष्टता सप्ताह और बस कंडक्टरों के लिए नम्रता सप्ताह होता है । ///

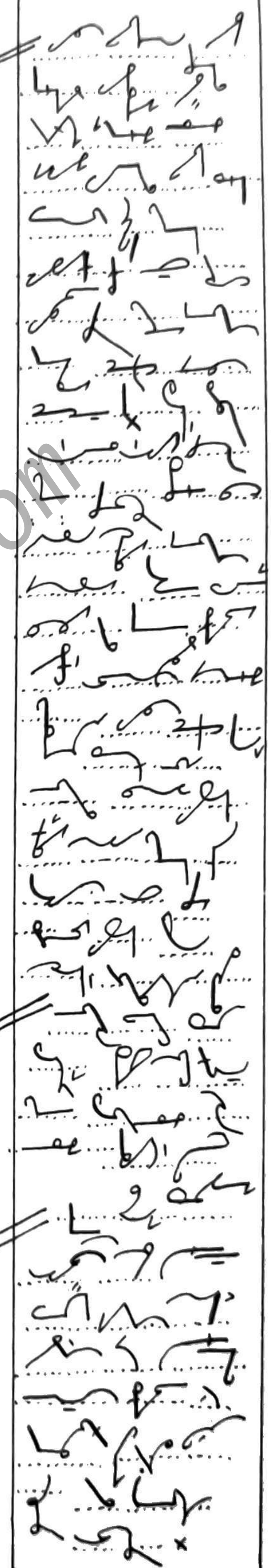

www.StenoIQ.com

लघु-उद्योग बड़ा नम्र-सा शब्द है । वे लोग जो इसमें लगी पूँजी और लाभ के विषय में नहीं जानते, इसे कुटीर उद्योग समझ कर §1§ बड़ी सहानुभूति से देखते हैं । प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का कहना है कि लघु-उद्योगों के कारण देश के करोड़ों लोगों का जीवन-स्तर / उठा है । लघु उद्योगपतियों का जीवन-स्तर तो निश्चित उठा है, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ । भारत में जीवन-स्तर उठने का अर्थ // होता है अपना बंगला, अपनी कार, घर में प्रत्येक सुख-सुविधा के साधन, दारू की पार्टी देने तथा कभी-कभी विदेश जाने की क्षमता । /// इस हद तक तो बहुतेरों का जीवन-स्तर उठ चुका है । पर ऐसा जीवन-स्तर बिना दो नम्बर के पैसे के नहीं उठता । लघु-उद्योगों §2§ का इस मामले में शानदार योगदान रहा है, इसमें सन्देह नहीं । लाइसेंस में गड़बड़ी, कर्ज़ का दुरूपयोग, उत्पादन का काले-बाज़ार में बिक्री, सेल्सटैक्स, / एक्साइज़, इनकम-टैक्स की चोरी, खातों में गड़बड़ और बैंक की ऋण सुविधाओं ने इतना दो नम्बर का रूपया पैदा कर दिया है कि और // किसी का नहीं तो लघु उद्योगपतियों का जीवन-स्तर तो उठ ही गया । इस तरह का काला-धन और व्यर्थ का धन बढ़ता रहा तो इसमें /// सन्देह नहीं कि उनका जीवन-स्तर उठता रहेगा ।

अब तय यह हो रहा है कि लघु-उद्योगों को क्वालिटी इंस्पेक्टरों से मुक्ति दी जाए क्योंकि §3§ इन इंस्पेक्टरों की खुद की क्वालिटी काफी गिर चुकी है । पर इन इंस्पेक्टरों को हटाकर कितना गुणात्मक सुधार होगा, यह कहना कठिन है । लेकिन / यह समझ में नहीं आता कि ये लघु-उद्योग कब तक लघु बने रहेंगे । इन लघु-उद्योगों के मालिक बड़े उद्योगपति बन चुके हैं लेकिन // उनके उद्योग लघु ही है । लघु-उद्योगों कहलाने के कारण इन उद्योगपतियों को कई तरह की रियायतें मिलती हैं तथा सरकार से अनुदान /// प्राप्त होता है । अब जब ये उद्योग लघु नहीं रहे, इनमें जितनी पूँजी लगी हुई है, उसके हिसाब से इन्हे लघु उद्योग की §4§ संज्ञा न देकर मध्यम उद्योग कहना ही अधिक उचित होगा । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अब समय आ गया है जब कि सरकार / उद्योगों का पुनः वर्गीकरण करें तथा उद्योगों के दो नहीं तीन वर्ग घोषित करे भारी उद्योग, मध्यम उद्योग तथा लघु या कुटीर उद्योग । उद्योगों // को तीन वर्गो में विभाजित करने के साथ-साथ यह भी निश्चित करना चाहिए कि किस वर्ग के उद्योग के लिए कितनी पूँजी लगाई /// जा सकती है तथा उद्योगपति इसका भी ख्याल रखें कि लघु अथवा कुटीर उद्योग को लगाने के लिए जापान की भाँति लाइसेंस की आवश्यकता न हो §5§ तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार इन उद्योगों की पूरी-पूरी सहायता करें । §515 शब्द§

शोकसंतप्त	शब्दनिर्माता	प्रश्नचिन्ह
लाठीचार्ज़	देशव्यापी	नम्रतापूर्ण
अश्रुगैस	सरकारीकरण	नम्रनिवेदन

120 श० प्र० मि० अभ्यास

www.StenoIQ.com

अभ्यास-76

मननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह बड़े पैमाने पर सारे विश्व में फैला हुआ है । राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी जड़ें शहर-शहर में और देश के/कोने-कोने में फैली हुई हैं । मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को दूसरे पहलू से और दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए । आखिर तस्कर व्यापार क्यों होता है । उसके पीछे // सबसे बड़ी मनोवृत्ति अधिक से अधिक धन कमाने की है । हमारे देश में अभी तक इस बात की पूरी चेष्टा नहीं की गई है कि हम परिश्रम करके कमाएं /// पसीना बहा कर जीविकोपार्जन करें । अभी तक हमने मेहनतकश लोगों को, परिश्रमी लोगों को, कमा कर लाने वाले लोगों को उतना सम्मान नहीं दिया है जिसके कि वे]1[पूर्ण अधिकारी है । यही वजह है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो केवल हेराफेरी से, तस्करी से, चोरी से, डाकेज़नी से और गलत काम करके / धन पैदा कर रहे हैं । हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि ऐसे लोगों की भर्त्सना कर सकें, ऐसे लोगों को सम्मान न दें और ऐसे लोगों को // सिंहासन न दें । हमारे देश में धन की पूजा होती है, पैसे की पूजा होती है । इसलिए जो भी इधर-उधर से, हेरा-फेरी से, चोरी से अथवा तस्करी से धन /// इकट्ठा करके अमीर हो जाता है, उसको हमारे समाज में सम्मान भी मिलता है । यही कारण है कि इन कामों को करने की लोगों में हिम्मत बढ़ती है और लोग]2[तस्कर व्यापार में और ज्यादा उलझते जाते हैं । इस तस्कर व्यापार के पीछे जो मुख्य मनोवृत्ति है वह अधिक से अधिक धन पैदा करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की / है । जब तक हम धन की प्रतिष्ठा करेंगे तब तक हम तस्कर व्यापार को रोक नहीं सकेंगे और यह दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहेगा ।

तस्कर व्यापार के पीछे जो दूसरी // महत्वपूर्ण मनोवृत्ति है वह है हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का बढ़ता हुआ प्रयोग । आज प्रत्येक भारतवासी अधिक से अधिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है और उनको ऊंचे दामों पर /// खरीदता है । इससे भी तस्करी को बढ़ावा मिलता है । अगर हम भारतवासी यह प्रण ले लें कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं तो समस्या]3[काफी सुधर सकती है क्योंकि जब विदेशी वस्तुएं बिकेंगी ही नहीं तो फिर उनकी तस्करी क्यों होगी । अतः यह सब हम लोगों के मनोबल पर निर्भर करता है । हम अगर / दिल से चाहें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके तस्करी का उन्मूलन कर सकते हैं । लेकिन इसके लिए ऐसे मनोबल की आवश्यकता है जो केवल महात्मा गांधी में था । //

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं दो तीन बातें और स्पष्ट करना चाहता हूँ । आज देश में सोने का आयात बढ़ रहा है और चांदी का निर्यात भी देश /// में बढ़ रहा है । हमारे देश के किसानों ने मेहनत करके अच्छी कमाई की है । मेरा निवेदन है कि]4[मेरी बात ध्यान से सुनी जाए । मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उस बात से चौधरी साहब नाराज़ न हों । किसान भाइयों ने पिछले दस पन्द्रह सालों में खूब / सोना खरीदा है । उनके अन्दर सोना खरीदने की आदत बैठी हुई है और वे निरन्तर सोना खरीद रहे हैं ।

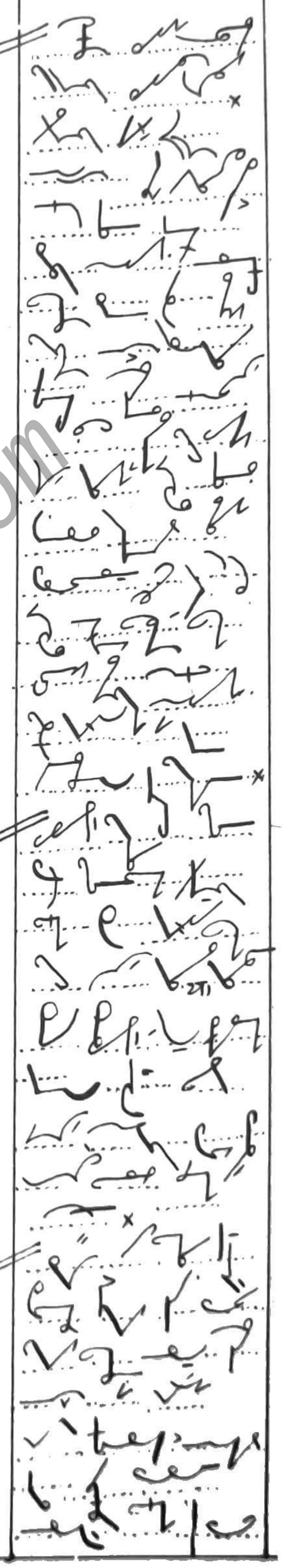

www.StenoIQ.com

इसका परिणाम वही तस्करी व्यापार को बढ़ावा देना है क्योंकि // दूसरे देशों में सोना सस्ता है और इसलिए सोना बाहर से स्मगल होकर आता है और अब भी आ रहा है । हमारे देश में उनको सोने का भाव काफी अच्छा /// मिलता है । अतः आज किसानों की यह हालत है कि वे अपने उत्पादन की कमाई से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में न पढ़ा कर और अपने जीवन-स्तर {5} को उपर न उठा कर निरंतर सोना खरीद रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप सोने के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं । {620 शब्द}

अभ्यास-77

उपाध्यक्ष महोदय स्कूलों को खुले दो महीने से उपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर छात्रों के पास किताबें नहीं हैं । छोटे कस्बों और देहातों में पाठ्य पुस्तकों का / अकाल पड़ा हुआ है । छात्र और उनके अभिभावक पाठ्य पुस्तकों की तलाश में जहां-तहां भटक रहे हैं । इन पाठ्य पुस्तकों की कमी केवल इसी वर्ष नहीं हुई, प्रत्येक वर्ष // यही परेशानी सामने आती है । बड़े-बड़े शहरों में स्कूली किताबों की कमी इतनी नहीं है जितनी कि छोटे-छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में । जैसा कि आप जानते हैं /// पहली से लेकर सातवीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें सरकार ही छापती हैं और सरकार ही उन्हें बेचती हैं । पाठ्य पुस्तकें के इस सरकारीकरण का कुछ फायदा होना चाहिए था {1} उन्हें समय पर और सस्तें दामों पर सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए था । मगर नौकरशाही का अभिशाप इन पाठ्य-पुस्तकों को भी झेलना पड़ रहा है और सरकारी दुकानों / पर अक्सर पाठ्य पुस्तकें सरकारी डिपों से साढ़े सात फीसदी कमीशन पर मिलती हैं । भ्रष्टाचार का // बोलबाला यहीं से शुरू हो जाता है ।

पाठ्य-पुस्तकों के अकाल के कारण खुदरा दुकानदार अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सरकारी डिपों से किताबें पाने में जी जान /// लगा देते हैं । पाठ्य-पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकारी डिपों चलाने वाले लोग साढ़े सात फीसदी कमीशन अपनी जेब में रख लेते हैं और खुदरा {2} दुकानदार को पूरी कि पूरी छपी कीमत अदा करनी पड़ती है । इसकी कमी पूरी करने के लिए वे अभिभावक से किताब की उंची कीमत वसूल करता है । यह उंची कीमत इस / बात पर निर्भर करती है कि अभिभावक उस किताब को पाने के लिए कितना देने को तैयार हैं ।

पाठ्य-पुस्तकों की इस कालाबाज़ारी में बहुत से लोगों के निहित // स्वार्थ पनप रहे हैं । इस कालाबाज़ारी को आसान बनाने के लिए और अभिभावकों को ऐतराज भी न हो, पाठ्य-पुस्तकों की पूर्ति में बनावटी कमी की जाती है । यह सिलसिला छपाई /// के दौरान ही शुरू हो जाता है । इस साल का उदाहरण है, कई पाठ्य-पुस्तकें तो अभी तक छप कर सरकारी डिपों पर ही नहीं आईं ।

परिणामस्वरूप ... निबेशक ... रहस्यपूर्ण

आठवीं, नवीं और दसवीं कक्षाओं के लिए {3} पाठ्य-पुस्तकों की छपाई का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। / इन कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत और भी ज्यादा होती है। इसलिए कालाबाज़ारी की गुंजाइश इतनी ही ज्यादा / होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अपना छापाखाना नहीं है। इसलिए वह किताबों को निजी प्रकाशक के यहां छपवाता है। किताबों की छपाई मुनाफे का धंधा है इसलिए // प्रकाशक यह काम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसकी वजह से अफसरों की चांदी होती है और प्रकाशक चुनने के मामले में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके खूब /// पैसा कमाते हैं। यही नहीं, जब प्रकाशकों को बोर्ड के कर्मचारियों की जेब गरम करनी पड़ती है तब वे किताब छपाई के लिए मिले आदेश से अधिक संख्या में किताबें {4} छाप लेते हैं। इसके बाद वह बोर्ड की किताब सौंपने में देर करता जाता है। इस बीच वह बोर्ड के अधिकारियों की मिली-भगत से छापी गई अतिरिक्त किताबों / को बाज़ार में भेज देता है। ये किताबें तुरन्त बिक जाती हैं, और इनके बिकने के बाद ही बोर्ड के दफ्फतर में उसके आदेश के अनुसार छपी किताबें अन्त में बिकती हैं जिससे प्रकाशकों को बहुत फायदा होता है। इससे साफ ज़ाहिर है कि इसमें किस /// तरह के निहित स्वार्थ पनपे हुए हैं। जब तक ये निजी स्वार्थ पनपेंगे तब तक लोगों को अपने बच्चों के लिए न तो उचित दामों पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी {5} और न पुस्तकें आसानी से मिल सकेंगी। {605 शब्द}

अभ्यास-78

आदरणीय सदस्यों, देश की चुनाव प्रणाली का उपयोगी होना स्वच्छ चुनाव पद्धति पर निर्भर करता है और देश के मतदाताओं का यह विश्वास है कि जब तक चुनाव-प्रणाली में / महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया जाता, मतपेटियों द्वारा किया गया निर्णय विश्वसनीय नहीं होगा। आपको याद होगा राष्ट्रपति ने जनवरी, 1985 में संसद का उद्घाटन करते हुए सरकार द्वारा इस // दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने का वचन दिया था। परन्तु इस दिशा में बहुत कम और धीमा कार्य किया गया है। चुनाव में मतपेटियों का बदला जाना, /// चुनाव-बूथों पर कब्ज़ा करना तथा गुण्डागर्दी और काले धन का उपयोग कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोगों में चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता से विश्वास उठता जा रहा है। {1}

पिछले चार दशकों के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल एक व्यक्ति का आयोग चुनाव के कार्यभार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा सुझाव है / कि प्रधान-मंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश और विपक्ष की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए तीन-व्यक्तिय आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस आयोग के // सदस्यों का वेतन, शिक्षा और नियुक्ति की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होनी चाहिए। अवकाश प्राप्त करने पर आयोग के सदस्यों की सरकारी नौकरी पर रोक /// लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार आयोग पूरे समय के लिए ऐसे क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की

नियुक्ति करें जो अपने-अपने क्षेत्रों में निष्पक्ष चुनाव कराएं तथा उनकी देखभाल करें । {2} इन क्षेत्रीय आयुक्तों का राज्य तथा केन्द्र की सरकारों से कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए । उनका वेतन, स्तर और शिक्षा आदि उच्चतम न्यायालय के जजों के बराबर होना चाहिए । चुनाव आयोग को ऐसे न्यायिक अधिकार भी दिए जाने चाहिए जिनके अन्तर्गत वह उन लोगों पर मुकदमा चला सकें जो चुनाव के अवसर पर कानून तोड़ते हैं अथवा जो // चुनाव-बूथों पर कब्ज़ा करते हैं और उसके पास मारपीट करते हैं । ऐसे व्यक्तियों को ऐसा अपराधी घोषित किया जाए जिन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। किसी दूसरे /// आदमी के नाम से मत डालने से लोगों को रोकने के लिए हमारा सुझाव है कि प्रत्येक मतदाता को परिचय-पत्र जारी किया जाए । कम्पूटर-प्रणाली के प्रयोग से {3} एक मतदाता को एक विशेष स्थायी नम्बर दिया जाना चाहिए । इससे मतदाताओं की सूची तैयार करने में भी सुगमता होगी ।

चुनाव राष्ट्रीय एकता का अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है । दूरदर्शन और आकाशवाणी का निष्पक्ष प्रयोग मतदाताओं के विचार को सही रूप से सामने लाने और उपयोगी सरकार का चुनाव करने में अत्यधिक सहायक होगा । परन्तु दुर्भाग्यवश दूरदर्शन और // आकाशवाणी को इस सम्बन्ध में बिलकुल निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता ।

केन्द्र में तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दल चुनाव के दिनों में अनुचित लाभ उठाते हैं । हमारा सुझाव है कि /// चुनाव आयोग को सरकारी हवाई जहाज़, कार, डाक बंगला तथा अन्य सुविधाओं को उपयोग में लाने के सम्बन्ध में नियम बनाने चाहिए तथा उन नियमों का कड़ाई के साथ {4} पालन होना चाहिए । मैं यह तो नहीं कहता कि चुनाव के दिनों में सारे भारत में सीधा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि यह न तो सम्भव है और न ही / उचित । लेकिन इस अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कार्यवाहक सरकार की तरह कार्य करना चाहिए । इसमें कोई नया कानून बनाने, नई नीति की घोषणा, आर्थिक सहायता तथा सत्तारूढ़ दल को // अन्य प्रकार की सहायता देने से रोका जा सकता है ।

चुनाव-प्रणाली में पैसे के दुरूपयोग की भूमिका से सभी परिचित हैं । इस सम्बन्ध में आवश्यक सुरक्षा मापदण्डों के अभाव में /// हमारे समाज का समस्त राजनैतिक तथा आर्थिक ढांचा बिगड़ गया है । अतः मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग को सभी राजनैतिक दलों तथा अन्य लोगों से विचार-विमर्श कर इसके {5} कुप्रभाव को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए जिनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए । कुछ दिनों पूर्व हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि / चुनाव खर्च राज्यों द्वारा किया जाए । इस सिफारिश को भी माना जाना चाहिए । {643 शब्द}

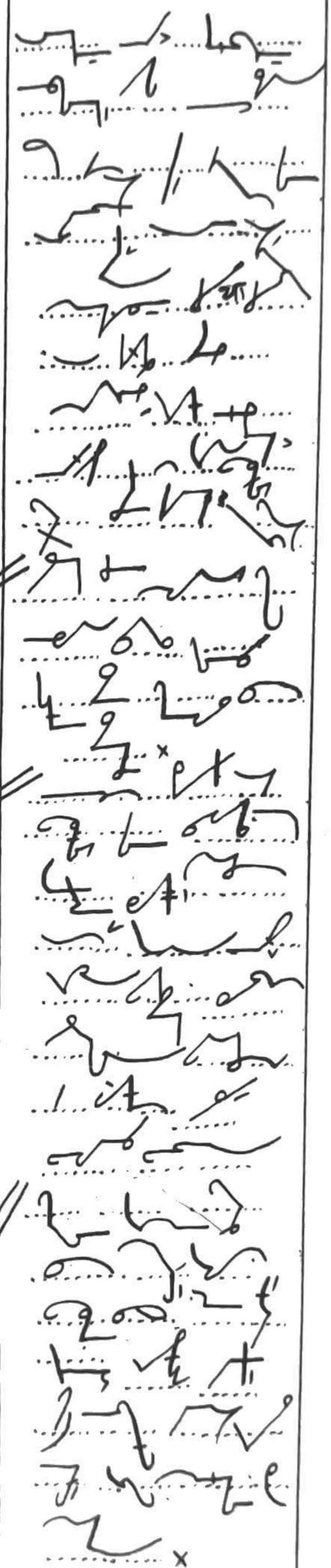

मुनाफाखोर बढोतरी मैत्रीपूर्ण
मुनाफाखोरी मुक्कदर भयभीत

www.StenoIQ.com

अभ्यास-79

महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने देश के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में काफी प्रगति की है । उदाहरण के लिए देश से प्लेग और चेचक का पूरी / तरह से सफाया हो चुका है, हैजे पर काफी सफलता हासिल हो चुकी है । इन // महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद देश में जन-स्वास्थ्य की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है ।

सातवीं योजना में इस बात को नोट किया गया है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं ///को असंतोषजनक अन्तरक्षेत्रीय समन्वय एवं सहयोग के कारण काफी चोट पहुँची है । यही कारण है कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग भी स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम ज़रूरतों {1} से वंचित है । दूसरे शब्दों में अभी भी भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं है । देश की स्वास्थ्य विकास सम्बन्धी नीति बनाते हुए इस बात पर ज़ोर दिया / गया था तथा सिफारिश की गई थी कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता, पोषण, साफ तथा सुरक्षित जल की सप्लाई तथा आवास जैसे पहलुओं को शामिल // किया जाए ।

देश के नियोजित विकास के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढाँचे का काफी विस्तार हुआ । अब तक स्वास्थ्य के उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों और औषधालयों /// की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है । यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि देश में अस्पतालों का काफी विस्तार हुआ है लेकिन बारीकी से {2} और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो यह विस्तार नगण्य दिखाई देता है । दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह संकेत भी / मिलता है कि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता नहीं मिलती । कुछ राज्यों में तो स्वास्थ्य सेवाएँ संतोषजनक कही जा सकती हैं लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े हुए राज्य // भी हैं जिन में स्वास्थ्य सेवाओं का बिलकुल अभाव बना हुआ है अतः इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी असमानता बनी हुई है । उदाहरण के लिए /// इस मामले में पंजाब का स्थान सर्वोच्च है जहाँ प्रति एक लाख आबादी के लिए 128 डॉक्टर हैं जबकि मध्यप्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है जहाँ पर एक लाख {3} लोगों के पीछे केवल 8 डॉक्टर हैं ।

भारत सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के विश्वव्यापी लक्ष्य में भागीदार है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य / रक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति की मुख्य कुंजी है । इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य ध्येय स्वास्थ्य कार्यक्रम का // विस्तार और पोषण, स्वच्छ पेयजल की सप्लाई, आवास, शिक्षा तथा समाज कल्याण से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है जिसमें से प्रथम दो तो प्राथमिक स्वास्थ्य /// रक्षा का ही अंग है । सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर-घर तक ले जाना

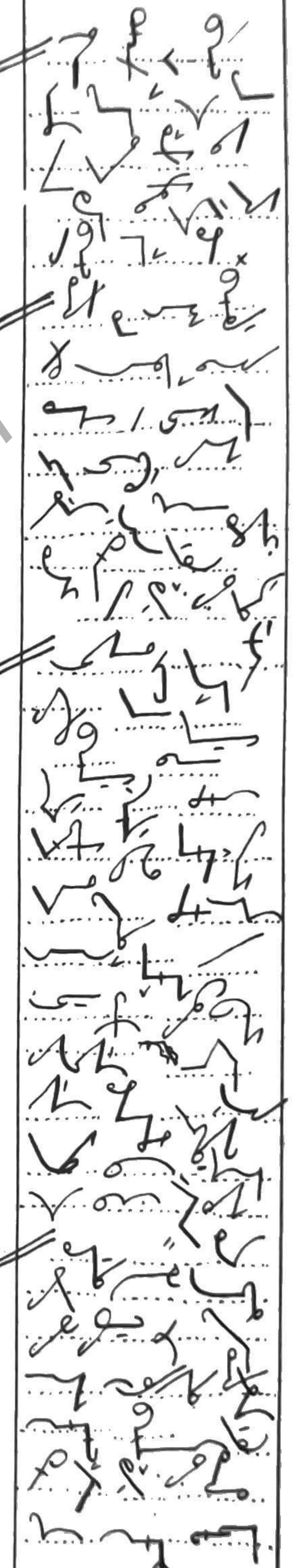

www.StenoIQ.com

है । लेकिन पोषण सम्बन्धी किए गए §4§ एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि देश में 50 प्रतिशत परिवारों के भोजन के कैलोरी तथा प्रोटीन दोनों की बहुत कमी होती है । इससे साफ ज़ाहिर है कि / देश का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण और अल्पपोषण का शिकार है और यही एक ऐसा पहलू है जो "सभी के लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य में बाधक है । अतः आवश्यकता // इस बात की है कि सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर अच्छा भोजन मिले । जब भोजन ठीक मिलेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बीमारियाँ उससे दूर भागेगीं और /// इस प्रकार उसे न तो किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी दवाई की । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि नए-नए अस्पताल खोलने के साथ-साथ §5§ इस बात का प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि लोगों को खाने को अच्छा भोजन मिले जिसमें मिलावट बिल्कुल न हो । §620 शब्द§

अभ्यास-80

उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार कर लिया है तथा अगले सप्ताह आयोग की पूरी बैठक में उसे मंजूर किए जाने की आशा है । प्रधानमंत्री / इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार योजना को अन्तिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक अक्तूबर के अन्त में बुलाने का प्रस्ताव है । // आयोग के उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी नहीं होगी । इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों /// और सरकारी उद्यमों को अतिरिक्त साधन जुटाने का अपना लक्ष्य पूरा करना होगा । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में बचतों में वृद्धि का लक्ष्य 24.5 प्रतिशत रखा गया है, जो §1§ मेरे विचार में ज्यादा नहीं है । बचतों का अब तक का अनुमान 23.3 प्रतिशत रहा है ।

सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 180 हज़ार करोड़ / रूपए की धनराशि की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । देश के पास साधन हैं, जिसे केवल एकत्र करने की ज़रूरत है । इस मामले में सरकारी उद्यमों को अपनी // ज़िम्मेदारी विशेष रूप से निभानी होगी, क्योंकि अधिकतर कठिनाई उनके बारे में ही है । खनिज तेल के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को भी पूरा करना होगा /// इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़ेगा । सरकारी उद्यमों की कीमत नीति पर भी विचार करने की आवश्यकता है । उनमें तैयार माल की कीमत बढ़ाने से उद्यम आर्थिक तौर पर §2§ लाभप्रद बन सकते हैं ।

सातवीं योजना के मसविदे में वित्तीय साधन जुटाने के लिए 13000 करोड़ रूपये घाटे की व्यवस्था से उपलब्ध किए जायेंगे । विदेशी मदद आदि के ज़रिए / लगभग 20,000 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा सकेगी । करों के जरिए योजना के कुल पूंजी निवेश का 48 प्रतिशत भाग एकत्र किया जा सकता है । मेरा // सुझाव है कि

www.StenoIQ.com

सरकार यदि यह कार्य करों में कमी के ज़रिए पूरा कर सकती है तो इसमें किसी को विरोध नहीं होगा । किन्तु करों में कहां तक कमी की जा /// सकती है इस पर आज की स्थिति में गम्भीरता से विचार करने की ज़रूरत है । आयोग ने करों की वसूली में वृद्धि, उत्पादकता में बढ़ौतरी, निर्यात में विस्तार, सरकारी {3} उद्यमों के लिए एक तर्कसंगत कीमत नीति के निर्धारण, सरकारी खर्च पर कड़ा नियन्त्रण, बचत को बढ़ावा तथा ग्रामीण क्षेत्र में साधन जुटाने की सलाह दी है । इन / उपायों से वित्तीय साधनों की समस्या पूरी तरह से हल की जा सकती है ।

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की सलाह पर आयोग ने साधनों के बटवारे पर गम्भीरता से / विचार किया है किन्तु उसमें ज्यादा परिवर्तन सम्भव नहीं है । आयोग की अगली बैठक में सम्पूर्ण स्थिति प्रधान मंत्री के विचार के लिए पेश की जाएगी मेरे विचार में /// उपलब्ध साधनों तथा अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को लक्ष्य में रखते हुए साधनों का बटवारा किया गया है, उसमें अब परिवर्तन योजना के हित में नहीं होगा । साधन {4} सीमित हैं और मन्त्रालयों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना कठिन है ।

चालू वित्तीय वर्ष सातवीं योजना का पहला वर्ष है । आयोग को आशा है कि इस वर्ष / में विकास के जो लक्ष्य तय किए गए हैं वे केन्द्र तथा राज्यों में काफी हद तक पूरे हो सकेंगे । इस वर्ष योजना का आकार छोटा रखा गया है किन्तु // 1986-87 की योजना बड़ी होगी ।

विदेशी मुद्रा की समस्या अगले दो वर्षों में कठिन होने की सम्भावना नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के ऋणों का भुगतान अगले वर्ष से /// शुरू होगा । किन्तु इसमें भारत के भुगतान सन्तुलन पर बुरा असर पड़ने की कोई आशंका नहीं है । यदि निर्यात में अपेक्षित वृद्धि की जा सकी तो बाद के वर्षों में भी {5} स्थिति नियन्त्रित रहेगी । इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि देश में खनिज तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए । इस दृष्टि से तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रमों / को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है । {638 शब्द}

अभ्यास-81

महोदय, नई दिल्ली में हुई लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को विदेश नीति की दृष्टि से निश्चित रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है । आश्चर्य है कि / राजधानी के समाचार पत्रों ने इसे अनदेखा कर दिया । कुछ समाचार-पत्रों ने तो लोक दल सम्बन्धी समाचार ही नहीं दिया और जिन्होंने दिया, उन्होंने विदेश नीति के बारे में // पार्टी की नई नीति का उल्लेख नहीं किया । लोकदल एकमात्र गैर-कम्युनिस्ट प्रमुख विपक्षी दल है जिसने /// खुलकर अमेरिकी नीतियों पर प्रहार किया है । इस विदेश नीति का

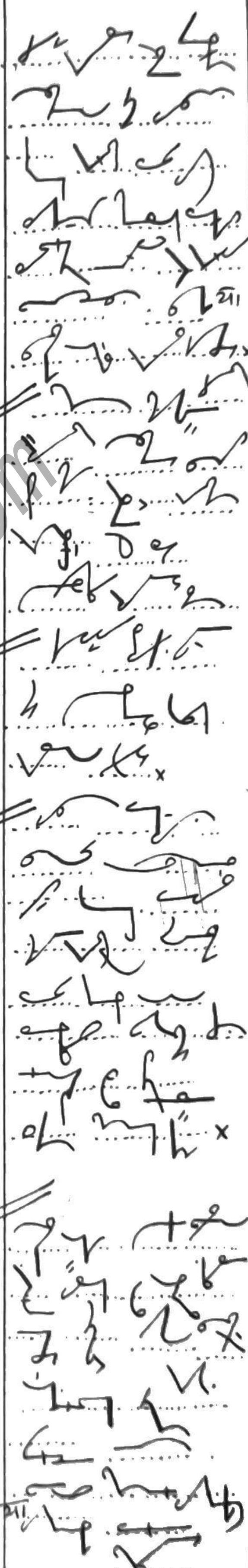

www.StenoIQ.com

एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि लोकदल विदेश नीति की मुख्य धारा में आकर असली गुट-निरपेक्षता (1) के प्रचारकों से स्पष्ट रूप में अलग हो गया है ।

लोकदल के प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत-सोवियत मैत्री दोनों देशों की सुरक्षा और स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व-शान्ति के लिए भी आवश्यक है । राष्ट्रीय सहमति पर आधारित भारत-सोवियत सम्बन्धों को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए । आज की राजनीतिक परिस्थितियों में भारत-सोवियत मैत्री // को सुदृढ़ करना ऐतिहासिक आवश्यकता हो गई है क्योंकि रूस हमारा पड़ोसी ही नहीं हमारा हितकारी भी है । भारतीय विदेश नीति के निर्धारक कभी-कभी सोवियत संघ और अमेरिका को /// महाशक्ति बताकर समकक्ष रखने की मूर्खता करते हैं । निस्सन्देह इस तरह के प्रयासों से सिर्फ अमेरिका के विस्तारवादी इरादों को प्रोत्साहन मिलता है इस तरह लोकदल ने (2) सोवियत संघ और अमेरिका को एक ही तराजू में तौलने की नीति का विरोध किया है ।

लोकदल का मानना है कि हिन्द महासागर में अमेरिकी सैनिक उपस्थिति के कारण भारतीय / उप-महाद्वीप क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक हो गई है । अमेरिका, पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है यह जानते हुए भी कि ये हथियार आखिर भारत के // विरूद्ध ही इस्तेमाल किए जाएंगे । इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है । यही नहीं 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत ने भारत के विरूद्ध परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल का भी विचार किया था ।

उत्तर भारत का एक प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण लोकदल साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरूद्ध संघर्ष का पूर्ण समर्थन (3) करता है । अभी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा ही यह समर्थन व्यक्त किया जाता रहा है । यहाँ भी लोकदल की विदेश नीति / में एक नए तत्व का प्रवेश दृष्टिगोचर होता है । साम्राज्यवाद, उपनिवेदशवाद और नस्लवाद के विरूद्ध संघर्ष भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष की विरासत है । लोकदल ने नाभिकीय अस्त्रों के // प्रसार और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए इस बारे में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की घोषणाओं का स्वागत किया है । प्रस्ताव में आगे कहा /// गया है कि नाभिकीय और अन्य प्रकार के अस्त्रों की अंधाधुंध होड़, अन्तरिक्ष युद्ध योजना और रासायनिक युद्ध की तैयारी से विश्व-शांति को खतरा पैदा हो गया है । (4) इसका एकमात्र समाधान है पूर्ण निःरस्त्रीकरण । आज की दुनिया में कोई भी राजनीतिक पार्टी घरेलू मामलों तक अपने को सीमित नहीं रख सकती । अतः भारत को अमेरिका और सोवियत / संघ के प्रति स्पष्ट नीति स्वीकार करनी ही होगी और गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा कि क्या अमेरिका हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा तो नहीं और क्या सोवियत संघ // से इन हितों की रक्षा होती है । अगर किसी देश में भारत को खतरा है तो उस देश से मित्रता करने का कोई लाभ नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ ही साथ // उससे शत्रुता रखना भी ठीक नहीं । अतः मेरा निवेदन यह है कि भारत को चाहिए कि रूस से मित्रता रखने के साथ-साथ अमेरिका को अपना शत्रु न समझे और (5) उसके साथ भी

मित्रता का व्यवहार करता रहे । एक दिन अमेरिका स्वयं महसूस करेगा कि भारत की स्थिति क्या है और वह क्या चाहता है । ‖625 शब्द‖

अभ्यास-82

महोदय, आज की सबसे विकट समस्या है-देश की बढ़ती हुई आबादी / आज हिन्दुस्तान की आबादी इस सीमा तक बढ़ती जा रही है इसे देखते हुए ऐसा लगता है / कि आगे आने वाले कुछ वर्षों के बाद हिन्दुस्तान में सभी प्रकार की वस्तुओं की कमी हो जाएगी । अभी भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत वर्ष में कई // समस्याएं ऐसी उभर कर आ रही हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है और सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या होगा । इस बढ़ती हुई जनसंख्या का बढ़ती हुई मंहगाई /// से चोली दामन का साथ है । अतः इसे रोकना हम सबका कर्त्तव्य ही नहीं, धर्म भी है ।

परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के सिलसिले में नई स्कीमों की खबरें इधर ‖1‖ लगातार आ रही हैं । दो या एक बच्चे वाले दम्पत्तियों को देश का सम्मानित नागरिक घोषित करने की योजना है । दूसरी योजना यह है कि लड़कियों के विवाह की उम्र / अठारह से बढ़ाकर बीस साल की जाए । एक सुझाव यह भी है कि दसवीं कक्षा के बाद लड़के-लड़कियों को अनिवार्य रूप से परिवार-नियोजन के लाभों के बारे में // बताया जाए । परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार को तेज़ करने के लिए नए नारे और नये पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं ।

जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरजेंसी के दौरान /// परिवार नियोजन कार्यक्रमों को निश्चय ही धक्का लगा था । कुछ महीने पहले योजना आयोग ने परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों का जो सर्वेक्षण किया था, उससे नतीजा यह निकला कि ‖2‖ नसबन्दी जैसे कार्यक्रमों से हिन्दुस्तान में बात बनने वाली नहीं है । कुछ विशेषज्ञों की राय तो यह भी है कि परिवार नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि तय न की जाए । ऐसा करने से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक हो सकती है । इससे सरकारी एजेंसियां निर्धारित आंकड़े प्राप्त करने की जल्दबाज़ी में // परिवार नियोजन के वास्तविक लक्ष्यों को गंवा देती हैं । लक्ष्य तो दरअसल यह है कि जनसंख्या में ज़रूरत से ज्यादा बढ़ोतरी न हो और इसके साथ-साथ दम्पति और /// बच्चे स्वस्थ रहें । कई विशेषज्ञों के मतानुसार परिवार नियोजन की कई प्रचलित विधियां स्वास्थ्य की गारंटी नहीं देती । ये विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में गुजरात का उदाहरण देते हैं, जहां परिवार नियोजन के ‖3‖ निर्धारित लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए गए हैं, पर वे जिस कीमत पर प्राप्त किए गए हैं उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । अर्थात् परिवार नियोजन की विधियों के / गुण-दोष पर उचित ध्यान नहीं दिया गया ।

भंडार भयंकर भाईभतीजावाद
भंडारन भयंकरता कालाबज़ारी

www.StenoIQ.com

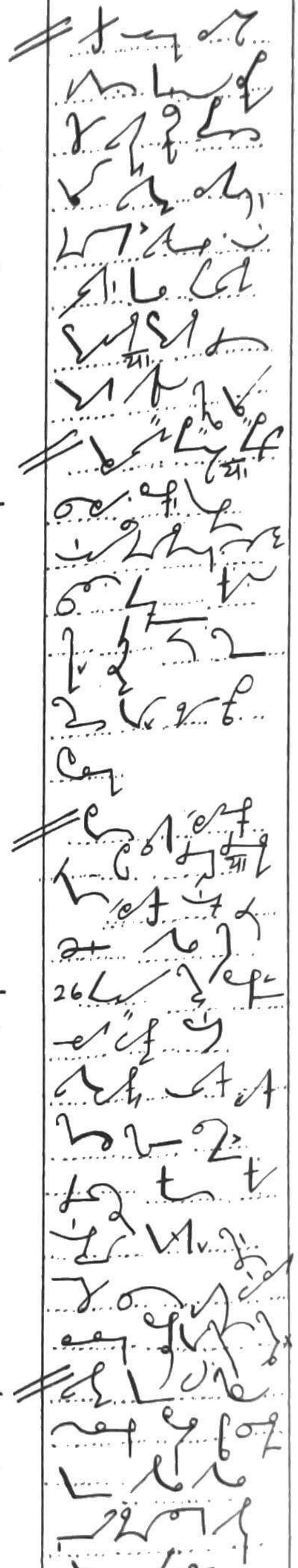

इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो नतीजा यही निकलता है कि परिवार नियोजन को अब केवल एक सरकारी आन्दोलन // के रूप में नहीं देखना चाहिए । उसे शिक्षा और समाज सुधार का आन्दोलन भी बनाना होगा । दरअसल सरकार भी यह चाहती है कि स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय की एक /// पहल यह भी है कि सरकारी एजेंसियों के बाहर के लोगों को भी इन कार्यक्रमों में और ज्यादा शामिल किया जाए । यह ठीक ही है । नहीं तो केवल कानून बना {4} देने से, नई रियायतें देने से भी काम चलने वाला नहीं है । बाल-विवाह के सम्बन्ध में कानून बनाने के बावजूद भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में / आज भी यह कुरीति प्रचलित है, वर्तमान कानून के बावजूद इसकी दर कम हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

अब सवाल यह है कि परिवार नियोजन एक सामाजिक // आन्दोलन कैसे बने । स्वयंसेवी संस्थाएं उसे अपनी सूची में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं मानतीं । अतः यह मान लिया गया है कि इस सिलसिले में जो कुछ करेगी /// सरकार ही करेगी । यह धारणा बनाने में सरकार ही उत्तरदायी है । आज ज़रूरत इस बात की है कि प्रत्येक परिवार और समाज का हर वर्ग परिवार नियोजन और परिवार कल्याण {5} को अपना कार्यक्रम माने तथा अपनी भलाई तथा देश के हित के लिए स्वेच्छा से उसे माने, तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है । {624 शब्द}

अभ्यास-83

सभापति महोदय, हिन्दी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 / के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है । यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 को प्राप्त हो गया और जहाँ तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिन्दी या अंग्रेज़ी में कार्य किया जाएगा । साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद ///अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी, 1965 से संसद में अंग्रेज़ी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा । किन्तु संसद ने {1} यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया । यह किन परिस्थितियों में / कैसे हुआ इस संबंध में यहां विस्तार से जाने का न तो अवसर है और न ही इसकी आवश्यकता क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं ।

यह स्पष्ट है // कि जब तक शासन और प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोग हिन्दी को दिल से स्वीकार नहीं करते तब तक हिन्दी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का /// गौरव नहीं मिल सकता । हिन्दी के द्वारा ही राष्ट्रीयता की भावना जाग सकती है । आज कांग्रेस की पहुंच जो जनता तक है वह मुख्य रूप से हिन्दी भाषा

www.StenoIQ.com

के {2} कारण ही है । पहले कांग्रेस में अंग्रेजी का ही ज़ोर रहता था तथा अंग्रेजों की वेशभूषा को ही पहना जाता था । लेकिन अब ऐसा नहीं है, तभी कांग्रेस का / नाम घर-घर में पहुँच चुका है । अब जब कि देश स्वतन्त्र है, हमारा अपना राज है तो फिर विदेशी भाषा का क्या काम ? अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना // बहुत हानिकारक है । अंग्रेजी में अपने घर काम करके आप स्वयं अपने मुँह से पुकारते है कि हम गुलाम हैं, गुलाम है । इस तरह से राष्ट्रीयता की आशा करना /// अपने देश पर गर्व होना व्यर्थ की बात है । राष्ट्रीयता फैलाने के लिए खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं, इससे बात नहीं बनेगी । इसके लिए तो हृदय {3} से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर अपने देश की वेशभूषा पर गर्व है ।

गांधी जी ने भाषा संबंधी एक टिप्पणी में कहा था-अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी । लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों गरीब जनता, भूख से पीड़ित जनता, करोड़ों // निरक्षरों का, निरक्षर बहनों और दलितों का हो और इन सब के लिए हो तो हिन्दी की एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है ।

गांधी जी का यह वक्तव्य मैंने इसलिए /// दिया है कि यह स्पष्ट हो कि आज़ादी के बाद आज राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है । संविधान की मर्यादाओं के अनुसार संसद सर्वोपरि है और 70 करोड़ जनता के {4} प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, जो सही मायने में देश की एकता, संवैधानिक प्रभुता और जनतन्त्र की आशा-आकांक्षा के प्रतीक है ।

संविधान द्वारा स्वीकृत 15 भाषाओं में से किसी / में भी संसद में बोलने का अधिकार किसी भी सदस्य को है और उसके भाषण का हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुवाद की व्यवस्था भी साथ-साथ की गई है // इस भांति संसद की पहल पर किसी प्रकार की रिपोर्ट, बिल, कागज़, टिप्पणी रखी जाएगी तो यह आवश्यक है कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी उसकी प्रतियां /// रखनी होगीं अन्यथा इसे संसदीय कार्य संहिता के प्रतिकूल माना जायेगा । लेकिन ये सारी की सारी बातें केवल एक श्रृंगार साधन मात्र बनकर रह गई हैं । सिद्धान्त और व्यवहार में यहाँ {5} पर वही फर्क है जो किसी देहाती मेले और दिल्ली के विशाल प्रगति मैदान में आयोजित मेले के बीच अन्तर होता है । {621 शब्द}

अभ्यास-84

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता से सम्बन्धित विधेयक लगभग तैयार हैं और सरकार बजट अधिवेशन के दौरान इसे संसद में पेश करना चाहती हैं । जानकार सूत्रों के अनुसार / मंत्रियों का एक दल इस विधेयक को अन्तिम रूप दे रहा है । इसमें विवाह, तलाक, गुज़ाराभत्ता, बच्चों को संरक्षण और उत्तराधिकार से सम्बन्धित निजी कानून को शामिल किया जाएगा। // नागरिकों को स्वच्छे से यह घोषणा करनी होगी

कि वे अपने ऊपर स्वैच्छिक समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए तैयार हैं । यह विधेयक केवल उन लोगों पर /// लागू होगा, जो नागरिक विवाह के लिए समान कानून के पक्ष में हैं । विधेयक में विशेष विवाह कानून 1954 को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है । जिन लोगों का विवाह (1) 1954 के इस कानून के तहत हुआ है, उत्तराधिकार के मामले में उन पर आज भी भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होता है ।

प्रस्तावित विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण / पहलू है गुज़ाराभत्ता । विधेयक की एक उपधारा में कहा गया है कि पत्नी को उसके पूरे जीवन काल तक पति से अलग रहते हुए भी उससे गुज़ारा-भत्ता // मिलेगा । पत्नी को अलग रहने का अधिकार ऐसी स्थिति में होगा जब पति ने उसे छोड़ दिया हो, उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया हो, पति को कोई खतरनाक /// बीमारी हो या अलग रहने का कोई अन्य उचित कारण हो । यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर, लड़के (2) अथवा लड़की से गुज़ाराभत्ता मिलेगा ।

सूत्रों के अनुसार विशेष विवाह का कानून 1954 के तहत हुए विवाहों को छोड़कर यह विधेयक लागू होने से पहले और बाद में हुए / अन्य किसी भी विवाह को इसी विश्लेषण के तहत पंजीकृत किया जा सकता है । वैवाहिक अधिकारों की बहाली और कानूनी तौर पर अलग रहने के अधिकार के लिए भी व्यापक // प्रावधान किए गए हैं । इस विधेयक के तहत विवाह करने वालों और उनकी संतानों और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के मामले में भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 लागू होगा । विधेयक में /// पत्नी के साथ-साथ वैध या अवैध संतानों के लिए भी पत्नी को भत्ते का भुगतान करने का प्रावधान है । बूढ़ों और अस्वस्थ माता-पिताओं को भी गुज़ाराभत्ता दिया जाएगा (3) गुज़ाराभत्ता की राशि निर्धारित करते समय कुछ बातों की ओर भी ध्यान रखा जाएगा । गुज़ारा-भत्तों का भुगतान करने वाले का आर्थिक और सामाजिक स्तर देखना पड़ेगा तथा वह गुज़ारा-भत्ता लेने वाले के उचित दावे के अनुसार होना चाहिए । /

विधेयक के अनुसार लड़के या अविवाहित लड़की का अभिभावक पिता होगा और उसके बाद माँ होगी । लेकिन // बारह साल से कम उम्र के बच्चों की अभिभावक समान्यतः माँ होगी । लेकिन अदालत संपति के मामले में अभिभावकों को ऐसा कोई काम करने की इज़ाजत नहीं देगी जो /// उनके नाबालिग बच्चों के हित में नहीं होगा । अदालत किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग का अभिभावक बनाते समय उस नाबालिग के कल्याण का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगी ।

इस विधेयक के (4) तहत विवाह प्रमाण-पुस्तिका भी रखी जाएगी और उसमें लिखे बयान दूसरी शादी की स्थिति में साक्षी माने जाएंगे । इस विधेयक के तहत बनाए जाने वाले कानूनों में विवाह / कराने वाले अधिकारी के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाएंगे । इसमें लिखा होगा कि अधिकारी किस ढंग से पूछताछ और जांच करेंगे, कितनी फीस वसूल

www.StenoIQ.com

www.StenoIQ.com Online Steno & Typing

की जाएगी, किस प्रकार // सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा इत्यादि-इत्यादि । मेरे विचार में यह विधेयक काफी असरदार सिद्ध होगा । आजकल बहुत-से झगड़े स्त्रियों को गुज़ाराभत्ता देने के सम्बन्ध में कई सालों से /// चलते आ रहे हैं तथा उनका निबटारा नहीं हो रहा । इस विधेयक के पास होने से तथा नागरिकों द्वारा इसे स्वेच्छा से स्वीकार करने पर तलाकशुदा अथवा पति से अलग (5) रहने वाली महिलाओं को गुज़ाराभत्ता शीघ्र मिलेगा । (607 शब्द)

अभ्यास-85

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में और बाहर भी इस बात पर काफी बहस हो चुकी है कि क्या कारण है कि कई देशों में आम-लोगों को इन्साफ जल्दी क्यों / मिल जाता है और भारत में इसके लिए इतनी देर क्यों लगती हैं । राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों और कानून मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन में कई // वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए जिनमें अधिकतर वक्ताओं के मतानुसार भारत में कानून दूर-दृष्टि से बनाए गए हैं । लेकिन खेद की बात है कि इन कानूनों का जैसा // अमल होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, खासकर औरतों के अधिकारों और छूआछूत और दहेज़ जैसी सामाजिक बुराईयों के कानून सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं । (1) गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की दिशा में भी बहुत काम नहीं हो पाया है ।

मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है जब हमें न्याय की / ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जो तेज़ हो, आसान और असरदार हो । इन्साफ दिलाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए अदालतों में करोड़ों के // दीवानी मुकदमें लटके हुए हैं । इस कारण गरीबी हटाने और अन्य विकास कार्यों में रूकावट पड़ रही हैं । मुझे पता चला है कि इस समय देश की विभिन्न अदालतों में /// सरकार को मिलने वाली दो हज़ार करोड़ रुपए की राशि मुकदमें बाज़ी के कारण फंसी हुई है । इससे गरीब लोग प्रभावित होते हैं न कि बड़े-बड़े उद्योगपति या एकाधिकार (2) वाले बड़े-बड़े घराने, जिनके पास लम्बे समय तक मुकदमें बाज़ी करने के लिए पर्याप्त पैसा है । इस तरह की देरी लोकतंत्री ढांचे को नुकसान पहुंचाती है- वह ढांचा जिससे पूरा / देश बंधा हुआ है ।

मेरे विचार में हर राज्य के लिए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, अलग से उच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए । साथ ही मुख्य न्यायालयों // में राज्य के बाहर से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार करने की जरूरत है । भविष्य में मुकदमें के निपटान में देर न हो, इस ओर ध्यान देना /// बहुत ज़रूरी है । विलम्ब के सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक बुलाई जाए तथा इस सम्बन्ध में उनकी सलाह ली जाए । सरकार न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के (3) लिए एक संस्थान का

Online Steno & Typing www.StenoIQ.com

गठन करें । इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए । कानून मंत्री का यह कथन भी स्वागत योग्य है कि हर स्तर पर / योग्य और कुशल न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए क्योंकि हमें देश में कानून की एक बहुत ही प्रभावशाली प्रणाली लागू करनी है ।

मेरा सुझाव है कि भारत में कोर्ट फीस या // तो कम कर दी जाए अथवा समाप्त कर दी जाए । मुकदमें में जीतने वाले लोगों पर एक टेक्स लगाया जा सकता है, इससे अदालतों की आमदनी बढ़ेगी । एक ऐसी /// व्यवस्था लागू की जाए जिससे विवादों पर अदालतों अथवा उनके बाहर तेज़ी से और कम खर्च पर फैंसला किया जा सके । लोक अदालतों का प्रयोग भी सफल रहा है । अतः इनके §4§ विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है । एक यह भी सुझाव है कि न्याय-अधिकारियों और सरकारी वकीलों के वेतनमान में वृद्वि और सेवा-शर्तो में व्यापक सुधार किया / जाए ताकि योग्य नवयुवक तथा नवयुवतियां इन सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित हों ।

न्यायलयों में सुनवाई की अवधि कम की जाए तथा फैंसले छोटे तथा तुरन्त हों । // सुप्रीम कोर्ट में केवल वही अपील मंजूर की जानी चाहिए, जिनमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो । इसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है । आर्थिक अपराधों के लिए /// विशेष अदालतें गठित की जानी चाहिए । एक अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा शुरू की जाए जिसके द्वारा योग्य व्यक्ति इस क्षेत्र में आएं और न्यायापालिका का सुधार हो । सरकार फौजदारी कानून §5§ और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करें, इससे कई कठिनाइयां दूर होंगी और इन्साफ आसान और असरदार बनाने में मदद मिलेगी । सरकार को फौजदारी मामलों की शीघ्र सुनवाई के / तरीकों पर भी सलाह मशविरा करना चाहिए । मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि सरकार चलती-फिरती अदालतों का गठन करें, जो गांव-गांव जाए । इससे देहात में मुकदमों की सुनवाई // में मदद मिलेगी । §663 शब्द§

अभ्यास-86

आदरणीय मंत्री जी, खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के अधिसंख्य सदस्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों पर असंतुष्ट हैं । समिति की एक बैठक बुलाई गई जिसमें / निगम के कामकाज और तौर-तरीकों पर गहन विचार किया गया । निगम के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे । खाद्य व अपूर्ति मंत्रालय के सांसद सलाहकार इस बात // पर विशेषतौर पर चिन्तित हैं कि इस बार रबी की अच्छी फसल होने के बावजूद, उस फसल के सम्भालने और जरूरत वाले क्षेत्रों को समय पर अनाज भेजने की /// और खाद्य निगम ने उचित ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि काफी मात्रा में अनाज के नष्ट होने से कुछ क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गई ।

www.StenoIQ.com

गेहूं की ढुलाई §1§ के बारे में खाद्य निगम की कोताही और लापरवाही की और रेल मंत्रालय ने भी इशारा किया है, जब उससे पंजाब सरकार ने अनुरोध किया कि गेहूँ की कमी वाले / राज्यों में भेजने पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि गेहूँ की कमी वाले / राज्यों में भेजने के लिए वेगन दिए जाएं । पंजाब में इस वर्ष गेहूँ की अच्छी फसल हुई है । रबी के अनाज की वसूली शुरु होने पर 58 लाख टन अन्न // पड़ा था । इसमें से अधिकांश खुले में पड़ा था, जिसके नष्ट हो जाने की आशंका थी । रेल मंत्रालय ने पंजाब को जवाब दिया कि अनाज ढुलाई के लिए वेगन /// भारतीय खाद्य निगम देगी, यद्यपि रेल मंत्रालय ने इन वेगनों को शीघ्रातिशीघ्र रवाना करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली । पंजाब में आजकल करीब 1 करोड़ 14 लाख टन गेहूँ व §2§ अन्य अनाज पड़ा है, जिसे बाहर भेजना है और भारतीय खाद्य निगम इसे भिजवाने में ढिलाई बरत रहा है ।

मानसून के वर्तमान अनुकूल रुख को देखते हुए पंजाब में / खरीफ के चावल की वसूली 38 लाख टन होने की आशा है । यह वसूली अक्टूबर में शुरु हो जाएगी । भारतीय खाद्य निगम यदि चावल के भंडारण की ठीक व्यवस्था नहीं // करता तो यह चावल खाने के काम का न रहेगा । गेहूँ तो खुले में तिरपाल डालकर पक्के फर्श पर रखा जा सकता है लेकिन चावल के भंडारण के लिए /// ठीक ढंग के गोदाम होना बहुत ज़रुरी है । पंजाब चावल मिल संगठन का शिष्ट मंडल इन दिनों दिल्ली में है और खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों से भेंट कर रहा है §3§ तथा उन्हें खाद्य निगम की सुस्ती व लापरवाही से अवगत करा चुका है । संगठन ने यह शिकायत भी की है कि भारतीय खाद्य निगम ने धान को मिलों की / ढुलाई की दरें करीब एक वर्ष से तय नहीं की हैं और जानबूझ कर इस मामले को लटकाया हुआ है ।

हरियाणा से भी भारतीय खाद्य निगम के बारे में // शिकायतें निरंतर मिल रही हैं । इस राज्य में निगम के कर्मचारियों की यूनियनों के अधिक हस्तक्षेप के कारण कामकाज में बहुत ढील हुई है । यहां तक कि हरियाणा सरकार के /// एक प्रवक्ता ने पिछले दिनों केन्द्र से कहा था कि खाद्य निगम को यदि राज्य से हल लिया जाए तो अनाज वसूली और भंडारण का काम ज्यादा सुचारु रुप में §4§ हो सकता है । पश्चिम बंगाल में अनाज की वसूली और वितरण का काम राज्य सरकार ने स्वयं सम्भाल लिया है और खाद्य निगम को राज्य से चले जाने को / कहा गया है । पश्चिम बंगाल में वसूली तथा वितरण के मामले में // अपनी विफलता स्वयं स्वीकार कर ली है । उत्तर प्रदेश तथा अन्य कुछ राज्य भी इस मत के हैं कि भारतीय खाद्य निगम अपने दायित्व निभाने में असफल रहा है । /// राजनीतिक कारणों से वे खुले तौर पर भले ही न कहें, लेकिन केन्द्रीय खाद्य मंत्री से बातचीत में निगम पर दोषारोपण कर चुके हैं । अतः मेरे विचार में भारतीय खाद्य §5§ निगम में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश बनी हुई है । §611 शब्द§

पंजीकृत > पंजीकरण > ध्यानाकर्षण

अभ्यास-87

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना-प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई पाँच करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पुस्तकें गोदामों में धूल खा रही हैं । लेकिन मन्त्रालय / अपने प्रकाशनों की लोकप्रियता और बिक्री बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम आज तक तैयार नहीं कर पाया है । पता चला है कि प्रकाशन विभाग पुस्तकों को छापने पर // अंधाधुंध खर्च करता है । "डीलक्स" यानी सुन्दर आवरण और साज-सज्जा की श्रेणी वाली पुस्तक की दो से पाँच हजार तक प्रतियाँ छापता या छपवाता है । लेकिन एक साल /// में उनकी केवल पच्चीस से पाँच-सौ प्रतियां ही बिक पाती हैं और वे भी सरकारी पुस्तकालयों में । बड़ी संख्या में पुस्तकें बाहरी मुद्रकों से छपाई जाती हैं और इस {1} स्थिति में प्रतियों की संख्या दो-तीन हजार की बजाय 5 से 12 हजार तक पहुँच जाती है । इसका कारण मुद्रकों से अधिकारियों का अच्छा खासा कमीशन मिलना बताया जाता है । /

प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों पर होने वाले खर्च और उनकी बिक्री से होने वाली आमदनी के सम्बन्ध में खोजबीन करने पर पता चला है कि हर साल कई ऐसी पुस्तकें // प्रकाशित की जाती है, जिनमें किसी पाठक की दिलचस्पी नहीं होती और पूरे साल में इन पुस्तकों की एक भी प्रति नहीं बिक पाती । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि /// आखिर ये पुस्तकें किस को खुश करने के लिए प्रकाशित की जाती हैं ? फिर हर वर्ष बदलने वाले आँकड़ों और जानकारियों पर आधारित सन्दर्भ ग्रंथ की दस हज़ार से अधिक {2} प्रतियाँ अंग्रेजी और हिन्दी में छापी जाती है । यह सन्दर्भ ग्रन्थ जब तक छपकर आता है तब तक उसमें दिए गए आँकड़े दो वर्ष पुराने हो जाते हैं, जिसका नतीजा / यह होता है कि उन्हें कोई नहीं खरीदता और उन्हें रद्दी में ही बेचा जाता है, यह राष्ट्र के धन की बरबादी नहीं तो क्या है ।

सबसे आश्चर्य की बात // यह है कि प्रकाशन विभाग के अधिकारी यह जानते हुए भी कि कई प्रकाशित पुस्तकों की एक भी प्रति नहीं बिकी उनके न बिकने के कारणों को जानने की कोशिश /// नहीं करते और धड़ाधड़ दूसरी पुस्तकें छापने का आर्डर दे देते हैं । इसके अलावा प्रकाशन विभाग की पुस्तकों की बिक्री व्यवस्था भी ठीक नहीं । आज का जमाना विज्ञापन {3} का है । जब तक पुस्तकों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा तब तक पुस्तकों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को उन पुस्तकों का पता नहीं चलेगा इस तथ्य को समझते हुए अब प्रकाशित पुस्तकों का कुछ/कुछ विज्ञापन हो रहा है, लेकिन यह उस हद तक नहीं किया जा रहा, जिस हद तक दूसरे निजी प्रकाशक करते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि प्रकाशन विभाग // पुस्तकों को अच्छी प्रकार से विज्ञापित करें विज्ञापन में केवल पुस्तक तथा उसके लेखक का नाम देना ही पर्याप्त न होगा । उस पुस्तक में ऐसी कौन सी विशेषता है /// उसे भी उस विज्ञापन में दर्शाया जाना चाहिए । ऐसा करने पर ही पुस्तकों की बिक्री बढ़ सकती है । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रकाशन

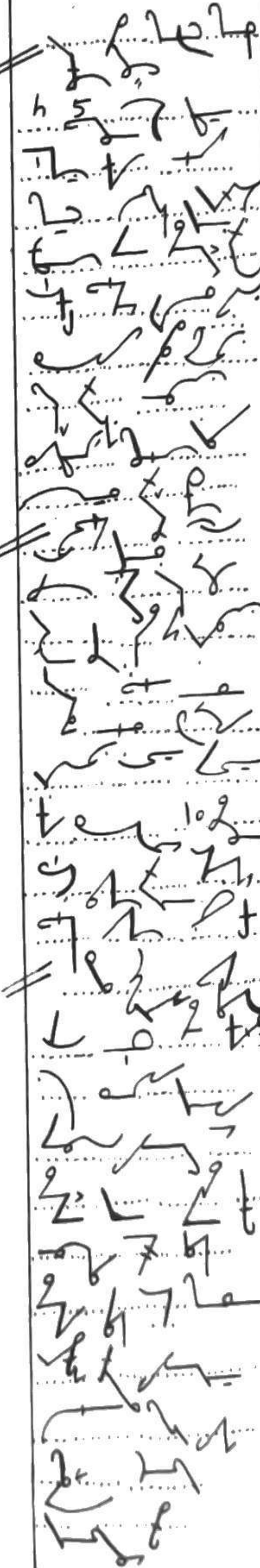

www.StenoIQ.com

विभाग किसी व्यक्ति विशेष को §4§ खुश करने के लिए किसी पुस्तक को प्रकाशित न करें, चाहे उसके लिए कितना ही जबरदस्त राजनीतिक दबाव क्यों न पड़े क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि कई पुस्तकें / राजनीतिक दबाव के कारण से ही प्रकाशित की जाती हैं और यह जानते हुए भी कि उनकी बिक्री या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर कम होगी, तब भी कई // हज़ार प्रतियाँ प्रकाशित की जाती है । सन्दर्भ ग्रंथ जिनमें आँकड़े ही मुख्य होते हैं, या तो समय पर प्रकाशित हो अथवा उन्हें हर पाँच वर्ष की अवधि में निकाला जाए /// ताकि ये सन्दर्भ ग्रंथ रद्दी में न बिकने पाएँ । मेरे विचार में अगर इन उपायों को सही तौर पर लागू किया जाए तो प्रकाशन विभाग को पुस्तकों पर अधिक लाभ मिलेगा । §5§ §600 शब्द§

अभ्यास - 88

आदरणीय सभापति जी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब किसी काम के करने में थोड़ी सी भी दुविधा मालूम हो कि उसे किया जाए या नहीं किया जाए तो / उसकी एकमात्र कसौटी यह है कि सबसे पहले यह सोचा जाए कि उस काम को करने से भारत के निर्धन से निर्धन ग्रामीण व्यक्ति का हित होता है // या नहीं । यदि उस काम को करने से उनका भला होता है तो उसे अविलम्ब किया जाना चाहिए । पं० जवाहरलाल नेहरू का चिन्तन था कि देश की असली /// आज़ादी नापने का पैमाना यह है कि यहाँ के लाखों गाँवों को स्वराज्य प्राप्त हुआ है या नहीं और स्वराज्य का अर्थ उन्होंने स्पष्ट रूप से खुशहाली ही माना है §1§ न कि केवल स्वतंत्रता हासिल करना ।

इसमें कोई शक नहीं कि आज गाँव का रूप बदल रहा है । नये-नये पक्के मकान बनते जा रहे हैं । रेडियो, टेलीविज़न तथा / बिजली वहाँ पहुँची है । गाँव के लोग भी आधुनिक सभ्यता से लाभान्वित हो रहे हैं । प्रतिव्यक्ति गेहूँ और चीनी की खपत भी बढ़ गई है । किन्तु फिर भी गांव का // युवक काम के लिए शहर की ओर दौड़ रहा है । तभी तो शहरों की आबादी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । एक मोटे अनुमान के अनुसार देश राजधानी /// की आबदी में हर साल दो लाख की वृद्धि हो जाती है । एक लाख नये बच्चे पैदा हो जाते हैं और एक लाख लोग बाहर से आ जाते हैं । §2§ यही स्थिति अन्य महानगरों की भी है । तभी तो 1947 की पाँच-छह लाख की आबादी वाली दिल्ली अब 80 लाख के निकट पहुँच रही है ।

आबादी बढ़ने से / समस्याएँ भी बढ़ी हैं और कुछ समस्याएँ तो ऐसी हैं जिन्होंने नागरी जीवन को बना दिया है । मकानों की कमी प्रायः सभी बड़े नगरों में अनुभव की जा / रही है । मकान कम होने से उनके किराए ऊँचे होते जा रहे हैं । दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ एक साथ मँहगी हो गई हैं । कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के /// लिए उचित दर दुकानों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है । किसी भी

दिन बिना पूर्व सूचना के पानी कब बन्द हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं । बिजली का {3} अकाल और आँख मिचौनी कई महीनों से चल रही है । उसकी बात करना तो इसलिए बेकार है क्योंकि सारे देश में ही बिजली की कमी ने / जहाँ उत्पादन को क्षतिग्रस्त किया है, वहाँ वातावरण भी अंधकारमय बना दिया है ।

घरों में चूल्हा लकड़ी और कोयले से जलता था, उस कारण मकानों की स्वच्छता // नहीं रह पाती थी । पिछले कुछ समय से स्वच्छता की दृष्टि से गैस का प्रयोग बढ़ा है किन्तु अब स्थिति यह है कि गैस के सिलेंडर मिलने में काफी असुविधा /// हो रही है । इसके साथ-साथ मिट्टी के तेल का भी अभाव बना हुआ है । गृहणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह आ खड़ी हुई है कि वे किस साधन {4} द्वारा भोजन बनाएँ । शहरों में आबादी बढ़ने से कई नगरों का जाल बिछा । इन उपनगरों की दूरी कहीं-कहीं तो पचीस-तीस किलोमीटर से भी अधिक हो गयी है । इसके कारण से शहरी जीवन और भी कष्टमय हो रहा है । वायु-दूषण एक और भयंकर समस्या बन // गयी है । हर क्षण सड़कों पर चलने वाली बसें, कारें, स्कूटर आदि जो ज़हरीला धुवां उगलते हैं, वह सीधा अनेक रोगों का कारण बन जाता है । अतः मेरा निवेदन /// यह है कि नगरों का आकार न बढ़ने पाये । इसके लिए सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिनसे ग्राम्य जीवन को सुख-सुविधा पूर्ण बनाया जाये और वहीं पर {5} शिक्षितों को काम दिलाने की व्यवस्था हो सके इसके लिए जरूरी है कि गाँवों में छोटे-छोटे कारखानें लगाने के लिए सरकार पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करे । {628 शब्द}

अभ्यास-89

मान्यवर, केवल काँग्रेस विरोधी दल ही इस बात की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि काँग्रेस ने गरीबी हटाओ का जो वचन दिया था वह पूरा नहीं किया । इस सम्बन्ध / में वे उत्पादन में कमी, बेरोज़गारी, भृष्टाचार और मँहगाई का हवाला देते हैं । यह भी कहा जा रहा है कि जब 54 करोड़ में से 22 करोड़ भारतवासी // घोर दरिद्रता की स्थिति में जी रहे हैं तो यह कैसे माना जा सकता है कि सरकार ने गरीबी हटाने की दिशा में कुछ किया है । काँग्रेस के अंदर भी /// ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो आर्थिक {1} कार्यक्रम निश्चित किया गया था वह केवल कागज़ी शेर बन कर रह गया है । वस्तुस्थिति यह है कि एकाधिकारवादियों की पूँजी दिन-ब-दिन बढ़ रही है । / सरकारी क्षेत्र में मूल्य नीति निर्धारण के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते । अनाज-व्यापार के राष्ट्रीकरण और भूमिहीनों को ज़मीन देने की दिशा में कोई उल्लेखनीय बात नहीं // हुई है । शहरी सम्पति की सीमा बाँधने सम्बन्धी विधेयक लाने में विलम्ब किया जा रहा है । मुख्यमन्त्रियों को छूट दे दी गई है कि वे क्रान्तिकारी नीतियों को नरम /// बना लें ।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन आलोचनाओं में कोई सत्य नहीं है, इनको एकदम निराधार नहीं कहा जा सकता । पर सवाल यह है कि देश में जो {2}

परिस्थितियाँ चल रही हैं और बाहर तथा अंदर के दुश्मन उनका जिस तरह बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या यह संभव है कि कांग्रेस ने जो / कुछ वचन दिये उन्हें अविलंब लागू किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सरकार और शासक दल को बदनाम किया जा सकता है, किन्तु क्या इस सबसे समस्या // के समाधान में कोई योग मिल सकता है ?

नीतियाँ और कार्यक्रम कुछ भी हों, किन्तु यह भूलने वाली बात नहीं कि उन्हें अमल में लाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण एवं /// परिस्थिति की ज़रूरत होती है। उसमें यह भी देखना होता है कि कहीं उन पर तेज़ी से अमल कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा न कर दे जो अगले काम में {3} रुकावट पैदा कर दे। आखिर यह लोकतंत्र है। इसमें जनमत की उपेक्षा करके तानाशाही या कम्युनिस्ट तरीके से नहीं चला जा सकता। नीतियों और कार्यक्रम कितने भी अच्छे हो पहले / उन जालों को हटाना होता है जो उनके अमल में बाधक है। फिर भी यह देखना होता है कि जो उत्पादन गरीबी और अन्याय मिटाने का एक बहुत बड़ा साधन है // उसमें सब का सहयोग प्राप्त हो सके। ऐसी सूरत में यदि कांग्रेस अपने वचनों को पूरा नहीं कर रही है तो वह बहुत अधिक आक्षेप योग्य बात नहीं है।

प्रधान मंत्री ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि "गरीब हटाओ" का कांग्रेस का नारा कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि उसके घुमाते ही गरीबी दूर हो जाए। यह इस {4} बातपर आश्रित है कि कांग्रेस में लोग कहाँ तक सहयोग दे रहे हैं। / यह स्पष्ट है कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण कांग्रेस विरोधी ही नहीं अपितु कांग्रेसी भी उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। असम और आन्ध्र में जो कुछ हो // रहा है वह इसका प्रमाण है। फिर कुछ कांग्रेसी तत्वों का यह सोचना भी गलत है कि बाहर का समाजवाद इस देश में आ जाएगा। इसीलिए प्रधान मंत्री को यह /// भी कहना पड़ा है कि हमारा समाजवाद हमारी मिट्टी और पानी से बना होगा। हम दूसरे देशों के समाजवाद की नकल नहीं कर सकते। यह उन लोगों को एक करारा {5} जवाब है जो एकदम सब चीज़ों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ठीक दिशा में चल रही है / और प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि सामाजिक न्याय को वह सार्वजनिक "महत्व" देती है और वह उसमें किसी चीज़ को बाधक नहीं बनने दे सकती। यदि ऐसा है // तो मुझे विश्वास है कि देर से ही सही कांग्रेस एक न एक दिन अपनी मंज़िल पर पहुंच जाएगी और तब जनता को लगेगा कि वह अपने वचनों /// के प्रति झूठी नहीं। फिर भी इतना कहना होगा कि इसमें आवश्यकता से अधिक विलम्ब की गुंजाइश नहीं है। यदि / ऐसा हुआ तो कांग्रेस पर से जनता का विश्वास उठने {6} लगेगा और उसकी वह स्थिति नहीं रहेगी जो आज है। {730 शब्द}

गोलीकांड ... कीटाणुनाशक ... कीटनाशक

अभ्यास-90

अध्यक्ष महोदय, आज मैं दूरदर्शन पर दिखाए गए बच्चों के कार्यक्रमों तथा बालचित्र समिति के सम्बन्ध में दो शब्द कहने की आज्ञा चाहूँगा । हमारे यहाँ बच्चों के मामले में / जो लोग सोचते है, लिखते या कार्यक्रमों का नियोजन करते हैं, उनके साथ एक कठिनाई यह है कि ऐसा करते समय वे आज के बच्चों को एकदम भूल जाते हैं // उनकी दृष्टि में बच्चों के लिए कुछ करने का मतलब है कोई भी किस्सा-कहानी पेश करना । दूसरे, वे सोचते हैं कि सब बच्चे एक जैसे होते हैं-चाहे वे /// पाँच साल के हों या पन्द्रह साल के । इन दोनों बातों का परिणाम यह होता है कि बच्चों के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है या उनके लिए जो ‖1‖ भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, वे या तो एकदम बचकाने हो जाते हैं या फिर बच्चों की समझ के बाहर हो जाते हैं । दूरदर्शन के बच्चों के कार्यक्रमों में / भी यही एक मूलभूत कमी रही है जिसके कारण न तो उनकी प्रस्तुतीकरण में सुधार हो पाता है और नहीं उनके विषय चयन में । अतः मेरा सुझाव है कि // कार्यक्रम नियोजन, लेखन और प्रस्तुतीकरण में बच्चों की उम्र, उनके ज्ञान तथा बौद्धिक स्तर को अवश्य ध्यान में रखा जाए । इनमें असन्तुलन से निश्चय ही कार्यक्रम प्रभावहीन बन जाएंगें । /// पिछले दिनों बच्चों के लिए जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर शुरु किए गए हैं उनमें भी यही बात आ गई है । दो कार्यक्रम तो विदेशी बाल-फिल्मों के हैं जिनमें ‖2‖ दूरदर्शन का अपना योगदान नहीं हैं, वे केवल इन्हें दूरदर्शन पर दिखा रहे हैं ।

इस सन्दर्भ में बाल-चित्र समिति की उन फिल्मों की भी चर्चा कर लें जो दूरदर्शन / कभी-कभी बच्चों को दिखाता है । इन फिल्मों में भी वही असन्तुलन है जिसकी हमने पहले चर्चा की है । इसी कारण से वे सारी फिल्में लोकप्रिय नहीं हो पाई । // यह बात और है कि इधर बाल-चित्र समिति के अध्यक्ष श्री अमोल पालेकर ने इन बुनियादी कमियों को समझा है और भविष्य में अच्छी और सार्थक बाल फिल्मों को तैयार /// करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है । राष्ट्रीय फिल्म वित-निगम के अध्यक्ष भी बच्चों को सार्थक बाल-फिल्मों में देने के लिए गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । ‖3‖

सच्चाई यह है कि आज के बच्चों के सामने जो प्रश्न हैं, आज वे जिन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में बताने से हम स्वयं घबराते / हैं, कारण चाहे हमारा अपना अज्ञान हो, मूल्यों का टकराव हों या परम्परा का मोह हो । आज के बच्चों के लिए लिखने या कार्यक्रमों का नियोजन करने के लिए // उनके सोच, उनके परिवेश और उनके मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है । बच्चों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए इतना कुछ जानने-समझने को मिलता है कि पिछले दो दशकों /// में उनके ज्ञान स्तर में बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है । आज दस वर्ष के बच्चे की बुद्वि पन्द्रह वर्ष के बच्चे के बराबर हो गई है । बच्चों के इस ‖4‖ बौद्धिक विकास के अन्तर को न तो बच्चों के अधिकांश लेखक और न ही संचार माध्यमों के / बाल कार्यक्रम नियोजक अपने लेखों में

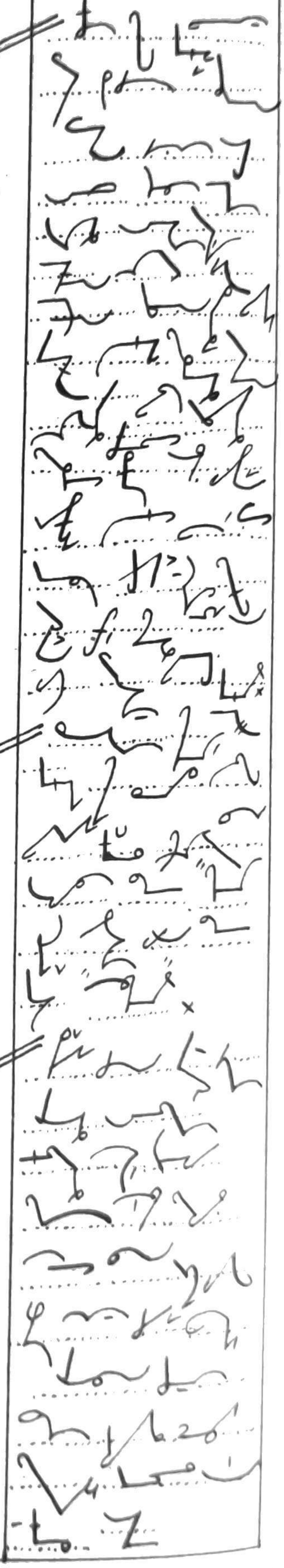

प्रस्तुत कर पाते हैं, जबकि ज़रूरी यह / है कि हमारा लेखन कार्यक्रमों का नियोजन ऐसा हो जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में हो रहे बौद्धिक विकास के अनुरूप हो । अब बच्चे नीति की बातें // सुनने को तैयार नहीं हैं, यह बात आज हर माता-पिता तथा सभी शिक्षा-शास्त्री जानते हैं । आज बच्चे अपने परिश्रम, अपने अनुभव और अपने आत्म-विश्वास से आगे बढ़ना /// चाहते हैं । ऐसे बच्चों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए, कैसा लेखन होना चाहिए, यह एक चुनौती है । यदि इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाता तो {5} हम जो कुछ करेंगे वह एकदम असामयिक तथा अनुपयोगी होगा । अतः दूरदर्शन के कार्यक्रम हों या बाल फिल्में हों या बच्चों की पत्रिकाएँ हों, बच्चों को रचनात्मक दिशा देने / के लिए, उन्हें आज के और भविष्य के समाज तथा जीवन से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उनके प्रति सोच में परिवर्तन लाएँ तथा उसके अनुरूप कार्यक्रमों के // नियोजन में नवीनता लाएँ । बच्चों के लिए ऐसे विषयों का चयन करें जिनसे बच्चे अपने को जुड़ा अनुभव करें और कार्यक्रम ऐसे हों जिन्हें देखकर बच्चे अपने को उसका /// भागीदार समझें । {692}

अभ्यास-91

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और सेना देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों को पूरी तरह समझती हैं और उनके मुकाबले का पूरा प्रबन्ध किया जा रहा है । इसके लिए सेना के / प्रशिक्षण, नए हथियारों की व्यवस्था हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण, आधुनिकतम हथियारों तथा अन्य साज-सामान के देश में ही उत्पादन, अनुसंधान व विकास तथा सामरिक क्षमता के विकास का // काम किया जा रहा है । अब समय आ गया है जब हमें आधुनिक तकनीक तथा अपनी संगठात्मक व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन कर नई परिस्थितियों के अनुकूल सामरिक व्यवस्था करनी होगी । /// यह प्रसन्नता की बात है कि इनके लिए पच्चीस वर्षों की नीति तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है । समय की अनिवार्यता के प्रति सेना और सरकार दोनों ही {1} जागरूक हैं तथा उसकी पूर्ति के लिए तत्पर और कृतसंकल्प हैं । हर मामले में प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है और उसका कार्यान्वयन चल रहा है । सैन्य और / शस्त्र दोनों ही शक्तियों का तेज़ी से विकास किया जा रहा है । भारत का अपना मुख्य युद्ध टैंक भी कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा इसमें विलम्ब हुआ है // लेकिन इस विलम्ब की आलोचना सही नहीं है क्योंकि विकास कार्य में समय लगता ही है । 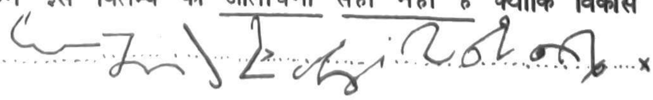

आज के जमाने में हथियार ही सब कुछ नहीं हैं । मुख्य बात है /// सैनिकों का प्रशिक्षण । उन्हें आधुनिक हथियारों तथा संयंत्रों के उपयोग के लिए लगातार तथा व्यापक प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी हैं । मुझे खुशी है कि यह काम भी तेज़ी से चल रहा है । हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊँचा है । यह सबसे महत्वपूर्ण बात है । पाकिस्तान को भले ही अमेरिका से आधुनिकतम हथियार मिलें लेकिन भारत की तैयारी के सामने /

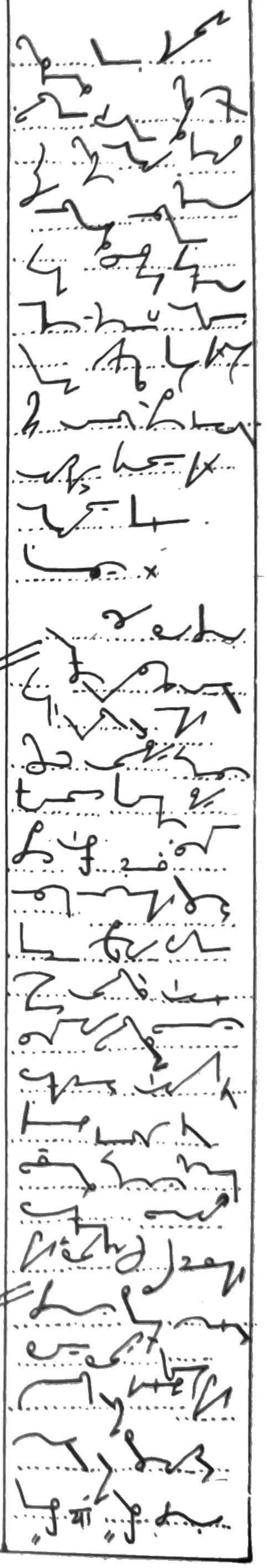

www.StenoIQ.com

पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा । और इससे ही हथियार जमा करने का उसका मनसूबा पस्त हो जाएगा । भारत के मुकाबले वह कब तक और कितनी // मात्रा में हथियार खरीद पाएगा और उसका लाभ क्या होगा यह देखना है । पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश के संदर्भ में देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय // किए जा रहे हैं । संगठन, तथा प्रशिक्षण तीनों ही मामले में इस खतरे का सामना करने का उचित प्रबन्ध किया जा रहा है । नये थल सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दरजी {3} का देश को दिया गया यह आश्वासन काफी महत्व का है कि राष्ट्र की पूरी तरह रक्षा की जाएगी । उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परमाणु / हथियारों का उपयोग किया तो हम उसे सही जवाब देंगे, इसकी पूरी तैयारी है । उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान के खतरे को देखकर नहीं की जा रही है । हम सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सभी खतरों के सन्दर्भ में अपनी सशस्त्र सेनाओं को सबल व सक्षम बना रहे हैं । इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है । /// इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं में तालमेल लाने तथा उनके समन्वित नियोजन व विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है । सरकार इसके महत्व को समझती है । एक ऐसी प्रणाली {4} का विकास किया जा रहा है जिससे तीनों सशस्त्र सेनाओं की क्षमता के अधिकतम विकास / का कार्य किया जा रहा है । पुनर्गठन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है । सरकार इस मामले में पूरी तरह से सचेष्ट और जागरूक है ।

उत्तरी सीमा // पहाड़ी होने के कारण अनेक कठिनाइयां है । इसलिए नये और आधुनिक यन्त्रों की व्यवस्था की गई है जिससे उत्तरी सीमा की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा । किन्हीं परिस्थितियों में // अचानक ही सैनिकों को युद्ध स्थल पर पहुँचाना आवश्यक हो जाता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि संचार तथा सूचना के मामले में भी सुधार लाया जाए । इलेक्ट्रोनिक {5} युद्ध की व्यवस्था भी आज की बड़ी ज़रूरत है । इसके लिए भी संयंत्र उपलब्ध किये जा रहे हैं ।

सेना का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है । इसके साथ-साथ / सेना में उत्तरदायित्व का विकेन्द्रीकरण करना भी ज़रूरी हो जाता है । इससे हर कमान अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तौर पर निर्वाह कर सकेगा । सेना में सेवा की शर्तों में सुधार // पर वेतन आयोग उसके हितों का ख्याल रख सकेगा । वित्त मन्त्रालय भी उनकी ज़रूरतों के प्रति जागरूक हैं, हालांकि हमें विकास की प्रक्रिया में भी ढील नहीं देनी है । /// यह मैं मानता हूँ कि सेना में पद कम हैं जिससे उन्नति की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती । इस तरह से रैंक के आधार पर वेतन-मान का निर्धारण {6} आकर्षक नहीं रह गया है । इसलिए मेरे विचार में वेतन सेवा की अवधि पर तय किया जाना चाहिए । अन्य सेवाओं को जो वेतन तथा सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उतनी तो सैनिकों / और अफसरों को भी मिलनी चाहिए । {756 शब्द}

लाइसेंसशुदा कार्यभार कार्यवाहक

अभ्यास-92

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिज़र्व बैंक के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार यहाँ पर रखने की अनुमति चाहूँगा । यह बड़े खेद की बात है कि रिज़र्व बैंक के पास आज तक बैंकों / के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं, उन को भी रिज़र्व बैंक काम में नहीं लाता । रिज़र्व बैंक का अन्य बैंकों पर नियन्त्रण दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है । // इसका नतीजा यह है कि दूसरे बैंक प्रत्येक मामले में अपनी मनमानी करते हैं । मैं आपको एक ताज़ा मिसाल बताता हूँ । अभी हाल ही में सरकार ने व्याज़ की दर /// कम कर दी जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम बैंक रेट कम कर दिया । दूसरे देशों में अगर मुख्य बैंक कोई कदम उठाती है तो स्वतः ही वह बात (1) अन्य बैंकों पर भी लागू हो जाती है। लेकिन हमारे देश में यह अजीब नज़ारा है कि मुख्य बैंक अर्थात् रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक रेट कम करने पर भी बहुत / से बैंकों ने उसको कम नहीं किया । बहुत कुछ दबाव डालने पर अब कहीं कुछ बैंकों ने इस पर अमल किया है, लेकिन अभी भी सारे बैंकों ने बैंक रेट // कम नहीं किया । इसके फलस्वरूप ऐसे बैंक रिजर्व बैंक से कम व्याज पर पैसा लेते हैं और ज्यादा व्याज पर बाहर देते हैं और इससे काफी मुनाफा /// कमाते हैं ।

इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक अभी तक इन बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण नहीं कर पाया और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में वह नहीं (2) कर पाएगा । इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकिंग उद्योग बहुत ही संवेदनशील उद्योग है । वह डूबता है तो / चारों ओर असुरक्षा पैदा होती है और देश की पूरी मुद्रा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले दक्षिण भारत केरल का // एक बैंक फेल हो गया था, डूब गया था । उसका असर यह हुआ कि उत्तर भारत विशेषकर दिल्लीमें यह अफ्वाह फैल गई कि पंजाब नैशनल बैंक भी शायद /// डूब जाएगा, हालांकि उसके डूबने की कोई बात नहीं थी, वह बहुत अच्छे आधार पर काम कर रहा था । अगर बैंक के पास एक लाख रुपया होता है तो वह (3) आठ लाख रुपये तक एड्वांसिस दे देता है, इसको गलत नहीं माना जाता है । कोई बैंक चाहे कितने ही सुदृढ़ तरीके से काम क्यों न करे, लेकिन अगर अचानक ही / कोई अफ्वाह फैल जाए और सारे लोग अपने-अपने पैसे के लिए बैंक के पास पहुँच जाएँ तो अच्छे से अच्छा बैंक भी पैसा चुकाने में समर्थ नहीं हो सकेगा । // सारी दुनिया में बैंको का यह सिद्धान्त है कि बैंक चलते हैं साख और विश्वास पर । थोड़ी सी अफ्वाह किसी भी बैंक को डुबाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि /// यह क्षेत्र ही संवेदनशील है । यह एक ऐसी चीज़ है कि इन बैंकों पर किसी प्रकार का सामाजिक नियन्त्रण चल नहीं सकता क्योंकि ज्यों ही किसी बैंक को धमकी दी (4) जैसा कि आज तक होता रहा है वह फौरन कहना शुरू करेंगे-देखिए साहब, अगर आप इसके अन्दर हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा सारा कारोबार गड़बड़ा जाएगा । लोगों में अफ्वाह / फैल जाएगी, उनका विश्वास डगमगा जाएगा, हमारा बैंक डूब जायगा और एक

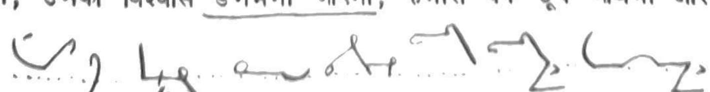

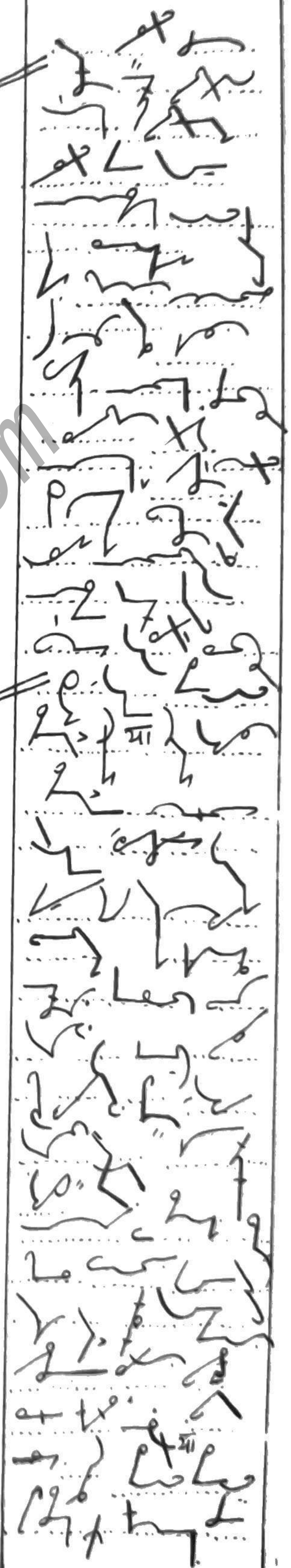

www.StenoIQ.com

बैंक डूबता है तो दूसरे बैंक के खिलाफ अफवाह फैलती है, और इसी प्रकार चक्कर चलता रहेगा // तो फिर रिजर्व बैंक और सरकार कहेगी कि अच्छा है जिस तरह चलता है चलने दो ।

आज इस सामाजिक नियन्त्रण के खिलाफ यह कहा जा रहा है कि यह हमारे /// अधिकारों के खिलाफ चुनौती है, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रहार है, हम इसको यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे । मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ कि, उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग (5) उद्योग पर किसी प्रकार का सामाजिक नियन्त्रण न दुनिया में आज कल चला है और न चल सकेगा । प्रश्न यह है कि मौलिक रूप से इसका स्वामी कौन होता है । / यह पैसा जो देश के करोड़ों गरीब लोगों ने जमा किया है उसका मालिक कौन हो और किस दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए । (654 शब्द)

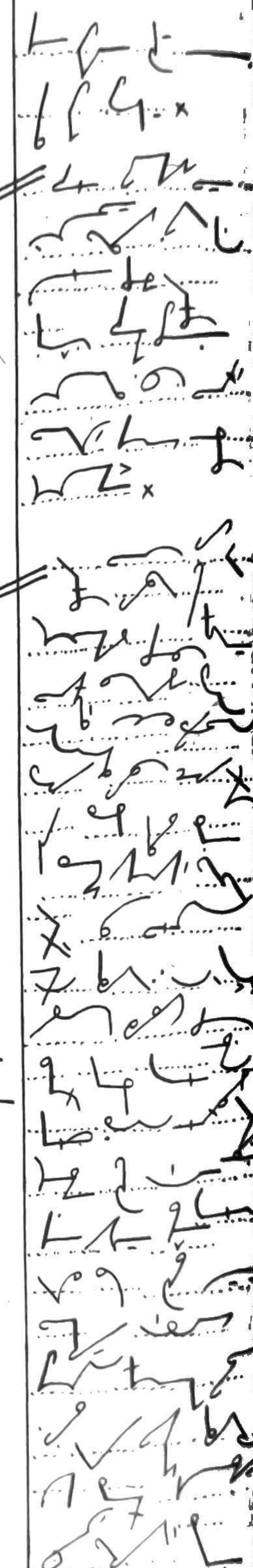

अभ्यास-93

उपाध्यक्ष महोदय, इस गरम वातावरण के बाद जिस विषय पर मैं चर्चा आरम्भ करने जा रहा हूँ और जिसका सम्बन्ध इस देश के कई लाख अध्यापकों और करोड़ों छात्रों से / है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसी वातावरण में इस चर्चा को भी लिया जाएगा लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना कर्तव्य है, मैं उसको निभाना // चाहता हूँ । मैं माननीय महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि 26 फरवरी, 1965 को अध्यापकों के विषय में एक वक्तव्य उप-शिक्षा मंत्री ने दिया था उसको वह फिर देखें । /// उससे इस सदन में और देश में भी बहुत चिन्ता उत्पन्न हो गई है । पिछले 18 वर्षों में संसद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा महाराजाओं और बड़े-बड़े पूँजीपतियों से लेकर खेत में काम करने वाले किसान और घरेलू नौकर तक के लिए कुछ न कुछ देशव्यापी कानून यहाँ बनाये गये हैं । लेकिन राष्ट्र-निर्माता / अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई देश-व्यापी सुदृढ़ कानून नहीं बनाया गया । मैं उसी उपेक्षित और भूखे अध्यापक की कहानी आज आपको यहाँ दुख के साथ // सुनाने खड़ा हुआ हूँ । क्योंकि इस बेचारे अध्यापक ने पिछले 18 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि तोड़फोड़ के अन्तर्गत आ सके । इसने कहीं जाकर /// रेल गाड़ियां नहीं गिराई, कहीं डाकखाने नहीं जलाए । कहीं अध्यापकों ने पुलिस के सिर नहीं फोड़ें और न ही कहीं अध्यापकों ने मंदिरों या गुरुद्वारों में किसी प्रकार का (2) कोई अनशन किया है या जल मरने की धमकी दी है । शायद यही कारण है कि सरकार के कानों तक अध्यापक की आवाज़ पूरी तरह नहीं पहुँची है । क्या सरकार / यह चाहती है कि कोई देशव्यापी निर्णय लिया जाए और साथ ही इस बात की इच्छा भी रहती है कि अध्यापक हल्के हथियारों का सहारा लें और उनसे भी ऐसी // प्रवृत्तियों का उदय हो । यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और देश में इस प्रकार के हल्के वातावरण का निर्माण हो गया तो वह राष्ट्र की सुरक्षा /// के लिए घातक होगा ।

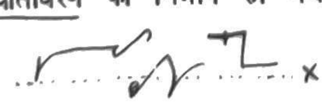

www.StenoIQ.com

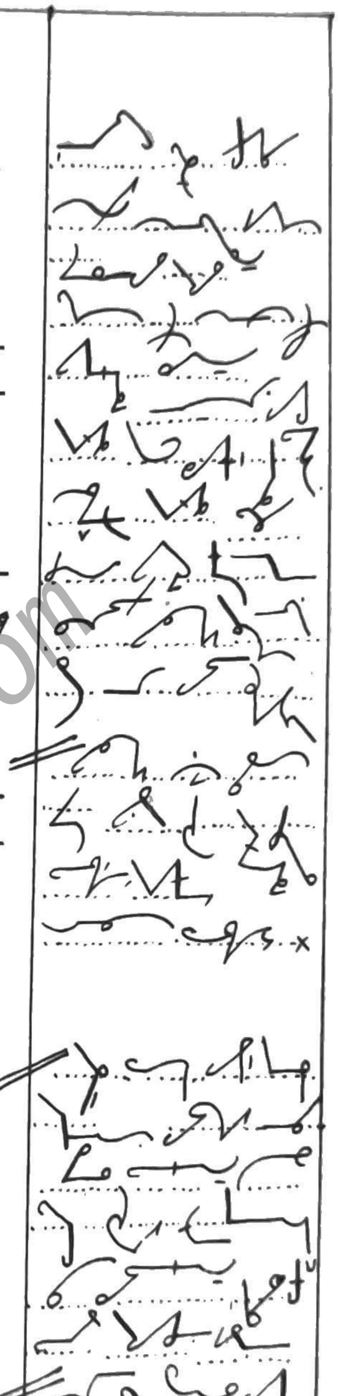

पिछले 18 वर्षों में अध्यापकों ने अपने गौरवपूर्ण पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं । (3) कभी मूक प्रदर्शनों के रूप में और कभी शिक्षक दिवस के रूप में कभी एक दिन का उपवास करके और कभी प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री के पास / अपने शिष्ट मंडल पहुँचा कर, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । जब अध्यापक आज यह देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, // उनके वेतन बढ़ाए जाते हैं, उनको पेंशन की सुविधाएँ दी जाती है, ग्रेज्युटी और मंहगाई भत्ते उनके बढ़ाए जाते हैं, उनको पेंशन की सुधिधायें दी जाती हैं, तो उनका /// भारत सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वे अपने धैर्य को कब तक सम्भाल कर रखें क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक जब बाज़ार में जाता है उसका (4) कपड़ा या सब्ज़ी या दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे गल्ला बगैरह वे सस्ते रेट पर मिल जाते हैं । क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापकों को जब अपनी / लड़की का विवाह करना पड़ता है तो उसको किसी प्रकार का दहेज़ नहीं देना पड़ता ।

क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक के बच्चों को एम॰ए॰ तक की हिन्दुस्तान // में मुफ्त शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है या चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ हैं । यदि ये सब बातें नहीं है तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे /// कर्मचारियों केलिए सरकार ने व्यवस्था की हुई है इन अध्यापकों ने क्या अपराध किया है जो इन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है । (5) (600 शब्द)

अभ्यास-94

पंचवर्षीय योजनाएं, सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षित मांग पैदा करने में विफल रही हैं और केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने में असफल रही है । / ठीक 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से लेकर मैं सरकारी कारखानों के इतिहास का अध्ययन कर रहा हूँ । पर बावजूद इसके मुझे इस बात का पता नहीं लग सका है // कि सरकारी कारखानों का उद्देश्य क्या है । वे क्या चाहते हैं ?

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस में भी सरकारी उद्योग चल रहे हैं । वहाँ उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि /// वे असाधारण खतरों की स्थिति में निर्मित हों । जैसे अंतरिक्ष तथा अणुशक्ति संबंधी कार्यक्रम को लेकर सरकारी कारखाने खोले जाते हैं, परन्तु उन देशों में सरकारी उद्योग क्षेत्र अपने आदर्शों (1) की पूर्ति के लिए निजी उद्योगों को काम में लाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं ।

कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है / और राष्ट्रीय उद्योगों में आदर्शों की ऊँची गद्दी पर बैठकर आर्थिक प्रगति लाना है । चौथी योजना तक तीनों योजनाओं के कागज़ भी बहुत कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के

www.StenoIQ.com

कारखानों के // अतिरिक्त मांगों पर निर्भर करते आ रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं, आदर्शों की ऊंची गद्दी क्या है और वह किस उद्देश्य से है ? मेरे विचार में सरकारी कारखानों /// को केवल लाभदायकता के मानदण्ड से मापना ठीक नहीं । हिन्दुस्तान इस्पात को देखिये । इसका उद्देश्य था देश में इस्पात की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के आम विकास (2) की आवश्यकता के अनुसार इस्पात की कई किस्मों को काफी मात्रा में तैयार करना लक्ष्य था । यदि केवल लाभ के लिये यह कारखाना खोला गया होता तो इसकी शक्ल-सूरत / कुछ और ही होती ।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों की सफलता के लिये दो स्पष्ट व महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और जो लोग उनमें काम करते हैं उनमें उचित मनोबल नितांत // आवश्यक है । हिन्दुस्तान इस्पात को केवल लाभदायकता के मानदण्ड से जांचना इसके उद्देश्यों को नज़र-अंदाज करना है । पहला उद्देश्य है कि उचित मूल्य पर देश को इस्पात मुहैया करना /// और विदेशी मुद्रा के खोने को रोकना, न केवल मुनाफा कमाना । यदि यह कारखाना मात्र लाभ के लिये खड़ा किया गया होता तो आर्थिक प्रगति रुक जाती । प्रशासनिक (3) कार्यकुशलता के बारे में श्री नेहरू ने कहा था, लोगों को स्पष्ट उद्देश्य के बारे में अवगत कराने के बाद उनके कार्यों के परिणामों को लेकर जांचना होगा ।

मैं महसूस करता / हूं कि जो लोग सरकारी कारखानों की इसलिये आलोचना करते हैं कि वे मण्डी से उत्तरदायित्वों तथा औद्योगिक उत्पादन के मांग संबन्धी पहलू के प्रति सजग नहीं, बेहतर // है कि वे लोग समूचे सरकारी क्षेत्र के 85 प्रतिशत भाग का उद्देश्य साधारण मांगों को पूरा करना नहीं था, /// बल्कि सुनियोजित विकास की आवश्यकता की पूर्ति करना था । परन्तु योजनाएं अनुमानित मांग पैदा करने में विफल रही हैं । यदि योजना ही विराम बिन्दु पर पहुंच जाती है तब (4) सरकारी क्षेत्र से क्या अपेक्षा करते हैं ? आपने सरकार की गद्दियों पर विराजमान होकर सरकारी उद्योगों में उत्पादन के इस्तेमाल के लिए मांग और वातावरण को तैयार नहीं किया । / और फिर ऊपर से सरकारी क्षेत्र की आलोचना की जाती है और सरकार भी इस आलोचना में शरीक हो जाती है ।

जहां तक वित्त मंत्रालय का संबंध है, वह खर्च // और उत्पादन खर्च के अनुमानों को सीमा तक परियोजनाओं की रिपोर्ट में दिलचस्पी रखता है । इसमें परीक्षा के तौर पर चलाए गए कारखानों जैसी बातों को किसी गिनती /// में नहीं रखा । इसने उचित मूल्य नीति के प्रति भी ध्यान नहीं दिया । परिणाम यह हुआ कि कई सरकारी कारखानों में गलत आदमी नियुक्त किये गए । इस पर उचित ध्यान दिया जाए । (5)

(600 शब्द)

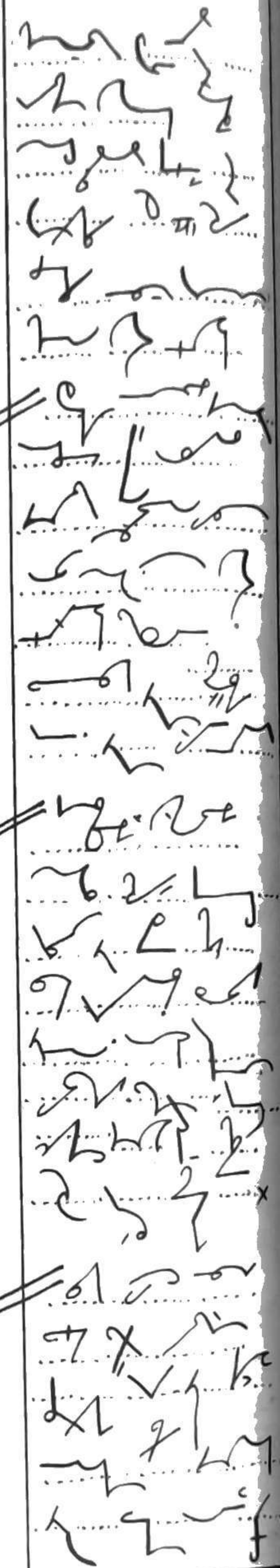

अनुमोदनार्थ ... प्रकाश्यक ... पुनर्वासि ... अनुपूरक

आदेशानुसार ... शब्दनायक ... सलाहकार ... मुहय्या

अभ्यास-95

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के जवाब से लगता है कि वह स्वयं किसान नहीं हैं और उनको किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं है । उन्होंने कहा कि किसान आठ महीने / तक अपने क्षेत्र में खेती करें और चार महीने के लिए वहाँ से हट जाए / अपने क्षेत्र से किसान तो वहीं रहेगा जहाँ उसकी जीविका या ज़मीन होगी ? आखिर चार महीने के लिए // किसान कहाँ चले जाएँ और क्यों जाएँ । मंत्री महोदय को किसानों के विषय में जानकारी नहीं है और वह बहुत ही अव्यवहारिक बात कर रहे हैं ।

बाढ़ के सम्बन्ध में /// मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सारी समस्याओं के समाधान के लिए वह इस मसले में माडल सर्वेक्षण के लिए फिर से तैयार हैं, क्योंकि गत वर्ष जो (1) बाढ़ आई थी, उसमें पंजाब को छोड़कर करीब-करीब समस्त उत्तर भारत ग्रस्त हो चुका था । बिहार और यू0पी0 भी पूरी तरह से प्रभावित थे । असम और बंगाल भी / प्रभावित थे । उस प्रकार के अनुभव के बाद क्या सरकार नये सिरे से इस पूरी समस्या को लेकर यू0पी0 और बिहार से समन्वित माडल सर्वेक्षण करने के लिए // तैयार हैं ? तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार इन तीनों की एक मिलीजुली कान्फ्रेंस में इस बात के हर पहलू पर विचार करके /// क्या आप कोई अंतिम निर्णय करेंगे । मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट अपने विचार हमारे सामने रखें और जो हमने सुझाव दिए हैं क्या (2) उनको स्वीकार करके केन्द्रीय सरकार इस विषय में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी और किसी तरह की कोई उलझन पैदा हो तो क्या उसको वह रोकेगी ? जिन एक हजार गाँवों / के डूब जाने की आशंका हो गई है, मान्यवर, ये वहीं गाँव हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद का कारण बने हुए हैं और बहुत // दिनों तक यह मसला अटका रहा है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने स्वीकृति दे दी है । मेरे पास यह चिट्ठी है जिसे यू0पी0 /// के चीफ इंजीनियर ने लिखा है । इस चिट्ठी में कहा गया है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है तथा उन्होंने लिखा है कि इस बारे में उन्हें (3) जानकारी दी जाए कि यह योजना क्या है और माडल सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है । इस चिट्ठी में बांध बनाने का साफ शब्दों में विरोध किया गया है ।

बिहार सरकार के / ऐतराज़ करने पर केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने ही बांध बनने से रोक दिये और माडल सर्वेक्षण के लिए बारह बरस तक लटकाये रखा । लेकिन केन्द्रीय सरकार // यह भेदभाव की नीति अपना रही है कि उत्तर प्रदेश के ऐतराज़ करने पर भी कहा जा रहा है कि यह बांध बनाया जायेगा । उत्तर प्रदेश को इस बारे में कोई /// जानकारी नहीं हैं । उसको जानकारी नहीं दी जाती है । बिहार भी हमारा सूबा है और उत्तर प्रदेश भी हमारा सूबा है । इस बांध के बनने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है । (4) लेकिन इंजीनियर्स को देखना चाहिए कि जो बांध बनाया जाए वह टूटे नहीं

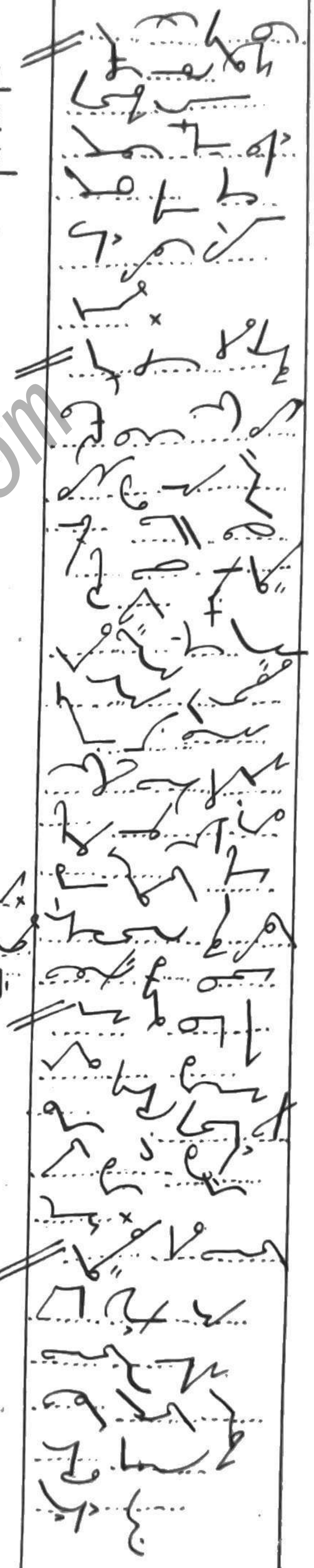

www.StenoIQ.com

क्योंकि पहले भी यू0पी0 में कोई बांध न बनाया जाए क्योंकि ऐसे बांध बनवाने से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है । अब तो यह भी साबित हो चुका है कि // बाढ़ की समस्या का हल बाँध नहीं है ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है, क्या मंत्री महोदय को उसकी जानकारी हैं ? क्या मंत्री महोदय /// उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमन्त्रियों और चीफ इंजीनियर्स के साथ बैठ कर कोई रास्ता निकालने की उन्होंने कोशिश की है । उन्होंने कहा है कि एक लाख लोग प्रभावित हैं । {5} लेकिन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि तीन लाख लोग प्रभावित हैं । हमारे सामने समस्या यह है कि ये तीन लाख लोग कहाँ जाएँ ? {623 शब्द}

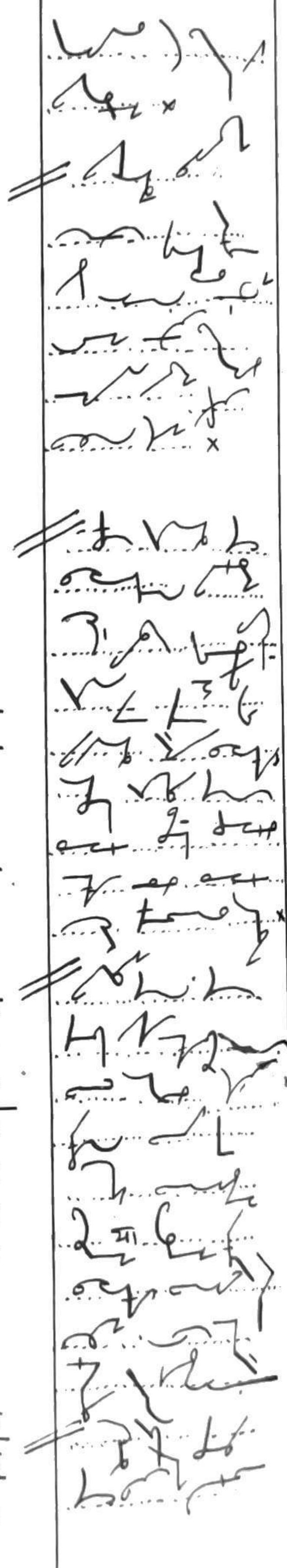

अभ्यास-96

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही विषय पर बोलना चाहता हूँ और वह है ज़मीन की सीमा निर्धारित करना । यह खुशी की बात है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस / विषय पर अपने उपयोगी सुझाव रखे । वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन चूँकि इसका ज़िक्र आ गया है इसलिए मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसको // मैं यहाँ रखना चाहता हूँ । जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा-निर्धारण हो अथवा निजी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, इस बदलते हुए ज़माने में, इसके खिलाफ़ /// कोई नहीं हो सकता और न मैं इसके खिलाफ़ हूँ । लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हों, यह उनके मन की बात है, उनसे {1} झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है ।

यह बात सही है कि कभी जमाना था जब बड़े-बड़े ज़मींदार थे उनकी बड़ी-बड़ी जागीरदारी थीं, आज वे नहीं रहे । / राजा लोग भी नहीं रहे । अब केवल बड़ी-बड़ी ज़मीन वाले कुछ लोग ज़रूर हैं जो अब भी अपने को ज़मींदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं । ऐसे लोगों // के लिए अब सरकार यह चौथी सीलिंग ज़मीन पर कर रही है । हम को दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की ज़रूरत इसलिए हुई कि अभी तक /// जितनी भी सीलिंग हुई है उसको क्रियान्वित नहीं किया गया और हम को डर इस बात का है कि यह जो चौथी बार सीमा-निर्धारण होने जा {2} रहा है उसका भी क्रियान्वयन इतना पेचीदा मसला है कि कानून मन्त्री अपनी सारी किताबें खोजते हुए रह जाएँ तब भी इसका हल नहीं निकलेगा तथा इसको क्रियान्वित नहीं किया / जा सकेगा । आखिर ऐसा क्यों ?

एक ही उदाहरण देता हूँ । हमारे यहाँ बटाईदारी पद्धति है जिसके अनुसार जिसके पास ज़मीन है और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो // ज़मीन वाले लोग लिख कर नहीं देते । अगर वह लिख दें कि 15 वर्ष से बटाईदार है हमारी ज़मीन का,

www.StenoIQ.com

और वह आदमी गरीब है और वह सीलिंग के /// अन्दर आता है, कानून उसके खिलाफ क्या करेगा और इसका नतीजा यह होगा कि ज़मीन उससे नहीं निकलेगी और वह ज़मीन का मालिक बना रहेगा ।

दूसरी चीज़ यह है कि चाहे ‖3‖ ज़मीन हो, चाहे नौकरी हो, या सिनेमा हो या कोई बिज़िनेस हो, हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जीवन—यापन का साधन मिले, उसके बच्चों के पढ़ने का इतज़ाम हो, जब बीमार पड़े तो दवा-दारू का इंतजाम हो, बूढ़ा हो तो उसकी परवरिश हो सही-सही देखभाल हो और उसकी आमदनी भी // किसी न किसी ज़रिए से चलती रहे । ज़मीन रखने का भी यही मतलब है । जो जमीन जोतता है, उसका भी यही मतलब है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या /// इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए । सरकार कम से कम पाँच आदमी का एक परिवार मानती है तो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए ‖4‖ जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने परिवार का भली-भाँति पालन-पोषण कर सकें, बच्चों की शादी कर सके । कम से कम एक मामूली मकान जिसमें / वह अपने तथा अपने परिवार को छुपा सके, इतना बना सके । इन बातों को सोचकर के क्या सरकार की तरफ से एक आमदनी फिक्स की गई है या नहीं ? //

जो लोग भूमि की सीमा-निर्धारण की बात करते हैं, चाहे 10,15, या 20 एकड़ तक की सीमा-निधारित करने की बात करें, उससे मतलब नहीं है । विशेष बात /// यह है कि आप भूमि की वही सीमा निधारित करें जिससे उसे इतनी आमदनी ज़रूर हो जिससे वह अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली-भाँति निभा सके, फिर चाहे ‖5‖ वह 5 एकड़ या एक एकड़ ज़मीन ही क्यों न हो । तो मेरा अर्ज़ यह है कि सरकार भूमि की सीमा-निधारित करने से पहले यह निर्धारित करे कि एक / आदमी की आय कितनी होनी चाहिए अर्थात् सब से पहले आमदनी की सीमा निर्धारित हो कि कम से कम एक व्यक्ति को कितनी आमदनी होनी चाहिए । ऐसा करने पर ही // सरकार भूमि की सीमा-निर्धारण में कामयाब हो सकेगी । ‖ 670 शब्द ‖

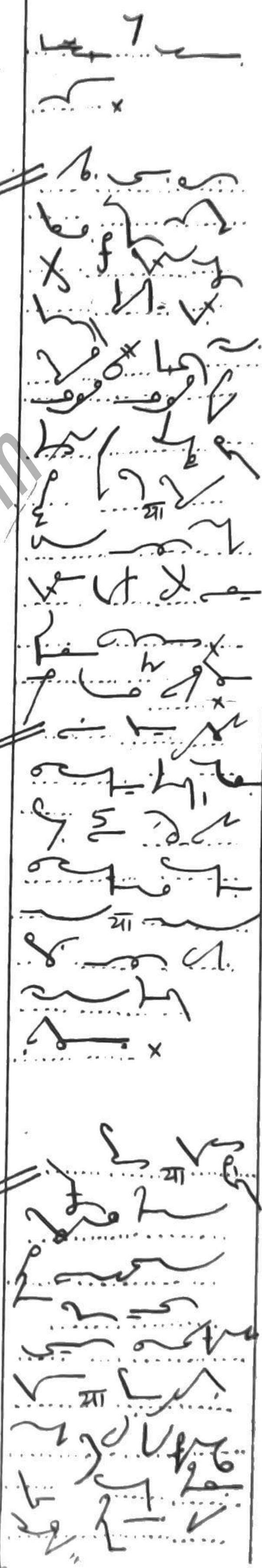

www.StenoIQ.com

अभ्यास-97

उपाध्यक्ष महोदय, बाल कल्याण सम्बन्धी सिफारिशों पर बड़ी सावधानी से विचार करना चाहिए और उन्हे सोच-विचार कर कार्यान्वित करना चाहिए । भारत में गाँवो में और नगरों में यह सामान्य / धारणा है कि बालक को ईश्वर-रूप माना जाता है । ब्रिटिश शासन में हम बालकों की दशा सुधारने की दृष्टि से कोई उपयुक्त बाल नीति निर्धारित नहीं कर सके । // जैसा पंडित नेहरू ने अपना विचार प्रकट किया था कि यदि बालकों की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता और बालक यह अनुभव करते हैं कि वह भी हमारे /// सभी क्रियाकलापों में सहभागी हैं तो देश का अधिक ठोस निर्माण होता ।

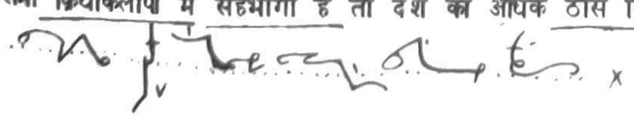

हमारे देश में अनेक संगठन और राज्य सरकारें बालकों की देखभाल करती हैं किन्तु धन की कमी के (1) कारण राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ठोस कार्य नहीं हुआ है । मुझे विश्वास है कि यदि सामान्य जनता में से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 5 पैसे का योगदान करें तो हमारे / पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र हो सकता है और हम बालकों के लिए केन्द्र और राज्यों के स्तर पर रचनात्मक और व्यापक नीति बना सकते हैं । बड़े खेद का // विषय है कि हमारे देश में बालकों और युवकों को सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । राष्ट्रीय क्षेत्र में बालकों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए कोई अनिवार्य /// व्यय मद नहीं है । हमारे देश में बालकों की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है । जब कोई देश समाजवादी होने का दावा करता है तो युवकों और बालकों की (2) देख-रेख का भार उस देश की नीति का मूल आधार होना चाहिए ।

प्रथम टिप्पणी में कहा गया है कि सभी बालकों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । / लेकिन स्वास्थ्य केन्द्र उन्हें साधारण औषधियाँ भी नहीं देते हैं । परिवार नियोजन के साथ-साथ सरकार की वित्त तथा प्रोत्साहन नीति के माध्यम से वर्तमान बालकों की उचित देख-रेख // की जानी चाहिए । यदि हमने इस पहलू की उपेक्षा की तो इस देश के युवकों और बालकों का मस्तिष्क एवं प्रतिभा पूर्णतः कुण्ठित हो जाएगी । क्या ये सिफारिशें केन्द्र के ///वित्तीय प्रोत्साहन तथा राज्य सरकारों के उचित प्रोत्साहन के बिना सफल सिद्ध हो सकती हैं ? अतः योजना आयोग के वित्तीय प्रोत्साहन से बालकों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष (3) यथार्थ नीति निर्धारित की जानी चाहिए । यदि बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए धन खर्च किया जाये तो बेहतर होगा । इस प्रयोजन के लिए दी गयी / राशि बढ़ा कर तीन-गुनी की जानी चाहिए । यह भी सिफारिश की गई है, जो स्वागत योग्य भी है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कठोर // काम पर नहीं लगाना चाहिए और उससे भारी काम नहीं करवाना चाहिए । यदि इसे सार्थक बनाना है तो इसे कठोरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि भावी /// पीढ़ी के निर्माण के लिए सरकार को चाहिए कि बालकों के लिए उचित शिक्षा तथा सही-सही देख-रेख का प्रबन्ध करें । बालक राष्ट्र की सम्पति है और यदि (4) इस प्राकृतिक सम्पत्ति का उचित उपयोग नहीं किया गया तो हम अपने देश की दशा सुधारने के बारे में सोच नहीं सकते ।

विभिन्न संवैधानिक उपबन्धों तथा राज्य सरकारों द्वारा / बनाए गए कानूनों के बावजूद हम अपने बालकों के लिए समुचित कार्य भी नहीं कर सकते हैं । कोई ऐसा विभाग भी नहीं है जो बालकों के स्वास्थ्य तथा उनकी विभिन्न // समस्याओं का दायित्व अपने ऊपर ले सकें । इसका यह परिणाम हुआ है कि बाल-कल्याण सम्बन्धी योजनाएँ तो आरम्भ की जाती है लेकिन इन योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित /// नहीं किया जाता है । अतः मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि बाल-कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी विभागों में बेहतर तालमेल हो । (5) (600 शब्द)

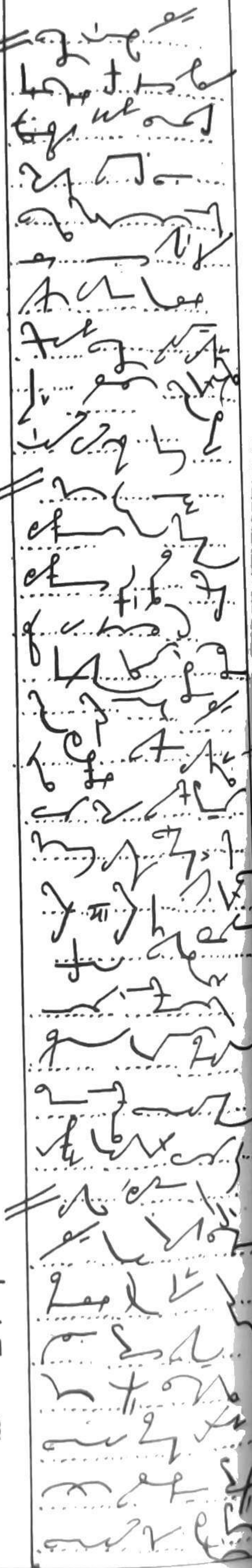

www.StenoIQ.com

अभ्यास-98

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों के खाद्यमंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन के बाद केन्द्रीय खाद्यमन्त्री ने बताया कि अगले अप्रैल में गेहूँ और धान का थोक व्यापार सरकार अपने / हाथ में ले लेगी । यह खुशी की बात है कि सब प्रदेशों के मन्त्री इस पर सहमत हो गये हैं । अन्न का जो संकट आज देश के सामने है, यह // किसी से छुपा नहीं है । हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात, निर्यात, चीनी, कपड़ा, कोयला, लोहा /// अनाज आदि सब के व्यापार पर सरकार अपना कब्ज़ा करना चाहती हैं । मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकारीकरण को ही समाजवाद का पर्याय समझा जा रहा है जो गलत है । §1§

दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले पचास लाख टन से अधिक के भण्डार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी दो करोड़ टन अनाज की / खरीद फरोख्त में 20 अरब रुपए फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके पीछे क्या आर्थिक तर्क है यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं । अभी // हाल तक सिर्फ छह प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं । ///

सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए । §2§ अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है । जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका अदा कर सकती है और अगर वह अनाज का अभाव न होने दे / तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार कई परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है । लेकिन अब जो कदम उठाया गया है, उसे सही // मानकर उसको कार्यान्वित किया जाए ।

राज्यपालों ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी थी कि थोक व्यापार के बाद खुदरा वितरण को भी गांव स्तर तक सरकार को संभालना होगा । /// फिलहाल वितरण के लिए सिर्फ एक लाख 58 हजार दुकानें हैं, जो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं । सरकार को अब छह लाख गाँवों की अन्य आवश्यकता को देखना होगा । §3§ इसके फलस्वरूप या तो स्थिति सरकार के काबू के बाहर होगी या फिर सरकार का काम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि उसे संभाल सकना असम्भव होगा ।

चीनी की तरह / अनाज के मामले में यदि सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्ट रहे तो जनता की कठिनाई बढ़ेगी । पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधान सभा में अनाज की सरकारी दुकानों की जो तस्वीर // पेश की गई, वह देश के गाँव-गाँव की ऐसी कहानी बनेगी जो आग में घी का काम करेगी । /// गल्ले के थोक व्यापार उपभोक्ता और ज्यादा

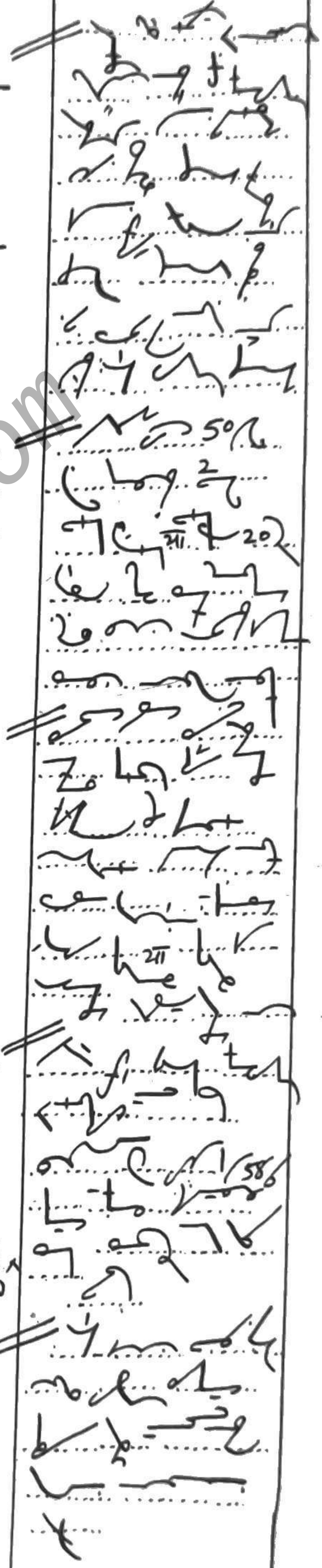

चोरबाजारियों के चंगुल में फंस जाएगा । /// गल्ले के थोक व्यापार के सरकारीकरण का गांव के भूमिहीन मजदूरों और सूखा पड़ने पर आम ग्रामीणों पर काफी असर पड़ने वाला है क्योंकि इस दिशा में सरकार की मशीनरी {4} इतनी सक्षम नहीं कि अन्न को ठीक समय पर पहुँचा सके । अन्न सरकार पहुँचा नहीं सकेगी और गाँव के बड़े किसान और छोटे गल्ला व्यापारी अनाज को मनमाने भाव पर / बेचना आरम्भ कर देंगे, जिससे जनता की कठिनाई कम होने के स्थान पर और बढ़ जाएगी । दूसरे, परिवहन और भण्डारन की कमी के कारण हालत और बिगड़ेगी । सरकारी अधिकारी // इस स्थिति को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोयला, लोहा आदि के मामले में किया है, उसी तरह गेहूँ और चावल के मामले /// में भी कर सकेंगे ।

लोकसभा में पिछले दिनों बताया गया था कि 1969-71 के बीच सरकारी खाद्य निगम को 17·23 करोड़ रुपया का घाटा हुआ । घाटे का {5} मुख्य कारण ढुलाई और भंडारन के दौरान हुई अनाज की बर्बादी बतायी गई । इतना घाटा होना ठीक नहीं । फिर सरकारी खाद्य निगम के क्रियाकलापों की जाँच का काम केन्द्रीय जाँच ब्यूरो / को सुपुर्द किया गया है, इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए । इस पृष्ठभूमि में बेहतर यही होगा कि सरकार इस सम्बन्ध में किसी के दबाव में न // आकर वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाए । {665 शब्द}

www.StenoIQ.com

अभ्यास-99

सभापति महोदय, अभी दो दिन पूर्व राज्य सभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही / है । हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किन्तु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं // की जा सकती । राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है । उन्होंने यह /// भी कहा कि जहाँ कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं जांच-पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है । सरकार इस सम्बन्ध में {1} कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए / जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराये जाए । यह सब सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक सम्पर्क रखा है, किन्तु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम // पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है । केवल हाथरस का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है स्वयं राज्यमंत्री नें इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्य सभा में /// रखा है उससे भी इसकी पुष्टि होती है ।

राज्यमंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि सन् 1969-70 के वर्ष में हरिजनों पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में {2} 1541 घटनाएँ घटी । आदिवासियों पर जो अत्याचारों

ने कितना भयंकर रूप धारण किया कि वह इस बात से साबित हो / जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिन्दा जलाया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई । शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर // लिया गया था उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया । इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं । वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया /// गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएँ हुई । क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई सन्देह रह जाता है ।

वक्तव्य में यह भी बताया §3§ गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठायें । पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं, जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि / हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएँ अब कम हो रही है । फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी । अकेले मध्य प्रदेश में // 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी । ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का हौंसला बढ़ेगा तथा हरिजनों का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास /// खत्म होता जाएगा ।

हरिजनों पर अत्याचार को रोकने के लिए कानून हो सकते हैं परन्तु इन अत्याचारों से यह स्पष्ट है कि एक तो उन कानूनों की बहुत परवाह नहीं §4§ की जाती और दूसरे पुलिस एवं प्रशासन दोनों उन पर अमल करवाने के लिए बहुत सतर्क नहीं है । पुलिस के संबंध में तो यह आरोप लगाया गया है कि किन्हीं / मामलों में पुलिस की मिलीभगत से अत्याचार हुए हैं । कुछ भी हो यह बहुत चिन्ता की बात है और इसे रोकने के लिए तुरन्त ज़ोरदार कदम उठाये जाने की ज़रूरत है । यह सही है कि केवल कानूनों के ज़रिए हरिजनों के साथ भेदभाव एवं अत्याचार को नहीं रोका जा सकता । उसके लिए समाज में एक आवश्यक चेतना पैदा करने /// की ज़रूरत है । लोग यह समझें कि हरिजनों के अन्दर भी वही खून है जो उसके अन्दर है । इसके साथ ही साथ सरकार यह भी करे कि जिन कारणों से §5§ ये अत्याचार होते हैं उन्हें हटाया जाय । इस सिलसिले में यह सुझाव भी कम विचारणीय नहीं है / कि जिन क्षेत्रों में हरिजनों पर अत्याचार हों वहाँ के समस्त लोगों पर दंडात्मक कर लगाया जाय । इससे निश्चय ही अत्याचार करने वालों पर अंकुश लगेगा । § 656 शब्द §

अभ्यास-100

मित्रों आप लोगों के बीच आज इस गोष्ठी में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । प्रसन्नता इस लिए हो रही है कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है / अब हम हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करेंगें और यह देखेंगे कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से किस प्रकार यह सम्भव हो // सकता है ।

www.StenoIQ.com

भारतीय इतिहास एक है और हमारी एकसूत्रता हजारों वर्षों से इसी रूप में चली आ रही है। गंगा का पानी चाहे जिस क्षेत्र में बहे, चाहे जहाँ /// रहे, उसकी पवित्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार चाहे हम अपनी भावनाओं को किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करें, हमारी भावनाएँ वही रहती हैं, उनका आवरण (1) भिन्न हो सकता है। जिस तरह से विभिन्न वेशभूषा में यहाँ बैठे हम सभी भारतीय हैं उसी प्रकार चाहे जिस भाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करें, विचार / तो हमारे भारतीय ही होंगे।।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार कार्य के साथ में भी बहुत वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और मेरी यह धारणा है कि // हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच कहीं कोई मतभेद नहीं है। यदि कहीं कोई मतभेद है भी तो वह क्षणिक है स्थाई नहीं। गांधी जी ने आज से 50 वर्ष /// पूर्व कहा था कि भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच किसी प्रकार की स्पृद्धा हानिकारक है और जिस तरह एक भाई अपनी अनेक बहनों को एक साथ लाड़-प्यार (2) देता है, हम अपने देश की सभी भाषाओं को उसी प्रकार लाड़-प्यार दें तथा उनकी रक्षा करें। भारतीय भाषाओं को यदि हम समुचित स्थान नहीं देंगे तो हम अपनी / मातृभाषा को भूल जायेंगे और धीरे-धीरे हमारे में राष्ट्रीय भावना समाप्त हो जायगी।

आज इस पुस्तक मेले में देश की सारी भाषाओं की पुस्तकें एक ही मंडप में // प्रदर्शित हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि ये भाषाएँ देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ रही हैं और इस मंडप के /// माध्यम से "अनेकता में एकता" की सिद्धि हो रही है। आज इस गोष्ठी में हमारे सम्मुख अनेक साहित्यकार, कवि, मनीषी, चिन्तक और विद्वान उपस्थित हैं जिनके विचार सुनने का आपको (3) सौभाग्य प्राप्त होगा। इन लेखकों की रचनाओं से हमें यह बोध होता है कि हमारा देश कितना महान है और हमें यह भी अहसास होता है कि हमारी सभी भाषाएं / एक है तथा भारत की अमूल्य निधि हैं।

आज का चर्चा का विषय है "हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान" मेरी यह मान्यता है कि इस प्रकार का // आदान-प्रदान सदियों से हमारे बीच अर्थात् हिन्दी और भारतीय भाषाओं के बीच होता रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हमारी सभी /// भाषाओं के बीच एक-दूसरे से आदान-प्रदान की परम्परा रही है। सभी भाषाओं में हमारी प्राचीन संस्कृति के स्वर बोलते हैं, सभी भाषाओं में पहले विदेशी शासन से मुक्ति (4) केलिए संघर्ष के स्वर गूँजे थे। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस पारम्परिक आदान-प्रदान और पारस्परिक समन्वय पर ही आधारित है। देश के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में / जो आदान-प्रदान सहज-सुलभ हैं, वह ज्ञान के क्षेत्र में भी होना चाहिए। भाषाएँ परस्पर आदान-प्रदान से विकसित होती हैं, आदान-प्रदान का विरोध नहीं करती। // हमारी भाषाओं ने कई शब्द विदेशी भाषाओं के अपनाएँ हैं और विदेशी भाषाओं ने हमारी भाषाओं के भी कई शब्द अपनाऐ हैं। हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि /// इस प्रकार के आदान-प्रदान को और गति मिले। प्रकाशन के क्षेत्र में आदान-प्रदान की समस्याओं, समाधानों और सम्भावनाओं की खोज करने वाली यह गोष्ठी स्वागत योग्य हैं। (5) जो एकता और दृढ़ता हमें साहित्य दे सकता है, वह किसी और साधन से सम्भव नहीं हो सकता। धन्यवाद। (619 शब्द)